General discussion on the Budget 2024-2025; General discussion on the Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-2025 and Demands for Grants in respect of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-2025

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह **(**अकबरपुर**) :** माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे लिए यह बड़ा अत्यंत गौरव का विषय है कि आपके द्वारा बजट पर मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया गया है । मैं केन्द्रीय बजट वर्ष 2024-25 की सराहना के लिए खड़ा हुआ हूं ।

13.05 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

हमारे मन में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत यह बजट वर्ष 2047 तक विकसित भारत के प्रति हमारी अडिगता का प्रमाण है । प्रधान मंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और समावेशी विकास के प्रति समर्पण हमारे देश की प्रगति को प्रेरित और संचालित करता है ।

महोदया, 11 सितंबर, 1893 को, जिस समय दुनिया के लोग भारत को कमजोर भारत बताते थे, उस समय 17 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उद्बोधन में आने वाले समय में भारत को मजबूत भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज यह बजट भारत के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उसी को पूरा करने वाला बजट है ।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी सुधार की क्षमता पर निर्भर करती है । यह बजट उसी सुधार की भावना को दर्शाता है तथा हमारे राष्ट्र को उज्ज्वल और समावेशी भविष्य की ओर ले जाता है ।

महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संविधान सभा में जाने के लिए इस लोक सभा का सदस्य होना जरूरी होता था । जब वे पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़े तो उस समय उनके खिलाफ सामने बैठे हुए लोगों ने प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन यह मेरा सौभाग्य है कि पूरे देश को ?एक विधान, एक प्रधान? बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उनका सहयोग करके उन्हें वहां से लोक सभा का सदस्य बनाने में मदद की । उन्होंने भारत का संविधान बनाने में अपनी महत्ती भूमिका का निर्वहन किया । केवल महत्ती भूमिका का निर्वहन ही नहीं किया, बल्कि उनके द्वारा बनाए हुए संविधान के तहत, चूंकि जिस समय इस देश में 25 जून, 1975 को इमरजेंसी लागू की गई थी, तब मैं बहुत छोटा बालक था । मुझे याद है कि हमारे सामने बैठे तमाम राजनीतिक दलों के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी यहां बैठे हुए हैं । जब कांग्रेस ने 19 जनवरी, 1977 को चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के बाद इमरजेंसी खत्म नहीं की थी, उस समय एक जनसंघर्ष समिति बनी थी । उस जनसंघर्ष समिति के माध्यम से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हमारे आवास पर कंचौसी बाजार में 200 लोगों का भोजन बना कर एक बड़ी सभा की थी । उस समय हमारे सामने सदन के नेता मुलायम सिंह यादव जी, कमांडर अर्जुन सिंह जी भदौरिया, बाबू राम जी शुक्ला, जो जनसंघ के नेता हुआ करते थे, रस्तोगी जी जनसंघ के नेता हुआ करते थे, चौधरी हरमोहन सिंह यादव, राम गोपाल यादव, सत्यदेव त्रिपाठी आदि बहुत सारे लोगों ने उस समय संघर्ष किया था । उसके बाद जनता पार्टी का गठन हुआ था । मैं कहना चाहता हूं कि आज जो लोग संविधान की बात करते हैं, वे भूल गए हैं कि उन्होंने साथ लेकर उन्हीं लोगों का विरोध करने का काम किया था, जो आज कहीं न कहीं

देश की सत्ता पर पहुंचने के लिए एक दोहरा स्वप्न देख रहे हैं कि किसी तरीके से हम सत्ता में पहुंचे । आज यह बजट हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है ।

जहां तक किसानों का सवाल है, भारत की सरकार समझती है कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । यह बजट कृषि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित करता है, जिसमें उच्च उत्पादकता और लचीलेपन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । यह सरकार 32 फील्ड और बागवानी फसलों की नई उच्च उत्पादक और जलवायु, लचीली किस्मों की शुरुआत करते हुए एक करोड़ किसानों के बीच में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरसों और तिलहन की पैदावार को भी और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा भी आया था कि जहां किसानों ने खाद और बीज के लिए लाठी खाई थी । एक समय ऐसा भी आया था कि जब दैवीय आपदा हुई थी तो लोगों ने अपने और पराये की पहचान करने का काम किया था । हमारी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, जिस समय 31 मार्च, 2016 के पहले के जो किसान के ऋण हुआ करते थे, अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने एक लाख तक के ऋण को माफ करने का काम किया था । यह बजट वही प्रदर्शित करता है ।

जहां तक नौकरी सृजन और कौशल विकास की बात है, एक ओर जहां नौजवानों को नौकरी देने के लिए, इस बजट में महिलाओं को भागीदारी देने के लिए विकास के उद्देश्य से प्रभावित होकर तमाम योजनाएं शुरू की हैं, वही महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, महिला छात्रावासों और बाल देखभाल सुविधाओं जैसे पहलों को प्रोत्साहित करने वाला यह बजट है । पीएम के पैकेज में तीन हजार रोजगारों से जुड़े शहर तमाम योजनाओं में शामिल हैं । जो विशेष रूप से निर्माण के क्षेत्र में कर्मचारियों और नियोक्ताओं को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती हैं ।

अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को उद्योगों से संबंधित कौशल प्रदान करने और शीर्ष कम्पनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम का अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है ।

एक समय ऐसा भी था, जहाँ नौकरी एवं रोज़गार देने के लिए तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने अवैध वसूली करके तमाम किसानों को खेत बेचने के लिए मजबूर किया था । लेकिन आज हमारी सरकार ने जब नौकरी देने की बात आई तो देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने नौकरियों के अवसर देकर और एक पारदर्शी तरीका अपनाकर बहुत-से लोगों को रोज़गार देने का काम किया है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें ।

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह: माननीय सभापति महोदया जी, कृपया मुझे दो मिनट का समय दें ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह : मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ ।

जहाँ अपहरण का उद्योग था, उसे बढ़ावा दिया जाता था, आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और पूरे देश में कानून-व्यवस्था का राज स्थापित करके यह बजट हमें आगे ले जाने का काम करता है । जहाँ यह बजट तमाम योजनाओं के माध्यम से, जैसे पीएम सूर्य घर जैसी योजना में एक करोड़ लोगों को रोशनी देने का काम करता है, वहीं शहरी विकास की योजनाओं में भी 10 करोड़ लोगों को आवास देने में यह बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में 70 साल से अधिक के लोगों को ?आयुष्मान भारत? में जोड़कर उनको लाभ देने का काम किया है । हमारे क्षेत्र में, स्पीच एंड हीयरिंग यानी गूंगे-बहरे बच्चों के लिए अस्पताल, ऐसा अस्पताल अगर देश के किसी कोने में है, तो वह केवल साउथ इंडिया के मैसूर में है । मेरा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में भी स्पीच एंड हीयरिंग हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है । माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे आज के स्वास्थ्य मंत्री और तत्कालीन मंत्री जी ने मिलकर उसे पूरा करने का काम किया है ।

मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन मांगों को रखते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ ।? (व्यवधान) हमारे क्षेत्र में 1980 मेगावाट का एक पावर प्लांट है, जिसका उद्घाटन वर्ष 2016 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री पीयूष गोयल जी ने किया था । इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए एक साथ जारी किये गए हैं ताकि उसके काम में और अधिक तेजी आए । इससे 600 मेगावाट का उत्पादन हो चुका है ।

मेरी आपसे मांग है कि इसे जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाए ।? (व्यवधान) हमारे देश में रेलवे के क्षेत्र में, अभी माननीय मंत्री जी यहाँ पर नहीं हैं, रेल के बजट में? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, धन्यवाद ।

SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR): Hon. Chairperson, today, I rise to speak on General Budget 2024-25. I heard Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman and I was shocked and wondered whether this Budget is meant for our entire country or for Andhra Pradesh and Bihar States only. We were skeptical about this Government?s power hunger, but now everybody is pretty sure that it is 100% true. Maharashtra tops in India in terms of GST collection but only Rs. 7500 crore have been allocated to Maharashtra. But on the other hand, Rs. 60,000 crores have been given to Bihar just because it is supporting them to secure power and I feel sorry about it. People residing in Maharashtra are also Indian citizens and they should not be ignored in this manner. They may be happy but, they should be ashamed of it as they have failed on all fronts. Around 1641 farmers have committed suicide in my constituency Chandrapur Yavatmal of Vidarbha region and no compensation has been given by the Government to the family members of the deceased. You started crop insurance scheme in the name of Prime Minister but no insurance benefits have been provided to farmers even after a year. The Government is indifferent towards the issues of farmers and it is not ready even to discuss them. The Union Government should give instructions to the State Government in this regard. The issue of MSP is not resolved yet, and farmers are not getting remunerative prices for their produces. The Government still continued to charge GST on seeds and fertilizers and this is very shameful.

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, आप अपनी बात एक मिनट में कंप्लीट कीजिए ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR Madam, it?s a rainy season and the people in my constituency are facing flood like situation. In some villages like Chichkholi and Pimpalkhut, most of the houses are submerged as the lakes are overflowing there. The paper leak case of NEET Exam is a matter of serious concern as bogus doctors like Munnabhai MBBS will be studying in Medical colleges. We have already seen a case of bogus IAS officer in Maharashtra. BJP ruled State Government had promised to continue with OPS, but the problem still persists and the teachers and allied staff have been waiting for it. Tri-party Government in Maharashtra is not ready to keep its promise and implement it once again.

Nobody is happy in Maharashtra under three party regime. They had promised to provide 2 crore jobs but the youths are still deprived of jobs. Same in the case of reservation too. BJP Government has dismissed the idea of conducting caste census and hence the issues of OBCs and Marathas are still pending.

Most of the coal mines in Maharashtra fall under my constituency and the issues related to it are also pending. The farmers who had handed over their farm lands for coal mines, still waiting for compensation.

Crimes against women are increasing in India day by day, but the Government is not looking into it seriously. We can look at the Manipur issue. This Government is also not honouring the sacrifices made by our brave soldiers.

I am a committed Congress worker and I consider myself very lucky that we are working for our Congress Party under the leadership of Shri Rahul Gandhiji. We all know about historical Dandi March led by Mahatma Gandhiji. Hon. Rahul Gandhiji also launched Bharat Jodo Yatra and I must say, it was historical event.

Thank you.

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Thank you, Madam for giving me an opportunity to speak on the Union Budget.

In the beginning, I would like to congratulate hon. Finance Minister for her record seventh consecutive Budget presentation. I really acknowledge our hon. Prime Minister and all our leaders of the party, and more than that the people of Chikkballapur to have elected me and allowed me to be present in this august House.

Madam, this Budget strikes a very fine balance between financial prudence and social welfare. I would like to call this Budget pragmatic. It reflects the hon. Prime

Minister's vision for Viksit Bharat, where farmers prosper, the poor lead a life of dignity, the middle-class people get their due for their hard work, and the Indian enterprises get a boost. It ensures that it empowers all sections of society to attain prosperity. They have laid down the nine priority areas, which I would not like to repeat because the other hon. Members of the House have already repeatedly mentioned it. It is unfortunate that the Opposition Leaders and a few members, have termed this Budget in a very negative way by saying, ?It is like a *kursi bachao* Budget. This Budget appeases the alliance partners. This Budget is like a Davidian budget. This Budget is like a copy of our manifesto. One of the hon. Members says that this is just a replica of the Chief Minister's Budget?. Madam, I would like to term this Budget as ?*kisan bachao* Budget?. This is ?*nari shakti bachao* Budget?. This is a ?*yuvashakti bachao* Budget?. This is a ?*gareeb bachao* Budget?. This is an ?Indian economy *bachao* budget?. This is the ?*desh bachao* Budget?.

There was a slogan of *?Gareebi Hatao, Desh Bachao?* in 1971. They won the election also. But who removed poverty in this country? The Economic Survey says that about 113 million Indians are out of poverty during our able Prime Minister Modi ji's regime, not in the earlier regimes. They say that we appease the alliance partners. But I want to know, when did the Congress Party come to power in this House on its own? They came to power way back in 1984 when the unfortunate assassination of Shrimati Indira Gandhi took place. They won 415 seats. In 1999, they won 114 seats. In 2004, they won only 145 seats. At that time, the strength of BJP was 138. Still, they ruled for five years with 34 alliance partners. In 2009, they won only 206 seats. That was UPA-II. But in 2014, it is our Party, under the able leadership of Shri Narendra Modi ji, which won 282 seats whereas Congress fell to 44 seats. In 2019, our Party won 303 seats.

Today, we may have lost a few seats, but this is a pre-poll alliance. This is not a post-poll alliance. From 2004 to 2009, it was UPA alliance. The alliance was made of 34 parties. Should we ask whether their Budgets were also only to impress their alliance partners or in the interest of the nation?

Madam, the Budget can only be deliberated and discussed based on numbers and statistics and not the political rhetoric. So, based on that, when I said the farmer's welfare was the first priority of Modi Ji's Government, I will come with the facts and figures. The very first file that the hon. Prime Minister signed after assuming office for the third-term was dedicated to the farmers, including the recently released 17th installment under PM-Kisan Samman Nidhi Yojana. Madam, eleven crore farmers

across the nation have received well over Rs. 3.24 lakh crore. This is the commitment of the Government towards farmers.

Similarly, during the UPA's regime, what was the budget for agriculture? What was the budget they had allocated for farmers? It was only Rs. 22,000 crore in 2014. But today, Modi Ji has increased this budget from Rs. 22,000 crore to Rs. 1,52,000 crore during 2024-25 Budget. They say, this Budget is against the *kisans*.

Similarly, in 2013 and 2014, the UPA Government extended a loan to the tune of Rs. 7 lakh crore to the farmers, whereas, Narendra Modi Ji's Government provided Rs. 19 lakh crore to the farmers today.

We have experienced a very unique situation during the last regime. One is the COVID-19 pandemic and the second one is the Russia-Ukraine conflict because of which, internationally, the fuel and fertilizer prices increased globally. But Prime Minister Narendra Modi Ji did not pass on any burden to our farmers. This is the commitment of the Government towards the farmers.

The total fertilizer subsidy during 2013-2014 was only Rs. 73,000 crore, whereas now, it has increased from Rs. 73,000 crore to Rs. 2,55,000 crore in 2023-2024. ? (*Interruptions*). Madam, This is the first time I am speaking. Please allow me three to four more minutes. I will make very, very valid points based on statistics and numbers only.

Now I will talk about MSP, their pet subject. As a farmer's son, I would like to say this. The paddy price per quintal, what they were giving was Rs. 1,310. But what is the increase that the Modi Ji's government gave? Today, in 2023-2024, there is 67 per cent increase and per quintal, we are giving Rs. 2,300 rupees. For jowar, they were giving only Rs. 1,500 per quintal, whereas our Government gives Rs. 3,371 per quintal, which is a 112 per cent increase. Similar is the case with pulses and oilseeds. For example, I would like to quote only one commodity, moong dal. During the UPA Government regime, moong dal was only Rs. 4,500 per quintal. But today, it is Rs. 8,682 per quintal. It means there is an increase of 124 per cent during our Government.

As I said, this year a provision of Rs. 1.52 lakh crore have been made for the agriculture sector to benefit the farmers, doubling their income.

They talk about cooperative federalism. But it is under Modi Ji's Government that the true spirit of cooperative federalism has accepted the recommendations of 14th and 15th Finance Commission.

Over the last decade, around 41 per cent to 42 per cent of Central taxes have been shared with the States, a substantial increase from the earlier devolution share of 32 per cent.

Today, the fiscal deficit has been reduced. As the Finance Minister has already said, the aim is to bring it from 5.5 per cent to below 4.5 per cent.

I would like to conclude by quoting Swami Vivekananda?s quote because Modi ji?s Government is for the welfare of the people. I quote:

?Appreciation or no appreciation, I am born to organise these young men; nay, hundreds more in every city are ready to join me; and I want to send them rolling like irresistible waves over India, bringing comfort, morality, religion, education to the doors of the meanest and the most downtrodden. And this I will do or die.?

This is exactly what the Modi Government will do for the youth. Whether you appreciate or not, we will continue our commitment towards the youth of this country. It does not matter whether you criticise or mock us. We will live for the youth, *mahila*, farmers, kisans and every segment, every section of this country. This is our Government?s strong commitment.

Thank you very much for the opportunity given.

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्यगण, जो माननीय सदस्य बजट पर अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं, वे सभा पटल पर दे सकते हैं ।

श्री अखिलेश यादव **(**कन्नौज**) :** सभापति महोदया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट 2024-2025 पर बोलने का मौका दिया ।

महोदया, यह इस सरकार का लगातार ग्यारहवां बजट है । ग्यारहवें बजट के बाद भी नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है । जो लोग सरकार में हैं, तो सरकार के लोग तो इसके बारे में अच्छी बातें कहेंगे ही । पर, इससे न केवल नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है, बल्कि सरकार बनने के बाद चेहरों पर जो खुशी होनी चाहिए थी, उन चेहरों पर उतनी खुशी दिखाई नहीं दी । इस ग्यारहवें बजट में बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, गांवों के लिए और उनकी तकलीफ-परेशानी का जो मुद्दा है, वह मुझे ?नौ-दो-ग्यारह? दिखाई दे रहा है ।

महंगाई में घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के बड़े-बुजुर्गों की दवा, इलाज़ में महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है, ये बातें परिवार वाले बखूबी जानते हैं । मैं जब सत्ता पक्ष के लोगों के आंकड़ों को देखता हूं और

सुनता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर दस सालों में इतना सब कुछ अच्छा हुआ है तो फिर आप ?हंगर इंडेक्स? में कहां खड़े हैं? दस सालों के बाद भी यही बात सत्ता पक्ष की तरफ से आएगी कि हम कहां खड़े हैं ।

आपने ?मेक-इन-इंडिया? का एक बड़ा सपना दिखाया । उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य से लोक सभा के सबसे ज्यादा सांसद चुने जाते हैं । पर, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला । हमें प्रधान मंत्री जी मिले हैं ।

सभापति महोदया, दस सालों में क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जैसे कोई आई.आई.एम. मिला हो, कोई आई.आई.टी. मिली हो? किसी समय उत्तर प्रदेश को जो आई.आई.आई.टी. मिली थी, उसमें सरकार की तरफ से क्या सहयोग हुआ है? न केवल ये संस्थाएं, बल्कि जो गवर्नमेंट के एडुकेशन के इंस्टीट्युशंस हैं, वैसे कौन से नए इंस्टीट्यूशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं?

मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ी संस्था आई हो, तो आप मुझे बता दीजिए । जो दो एम्स आए हैं, मुझे याद है कि रायबरेली एम्स के लिए समाजवादी सरकार में ज़मीन दी गई, उसका परिणाम है कि वहां एम्स बन गया । गोरखपुर में भी जो एम्स आया, उसके लिए भी समाजवादी सरकार ने ज़मीन दी थी, तब वह एम्स आया । अगर वहां दो एम्स आ भी गए हैं, तो क्या उनमें पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है? केवल यही नहीं ?मेक इन इंडिया? है । सपना तो यह भी दिखाया गया था कि अगर प्राइवेटाइज़ेशन हो जाएगा तो नौकरियां मिल जाएंगी । कुछ हद तक तो बहुत सी चीज़ें प्राइवेटाइज़ हो गई हैं, लेकिन नौकरियां कम होती चली गईं और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो पीडीए परिवार के लोगों को जो हक़ और सम्मान मिलता है, क्या यह सरकार वह दे पा रही है? टैक्स कलेक्शन में सपना दिखा रहे हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं । आखिरकार एक्सपोर्ट क्यों कम होता चला जा रहा है? हम ट्रेड डेफिसिट को कैसे खत्म करेंगे? दस सालों में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और ऐसा कुछ न दिख रहा हो और यूपी के जो परिणाम आए हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है ।

सभापति महोदया, अगर यह सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां आप हारे ही नहीं हैं, आपकी सीटे ही कम नहीं हुई हैं, देश के प्रधान मंत्री जी भी वोट से हारे हैं । जो कभी पांच लाख वोटों से जीते थे या दस लाख वोटों से जीतने का टार्गेट बनाया था, वे इस बार कितने वोटों से जीते हैं? आप कम से कम इन चीज़ों को तो देखें ।

महोदया, जब मैं सत्ता पक्ष के लोगों को सुनता हूँ तो मुझे लाइनें याद आ जाती हैं कि

?वह झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से ।

मैं ऐतबार न करता तो क्या करता॥?

सभापति महोदया, मुझे याद है कि देश के प्रधान मंत्री ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया था और उस बस में 35 लोग बैठ कर अयोध्या आए थे । महोदया, उस समय भी मैंने यह माँग की थी कि जनकपुर से यह यात्रा शुरू हो रही है और अयोध्या तक बस से लोग आएंगे तो पता नहीं कितने घंटों में पहुंचेगे? मैंने उस समय मांग की थी कि वहां से ले कर आयोध्या तक एक्सप्रेसवे बनना चाहिए कि जो लोग जनकपुर से अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं, और बस से आ रहे हैं, कम से कम उनकी तकलीफ और परेशानी तो कम होती । जो आप कहते है एफडीआई बहुत आया है । मैं अभी सुन रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि मोबाइल फोन बनने लगे हैं । मैं आपको बताना

चाहता हूँ कि मोबाइल फोन बन नहीं रहे हैं । समाजवादी पार्टी की सरकार में, नोएडा में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी थी, उसके तहत वे इंडस्ट्रीज़ आई थीं । वे इंडस्ट्रीज़ जितनी आई हैं, उस समय की पॉलिसी के तहत आईं हैं और वहां मोबाइल बन नहीं रहे हैं, मेक इन इंडिया नहीं हो रहा है । ? (व्यवधान) लेकिन ज़मीन किसने दी है? उन लोगों को ज़मीन किसने दी है? बिना ज़मीन के हवा में बना दो तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा । ? (व्यवधान) आप कह रहे है कि आप एफडीआई लाए हैं । अगर हम पूरे देश का एफडीआई देखें तो उत्तर प्रदेश को कितना एफडीआई मिला है?

सभापति महोदया, अगर एक पर्सेंट से भी ज्यादा एफडीआई उत्तर प्रदेश को मिला हो तो बता दीजिएगा ।

सभापति महोदया, जो प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवर रन हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है?

सभापति महोदया, आज ही जब हम लोग सदन में आए, तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है । जब से यह सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंप्टीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा ।

सभापति महोदया, मैं तो अखबारों में पढ़ता था कि ये तोड़-फोड़ करके सरकार बनाते हैं । पिछली बार के एक सदस्य तोड़-फोड़ करके शायरी भी बनाने लगे हैं । जिस प्रोजेक्ट के लिए, प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे बड़े हवाई जहाज हरक्यूलस विमान को लेकर आए थे और वह सड़क पर उतरे थे । वह एक्सप्रेस-वे पर उतरे थे ।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि यहां जितने भी माननीय सदस्य हैं, सबने देखा होगा और सबने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा ।

सभापति महोदया, उस एक्सप्रेस-वे को अगर किसी ने बनाया था, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी का पार्ट और एलाइनमेंट थी, वह समाजवादियों की देन थी । वह आपकी देन नहीं है । यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस बजट में शायद सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है । पैकेज देने में हमें कोई नाराजगी नहीं है । आप और पैकेज दीजिए । अगर आप बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप केवल 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे रूक गया था, तो दूसरे के काम को जो अपना काम बताते हैं, आप यह कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर भागलपुर तक आपने एक्सप्रेस-वे दिया है ।? (व्यवधान) वह अभी से नहीं, बल्कि बहुत पहले से बन रहा है । मैं यह नहीं कहना चाहता कि आपने क्या दिया । मैं यह कहता हूं कि आप केवल बिहार के लोगों को खुश करने के लिए बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेस-वे दे रहे हैं । मैं उससे सहमत हूं कि आप बिहार की तरक्की के लिए एक्सप्रेस-वे दें, लेकिन पखनपुरा जो आखिरी गांव है, जहां पर एक्सप्रेस-वे छूट गया है, वहां से आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं । हमारे स्टेट के लिए आप कोई नया एक्सप्रेस-वे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दिल्ली के बजट से क्यों नहीं दे रहे हैं? यू.पी. अपने बजट से एक्सप्रेस-वे बना रहा है । आप बताइए कि आपने यू.पी. को कोई एक्सप्रेस-वे दिया हो । आपने कोई एक्सप्रेस-वे नहीं दिया । मैं कहूंगा और आप अपनी सरकार को याद दिलाइएगा ।

सभापति महोदया, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बना था ।? (व्यवधान) अभी आपको उसका भी बताएंगे । उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे दिया है, यह दिल्ली के बजट का नहीं है । मैं मांग कर रहा हूं कि

दिल्ली की बजट से कोई एक्सप्रेस-वे मिलना चाहिए । जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे दिया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके वापस लौटे, अब रिपेयर का पैसा कौन देगा? वह एक्सप्रेस-वे आज भी रिपेयर माँग रहा है ।

सभापति महोदया, कोई कल्पना कर सकता है कि नया एक्सप्रेस-वे बना हो, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, वह आज रिपेयर माँग रहा हो! वह एक्सप्रेस-वे सिक्स लेन नहीं है । वह फोर लेन है । इसमें भी मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेस-वे है, यह अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बना है । इसको मुनाफा नहीं हो रहा है । बहुत ज्यादा टोल कलेक्शन नहीं है । इसको सतना से जोड़ दिया जाए । बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे जहां से शुरू हो रहा है, यह हमारे डिस्ट्रिक्ट इटावा से शुरू हो रहा है, कम से कम इसको हरिद्वार तक ले जाना चाहिए । हरिद्वार से लेकर सतना तक लोग चले जाएंगे, तो शायद बुंदेलखंड के लोगों को भी लाभ होगा । सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली और लखनऊ मिलकर उन एक्सप्रेस-वे की सेफ्टी से और उसकी डिजाइन से खिलवाड़ कर रहे हैं । जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जो डॉक्यूमेंट कहता है, वह कहता है कि सड़क का मीडियन 12 मीटर से लेकर 14 मीटर होना चाहिए । आप जाकर देखिए, जो पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस-वे बना है, उसका मीडियन कितना है? क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया है या नहीं? यह आपको विचार करना पड़ेगा ।

महोदया, जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर सवाल उठा था, उस समय पोलिटिकल पार्टीज़ से सुझाव मांगे गए थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं । उस समय समाजवादी पार्टी ने सुझाव दिया था कि लिपुलेख से लेकर ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनना चाहिए । कभी जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फौज का आना-जाना जल्दी हो जाए । मुझे याद है, जो अखबारों में मैंने पढ़ा था, सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया था कि वह 6 लेन हाईवे बनेगा । लेकिन जब टेंडर की बात आई तो सुनने में आया कि वह फोर लेन बनने जा रहा है । जब वह काम हो रहा है, मैंने दोबारा उसको देखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव्ड शोल्डर बन रहा है । सोचिए, कहां 6 लेन बनाने की बात थी, अब आप डबल लेन पेव्ड शोल्डर बना रहे हैं । पता नहीं किसने उस हाइवे को डिजाइन किया है? जितने भी कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं, कस्बे वाले नाला कहां बनायेंगे, घर ऊंचा करें या सड़क को तोड़ें? बहुत सारे कस्बों को सरकार ने समस्या के संकट में डाल दिया है ।

जो सरकार मंचों से यह कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे । आज तो सरकार को 11 साल हो गए । क्या किसान की आय दो गुनी हो गई? सरकार बताए । मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वे कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं । अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कानूनी गारंटी दीजिए । हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप एमएसपी की तैयारी कब करेंगे? दो गुनी आय में आप किसान को कितना देंगे? पिछली बार बजट में कहा गया था कि एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए देश को एक लाख करोड़ रुपये मिलेंगे । अगर देश के एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक लाख करोड़ रुपये मिले होंगे तो कम से कम यूपी का शेयर कुछ तो रहा होगा ।

सभापति महोदया, सरकार ने एक भी मंडी बनाई हो, तो बता दें । हां, यह अलग बात है कि कोई चीज सुधारने के लिए आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए किसी को पहले ही बता दे रहे हैं, तो वह बात अलग है । किसान वहां जाएगा, जहां उसको रेट मिलेगा । यह इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई-यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़ लाएंगे । हम अपने माननीय मंत्री जी से पूछेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? कॉप-21 में भी आप हो आए, जी-20 में भी आपने आश्वासन दिया । कुछ नहीं किया तो आपको क्या लाना पड़ रहा है, 109 हाई-यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़ । आप मुझे बताइए कि किसान तक इसे कब तक पहुंचाएंगे और उसको पहुंचाने के लिए

आपके पास क्या इंतजाम हैं? दूसरे पैराग्राफ में आप फिर बदल जाते हैं । अभी आप रेजिलिएंट वैराइटीज़ की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा देंगे । सरकार बताए कि रेजिलिएंट क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे किसानों को कैसे लाभ मिलेगा और नेचुरल फॉर्मिंग, जो किसान अभी भी कई जगह पर कर रहा है, क्या उसके लिए आपके पास बजट में अलग से पैकेज है?

सभापति महोदया जी, पारले जी बिस्किट से एक चीज सीखी है, महंगाई और मुनाफा । इस सरकार ने दस साल डीएपी खाद की बोरी को छोटा कर दिया, इससे और ज्यादा छोटा मत करना । जब किसान डीएपी लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आपको नहीं मिलेगा । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से किसानों को क्या लाभ पहुंचा है, इसे सरकार बताए । हमारे यहां इन्वेस्टमेंट मीट के बड़े-बड़े आयोजन हुए । पांच लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हो गए । उत्तर प्रदेश में उद्योग लाने के लिए यह बजट क्या मदद कर रहा है? ऐसे आयोजन हुए, जिसमे देश के प्रधानमंत्री आए, देश के राष्ट्रपति आएं, देश के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, वे सभी आए थे । लेकिन आज यूपी को क्या मिला? किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े-बड़े एमओयूज हुए, लेकिन आज जमीन पर कुछ दिखायी नहीं दे रहा है ।

अगर दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है । उस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उस समय की सरकार ने फैसला लिया कि अगर बाहर से भी कोई डेयरी या डेयरी प्लांट लगाना चाहेगा तो उसमें सरकार सहयोग देगी । इसका परिणाम यह हुआ कि गुजरात की तीन अमूल के प्लांट उत्तर प्रदेश में लग गए । दो मैंने उद्घाटन किए और एक का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी ने किया । लेकिन उसके बाद कोई नया प्लांट आया हो तो बताएं । जो अमूल से पुरानी संस्था है, क्या उसको आप लोग कुछ सहयोग करेंगे । क्या पराग का सहयोग करेंगे? न केवल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है बल्कि चीनी और गन्ने की पैदावार में भी कभी आगे कभी पीछे होता है । किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि उनकी भी आय दोगुनी हो जाएगी । उनको भी बहुत सुविधाएं दी जाएंगी, बिजली फ्री दी जाएगी, यह आपका आश्वासन था । आज उत्तर प्रदेश इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि सबसे महंगी बिजली कहीं पर मिल रहा है तो वह उत्तर प्रदेश मिल रहा है । मुझे याद है, यह बात मुझे इसलिए कहनी चाहिए कि बीजेपी के विधायक जो सबसे बुजुर्ग थे, देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र बिजली 24 घंटे आए, उसके लिए वह धरने पर बैठ गए थे । वहां के अधिकारियों ने कहा कि बुजुर्ग हैं, इनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, इनका धरना आप रुकवा दीजिए । मैंने उनको बुलाया, मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि प्रधामंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए । उसी दिन मैंने फैसला ले लिया कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली रहेगी । उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री को बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग किया है । कम से कम यूपी का बिजली का कोटा तो बढ़ जाए, आठ साल बीत गए । उत्तर प्रदेश ने देश को प्रधानमंत्री तो दे दिया, लेकिन अभी तक बिजली का कोटा नहीं बढ़ा । हमें उम्मीद है कि 11 अंक शुभ होता है । इस 11 वें बजट में कुछ सुविधाएं उत्तर प्रदेश को दी जाएगी, जिससे वहां के लोगों को लाभ मिले, मदद पहुंचे । जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, पिछले दस सालों में सरकार जानती होगी कि लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं ।

किसान तकलीफ और परेशानी में हैं और सबसे ज्यादा संकट अगर किसी चीज पर आया तो नौकरी पर आया, रोजगार पर आया । मैं सरकार का बजट पढ़ता हूं तो देखता हूं कि स्कीम्स लाई जा रही हैं । क्या ये स्कीम्स नौजवानों को पक्की नौकरी दिलाएंगी? क्या आप इन स्कीम्स में पांच हजार रुपये देकर नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या दे रहे हैं? मुझे लगता है कि आप ट्रेनिंग देकर जो वर्क फोर्स सरकार के पैसे से बना रहे हैं, अंततोगत्वा, इन्हें वही उद्योगपति एक्सप्लाइट करेंगे । आखिरकार, जब इतनी टेक्नीकल इतनी ट्रेंड फोर्स

होगी तो आप ही बताएं कि उनका भविष्य क्या होगा? अगर आप इतने बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग करा रहे हैं और सरकार का बजट इस पर खर्च हो रहा है तो उनका भविष्य क्या होगा?

माननीय सभापति जी, जो अग्निवीर वाली नौकरी है, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है, वह इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता । जब पहली बार अग्निवीर स्कीम आई थी, बड़े-बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे । ? (व्यवधान) शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है कि यह स्कीम ठीक नहीं है तभी वह राज्य की सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर, जो लौटकर आएंगे, उनको कोटा दीजिए, नौकरी दीजिए । ? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर **(**हमीरपुर**) :** माननीय सभापति जी, यह गलत बोल रहे हैं । सरकार ने कहां कहा कि यह ठीक नहीं है । 100 परसेंट ठीक है । ? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** माननीय सभापति जी, मैं बैठ जाता हूं, माननीय सदस्य खड़े होकर कह दें कि अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है । ? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** माननीय सभापति जी, मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं । मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, जिसने पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए । कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवाना थे । चार परमवीर चक्र विजेता हुए, इनमें दो, कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से थे । मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी, वन रैंक वन पेंशन, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है । ? (व्यवधान)

मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन लें, ? (व्यवधान) अग्निवीर में 100 परसेंट एम्पलाइमेंट की गारंटी है और रहेगी । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरी करें ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** सभापति जी, मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था । मैं दूसरी बात कहता हूं, आप जो बात कह रहे हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपको उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में दस परसेंट कोटा देना पड़ रहा है? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, आप बजट पर चर्चा करें ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** माननीय सभापति जी, आप जानते हैं कि चैल कहां है? क्या कभी आप मिलिट्री स्कूल में गए हैं? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हैं । ? (व्यवधान) हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि कितने परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश से हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह कर रही हूं कि आप आपस में चर्चा न करें । आप बजट पर अपनी बात कहें ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** माननीय सभापति जी, मैं एक मिनट से भी कम समय में अपनी बात कहूंगा ।

मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि यह तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं । मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 वें रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं । अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए । राहुल गांधी जी के साथ बैठकर आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, आप बैठिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रही हूं कि आप बजट पर चर्चा करें । आपके बोलने का समय भी पूरा हो गया है । प्लीज़, आप कम्पलीट करें ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** महोदया, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं क्या बात कहना चाहता हूं । शायद ये मंत्री जी नहीं रहे, इसलिए इनको तकलीफ, परेशानी ज्यादा है । हमारा दर्द आप नहीं समझेंगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं । दर्द मैं बताता हूं । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रही हूं, आप बजट पर चर्चा कीजिए ।

?(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** आप खुद भी तो मुख्य मंत्री नहीं रहे । ... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** महोदया, उत्तर प्रदेश में जबसे ये हारे हैं, तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। यह तकलीफ आपको है । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, कृपया कम्प्लीट कीजिए ।

श्री अखिलेश यादव**:** कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है । जो अपने-आप को बहुत ताकतवर कहते थे, जिसने हराया, उसे ये हटा नहीं पा रहे हैं । आपको बात समझ में नहीं आई न ? जिसने हराया, उसको नहीं हटा पा रहे । अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, कृपया बजट पर अपनी बात रखिए ।

.. (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** हम भी सत्ता में आएंगे, साल, दो साल बाद । यह चलने वाली सरकार नहीं है, यह गिरने वाली सरकार है । ... (व्यवधान) आप याद रखिएगा । आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि साइकिल हमारा चुनाव

चिन्ह है और साइकिल ही आपकी सरकार चलवा रही है । जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलेंगे? हमारे दूसरे साथी, जो हमें यहां लेकर आए थे ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रही हूं, कृपया कम्प्लीट कीजिए ।

?(व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** महोदया, मैं दो-तीन बातें कहता हूं । यूपी को लेकर मैं मांग करता हूं कि चम्बल एक्सप्रेस भी बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो एक लाख करोड़ का बना है, वह दिल्ली-मुंबई से है, आप यूपी से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? गंगा को लेकर सब चिंतित हैं । गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है । जो बजट गया, वह पता नहीं कहां चला गया, किसी को नहीं पता । जैसे पानी बहा, वैसे बजट भी चला गया । मंत्री जी बैठे हुए हैं । वह जानते होंगे कि देश की सबसे अच्छी लायन सफारी इटावा में बनी है । उसे बनाने में हमें बहुत समय लगा, क्योंकि एक लायन/एनिमल सफारी यदि बननी हो, तो उसको बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत जगहों से परमिशन लेनी पड़ती है । हम लोगों को परमिशन नहीं मिली । चूंकि वह प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लॉएन्स की बिडिंग वहां पर शुरू हो गई है । यह सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है, क्योंकि वह समाजवादियों ने बनाई है । पहली बार देश में एशियाटिक लॉएन्स पैदा हो रहे हैं । इटावा में पहली बार हो रहे हैं । और वह शेर मैं आपको बता दूं, शेर आया था या कोई और था वह कहानी मैं यहां नहीं पढ़ूंगा । मैं बोल दूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि मैंने क्या बोल दिया, इसलिए मत बुलवाइए तो ही अच्छा है । कुछ तो रिश्ते बने रहें ।

माननीय सभापति **:** धन्यवाद ।

श्री अखिलेश यादव**:** महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि लायंस सफारी, एनिमल सफारी यूपी क्षेत्र की प्राइड है । पहली बार एशियाटिक बिडिंग सेंटर वहां पर बन गया है । दिल्ली की सरकार और यूपी सरकार मिलकर उसे शुरू नहीं होने दे रहे हैं । मुझे उम्मीद है कि उसे आप शुरू करवा देंगे । अंत में मैं दो लाइनें कहता हूं-

बुनियाद को नकारकर जो इमारतें उठाएंगे,

हम भी देखते है, वे किस मंजिल तक जाएंगे ।

श्री रविशंकर प्रसाद **(**पटना साहिब**)** : अखिलेश जी, कुछ ज्ञान माननीय नेता, विपक्ष को भी दे दीजिए । आपने अच्छा भाषण दिया, उनको भी सिखा दीजिए । ... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** महोदया, हालांकि अयोध्या के बारे में मैंने कहा, हम काम नहीं रोक रहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों का कौन टाउन प्लानर है, कौन आर्किटेक्ट है, मैं नहीं जानता, लेकिन जब ये सरकार से चले जाएंगे, तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बनेगी, वह अयोध्या नगरी होगी । धन्यवाद ।

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam.

I thank you for allowing me to take part in this discussion on Budget 2024-25. Our country India is a role model to the whole world in upholding the principle of federalism and of vibrant democracy. The Budget presented by this BJP government is against the federal structure and its principles. I wish to say that this

Budget is reflective of the antidemocratic policies of the government. This Budget is the worst budget presented so far by this government during the last 10 years. Whether this Union government is aware of the fact Tamil Nadu too exist in this country. This Budget creates such a doubt in our minds. In order to protect your government from falling, you have failed to uphold federalism and acted against the federal principles. This government has shown partiality towards some States which is no good for our country set-up on the basis of federalism. This Budget is resemblance of your anger that you wanted to show towards those States where you could not win any MP seat or get sufficient votes. Whichever party is supporting you for making you remain in power, you have extended special assistance to such States. You have just used the public money, the tax payers? money and distributed to the States like Andhra Pradesh and Bihar as these States are behind you government formation at the Union. In the past you uttered Tirukkural couplets at least for name sake. But now in this Budget there is not even a single mention about Tirukkural. You have easily ignored Tamil and Tamil Nadu without making a mention in your current Budget. BJP may have its own politics. They may have separate policies and ideologies. But such issues should never be forced upon any government which will automatically turn to be a threat to our sovereignty. You are not giving our rightful share of funds from the taxes collected from our States. But you are lavishly giving away such a huge allocation of money to some States. Is it justified?

We in our Tamil Nadu have more unmet needs than any other State, You have not given disaster relief fund as demanded by the State government of Tamil Nadu. You have neither provided funds for the execution of second phase of Chennai Metro rail project. Even before the Union Budget was prepared, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thalapathy M.K. Stalin listed out all the demands of Tamil Nadu. But even though it was listed, you have not announced any special scheme in this Budget as regards Tamil Nadu and no funds were allocated for us. Even funds are not allocated for the projects which are already in progress in our State. This is a gross injustice faced by Tamil Nadu. This government has not fulfilled any demand as regards job creation during last 10 years, as promised. Now they have announced about employment generation programme which is all confusing. There is no clarity. How will they provide jobs? There is still confusion. Unemployment issues are rampant in our country. Moreover, incentives are planned to be given to employers. And the salaries of the employees are to be allocated from CSR funds. If that is so, it will create further more confusion. It will affect the developmental programmes carried out by way of CSR funds. This

Scheme was mentioned in the election manifesto of the Congress party. You have tried to copy it but did not do it properly. My parliamentary constituency has a long coastal area. Industries based on sea products, palm tree and coconut tree should be set up in these areas and employment should be generated. I have demanding this for the last 5 years in this House. But so far no Scheme has been announced by this Government. The number of man days should be increased from 100 to 200 of MGNREGA. The wages under this Scheme should also be increased to Rs 400 per day. This Scheme is a wonderful scheme brought during the UPA government led by Congress party for strengthening the rural economy. We have requested that this Scheme should be extended to the town panchayats. Under the MPLAD Scheme, Rs 5 Crore is given to each parliamentary constituency per year. In Tamil Nadu, every Assembly constituency has Rs 3 Crore as the local area development scheme fund. As the plan estimates have increased nowadays, many such works could not be completed with this sum of Rs 5 Crore.

I therefore urge that this amount under MPLAD Scheme should be enhanced from Rs. 5 Crore to Rs. 15 Crore per year. This Budget as usual is a disappointing one for the minorities and the people belonging to the marginalised sections of the society. There are 25 Crore Muslims living in this country. But there is no place for a Muslim in the Union Cabinet. You are just coming out with the slogan of ?Development for all and development with all.? This is just for name sake. India is seen as a country with religious harmony at the international arena. The Government which was in power before this BJP government had brought several Acts. One important act is the Places of Worship (Special provisions) Act 1991. This is an act aimed to protect the places of worship. Another religion cannot claim the place of worship belonging to a particular religion. There is another Act dating back before 15 August 1947, for the Places of Worship, even after the Ayodhya verdict, 25 Crore Muslims in this country have come forward to maintain peace in this country after accepting the verdict on Ayodhya. But this Government is not willing to have peace in this country, they are searching Hindu places of worship in the places where mosques and other places of worship of Muslims are situated. This should be stopped by this Government. In the name of religious politics, whatever politics you do in the name of religion, people of Ayodhya in Uttar Pradesh have taught you a lesson. In Faizabad parliamentary constituency where Ayodhya is situated, you have lost the elections. Do not engage in politics by using religion. You should rule this country by respecting the democratic credentials and the Constitution of India. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu is in power serving the people who voted him to power and also to those who did not vote for him.

This Union Government should try to emulate from him. We are asking to release the funds that are to be released to us as our right. You have allocated additional funds for two States. We are paying you more GST than those two States which are benefitted by your wind fall of fund allocation. We want our rightful share of money that is due for Tamil Nadu. We want our funds to be released immediately. Tamil Nadu was creating more number of doctors in the country and serving this nation in a bigger way. Unable to digest, this Government has brought NEET and as a result, the future of many of our bright students is lost in the lurch. We wanted a ban on NEET. We wanted that Tamil Nadu should be exempted from NEET. Other than BJP all the political parties in Tamil Nadu under the leadership of DMK, have passed a resolution seeking exemption for Tamil Nadu from NEET. This resolution was sent to the Union Government for its assent. Without considering that proposal of exempting Tamil Nadu from appearing in NEET, this Government is engaged into diversion politics. I therefore urge that there should be exemption for Tamil Nadu from NEET. Thank you.

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद) **:** आपको सादर घन्यवाद, जो आपने मुझे पूर्ण बजट 2024-25 पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर दिया ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रत्व में दिनांक 23/07/2024 को तीसरे कार्यकाल का ये पूर्ण बजट फिर से एक और एतिहासिक बजट जोकि अमृतकाल का ये तीसरा बजट है, को पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं ।

इस बजट में नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रकट किया कि विकसित भारत का लक्ष्य उनकी निगाह में है । इसी कारण आम बजट अंतरिम बजट की कड़ी दिख रहा है । इस बजट से यह साफ है कि कृषि उत्थान के साथ-साथ रोजगार के अत्यधिक अवसर पैदा करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है।

बजट का जोर कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर करने पर है, लेकिन कृषि और किसानों की दशा सुधारने के लिए जो उपाय किए जाने हैं, उन्हें वांछित सफलता तब मिलेगी, जब राज्य सरकारें कृषि संबंधी केंद्रीय योजनाओं को सहयोग देने के साथ किसानों की दशा सुधारने के लिए अपने हिस्से की भी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगी ।

सरकार की मंशा साफ है सकारात्मक है जिसकी झलक तो 18 विं लोकसभा शुरुआत में ही दिख गई जब मा० प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का पहला कार्य देश के किसानो प्रति समर्पण है पीएम किसान निधि की 17 वीं किस्त जारी कर दी है । इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा हो रहा है । इस किस्त के तहत करीब 20,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में जारिए किए गए । ये पहला क्रन्तिकारी कदम से ही दर्शाता है कि मोदी 3.0 सरकार की पूरी तरह किसान कल्याण के लिए समर्पित है । पदभार संभालने के बाद पहला फैसला किसानों के कल्याण के लिए किया गया है । और आने वाले समय समय में किसानों और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए और कदम उठाएंगे ।

इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान हैं । अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम Vegetable Production Clusters बनाने जा रहे हैं । इससे एक ओर छोटे किसानों को फल-सब्ज़ियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे... तो दूसरी ओर, हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल-सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा । कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है । इसलिए, दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है ।

किसान हमारे 'अन्नदाता' हैं'. प्रत्येक वर्ष, पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत सीधे 11.8 करोड़ किसानों को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मार्जिनल और छोटे किसान शामिल हैं. पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल इंश्योरेंस दिया जाता है. इनके अलावा, कई अन्य कार्यक्रमों के अलावा, देश और विश्व के लिए भोजन बनाने में 'अन्नडेटा' की सहायता कर रहे हैं.

इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडी को एकीकृत किया है, और 3 लाख करोड़ की ट्रेडिंग मात्रा के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है. यह क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्च विकास और उत्पादकता के लिए तैयार है. ये किसान-केंद्रित पॉलिसी- आय सहायता, कीमत के माध्यम से जोखिमों के कवरेज और 6 इंश्योरेंस सहायता, स्टार्ट-अप के माध्यम से प्रौद्योगिकियों और इनोवेशन को बढ़ावा देने से सुविधाजनक हैं।ये कदम दिखाते है कि बजट फिर से भारत वर्ष को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला बजट है जिससे स्पस्ट होजाता है भारत वर्ष आगामी पञ्चवर्षीय में, विकाशील भारत से विकसित भारत की और जाने वाली गाडी और भी सुपर फ़ास्ट स्पीड से दौड़ने लगेगी । वर्ष 2047 का जो विकसित भारत लक्ष है मा० प्रधानमंत्री की सरकार का विकास को देखते हुए लगता है कि वो पहले ही प्राप्त हो जाएगा ।

· कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन

· रोजगार एवं कौशल

· समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय

· विनिर्माण एवं सेवाएँ

· शहरी विकास

· नवाचार, अनुसंधान एवं

· विकास नई पीढ़ी के सुधार

ये वो बिंदु है जिन्ह पर इस बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. और यही इसकी इस बजट की प्राथमिकताएं भी है ।

सम्पूर्ण भारत के लिए, आधुनिकता की दिशा में, पिच्छले दस सालो में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं पिछले वर्षों में जो फैसले लिए गए, नीतियां बनीं, उसकी वजह से आज अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है । और श्री नरेंदर मोदी जी की सरकार के सभी बजट, विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक

मजबूत नींव का निर्माण करेगा । इसमें वंचितों को वरीयता दी गई है ये बजट आज की आकांक्षा समाज गांव-गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ये बजट, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर पैदा करने वाला ऐतिहासिक बजट है । ये बजट देश में अधिक तेज विकास, तेजी से बढ़ता नया बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश के नए स्रोत, अधिक नौकरियों की संभावना ओं से भरा हुआ है । सच मे ये देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करने वाला बजट है । विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण किया है । यह बजट वंचितों को वरीयता देता है और आकांक्षी समाज, गरीबों, गांवों और मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करने का प्रयास करता है ।

यह बजट युवा, गरीब, महिला व किसान को सुदृढ़ करने वाला बजट है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इन चारों को विकसित भारत का स्तंभ माना है । यह बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट है ।

ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है । ये देश के गांव-गरीब-किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है । पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं । ये जो नीयो मीडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है । ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है । इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी । ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है । ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है । इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी । इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMEs को, यानि की लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा । बजट में मैन्यूफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है । इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी ।

आदिवासियों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट परिव्यय 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 73.60 प्रतिशत बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ रुपये हुआ पिछले बजट में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अंतरिम बजट 2024- 25 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटन से 70 प्रतिशत अधिक है । जनजातीय मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 7,605 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे ।

जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, Saturation Approach के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा । प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान घोषितः 63,000 गांवों के परिपूर्णता कवरेज का लक्ष्य 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करना है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की । इस पहल का उद्देश्य जनजातीय बहुसंख्यक गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता कवरेज प्रदान करना है, जिसमें 63,000 गांव शामिल हैं और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभान्वित करना है । प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार|

वर्ष 2013-14 से अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्रवाई योजना (डीएपीएसटी) कोष आवंटन में 5.8 गुना वृद्धि, आवंटन 21,525.36 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) से बजट अनुमान 2024-25 में 1,24,908.00 करोड़ रुपये हुआ

केंद्रीय बजट 2024-25 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए कुल परिव्यय लगभग 13,000 करोड़ रुपये है । यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में 73.60 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है ।

हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के आभारी हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है । यह पहल पूरे भारत में जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास, अवसंरचना विकास और आर्थिक अवसरों के सृजन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है ।

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए योजनाएं वित्तीय सहायता प्रदान करके और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर को पाटकर अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का समर्थन और पूर्ति करती हैं । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 2024-25 में 13,000 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो लगभग 189.02 प्रतिशत की वृद्धि है ।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना जाता है, के अंतर्गत 42 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी कुल योजना आवंटन का 4.3 से 17.5 प्रतिशत तक धन आवंटित करते हैं । डीएपीएसटी कोष आवंटन 2013-14 के बाद से लगभग 5.8 गुना बढ़ गया है, जो 2013-14 में 21,525.36 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) से बढ़कर बजट अनुमान 2024-25 में 1,24,908.00 करोड़ रुपये हो गया है ।

सरकार का फोकस अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास पर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें देश के अन्य समुदायों के बराबर लाना है । 2024-25 के लिए योजना-वार आवंटन इस प्रकार है:

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

क्रम सं.	योजना का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)
1	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	6399.00
2	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	160.00
3	अनुसूचित जनजातियों के लिए	30.00

	उद्यम पूंजी कोष	
4	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	152.32
5	जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआईरआई-ईसीई)	32.00
6	निगरानी, मूल्यांकन, सर्वेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा (एमईएसएसए)	20.00
7	अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति	165.00
8	राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना	6,00
9	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)	25.00
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास	107.52
	कुल	**7096.84**

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

क्रम सं.	योजना का नाम	राशि **(**करोड़ रुपए में**)**
1	अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-	440.36

	मैट्रिक छात्रवृत्ति	
2	अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2432.68
3	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	111.00
4	विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	20.00
6	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना	1000.00
7	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक लागत	55.96
	कुल	**4300.00**

अन्य अनुदान/अंतरण

क्रम सं.	योजना का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)
1	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदान (प्रभारित)	1541.47
2	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के दूसरे प्रावधान के खंड ए के अंतर्गत असम सरकार को अनुदान	0.01
	कुल	**1541.48**

योजनाओं के लिए कुल आवंटन **12938.32** करोड़ रुपये

सरकार ने पिछले 2024-25 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के निर्माण के लिए 6,399 करोड़ रुपये रखे हैं, जो 2023-24 में इस उद्देश्य के लिए आवंटित 2,471.81 करोड़ रुपये से 150 प्रतिशत अधिक है ।

ईएमआरएस का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उन्हें सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों और नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, साथ ही गैर-एसटी आबादी के बराबर शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो सके । प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए आवंटन 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

इस योजना के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार-सह-आय सूजन जैसे क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिए जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण के लिए अधिसूचित एसटी आबादी वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को धन प्रदान किया जाता है । आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 111 करोड़ रुपये कर दी गई है । हालांकि, 'एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति' के लिए बजट आवंटन 2023-24 में 230 करोड़ रुपये से घटाकर 2024-25 में 165 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

रेलवे ने बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नया दृष्टिकोण अपनाया है । बजट में रेलवे की क्षमता वृद्धि, उच्च घनत्व वाले नेटवर्क की भीड़भाड़ को कम करना, देश में लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और उनकी सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने हुए हैं ।

अब अर्थव्यवस्था आज पहले की तुलना में अधिक सहनीय और मजबूत स्थिति में है । ये बजट, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी विकास पर केंद्रित आर्थिक नीतियों की निरंतरता के रूप में है, जो पिछले दस वर्षों में इस सरकार का मुख्य आधार रही है । रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने पर विशेष जोर दिया है । वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है । 2024-25 के दौरान रेलवे के लिए सकल बजटीय सहायता 2,52,200 करोड़ रुपये है । इससे पहले, 2023-24 में सकल बजटीय सहायता 2,40,200 करोड़ रुपये थी, जो 2013-14 में केवल 28,174 करोड़ रुपये था । भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1588 मीट्रिक टन का अभूतपूर्व सर्वाधिक माल लदान हासिल किया है, जो 2014-15 में 1095 मीट्रिक टन था और रेलवे 2030 तक 3,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है । रेलवे ने 2023-24 में 2,56,093 करोड़ रुपये की सर्वकालिक सर्वाधिक कुल प्राप्तियां हासिल की और पूंजीगत व्यय के पूरक के लिए 3,260 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व का सृजन किया ।

रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं । पिछले 10 वर्षों में, रेलवे ने 31,180 ट्रैक किलोमीटर चालू किए । ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किमी प्रति दिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54

किमी प्रति दिन हो गई । 2014-2024 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 41,655 रूट किलोमीटर (आरकेएम) का विद्युतीकरण किया है, जबकि 2014 तक केवल 21,413 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था ।

2014-24 के दौरान रेलवे में 5.02 लाख उम्मीदवारों की भर्ती की गई; कोविड-19 के चलते लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के बाद कंप्यूटर आधारित टेस्ट के जरिए 1,30,581 उम्मीदवारों की भर्ती हुई

भारतीय रेलवे के आकार, स्थानिक वितरण और संचालन की गंभीरता को देखते हुए इसमें रिक्तियां होना और उन्हें भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है । इसके नियमित संचालन, प्रौद्योगिकी में आते बदलाव, मशीनीकरण और इनोवेटिव पद्धतियों पर खरा उतरने के लिए समुचित और उपयुक्त कार्यबल प्रदान किया जाता है । रेलवे के ऑपरेशंस और तकनीकी जरूरतों के अनुसार ही उसके द्वारा भर्ती एजेंसियों के जरिए मांगपत्र जारी करके रिक्तियों को मूलतः भरा जा रहा है ।

कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के बाद 2.37 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों की प्रतिभागिता वाली दो प्रमुख परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं ।

· 1.26 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) परीक्षा 28.12.2020 से 31.07.2021 तक 7 चरणों में, 68 दिनों में, 133 शिफ्टों में, 211 शहरों और 726 केंद्रों पर आयोजित की गई थी ।

· इसी तरह 1.1 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए सीबीटी 17.08.2022 से 11.10.2022 तक 5 चरणों में, 33 दिनों में, 99 शिफ्टों में, 191 शहरों और 551 केंद्रों पर आयोजित की गई थी ।

इन परीक्षाओं के आधार पर रेलवे में 1,30,581 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है ।

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की परीक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और संसाधनों को जुटाना और जनशक्ति को प्रशिक्षित करने का काम शामिल होता है । रेलवे ने इन सभी चुनौतियों को पार किया और सभी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती सफलतापूर्वक आयोजित की । पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इसी तरह की किसी भी गड़बड़ी की घटना नहीं हुई ।

भारतीय रेलवे में 2004-2014 के दौरान और 2014-2024 के दौरान की गई भर्तियों को देखे पाएँगे की प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के कार्यकाल में अधिक नौकरिया दी गई है

अवधि	भर्ती
2004-14	4.11 लाख
2014-24	5.02 लाख

रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बनाना, ये हमारी सरकार की पहचान रही है । आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है । देश और दुनिया ने PLI स्कीम की सफलता देखी है । अब इस बजट में सरकार ने Employment Linked Incentive scheme की घोषणा की है । इससे देश में करोड़ों-करोड़ों नए रोजगार बनेंगे । इस योजना के तहत, जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह, हमारी सरकार देगी । स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे-बेटी, देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे । हमें हर शहर, हर गाँव, हर घर entrepreneurs बनाना हैं । इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है । इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा ।

लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाएंगे । देश का MSME सेक्टर, मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से MSME सेक्टर की ownership मध्यमवर्गीय है । और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है । छोटे उद्योगों को बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है । इस बजट में MSMEs के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है । मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है । E-Commerce Export Hubs और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी ।

ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है । रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकॉनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा । 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स देश में नए सैटलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए Transit Plans… इससे देश में नए economic hub विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोज़गार बनेंगे ।

देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं । गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है ।

आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है । ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है । ये Better Growth और Bright Future लेकर आया है । आज का बजट, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के, उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा ।

यह बजट देश के युवाओ में नया जोश भर देता है, एक नई दिशा देने की बात करता है । युवाओं की इनकम बढ़ने की पूरी पूरी उम्मित इस बजट में दिखती है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है । साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बन जाएगा और जिसकी बुनियाद आज युवा ही होंगे ।

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत इस बजट में हमने मुख्य रूप से रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म, और मध्यम उद्यम तथा मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित किया है । पांच योजनाओं और नई लघु पहल के एक पैकेज की घोषणा की ।

इस पैकेज का उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराना है, जिसके लिए पांच वर्ष की अवधि में दो लाख करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि निर्धारित की गई है । शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए एक लाख 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ।

प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए तीन योजनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार रोजगार पाने वाले को पहचान दिलाने में मदद करेंगी साथ ही रोजगार देने वाले तथा रोजगार प्राप्त करने वाले का सहयोग करेंगी ।

योजना ए**:** यह योजना सभी प्रमुख औपचारिक कार्य क्षेत्रों में कामगार के रूप में शामिल होने वाले नये युवाओं को एक महीने का वेतन उपलब्ध करायेगी । इससे दो वर्ष तक 2.1 करोड़ युवा लाभांवित होंगे । इस योजना में शामिल होने के लिए पात्रता की सीमा वेतन के रूप में एक लाख रुपये प्रतिमाह तक होगी । कर्मचारी भविष्य निधि- ईपीएफओ में पंजीकृत हुए पहली बार रोजगार पाने वाले लोगों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से एक महीने का वेतन 15 हजार की तीन किस्तों में दिया जाएगा और यह अधिकतम होगा । इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है।

योजना बीः इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो पहली बार रोजगार पाने वाले कामगारों के रोजगार से जुड़ा हुआ है । योजना के अंतर्गत पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा है । मुख्य रूप से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सीधे तौर पर एक विनिर्दिष्ट पैमाने पर रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी । यदि पहली बार रोजगार पाने वाले कामगार की सेवाएं उसकी नियुक्ति के 12 महीनों के अंदर समाप्त कर दी जाती है तो सब्सिडी नियोक्ता के द्वारा लौटाई जाएगी ।

योजना सीः रोजगार देने वाले नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा । इसमें एक लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी । सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं को ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी । इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा है ।

प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की जा रही है । इस योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा । इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को समझते हुए कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और कार्य योजना तैयार किए जाएंगे तथा नई संभावनाओं के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे ।

सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 5 वीं योजना के रूप में 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों के दौरान एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण (इसमें कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी) प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरूआत करेगी । उन्हें वास्तविक व्यवसायिक वातावरण, विभिन्न कार्य क्षेत्रों और रोजगार के अवसरों के लिए 12 महीनों का अनुभव मिलेगा । इस योजना के तहत 5,000 रुपये प्रतिमाह का प्रशिक्षण भत्ता और 6,000 रुपये की एकबारगी सहायता राशि प्रदान की जाएगी । श्रीमती सीतारमण ने कहा कि

इसके लिए कंपनियों से प्रशिक्षण और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा अपनी सीएसआर निधियों से वहन करने की अपेक्षा की जाती है । ऐसे युवा जो 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के हैं और बेरोजगार हैं, साथ ही किसी भी शैक्षिक गतिविधि में पूर्ण रूप से शामिल नहीं है, वे इस योजना के पात्र हैं और आवेदन कर सकते हैं ।

युवाओं को अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें थीं । जो इस बजट में लगभग पूरी हुई है । पिछले बजट में सरकार की ओर से कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की गई थी । वित्त मंत्री ने 30 स्किल इंडिया नेशनल सेंटर खोलने का ऐलान किया था । रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान किया था । वहीं 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले तीन सालों में 38 हजार टीचर्स और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की घोषणा की थी

यह देश खेलों में हमारे युवाओं की नई ऊंचाइयों पर गर्व करता है । 2023 में एशियन गेम्स और एशियन पारा गेम्स में सबसे अधिक मेडल टैली एक उच्च आत्मविश्वास स्तर को दर्शाती है. चेस प्रोडिजी और हमारे नंबर वन रैंक वाले प्लेयर प्रम्नानन्धा ने 2023 में राइनिंग वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्ल्सन के खिलाफ कठोर लड़ाई लड़ी । आज, भारत में 2010 में 20 से अधिक की तुलना में 80 से अधिक चेस ग्रैंडमास्टर हैं ।

उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण, जीने में आसानी, और उनके लिए गरिमा ने इन दस वर्षों में गति प्राप्त कर ली है । महिला उद्यमियों को तीस करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं उच्च शिक्षा में महिला नामांकन दस वर्षों में 28 प्रतिशत बढ़ गया है. स्टेम पाठ्यक्रमों में, लड़कियों और महिलाओं में नामांकन का तीन प्रतिशत है- जो विश्व में सबसे अधिक है । ये सभी उपाय कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में प्रतिबिंबित हो रहे हैं।

भारत ने विश्व के लिए बहुत कठिन समय के दौरान जी20 प्रेसडेंसी का अनुमान लगाया वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें, कम वृद्धि, बहुत अधिक सार्वजनिक कर्ज, कम व्यापार वृद्धि और जलवायु चुनौतियां शामिल थीं । महामारी ने विश्व के लिए खाद्य, उर्वरक, ईंधन और वित्त के संकट का कारण बन गया था, जबकि भारत ने सफलतापूर्वक अपना रास्ता दिखाया । देश ने उन वैश्विक समस्याओं के समाधानों पर आगे बढ़ने और सहमति बनाने का तरीका दिखाया ।

हाल ही में घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे भारत और अन्य लोगों के लिए एक रणनीतिक और आर्थिक खेल परिवर्तक है । माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में, कॉरिडोर "आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनेगा और इतिहास यह याद रखेगा कि यह कॉरिडोर भारतीय भूमि पर शुरू किया गया था" । 'विक्सित भारत' के लिए विजन । 'सबका विश्वास' अर्जित करने वाले प्रदर्शन और प्रगति के मजबूत और अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड से उत्पन्न होने वाले विश्वास के साथ, अगले पांच वर्ष अभूतपूर्व विकास के वर्ष होंगे, और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वर्ण क्षण होंगे ।

सबके प्रयास द्वारा समर्थित लोकतंत्र, लोकतंत्र और विविधता की त्रिमूर्ति में प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है । 'सुधार, निष्पादन और रूपांतरण' सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित, सरकार अगली पीढ़ी के सुधार करेगी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और हितधारकों के साथ सहमति बनाएगी । इन्वेस्टमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोदी सरकार आकार, क्षमता, कौशल और नियामक ढांचे के मामले में फाइनेंशियल सेक्टर तैयार करेगी ।

महत्वाकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के लिए मोदी सरकार पर्याप्त आर्थिक अवसरों के उत्पादन सहित महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के तेजी से विकास में राज्यों की सहायता करने के लिए तैयार है । कोविड के कारण चुनौतियों

के बावजूद, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन जारी रहा और हम तीन करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं ।

परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ से अधिक मकान लिए जाएंगे । रूफटॉप सोलराइजेशन और मफ्ट बिजली, रूफटॉप सोलराइज़ेशन के माध्यम से, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने के लिए एक करोड़ घरों को सक्षम किया जाएगा । फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी के घरों के लिए वार्षिक रूप से पन्द्रह से अठारह हजार रुपये तक की बचत और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सरप्लस बेचना; इलेक्ट्रिक वाहनों का शुल्क; आपूर्ति और संस्थापन के लिए बड़ी संख्या में विक्रेताओं के लिए उद्यमिता के अवसर;

निर्माण, संस्थापन और रखरखाव में तकनीकी कौशल के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर; मिडल क्लास के लिए हाउसिंग, सरकार मध्यम वर्ग के योग्य सेक्शन में मदद करने के लिए एक स्कीम शुरू करेगी "किराए के घरों में रहना, या स्लम, या चाल और अनधिकृत कॉलोनी" अपने घरों, मेडिकल कॉलेजों को खरीदने या बनाने के लिए ।

कई युवाओं को डॉक्टरों के रूप में योग्यता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है । उनका लक्ष्य सुधारित स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से लोगों की सेवा करना है । मोदी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल मूल संरचना का उपयोग करके अधिक चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है । इस उद्देश्य के लिए एक समिति नियत की जाएगी ।

देश भर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की संख्या बढ़ने पर कहा था कि जहां अन्य दलों के शासन के दौरान केवल एक AIIMS बनाया गया था, वहीं वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 6 AIIMS का निर्माण किया, उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के कारण पिछले 9 वर्षों में 15 नए AIIMS समर्पित किए गए । देशभर में 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs), 16 IIIT (ट्रिपल आईटी) और 390 यूनिवर्सिटीज बनाई गई । इसके अलावा 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) खोले गए हैं ।

बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बनें और देश के लिए स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें । इसके लिए और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय बनेंगे, सबसे पहले एक समिति बनाई जाएगी जो कि इसका निर्धारण करेगी । अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्किल इंडिया ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है ।

भारत में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव और इसके लिए एक समर्पित समिति का गठन सराहनीय कदम है । यह कदम निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी चिकित्सा पेशेवरों के लिए कई अवसर पैदा करेगा, एक अधिक अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देगा और वर्तमान में छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिस्पर्धी दबाव को कम करेगा । मेडिकल एजुकेशन तक बढ़ी हुई पहुंच प्रदान करके, हम डॉक्टरों की भावी पीढ़ियों को सशक्त बना सकते हैं और राष्ट्र के लिए एक उज्जवल स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में योगदान दे सकते हैं ।

स्वास्थ्य के संबंध में भारत में अभी दिया गया अभी तक महत्वपूर्ण बजट है और जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में साल-दर-साल ज्यादा बढ़ोत्तरी देखी जा रही है ।

किफायती कैंसर उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, तीन अतिरिक्त कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई ।

मेडिकल एक्स-रे मशीनों में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर सीमा शुल्क संशोधित किया गया ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट व्यय में लगभग 4000 करोड़ रुपये की वृद्धि; बजट व्यय 31,550 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 36000 करोड़ रुपये किया गया । उत्पादकता और नवाचार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) अनुप्रयोगों का प्रस्ताव । स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक "हाट" या स्ट्रीट फूड हब शुरू होंगे ।

बजट में कैंसर की तीन अतिरिक्त दवाओं- ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब- को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की । देश में 27 लाख कैंसर रोगियों को इससे फायदा होगा । इन दवाओं को सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क से छूट दी है ।

तीन कैंसर दवाएं अर्थात् ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब का उपयोग विभिन्न ट्यूमर प्रकारों के लिए किया जाता है ।

1. ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन - स्तन कैंसर

2. ओसिमेरटिनिब - फेफड़ों का कैंसर; तथा

3. डुरवालुमाब - फेफड़ों का कैंसर और पित्त नली का कैंसर

केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर सीमा शुल्क दरों में भी संशोधन किया । इन संशोधित दरों से एक्स-रे मशीन उद्योग की कीमतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे कम लागत पर घटक उपलब्धता बढ़ेगी । इस परिवर्तन से घरेलू चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने, कम लागत पर घटक उपलब्धता में योगदान देने और स्वास्थ्य सेवा लागत में कमी आने की उम्मीद है । इससे उन्नत चिकित्सा इमेजिंग अधिक सुलभ और सस्ती हो जाएगी ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट व्यय में लगभग 4000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जो 31,550 करोड़ रुपये से बढ़कर 36000 करोड़ रुपये किया गया है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है जो मुख्य रूप से राष्ट्र में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है । सरकार का ध्यान स्वास्थ्य के निवारक और उपचारात्मक पहलुओं को लागू करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश करना है ताकि बड़े पैमाने पर जनता के खर्च को कम किया जा सके ।

निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, बजट में जनसंख्या के पैमाने पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोगों के विकास का प्रस्ताव है । इन पहलों का उद्देश्य क्रेडिट ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई सेवाएं, वितरण और शहरी शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना है ।

केंद्रीय बजट 2024-25 में कुछ चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक "हाट" या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है । इस प हल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुद्ध करना और स्ट्रीट फूड के अनुभव को बढ़ाना है, जिससे शहरी विकास और सामुदायिक जुड़ाव में और अधिक योगदान मिलेगा ।

ट्रैस्टुजुमाब इंजेक्शन 440 मिलीग्राम/50 मिलीलीटर आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) 2022 के तहत एक शेड्यूल दवा है और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इसकी अधिकतम कीमत तय कर दी है । वर्तमान में लागू अधिकतम कीमत 54725.21 रुपये प्रति शीशी है, जो कि एसओ 1547 (ई) दिनांक 26.03.2024 के अनुसार है । हालांकि, इसका अन्य वेरिएंट शेड्यूल सूची में नहीं हैं । ट्रैस्टुजुमाब अलग-अलग क्षमता और खुराक में आता है और इसका संयुक्त वार्षिक कारोबार 276 करोड़ रुपये से अधिक है ।अन्य दो दवाएँ यानी ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब डीपीसीओ, 2013 के तहत गैर- अनुसूचित दवाएँ हैं । इसलिए, एनपीपीए गैर- शेड्यूल फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले बारह महीनों के दौरान इसमें एमआरपी से 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न हो । वर्ष 2023-24 के लिए डर्वालुमैब का वार्षिक कारोबार 28.8 करोड़ रुपये था ।

ओसिमर्टिनिब 42 कैंसर रोधी दवाओं की सूची में शामिल है, जिसके लिए व्यापार मार्जिन को एसओ 1041 (ई) दिनांक 27.02.2019 के तहत व्यापार मार्जिन अवलोकन के तहत विनियमित किया गया था । एनपीपीए के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023- 24 के लिए ओसिमर्टिनिब का वार्षिक कारोबार 52.26 करोड़ रुपये था ।

मेडिकल एक्स-रे मशीनों और निर्दिष्ट उप-असेंबली/भागों/उप-भागों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, 22 जनवरी 2021 को डीओपी द्वारा एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) अधिसूचित किया गया था । इसके तहत मेडिकल एक्स-रे मशीनों और एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट उप-असेंबली/भागों/उप-भागों पर चरणबद्ध तरीके से बढ़ती दर पर टैरिफ परिवर्तन प्रस्तावित किए गए थे ।

चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) का उद्देश्य मेडिकल एक्स-रे मशीन और संबंधित सब-असेंबली/पार्ट्स/सब-पार्ट्स उद्योग को इस क्षेत्र में अपने निवेश की योजना बनाने और एक्स- रे मशीन और संबंधित सब-असेंबली/पार्ट्स/सब-पार्ट्स पर बढ़ते शुल्क ढांचे को ध्यान में रखते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाने में सक्षम बनाना था । इससे घरेलू मूल्य संवर्धन में वृद्धि होने और भारत में एक मजबूत मेडिकल एक्स-रे मशीन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित होने की उम्मीद थी ।

देश में एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों के लिए विनिर्माण क्षमता अभी तक विकसित नहीं हुई है और इन वस्तुओं से संबंधित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) अनुसूची में संशोधन के लिए अनुरोध किया है । इस संबंध में, सावधानीपूर्वक जांच के बाद, यह पाया गया कि घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों के लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता स्थापित करने में कम से कम दो साल लग सकते हैं । इसके बाद, विभाग ने 24.5.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से संशोधित दरों के लिए राजस्व विभाग से अनुरोध किया है । वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 30/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई, 2024 (क्रम सं. 71) के जरिए विभाग द्वारा यथा प्रस्तावित वस्तुओं के लिए शुल्क दरों को संशोधित किया है ।

बड़ी दूरदृष्टि है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, प्रमुख स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को पूरे भारत में आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा । इस योजना के तहत, भारत के लगभग 10 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक की द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती कवरेज (Hospitalization Coverage) की पेशकश की जाती है.

अनुमान के मुताबिक, देश में लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ता हैं जो सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता के रूप में काम करती हैं और स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता फैलाती हैं । प्रीस्कूलर और गर्भवती महिलाओं के बीच पोषण संबंधी मापदंडों को बढ़ाने के लिए केंद्र की एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत स्वयंसेवकों के रूप में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 13 लाख है. सरकारी अनुमान के अनुसार, राज्यों में लगभग 11.6 लाख आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं. अंतरिम बजट में वित्त मंत्री द्वारा मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश में और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई और इसके लिए एक समिति भी गठित की जायेगी |

शुरू की गई अन्य पहलों के बीच, माननीय वित्त मंत्री जी ने यू-विन पोर्टल के राष्ट्रव्यापी लॉन्च की घोषणा की जो कि कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन प्रणाली को-विन के समान है- जिसका उद्देश्य पंजीकरण, फॉलो-अप और टीकाकरण सहित देश में सभी टीकाकरण और टीकाकरण सर्टिफिकेट कार्यक्रमों का दस्तावेजीकरण करना है. इस पहल से संबंधित एक पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल जनवरी में शुरू किया गया था ।

"जय जवान जय किसानः

प्रधानमंत्री शास्त्री ने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया । प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बताया कि 'जय जवान जय किसान जय विज्ञान', प्रधानमंत्री मोदी ने यह आगे बढ़ाया है कि "जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान", क्योंकि इनोवेशन विकास की नींव है.

हमारे टेक सेवी युवाओं के लिए यह एक सुनहरा युग होगा. पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा. कॉर्पस लंबी अवधि और कम या शून्य ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण प्रदान करेगा. इससे निजी क्षेत्र को सूर्योदय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से अनुसंधान और नवान्वेषण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. हमारे पास ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो हमारे युवाओं और प्रौद्योगिकी की शक्तियों को संयोजित करते हैं.

विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार: विकसित भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए राज्यों में कई विकास और विकास सक्षम सुधारों की आवश्यकता होती है. राज्य सरकारों द्वारा माइलस्टोन से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए इस वर्ष पचास हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल प्रस्तावित किया जाता है.

सरकार तेजी से आबादी की वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाएगी. 'विक्सित भारत' के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए सुझाव देने के लिए समिति को अनिवार्य किया जाएगा'.

कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल. मोदी सरकार उच्च विकास के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों के लिए अपनी आकांक्षाओं को समझने के लिए शर्तें बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

केंद्रीय बजट 2024-25 आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर दिया गया है । उत्पादकता में सुधार, बाजार दक्षता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का लक्ष्य एक मजबूत और समावेशी आर्थिक ढांचा बनाना है । भूमि, श्रम, वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रस्तावित सुधार स्थायी विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ।

इस अमृतकाल के तीसरे बजट में भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है, सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है और साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बन जाने के लक्ष को प्राप्त कर लेगा है ।

देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले, इस बेहतरीन बजट पेश करने के लिए मैं मा० प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ ।

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : मैं आभारी हूं कि बजट वर्ष 2024-25 के समर्थन में मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया गया है । देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरे कार्यकाल के इस बजट में विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया गया है । इसके लिए मैं देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी एवम माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं । बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश की आर्थिक बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के कई प्रगतिशील उपाय पेश किए है ।

बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास की रूप-रेखा तैयार किया गया है । और युवाओं के लिए भी बजट में शिक्षा और कौशल विकास जैसे खास इंतजाम किया गया है ।

बजट काफी अच्छा है, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजेल टैक्स समाप्त करना सरकार का महत्वपूर्ण कदम है । यह कदम उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देगा ।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और महिलाओं के लिए एआई- संचालित अपस्किलिंग पर जोर लैंगिक समानता और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है ।

एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है । इस योजना पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है जिसके अंतर्गत 1.28 करोड से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं इसे आगे और प्रोत्साहित किया जाएगा ।

अधिक उत्पादकता व प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी है । जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के लिए अनुसंधान व शोध के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है । साथ ही जलवायु के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए 32 व बागवानी फसलों की अधिक उपज देने वाली नई 109 किस्में किसानों को देने की बात कही है, जो कि अच्छा कदम है । कृषि एवं किसान के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से स्पष्ट होता है कि 2013-14 में कृषि का बजट 23 हजार करोड़ था, जो अब बढकर 2024-25 में कृषि का बजट 1 लाख 52 हजार करोड़ का हो गया है ।

कांग्रेस पार्टी एवं उनके सहयोगी मित्रों ने किसानों के लिए नारे लगा लगाकर इस सदन में चिंता कर रहे थे लेकिन इन्होंने कभी भी निष्ठा के साथ किसान कल्याण के लिए काम नहीं किया है । इन्होंने क्या किया मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे सदन के ध्यान में एक जानकारी लाना चाहता हूं की स्वामीनाथन जी के संबंध में कई मित्रों ने चर्चा की स्वामीनाथन जी स्वयं क्या बोले हैं यह 6 अगस्त 2018 के टाइम्स आफ इंडिया में उनका एक आलेख छपा है जिसमें लिखा है:

"स्वतंत्र भारत तथा उप-निवेशित भारत के इतिहास में पहली बार वर्ष 2004 में तत्कालीन कृषि मंत्री श्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी । इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य किसान परिवारों की समस्याओं की समीक्षा करना तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने के साथ-साथ युवा पीढ़ी के लिए आकर्षक बनाने के वास्ते विभिन्न तौर-तरीकों का सुझाव देना था ।"

"वर्ष 2006 में प्रस्तुत इस आयोग की सिफारिश में न केवल कृषि के उन्नयन के लिए सुझाव दिए गए थे बल्कि किसानों के परिवारों के आर्थिक हित के लिए भी सुझाव दिए गए थे । इस आयोग ने किसानों को न्यूनतम सकल आय प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने के वास्ते किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य स्थापित किया था । इसके साथ ही इस सिफारिश में कृषिगत प्रगति के आकलन के मानदंडों में किसानों की सकल आय में सुधार को शामिल किया गया था । "

"सातवें पैरा में उन्होंने लिखा है कि यद्यपि राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई थी परंतु जब तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी, तब तक इस पर बहुत कम काम हुआ था । सौभाग्यवश पिछले 4 वर्षों के दौरान किसानों की स्थिति और आय में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं । "

2024-25 का यह बजट ऐसा संतुलित बजट है जिसके सकारात्मक प्रभाव आने वाले दिनों में दिखने आरम्भ हो जाएंगे ।

यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के असंख्य अवसर बढाने एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एंव ऐतिहासिक कदम हैं ।

यह बजट भारत को वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी बडी अर्थव्यवस्था एवं वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनाने के माननीय मोदी जी के संकल्प को मूर्तरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

· मैं बिहार राज्य से आता हूं, इस बार बजट में जो बिहार के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया गया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं ।

· बिहार जो इतिहास, संस्कृति और संभावनाओं में भरी हुई एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के कगार पर है, इस बजट से विकसित बिहार बनाने का सपना पूरा होगा ।

· बिहार लंबे समय से बार-बार आने वाली बाढ़ के संकट से पीड़ित है, जिससे जान और माल का भारी नुकसान होता है । माननीय वित्त मंत्री द्वारा बाढ़ सहायता और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता की घोषणा हमारे राज्य के लिए एक स्वागत योग्य राहत है ।

· मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र मोतिहारी में अरेराज के बगल में बराज प्रस्तावित है जिसके कारण इस क्षेत्र में आने वाली बाढ़ से निजात मिलेगी तथा सिंचाई की सुविधाओं में भी सुधार होगा ।

· ये उपाय किसानों की रक्षा करेंगे, कृषि उत्पादकता की बढ़ाएंगे और लोगों के लिए खाद सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे । मोदी सरकार की इस समस्या को सुलझाने की प्रतिबद्धता बिहार की कल्याण और समृद्धि के प्रति समर्पण को दर्शाती है ।

· इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किसी भी सम्पन्न अर्थ व्यवस्था की रीढ माना जाता है, और बिहार को सड़क कनेक्टिविटी में 26 हजार करोड़ रूपये के निवेश के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी ।

· बिजली आधुनिक विकास की जीवन रेखा है और बिहार में भागलपुर जिले के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रूपये की लागत से 2400 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना से बहुत लाभान्वित होगा । यह पावर प्लांट हमारे राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा तथा घरों, उद्योगों और व्यवसायों को लगातार निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी ।

· अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर पर बिहार के गया में एक औद्योगिक नोड का विकास राज्य के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा । यह परियोजना केवल औद्योगिक विकास के बारे में नहीं है । यह हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास को मिलाने वाला एक मॉडल है । जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह मॉडल विकास भी विरासत भी प्रदर्शित करेगा ।

· बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत हमारे सभी के लिए गर्व का स्रोत है । सरकार के द्वारा विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और नालंदा के पर्यटन स्थलों के रूप में व्यापक विकास के लिए समर्थन योजनाएं सराहनीय हैं । हिन्दू बौद्ध और जैन धर्म के लिए धार्मिक महत्व रखने वाले राजगीर को भी व्यापक विकास पहले के तहत लाया जाएगा ।

· बिहार में नये हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उसके समग्र विकास के दृष्टिकोण का प्रमाण है । आधुनिक हवाई अड्डे कनेक्टिविटी को बढाएंगे जिससे सुगम यात्रा और व्यापार की सुविधा मिलेगी । मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को पूरा करेगे, चिकित्सा पेशेवरों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगे और हमारे लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे ।

· खेल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे युवाओं को विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा । स्वस्थ्य जीवनशैली को बढावा देगा और प्रतिभा को पोषित करेगा । ये पहले विकास, विकास और समग्र कल्याण के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाएँगी । ये बिहार को विश्वस्तरीय सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए सरकार के संकल्प को दर्शाते हैं जिससे हमारा राज्य राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके ।

· बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त आवंटन के माध्यम से पूंजी निवेश के समर्थन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण कदम है ।

· वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बजट भाषण 2024 में की गयी घोषणाएं विहार के लिए एक नए सवेरे का संकेत देती हैं । "पूर्वोदय? पहले और इसमें शामिल विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं हमारे राज्य को बदलने के लिए तैयार हैं ।

· विकास और प्रगति की इस यात्रा पर यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी एकजुट होकर इन पहलों का समर्थन करें । सरकार की बिहार के लिए दृष्टि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे राज्य के हर नागरिक के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य बनाने के बारे में है । यह हमारी विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिकता को अपनाने, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में है ।

· अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को बिहार वासियों की ओर से विशेष बधाई देता हूं एवं बिहार के सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि आइए मिलकर हम इन दृष्टियों को वास्तविकता में बदलें, बिहार को विकास संस्कृति और समृद्धि का एक शानदार उदाहरण बनाएं ।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : मैं बजट पर अपने विचार रखता हूं ।

हमारे पूर्व बहुत सारे विद्वान नेता बजट पर अपने विचार रख चुके हैं, और मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा । बजट में कहा गया है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर तीनों पर ध्यान दे रही है । यह कहना सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे किसान अनेकों मुसीबतों से अभी भी जूझ रहे हैं, और सरकार उन्हें कोई सहायता नहीं दे रही है । वित्त मंत्री महोदया ने कहा है कि उनकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक

काम कर रही है, लेकिन हम लोग छोटे जगह से आने वाले लोग यह महसूस करते हैं की सड़कों का निर्माण गांवों तक नहीं पहुंचा है । इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रेलवे की एक बड़ी समस्या है । वर्तमान सरकार हाई स्पीड रेल और बुलेट ट्रेन पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है । जिसमें की भारी निवेश होगा लेकिन जिसका उपयोग सिर्फ समाज के संपन्न लोग ही कर पाएंगे । मेरा यह मानना है की सरकार को हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट रेल की बजाय मौजूदा रेल नेटवर्क को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि देश में रेल से संबंधित घटनाओं पर रोक लग सके और साधारण लोगों को जरूरत के अनुसार रेल में टिकट मिल जाए ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं क्योंकि सरकार गरीबी दूर करने का लगातार प्रयास कर रही है । लेकिन सच्चाई यह है की यह नारा पिछले 70 वर्षों से चल रहा है, पर गरीबी अभी भी दूर नहीं हुई है । सरकारी आंकडो से यह पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में देश में अमीर लोग ज्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब लोग अधिक गरीब हो गए हैं । गरीब और अमीर के बीच की खाई बड़ी होती जा रही है । सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है की सरकार जन औषधि केंद्र खोलकर दवाइयां कम कीमत पर मुहैया करा रही है, लेकिन चिकित्सकों का मानना है की जन औषधि की दवाइयां अपेक्षित कार्य को पूरा नहीं कर पा रही हैं और दवाइयां के खुराक को 4 से 5 गुना तक बढ़ाना पड़ता है, ताकि वह रोगी पर असर कर सके । इसलिए जन औषधि केंद्र खोलने के साथ-साथ सरकार को दवाइयों के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि मरीज उचित दवा खाकर स्वस्थ हो जाए ।

बजट में कहा है कि सरकार युवाओं के लिए बहुत काम कर रही है और उनके भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत तरह की प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है । लेकिन जब आप सच्चाई को देखते हैं तो यह पाएंगे की पिछले 10 वर्षों में देश में बेरोजगारी बढी है, करोडों युवा रोजगार की तलाश में आज भी बड़े-बड़े शहरों में भटक रहे हैं । बीटेक, एमटेक, एलएलबी जैसे उच्च स्तरीय डिग्री लेकर युवा मात्र दस हजार रुपए की नौकरी के लिए मारे - मारे फिर रहे हैं ।

मेरा मानना है कि सिर्फ योजनाएं चलाने से नहीं होगा, सच्चाई में भी उन्हें देखना होगा कि योजनाएं कितनी अपने उद्देश्य में कितनी कारगर है । महोदय, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि एक ओर इतनी बेरोजगारी है वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की 40 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं और इसके लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है ।

सिर्फ प्रधानमंत्री जी यह दिखाते हैं कि मैं एक लाख लोगों को ऑनलाइन नौकरी दे रहा हूं लेकिन पिछले 10 वर्षों में इनकी नौकरी देने की संख्या रिटायर होने वाले लोगों से बहुत ही कम हो गयी है । यही कारण है की आज हर विभाग में हर मंत्रालय में पदों की रिक्तियां बनी हुई है ।

मैं एक और महत्वपूर्ण विषय नए आपराधिक कानूनों के बारे में बताना चाहूंगा, जो की १ जुलाई से लागू हो गए हैं । पता नही सरकार ने किन कारणों से आनन फानन में इन्हें संसद में पास करवाया और उसे कार्यान्वित कर दी है । बड़े बड़े कानून के जानकार एवं विश्लेषक इसमें कई सुधार के सुझाव दिए पर सरकार इनपर विचार किए बिना उसे पारित करवा दी । संसदीय समिति में विचाराधीन इन कानूनों पर भी कई सदस्यों ने अपने असहमति नोट दिए पर सरकार ने सबकी अनदेखी करके उन्हें पारित कर दिया ।

सरकार के उत्तर पूर्व क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के संदर्भ में यह कहना चाहता हूं की सरकार उत्तर पूर्व में राज्य सरकारों को बदलने के लिए सभी प्रयास कर रही है, सरकार का सही मायने में क्षेत्र के विकास से कोई लेना नही

है । मणिपुर में कई महीनों तक होनेवाले हिंसा और केंद्र सरकार का मूकदर्शक बने रहना इसका उदाहरण है । धन्यवाद ।

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : सभापति महोदया, आपने मुझे आज बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की तरफ से इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा यहां हुआ हूं ।

सभापति महोदया, जहां इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों और दलितों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है, वहीं इस बजट ने देश के पिछड़े राज्यों में जैसे हमारा बिहार प्रदेश है, उसको विकसित राज्यों के बराबर खड़ा होने की जो ताकत दी है, उसके लिए मैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदया, जब बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा था, तब मैं यह देख रहा था कि जहां विपक्ष के अन्य प्रदेशों के वरिष्ठ सांसद इसका विरोध कर रहे थे, तब मुझे इसके बारे में बड़ी चिंता हुई कि हमारे बिहार प्रदेश के विपक्ष के भी सांसद इसका विरोध कर रहे थे, यह समझ से परे है।

सभापति महोदया, यह वही बिहार है, जिस बिहार को देश भर के लोग केवल मजदूर सप्लाई के रूप में देखते हैं । आज इस बिहार की परिभाषा बदल रही है । आज बिहार देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने की उड़ान के साथ आगे बढ़ रहा है, इस उड़ान को पंख देने के काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी कर रही हैं । हमारे प्रदेश के विपक्ष के सांसद महोदय इसका विरोध कर रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि इनको बिहार से और बिहारियों से कोई लगाव नहीं है । इनको केवल और केवल राजनीति करने से मतलब है । इसीलिए बिहार को जो पैकेज मिला है, वे उसका विरोध कर रहे हैं ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में 2024-25 के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है । विगत 10 वर्षों में चार करोड़ ?पीएम आवास योजना? के माध्मय से जो आवास आवंटित किए गए हैं, वे ज्यादातर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए हैं । इस बजट में कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है । इस बजट में विशेष रूप से रोजगार कौशल प्रशिक्षण और एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को न केवल स्किल डेवलेपमेंट, बल्कि उनको रोजगार से भी जोड़ने का काम किया गया है ।

सभापति महोदया, सबसे सुखद है कि इस बजट में प्रधान मंत्री जी के पैकेज के अंतर्गत पांचवीं योजना के रूप में हमारी सरकार ने 500 शीर्ष कंपनियों में पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए जोड़ने का व्यापक अभियान चलाया है । इसके लिए भी हम लोग अपने यशस्वी प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं । मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूं कि जहां बिहार नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से शिक्षा के जगत में पूरे विश्व भर में जाना जाता था और यदि मैं वर्ष 2005 के पहले की बात कहूं तो कुछ कालखण्डों में यह देखा गया कि न केवल बिहार से लोग बाहर मजदूरी के लिए पलायन कर रहे थे, बल्कि व्यापारी वर्ग भी बड़ी आबादी में पलायन कर रहा था । आज यह सौभाग्य है कि हमारे बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, बिहार से पलायन रुक रहा है और उद्योगों की संभावनाएं बढ़ रही हैं । बिहार को मिले

इस विशेष पैकेज से न केवल एक्सप्रेस वे बनेंगे, न केवल एयरपोर्ट्स और अस्पताल बनेंगे, बल्कि औद्योगीकरण के लिए भी बिहार अब अपने आप को आगे बढ़ा रहा है । जब उद्योग लगेंगे तो बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करेंगे ।

सभापति महोदया, मैं इसके साथ ही साथ आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के बहुत सारे साथी बार-बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और वह शब्द हिंदुओं को हिंसक कहने की बात हो, चाहे वह प्रभु राम के बारे में कहने की बात हो । मैं बिहार से आता हूं, मां सीता की धरती से आता हूं । हम लोग पुरुषोत्तम प्रभु राम के दिए गए और बताए गए मार्गदर्शन पर चलने वाले लोग हैं । मैं बता देना चाहता हूं कि जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, अगर आपको हिंदू और राम की परिभाषा जाननी है तो मैं सिर्फ चार पंक्तियों से आपको परिभाषा से बताना चाहता हूं:-

?शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं,

ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् ।

रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं,

वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्॥?

इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रभु श्री राम शांत हैं, सनातन हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं । यही परिभाषा हमारे प्रभु राम की है और यही परिभाषा हिंदू की है । हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू शांत है । बिहार सबको साथ लेकर चलने की परिभाषा पर विश्वास रखता है । मैं आप सबसे और प्रदेश के विपक्ष के सभी साथियों से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप प्रगति करें, इससे बिहार को कोई कोताही नहीं है, इससे बिहार को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब बिहार पिछड़पेन से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी बिहार की ओर अपनी निगाह सकारात्मक रखें । जिस तरीके से हमारे देश के प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने बिहार को विशेष पैकेज दिया, मैं फिर से कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूं । बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न के साथ आगे बढ़ाने की जो सोच हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने रखी, मैं उनका भी कोटि-कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । जय हिंद, जय भारत ।

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : सबसे पहले, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कौशांबी की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे इस सदन में भेजा । मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी और मुझे भारत का सबसे युवा सांसद बनने का गौरव प्रदान किया ।

मैं वर्ष 2024-2025 के बजट पर अपने विचार रखता हूँ । यह बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह बजट हमारी जनता की वास्तविक समस्याओं को कितनी प्रभावी रूप से संबोधित करता है । विशेष रूप से, हमें इस बजट के चार प्रमुख स्तंभों - युवा, अन्नदाता, महिला, और गरीब - के प्रति सरकार की नीतियों का गहन विश्लेषण करना होगा ।

सबसे पहले, मैं युवाओं के बारे में बात करना चाहूंगा । हमारे देश की आधी से अधिक आबादी युवा है, लेकिन इस बजट में उनके लिए ठोस कदम उठाने की बजाय खोखले वादे किए गए हैं । कौशल विकास और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन की बातें तो बहुत की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के उचित अवसर नहीं

मिल रहे हैं । पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ है और यह बजट इस समस्या का समाधान करने में विफल है ।

एक उदाहरण के तौर पर, प्रयागराज में एनटीपीसी परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को उनके हॉस्टलों में घुसकर पीटा गया । यह घटना इस सरकार की युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है । इसके अलावा, सरकार के कार्यकाल के दौरान 70 से अधिक पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए हैं, जो हमारे शिक्षा प्रणाली की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं ।

इस बजट में एक नई नीति के तहत 21-24 वर्ष के युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की गई है । लेकिन यह समझना होगा कि केवल इंटर्नशिप ही पर्याप्त नहीं है । युवाओं को सुरक्षा और निश्चित आय वाले रोजगार की आवश्यकता है । सरकार को यह बताना चाहिए कि वे इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कैसे करेंगे ।

अब बात करते हैं अन्नदाताओं की, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं । हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा कृषि पर निर्भर है, फिर भी इस बजट में किसानों के लिए केवल 3.15% धनराशि का आवंटन किया गया है । यह दिखाता है कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है ।

हमारे किसानों की मुख्य मांगें जैसे कि कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादनों पर जीएसटी हटाना, इस बजट में पूरी तरह से अनदेखी की गई हैं । किसानों के लिए यह एक बड़ा धक्का है, क्योंकि जीएसटी के बोझ से उनके उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और उनकी आमदनी घट जाती है ।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में कृषि मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है । यह एक बड़ी विफलता है, क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में कृषि मजदूर हैं, जो इस सहायता के पात्र हैं लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है । सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने की बात नहीं की गई है । एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों के लिए सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिससे उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके । लेकिन सरकार ने इस मांग को भी नजरअंदाज कर दिया है ।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन योजनाओं का क्या हश्र हुआ है, यह हम सब जानते हैं । महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो वादे किए जा रहे हैं, वे केवल कागजों पर ही सीमित हैं । जमीनी हकीकत में महिलाएं आज भी असुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

अंत में, मैं गरीबों की बात करना चाहूंगा । यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दस साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को अपने संबोधन में गरीबों का उल्लेख करना पड़ता है । इसका मतलब है कि आज भी हमारे देश में गरीबी एक गंभीर समस्या बनी हुई है । इस बजट में गरीबों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान किया गया है, लेकिन पिछले अनुभवों से हम जानते हैं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना कमजोर रहा है ।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कौशांबी की समस्याओं की बात करना चाहूंगा । यहां बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है, जिससे आम जनता और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है । किसानों के खेत आवारा पशुओं से सुरक्षित नहीं हैं, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं । इसके अलावा, हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है ।

किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं पा रहे हैं, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही हैं । यह सब समस्याएं दिखाती हैं कि सरकार जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है ।

यह बजट केवल खोखले वादों और आंकड़ों का खेल है । यह बजट हमारी जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने में विफल है । हम, विपक्ष के तौर पर, इस बजट की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि वे वास्तविकता की धरातल पर उतरकर देश की जनता के हित में ठोस कदम उठाएं । धन्यवाद ।

SUSHRI IQRA CHOUDHARY (KAIRANA): Today, I would like to express my views on critical issues concerning our budget and its impact on vital sectors. The Union Budget 2024-25 is presented with the objective of fostering macroeconomic growth and ensuring fiscal stability. However, while the budget outlines ambitious plans, its approach to addressing the needs of the poor is marked by limited entitlements. The effectiveness of new welfare schemes will depend heavily on their implementation-a significant challenge given the government's track record of project delays. Our nation's development hinges on how we allocate and use our resources, especially in areas affecting women, children, rural communities, minorities, agriculture, and youth.

Kofi Annan had said, "The measure of a nation's progress is not only in its economic growth but in its commitment to the welfare of its women and children." The Union Budget 2024-25 allocates 26,000 crore for Women and Child Development, marking only a 2.52% increase from the previous year. This modest rise is particularly troubling given the pressing needs within this sector.

Further compounding this issue is the reduction in funding for crucial autonomous institutions. The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and the National Commission for Women (NCW) are both facing budget cuts, which undermines their essential role in safeguarding the rights of women and children.

The budget also boasts an allocation of over 3 lakh crore for women and girls, which initially appears to be a significant increase. However, a closer examination reveals that this rise may be more attributable to accounting adjustments rather than a genuine boost in funding. It is crucial that we address these discrepancies to ensure that our commitment to protecting and empowering women and children is both substantive and effective.

The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is crucial for improving rural connectivity. Yet, its budget has been slashed from 19,000 crore to 12,000 crore.

This drastic cut, coupled with the imposition of toll booths on rural highways, will severely hinder connectivity and development in our rural areas, isolating communities and stalling progress.

For the financial year 2024-25, the government has allocated *86,000 crore to MGNREGS, which sounds like a big increase from last year's *60,000 crore. However, this amount is still 19,297 crore short of the actual spending of 1.05 lakh crore last year. This year's funding represents only 1.78% of the total budget, the lowest in a decade. This significant shortfall means fewer jobs and less support for rural workers who rely on this program, potentially leaving millions without the crucial assistance they need. Witha 41,500 crore already spent in first four months, only 44,500 crore remains for the remaining eight months, risking significant shortfalls in job creation and support for rural workers.

The budget for minority welfare has seen only a marginal increase of 86 crore, rising from 3,097.60 crore in 2023 24 to 3,183.24 crore in 2024-25. This is painfully inadequate. The budget reveals a disturbing pattern of targeted discrimination against minorities. Funding for coaching schemes has been cut from 30 crore to 10 crore, with reduced revised estimates for the previous year. Similarly, interest subsidies for educational loans have decreased from 21 crore to 15.30 crore. Support for Madrasas and minority education has also dropped significantly. The closure of the Maulana Azad Foundation, despite the Prime Minister's vision of minorities progressing with "Quran in one hand and computer in the other," undermines efforts to boost educational opportunities. Moreover, the PM Jan Vikas Karyakram (PMJVK) receives only 910.9 crore, falling short of what is needed to genuinely support our minority communities.

Despite promises of doubling farmers' incomes over the past decade, the reality remains grim, with over 112,000 farmer suicides reported in the last ten years according NCRB 2022 data. As P. Sainath aptly put it, "How agonized we are by how people die. How unconcerned we are by how they live."

The Finance Minister's budget promises significant enhancements in agricultural productivity and climate resilience, including the release of new crop varieties and a commitment to natural farming. However, the reality falls short: past commitments to support natural farming have seen reduced budgets and no clear progress.

The reduction in fertilizer subsidies by 24,894 crore will force farmers to face higher costs for urea, DAP, and MOP, increasing their financial burden. There is also a troubling absence of a Minimum Support Price (MSP) guarantee. Over 700 farmers lost their lives demanding MSP, yet their calls for fair pricing are ignored. The land acquisition process remains slow and cumbersome, with farmers receiving inadequate compensation. In Western Uttar Pradesh's sugarcane belt, the Fair and Remunerative Price (FRP) set by the central government is often below market rates. Furthermore, delayed payments from mills, with ₹450 crore due in Shamli and 150 crore in Saharanpur, force farmers into protests to secure their rightful earnings.

While PM Modi and others emphasize the **"demographic dividend"** from a growing workforce, experts warn that this potential benefit could quickly become a **"liability"** if the economy fails to generate sufficient jobs to absorb the influx of labor.

According to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), India's unemployment rate surged to 9.2% in June 2024, up from 7% May 2024. Educated young people suffer higher rates of unemployment: 18% of those who have completed secondary education or higher are unemployed, compared with 3.4% of those who cannot read or write.

The government claims that 1.4 crore youth have been trained under skill development programs, yet there is little transparency regarding actual employment outcomes. The share of educated youth among the unemployed has surged from 54.2% in 2000 to 65.7% in 2022. The Agniveer scheme, while increasing the defence budget, offers no job security or pension, leaving our soldiers without the support they deserve.

In light of these pressing issues, I must bring forward several key demands from my constituency Kairana, that require immediate attention.I demand the following actions from the government:

1. **Establish a railway line between Panipat and Meerut** to enhance connectivity and economic growth in the region.

2. **Address the critical shortage of bank employees in rural areas** by increasing recruitment and training improve financial services and inclusion.

3. **Build a trauma center in Shamli** to provide essential. timely medical care in response to the rise in highway traffic accidents.

4. **Set up a dairy research institute in Shamli** to support local farmers with research and innovations.

5. **Develop a hand-weaving industry in Shamli** to support our local weavers and preserve traditional crafts, which will also foster economic development.

6. **Open new Kendriya Vidyalayas and Jawahar Navodaya Vidyalayas** to expand access to quality education, particularly in underserved areas.

7. **Create skill centers offering management, computer science, and artificial intelligence** to equip our youth with relevant skills for emerging job markets.

8. Develop a Pakka Ghat at the Yamuna Ghat to enhance its appeal as a tourist destination and improve the Yamuna Ghat to the overall visitor experience.

9. **Introduce professional courses such as LLB, BEd, B. Pharma, and D. Pharma in existing colleges or establish new institutions** to meet growing demands and improve career opportunities for our students.

These issues and demands reflect the urgent needs of nation's development. We must address these challenges with the seriousness they deserve and ensure our policies translate into real, positive change for all citizens.

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): I thank you for allowing me to place my views on the Union budget presented by our hon'ble Finance Minister.

While listening to the budget speech carefully, it really shocking that whether the Hon'ble Finance Minister was making a speech of Union budget or the budget presentation of one or two States. I can understand the helplessness and compulsion of the government to remain in the hot seat of power of the country. Later on I went to my home and searched all the budget documents on portal, but to my surprise the name of a beautiful State, Kerala, was not found anywhere in these documents. What a discrimination, I think it is not only against Kerala but with other majority of the States too. But at the same time, I must congratulate the Hon'ble Finance Minister for wonderfully copying some of the election manifesto of the Indian National Congress and the budget of INC led UPA governments. Copying business does not require any vision, the skill is sufficient, which the hon'ble Finance Minister did it correctly.

Many promises were made before the people of Kerala by both Central and State leaders of Bharatiya Janata Party and its candidates during just concluded general election campaign and the people were expecting a big thing is going to come for the State, but the budget really befooled them with zero benefit for the State of Kerala. I think the Hon'ble Finance Minister has forgotten that there is a State called Kerala in the country while preparing the Union budget.

Kerala, which has been fighting newer diseases every now and then, has been demanding to set up an All India Institute of Medical Sciences in the State. Kerala is willing to give sufficient land for the same, but the Centre is yet to take a decision. The Centre is keeping a blind eye on the said demand and this budget also has no mention about it whereas there are 25 AIIMS - some of them are functional, under construction, announced and proposed. What a step motherly attitude towards Kerala and what a discrimination.

Kerala has been demanding for a Rs.24,000 crore special economic package to tide over the current liquidity stress, but the same has been ignored.

Also, the demand of the Kerala for a Rs.5,000 crore Vizhinjam seaport has also been neglected by the Centre as well as a proposal of Rs.5,000 crore assistance for financing infrastructure projects. This budget has totally sidelined the agriculture, employment, coastal areas and there has been no mention of Kerala in the disaster relief package.

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has been a lifeline for the rural masses when they do not see any other job opportunity for them. But here again the Union government has reduced the allocation. The allocation made under the budget for 2024-25, is less than by Rs.19,297 crore than th scheme's actual expenditure of Rs.1.05 lakh crore in the financial year 2023-24. This year's allocation for MGNREGS is a 10 year low in the scheme's funding. This reduced allocation will definitely have an adverse impact on the implementation of the scheme.

The farmers in the country have been demanding for legal guarantee for the Minimum Support Price for their produce, but there has been no mention about it instead the subsidy on fertiliser has been increased. This will make the farming unaffordable for the farmers in the country.

The budget forces some cut in the schemes like coaching and education loans, etc. meant for minorities, the rationale behind this cut is unknown.

Kerala is a State for a potential growth of tourism in the country. It has been in the news across the State that many proposals are being worked out in the area of tourism, but to my surprise there is nothing in black and white in the budget documents.

The retail or small scale business sector which produces a good number of employment in the country has been neglected without any corresponding support in the budget. This will further increase the unemployment in the country and the percentage of unemployment has already broken the 45 years of record.

It has been a demand for a long time to increase the health care spending atleast 2.5% of our Gross Domestic Product (GDP) as India is far behind even other developing nations. But this budget has not made any commitment of increasing healthcare spending arising out of our GDP.

With this I conclude and oppose the budget. Thank you.

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): The NDA government has attempted to presented an optimistic outlook, but there are several areas where this budget falls short. Let me elaborate on some of the key concerns:

Lack of Focus on Job Creation: Despite the Government's claims of economic growth, this budget does little to address the pressing issue of unemployment. The budget for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) has been slashed by 15%, reducing it to 60,000 crore from last year's 70,000 crore. This reduction will severely impact rural employment.

Insufficient Support for Agriculture: Our farmers, who are the backbone of our economy but this budget provides little relief to the agricultural sector. The allocation for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has been reduced by 20%, bringing it down to 12,000 crore from 15,000 crore last year.

Neglect of Healthcare and Education: Investment in healthcare and education remains inadequate. The health sector has seen only a marginal increase of 5% in its allocation, from 86,000 crore to 90,300 crore, which is insufficient given the ongoing public health challenges and the need for robust healthcare infrastructure. The Interim Budget 2024 had focussed health through new steps-HPV vaccine to protect against cervical cancer, extending PMJAY benefits to ASHA and ANGANWADI workers, U-WIN digital program. The main budget speech has not prioritized health. Similarly, the education sector has been allocated 1.1 lakh

crore, a mere 4% increase from the previous year, which does not address the urgent need for quality education, especially in rural areas.

Ignoring the Needs of the Middle Class: The budget does not provide meaningful tax relief to the middle class, which is struggling with rising living costs. The standard deduction remains unchanged, and there are no new incentives to ease the financial burden on middle-income families. Instead, the budget focuses on policies that disproportionately benefit a select few, thereby widening the economic disparity in our society

Environmental Concerns Overlooked: Despite the growing threats of climate change, this budget does not prioritize sustainable development. The allocation for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has seen only a modest increase of 6%, from 3.100 crore to 3.286 crore. This is inadequate to address the pressing environmental issues we face, such as pollution control and the promotion of renewable energy

Reduced Allocations for Census: The allocation for the Census and National Population Register (NPR) has been cut by 30%, from 3.768 crore last year to 2,638 crore this year. Conducting an accurate and comprehensive census is crucial for effective policy-making and resource allocation. This reduction raises serious concerns about the government's commitment to data-driven governance and transparency.

Reduced Allocation for Karnataka: We also note with disappointment the reduced allocation for Karnataka. The state, which is a key contributor to the nation's economy, has seen a reduction in its central funding by 10%. This will adversely affect ongoing and future development projects, hampering the state's growth and progress.

In conclusion, while the government may present this budget as a progressive step forward, it fails to address the real and immediate needs of our people. We must advocate for a more inclusive and equitable financial plan that truly serves the interests of all citizens, particularly the most vulnerable among us. It is imperative that we push for increased investment in job creation, agriculture, healthcare, education, and environmental sustainability. Furthermore, we must ensure that the census is adequately funded to provide the reliable data needed for informed decision-making.

Thank you.

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): I oppose the Budget for the year 2024-25 as it does not center the best interests of the common man in our country. Today, I stand before you, not just as a Member of Parliament, but as a representative of the resilient people of Karur and the voice of Indian National Congress. As we scrutinize the Union Budget 2024-25, it is crucial to assess its impact on every section of our society, particularly those who have historically been marginalized.

Firstly, let us address the perspective of women. Despite their integral role in our economy and society, women continue to face multifaceted challenges. The allocation for women-centric schemes and initiatives in this budget is disappointing. The funds for the POSHAN 2.0 scheme have been reduced compared to the Revised Estimates in 2023-24. The government has persistently ignored the cries of Anganwadi and ASHA workers, who are overburdened with tasks outside their remit, with no wages to compensate them proportionately. According to the Time Use Survey, 2019, 81.2% of women engage in unpaid domestic services for household members. And yet, there is no effective policy or agenda to improve the female labour force participation. I welcome that the budget borrows significantly from the Indian National Congress' manifesto ? perhaps, in my humble opinion, even the Mahalakshmi scheme should have been emulated to bring relief to the women of our country.

When it comes to children - there was no mention of children in the Honourable Finance Minister's speech. The total school education budget at Rs 73,008 crore makes up around 1.51% of the total budget expenditure. It has reduced consistently since 2017 (when it was at 2.2% of the total budget expenditure). This, despite the fact that high school students have to face national-level entrance examinations that have been marred with malpractice and other deficiencies in the recent past.

The Congress Party initiated the Mid Day Meals scheme under the leadership of K Kamaraj and later expanded it with the vision of Ms. Sonia Gandhi. Budget Expenditure as a percentage of the total budget has come down from 0.48% in the pre-pandemic years (2016-17) to 0.26% for the POSHAN 2.0 scheme. It is the lowest in nine years. As per the Comprehensive National Nutrition Survey (2016-18), 22% of school-age children (5-9 years) were stunted and 24% of adolescents (10-19 years) were thin for their age. India is one of the 20 nations with severe child food poverty, according to UNICEF. It also ranked 111 on the Global Hunger Index. We urge the government to ensure uninterrupted funding and quality improvement in

this crucial program, which not only enhances nutrition but also boosts school attendance and learning outcomes, particularly in Tamil Nadu, where educational reforms are pivotal.

MNREGA has seen a reduction compared to the actual expenditure from Rs 1.05 lakh crore of actual expenditure in 2023-24 to Rs 86,000 crore of budget estimates this year.This year's allocation for MGNREGA is just 1.78% of the total budgetary allocation, which marks a ten-year low in the scheme's funding. The Parliamentary Standing Committee on Rural Development, in February, noted that reduced budgeted allocation can negatively affect the timely release of wages and materials. We demand increased funding to expand coverage, raise wages, and ensure timely payments to beneficiaries, especially amidst economic uncertainties and rural distress exacerbated by recent agricultural reforms.

The overarching problem with the implementation of these schemes under the Modi government is the intent with which they have been brought to life. Schemes are being introduced with the mere intention of prefixing the PM's title to them, to build a smokescreen of welfare governance under the Modi government. When the UPA government introduced MGNREGA, NFSA, ctc., they were rights-based legislations enshrined in the Constitution. However, with the Modi government, welfare schemes have been reduced to endowments dependent on the State's largesse.

With an outlay of Rs 6.22 lakh crore, the budget for the defense ministry has reduced by one percentage point compared to 2023-24. Defense expenditure, as a share of the total expenditure, has decreased by over 4 percentage points. There is a shortfall in the number of IAF aircraft squadrons as against the sanctioned strength. There has been a delay in the supply of Tejas MKIA multirole combat aircraft to the Indian Air Force. Further, after waxing cloquent about the nation's indebtedness to its soldiers, the government has refused to scrap the Agnipath scheme, despite multiple pleas by the soldiers.

Our Constitution envisions cooperation between the Centre and States. It envisions a Centre that is benevolent and benign towards States- not a Centre that is biased, deceitful, and arbitrary. My State of Tamil Nadu has been met with a step-motherly treatment in this budget and our genuine financial grievances have been ignored. My state saw immense devastation in the wake of Cyclone Michaung last December. However, the Centre has refused to disburse an adequate disaster relief package to compensate for the damage caused. The Centre also pulled the plug on

the GST compensation cess in 2022. The state was left to fend for itself to compensate for the losses incurred due to the implementation of GST. We demand a review of GST rates to ease the burden on small businesses and stimulate job creation in the MSME sector, which is crucial for India's economic growth and employment generation, especially in states like Tamil Nadu with a vibrant MSME ecosystem. The central government must change its approach to the Southern States, to opposition-ruled states, and work towards Jana Kalyana.

The Budget fails to address the cries for justice by the most vulnerable sections of our society, including Dalits, Adivasis, Muslims, and other marginalized communitics. Instead of empty slogans and cringe acronyms, these communities require targeted interventions. The funds for the Prevention of Atrocities Act have remained abysmal, despite the rising crimes against minorities, as observed by the NCRB. Manual scavenging has endured, and associated deaths have endured, contrary to the claims of the government. The Ministry of Social Justice conceded that it did not have any report on the number of manual scavenging incidents in the last five years. This systematic neglect is mirrored by the fact that there is no mention of manual scavenging in the Budget. Speaker Sir - this Budget totality ignores the educational rights of the backward classes. That is why our leader Shri Rahul Gandhi has been demanding the caste census so we can target social policies for the deprived sections. Otherwise, the Raj of 1% over 99% would continue. But caste census aside, the government has also not notified when the nationwide census and NPR will take place. The 2024-25 Budget allocated only Rs 1,309 crore. This, despite the fact that the Union Cabinet had, in a 2019 meeting, estimated that the census and NPR exercise would cost over Rs 12,000 crore.

Ten years ago, in his Budget Speech, then Minister of finance Jaitley said, "Government will make all-out efforts to create a more inclusive society for Persons with Disabilities to cnable them to enjoy equal opportunities to lead an empowered life with dignity." This year's speech contained no mention of disability. Further, the National Social Assistance Programme for disability benefits and pensions has been allocated the same amount as last year. According to the NFHS-5, persons with disabilities make up 4.52% of the population. The NFHS-6 is also stripped of sociocconomic data, thereby precluding targeted schemes responsive to the specific challenges faced by disabled persons from the most disadvantaged sections of society.

In conclusion, while we acknowledge some positive initiatives in this budget, such as digital infrastructure investments, we cannot overlook the gaps and missed opportunities that fail to address the urgent needs of our people. As elected representatives, it is our duty to hold the government accountable for its promises and allocations. We must strive for a budget that truly reflects the aspirations and priorities of all Indians, leaving no one behind. Let us work together, across party lines, to ensure that every rupee spent serves the best-interests of our nation and its citizens. Thank you.

DR. PRADEEP KUMAR PANIGRAHY (BERHAMPUR): Thank you for giving me the opportunity to express my views on the Union Budget 2024-25. firstly I would like to congratulate the hon. Speaker on becoming the first Speaker to be re-elected in 20 years.

The historic budget presented by the hon'ble Finance Minister for the year 2024-25 has a clear road map for a futuristic fiscal policy path for the country. This is the Maiden budget of the Modi 3.0 and full of vision and clarity to materialize the vision of a Viksit Bharat 2047 of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, under whose leadership India has become an international force in all sectors including foreign relations, economy and defence. Sir, in 1000 AD India contributed to 25% of the world's GDP and remained the largest economy till 1700 AD. Sir, the PM's vision is the key to bringing the Indian economy back up to where it belongs. The budget announcements will further push for fulfilling the aspirations of 140 crore Indians. This budget is also going to further strengthen and reassure cooperative federalism.

I congratulate the finance minister for living up to the expectations set by the previous budgets presented by her, including being able stabilize the economy and absorbing the shock of the Covid pandemic. Post stabilization, this budget is a bold step towards growing and developing the economy by the path of fiscal prudence and adherence to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBM Act) and with the target of reducing fiscal deficit to 4.5 per cent by FY 2025-26. The budget has made adequate provision for a 30 trillion dollar economy by 2047 and even the opposition should find pride in appreciating the budget instead of looking for flaws in desperation as this budget is to build the nation not break the nation.

I will start with this budget's focus on infrastructure and capital development with a total allocation of 11 Lakh Crores. Allocations have been made for railway corridor

development under PM Gati Shakti, airport expansion and setup under UDAN for Tier 2 and Tier 3 cities and promoting foreign investment via bilateral investment treaties among many more allocations. 10 lakh crores have also been allotted to the PMAY for urban housing and the government is also focusing on transit oriented development in major cities. The NDA government has already established its credibility in infrastructure development. Already the stretch of electrified rail route and the number of. airports have more than doubled since 2014 along with improvements in several other infrastructural. metrics. The capex expenditure, which in simple terms is expenditure on asset development, of the government is projected to be 4.5 times that in 2014, showing the NDA government's. commitment to India's growth.

This budget has also focused tremendously on the health sector with 90 thousand crore being allocated, a 13% increase and a focus on expediting Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, encouraging Cervical Care Vaccination for girls and providing health cover to ASHA, Angawadia workers while also looking after patients by exempting customs duties on three additional cancer medications. The government is also pushing for Aatmanirbhar Bharat in all sectors. There has been a total increase of almost 50% in allocation of funds towards research and development projects.

The FDI inflow during the period 2014 to 2023 is double that of 2005-14 from 298 billion USD to 596 billion USD. The government has proved time and again that its foreign policy pragmatic-yet aggressive' and 'diplomatic yet Bharat-first' by putting the interests of the Indian people first while establishing India as a major global player in all sectors. This has led to treaties and agreements that have brought benefits including infrastructure development, employment opportunities, mobility agreements and improved trade. Thanks to the government's efforts today India's foreign reserves are at a record high and are the 4th largest in the world. Further, a testament to the economy's growth is that the RBI declared a Rs 2.1 Lakh Crore record dividend payout to the government for FY24 which is 141% larger than FY23.

This government has led to the Indian people developing a trust in the economy. Pre-2014 the GDP growth was below 5% and the headline inflation was more than 9% which has come down to 5.4% for FY 2024 and Bharat has emerged as the fastest-growing economy among G20 nations. This government, under the leadership of PM Modi, through a commitment to India's development has gained the support of its citizens that India shall become a 30 trillion dollar economy by

2047, truly becoming Viksit Bharat, having already proven itself by taking India from 10th in 2014 to today being 5th in the world's largest economies

While working tremendously for Amrit Kaal, this budget also focuses on sustainable development. The 19 thousand Crore allocation made to the ministry of new and renewable energy is more than double that of last year's revised estimates. Under this budget, 1 crore households will be enabled to obtain up 300 units of free electricity per month through rooftop solarization, an initiative that contributing truly the people's development while bringing sustainability to the grassroot level. would like to highlight that during the 2004 to 2014 government, in 10 years there was an increase of only 1.9% in percentage of Non - Fossil fuel electricity capacity whereas during 2014 - 2023 there was an increase of more than 11.6%, a 35% increase over the capacity inherited from the UPA government.

This is truly a people's budget as it focuses upon four crucial sections of our society to achieve Viksit Bharat by working towards garib kalyan, youth empowerment, farmer welfare and nari shakti. The extended benefit Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for another five years. benefitting more than 80 crore people of India, shows the commitment of the Government towards the problems of the poor. The budget touched upon each and every sector and section of population and also gave top priority for employment generation and skilling. This budget facilitates employment and skilling more than 4 crore youth for a five-year period with an allocation of Rs. 2 lakh crores, through the PM package which includes schemes for first time employees, job creation manufacturing, support to employers, upgradation of Industrial Training Institutes and internships in top companies. The education sector too with an allocation of 1.48 lakh crores has seen a significant increase from last year.

The government has also allocated over Rs. 3 lakh crores for schemes benefiting women and girls. showing its commitment to make women economically independent. Proposals have been made to launch employment-linked schemes and set up working women hostels to promote women participation in the workforce. The budget's supportive approach to MSMEs also contributes in this regard as nearly 60% of the entrepreneurs in the MSME sector are women. This support includes the doubling of the upper limit of Mudra yojana to 20 lakhs.

The current budget stresses on results and outcomes of public spending. Rs. 1.52 lakh crore has been made for agriculture and allied sectors to increase the productivity and resilience in the agriculture sector as well. The push for natural

farming for 1 crore farmers, with the provision of certification and branding and to achieve Aatmanirbharta in pulses & oilseeds, their production. storage, and marketing initiatives have been made in this budget. The government has also taken measures to digitize the farming sector by implementing Digital Public Infrastructure and digital crop surveys in 400 districts.

In the governing council meeting of the NITI Aayog, the PM emphasized that Viksit States are required for a Viksit Bharat. The budget too contributes to this vision with a 20% higher devolution to states compared to last year's budget estimates and Rs 1.5 lakh crore being budgeted for special interest-free loans to states for capital expenditure which is 15% more than last year. I come from Odisha. state, which has historically lagged behind in several important metrics of development. Sir. I want to emphasize that a Viksit bharat also relies on a Viksit Odisha.

For this, the vision of our Hon'ble Prime Minister all-round development of 'Purvodaya' is a welcome initiative. The budget has made commitments towards human resource development, infrastructure and economic opportunities as a part of this vision, which I hope shall contribute towards Odisha's upliftment. In her speech, the Finance Minister also emphasized Odisha's tourism potential and that the government shall provide adequate support to boost the same.

On behalf of the people of Odisha and my constituency Berhampur I draw the attention of the government to the fact that in the last 24 years, Odisha was under the leadership of the BJD but it failed to be a progressive vibrant state due to lack of proper governance and administration, rampant corruption, deprivation of people of basic amenities. particularly in, Southern Odisha. Despite the honourable ex-chief minister belonging to the district o Ganjam which is my district, it has the maximum number of migrant labourers who have to move livelihood. I place trust in this government to ensure the devolution of funds and trickling down of schemes to help secure availability of drinking water, economic stability of farmers and labourers. increased tele-density, One GP One Bank, development of health sector including setup of an AIIMS and establishment of educational institutes as Odisha has the highest dropout rate in the country at the secondary level.

An integrated package for fishermen with cold storage, market linkage, fish processing units and a fisheries university would contribute greatly to the large fishermen community in the region as well as address the issues they face with the sea mouth openings.

The measures taken for MSMEs in the budget can prove to be of great help to address unemployment in Odisha. The budget has also made provisions for the tribal population through schemes like PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan covering 5 Crore tribals. I would like to express the need for upliftment of tribals in the Gajapati district of my constituency, which is also an aspirational district. Tailored development programs for the Gajapati tribal sector and marginalized communities will empower them and foster inclusive growth.

The transport sector combined has an allocation of 5.4 Lakh Crores, the largest of any sector. I request the honorable finance minister to give a development package to the southern part of odisha, particularly the district of Ganjam, to ensure further development of Gopalpur port a 6 lane highway with railway overbridge, footover bridge and highway amenities wherever y aka development of Gopalpur-Chilika coastal highway, adequate provision the railway sector for Gopalpur-Sambalpur railway line, Gopalpur-Raipur line, via Digapahandi, Mohana, Paralakhemundi Gunpur, Rayagada and the Gopalpur-Talcher line along with the development of Berhampur railway station. I also request support for the establishment of a greenfield airport in Ganjam.

I would like to end by stating that this is the beginning of a new historic era of India's development under this government. The expectations of 140 crore Indians and 4.5 crore people of Odisha have set a new height, and this budget is an excellent step towards fulfilling these expectations. Now the focus on effective implementation of development programmes to translate outlays into real and visible outcomes should be the thrust of the Government.

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं । विश्व के सबसे बड़े नेता और हम सब के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और सहयोगी मंत्री श्री पंकज चौधरी जी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत पूर्ण बजट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं । सदन में प्रस्तुत यह बजट सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला बजट है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बजट समावेशी विकास और भविष्य की दृष्टि से तैयार किया गया है । इसमें सभी क्षेत्रों को प्रगति की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया है ।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस बजट में ग्रामीण और शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचनाओं, उद्योग और स्मार्ट सिटी इत्यादि सभी क्षेत्रों को संतुलित करके प्रमुखता दी गयी है । युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किए गए हैं ।

महोदया, देश को आगे बढ़ाने और वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की यह एक महत्वपूर्ण आधारशिला है । महिलाओं के लिए जो योजना है, भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा । रोजगार के लिए व्यापक रोडमैप बनाया गया है । वह बहुत ही सुंदर है । इस बजट से रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा ।

महोदया, परम पूज्य बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया । यह कांग्रेस ही थी, जिसने संसदीय चुनावों में उन्हें हराया । बाबा साहब अम्बेडकर ने निचली जातियों के लिए बहुत बड़ा काम किया । कांग्रेस ने उनकी कड़ी आलोचना की ।

महोदया, आजादी के बाद के प्रथम आम चुनाव में बाबा साहब ने बाम्बे नॉर्थ सैंट्रल से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने उनको संसद में पहुंचने तक नहीं दिया । उस चुनाव में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर धांधली की, जिसकी शिकायत परम पूज्य बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव आयोग से की थी । बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे कि कुल 74333 मतों को गैर तरीकों से खारिज कर दिया गया था । इसके पश्चात बाबा साहब ने वर्ष 1954 में महाराष्ट्र राज्य के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा था । वहां से भी कांग्रेस ने उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया । आज कांग्रेस, जिसने बाबा साहब को संसद में पहुंचने तक नहीं दिया, वह संविधान की आड़ में राजनीति कर रही है ।

लोक सभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी द्वारा जनता को भ्रमित करके झूठ फैलाया गया कि भाजपा सरकार आने के बाद संविधान को बदल दिया जाएगा । जबकि उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जब लगा कि सत्ता उनके हाथों से जाने वाली है तो उन्होंने सत्ता के मोह में 25 जून, 1975 को संविधान की हत्या करते हुए देश में आपातकाल लगा दिया । जिनकी दादी ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की, आज वह संविधान की किताब साथ लेकर चलते हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ।

महोदया, मैं पुन: माननीय प्रधान मंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और उनके सहयोगी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए सदन में प्रस्तुत जनरल बजट का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं ।

SHRIMATI SHAMBHAVI (SAMASTIPUR):

· I support the Union Budget, a budget which is transformative, a budget which is reformative and a budget which takes care of the aspirations of not just Bihar, but the entire country.

· I would like to begin by a quote from Victor Hugo, "An invasion of armies can be resisted, but not an idea whose time has come.?, the idea for youth to take charge and come at the forefront of development.

· I represent two most important sections of the country- women, who have been at the forefront of the development story of India and the youth, who are going to define the future as India becomes the youngest country on the globe.

· I congratulate the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Finance Minister for giving special attention to the state of Bihar, which has always been neglected by the erstwhile government.

· The development infrastructure that has been given to Bihar, is going to transform it from a "Vikasheel Bihar? to a "Viksit Bihar"

· It is a moment of pride for me that I am a member of this August house as one of the youngest members of the house.

· The way the NDA government has been working for each and every section of the society, I ain sure that we will achieve all our development goals in the coming five years.

· John F. Kennedy said that, "American roads are not good because America is rich but America is rich because American roads are good"

· The Union budget has allocated 26,000 crore for highway ndevelopment in Bihar for the construction of a two-lane bridge over the Ganga and the developm:ent of highways like the Patna Purnea Expressway and Buxar-Bhagalpur Expressway and Bodhgaya-Rajgir-Vaishali-Darbhanga Expressway.

· Because of this allocation, Kennedy's quote would be applicable to the state of Bihar in the coming five to ten years.

Bihar Budget Highlights

Ø The Gross State Domestic Product of Biiar for 2024-25 is projected to be Rs 9.76 lakh crore, amounting to growth of 13.5% over the previous year

Ø Fiscal deficit for 2024-25 is targeted at 3% of GSDP (Rs.29,095 crore).

Ø In 2023-24, as per the revised estimates, the fiscal deficit is expected to be 8.9% of GSDP, significantly higher than budgeted (3% of GSDP).

· The Union budget announcements for the state of Bihar will serve as a huge catalyst to the ongoing development projects of the state government and will propel the economic growth of the state.

· The budget is like a launch vehicle to the satellite of the growth of Bihar.

· Union Budget Announcements for Bihar:

Ø The request from the Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited.

Ø Power Projects in Bihar, including setting up of a new 2400 MW power plant at Pirpainti, will be taken up at the cost of Rs. 21,400Cr

Ø The Budget also announced provisions to construct new airports, medical colleges and sports infrastructure in the state of Bihar.

Ø The Finance Minister acknowledged that Bihar frequently suffers from floods, therefore, plans to build flood control structures in Nepal have yet to make significant progress.

Ø The government will provide financial support with an estimated cost of Rs 11,500 crore to deal with flood-related disasters.

Ø The Finance Minister proposed supporting the development of corridors at Vishnupad Temple and Mahabodhi Temple.

Ø The budget allocated *26,000 crore for highway development in Bihar, including the construction of a two lane bridge over the Ganga and the development of highways like the Patna-Purnea Expressway and Buxar Bhagalpur Expressway and Bodhgaya-Rajgir-Vaishali Darbhanga Expressway.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): This Government in its first year in power has chosen to completely ignore the welfare schemes about which they had made much of the speech in the run-up to the election. Total expenditure for the National Social Assistance Programme covering pensions and disability benefits, which stood at 79,652 crore in 2023-24 as per the revised estimates, has been allocated exactly the same amount in the Budget for 2024-25. That is the fate of the National Rural Employment Guarantee Programme, as well, where the allocation for 2024-25 is exactly the same as the revised estimate for expenditure in 2023-24. Even a minimum revision is not made considering the inflation rate the economy is facing. Effectively they have reduced these allocations. Despite the extension of the free food grain allocation under the National Food Security Act, the food subsidy is budgeted to fall from 2,12,332 crore to 22,05,250 crore.

This Government has received huge dividends and surpluses from Reserve Bank and public financial institutions. Dividends and surpluses from the Reserve Bank of India and leading public financial institutions, which, having risen from 39,961 crore in 2022-23 to a huge *21,04,407 crore in 2023-24, are budgeted to spike

again to 2,32,874 crore in 2024-25. But even these funds garnered through transfers within the state are not available for welfare spending. Prime Minister Narendra Modi and his advisers have not learnt the lesson that the voters want them to learn from this election result.

Budget 2024 is no different from previous years as far as allocations for the social sector are concerned. This is despite the fact that the youth, farmers, women, and the poor are identified as the main focus groups in the Economic Survey Report .

Critical schemes that address vulnerable populations also have not got much attention. There is a slight increase from 2023-24 of 11,600 crore to 12,467 crore for the POSHAN scheme (school mid-day meal). This is, however, less than the actual expenditure on this scheme in 2022-23 (12,681 crore). The Saksham Anganwadi scheme for children under six years, pregnant and lactating women, and adolescent girls has got a budgetary allocation of *21,200 crore which has hardly any hike from the last year. There is clearly no hope for higher salaries for Anganwadi workers (which have not been revised since 2018), or for higher honorarium for mid-day meal cooks, or for higher allocations for the supplementary nutrition given to children.

The allocation for Samarthya, which includes maternity entitlements (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, PMMVY) and the creche schemes, has reduced to 2,517 crore from 2,582 crore of the last year. The PMMVY is known to exclude at least half the eligible women, and the amount of *5,000 per pregnant woman has remained unchanged since the inception of the scheme in 2017. The budget for the National Social Assistance Programme (NSAP). which gives social security pensions to the elderly, single women, and disabled, remains unchanged at *9,652 crore. Once again, this is a reduction in real terms and does not leave any room for either increase in coverage or in the amount to even adjust for inflation. The central contribution to these social security pensions has been 200 per person per month since 2009.

In the case of education or health, the shift is towards increased privatisation and commercialisation with a greater emphasis on 'cost-effectiveness' in social spending. Due to a shortfall in the University Grants Commission's funding, universities are increasing their fees drastically. As a result, students are being forced to take loans. Instead of providing loan facilities, the Government should focus on reducing the fees of educational institutes. The government should have reduced privatisation of public institutions in the area of education and public

health. Government should have worked towards providing grants and lowering fees instead of forcing students to take loans.

The budget has allocated Rs 1.52 trillion for the agriculture and allied sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare received a budget allocation of Rs 1.22 trillion, an increase of just 5 per cent from Rs 1.16 trillion (RE) in FY24 - this barely compensates for inflation. The vision of Viksit Bharat@2047 could remain unrealised if the agrarian-rural economy is left behind. Almost two-thirds of India still lives in rural areas and agriculture engages the largest segment of the working population (45.8 per cent in 2022-23). But this area not granted sufficient allocation proportionate to its significance.

There is an urgent need to transform agriculture into an engine of growth through farming practices that benefit both farmers and the country as a whole.

The announcement regarding schemes and allocation for employment generation is also disappointing. Rather than discussing dampened demand, stagnant wages, and what can be done to revive employment, the announcement only includes supply-side schemes towards incentivising the private sector to increase employment.

It is painful that the BJP-led Centre is using the Union Budget to settle electoral scores. There is clear regional discrimination and hostile approach towards certain states. Most of the states have not received what they are constitutionally and legitimately entitled to. Favouring a few states disproportionately at the cost of others only for saving the government and with political motives is a violation of federal principles of Constitution and threat to inclusive development and national integrity.

This budget not only deprives states of their legitimate share but also casts more burdens on them. For instance, the announcement that three crore houses would be constructed over five years without increasing the unit cost would only "increase the burden on the State governments".

There is hardly any increase in funds allocated for upliftment of backwards and minorities. Most of the schemes in this regard see cuts. The ministry of minority affairs has got a mere 2.7% increase from last year's allocation. The estimate for coaching and allied schemes for minorities has been slashed from 30 crore in 2023-24 to 10 crore in 2024-25. The estimate for interest subsidy on educational loan for

overseas education for minorities has also been reduced from 21 crore to 15.3 crore.

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : मैं वितीय वर्ष 2024-25 के बजट का समर्थन करता हूँ । सरकार ने इस बार बिहार को विकास के दृष्टिकोण से जो बजट दिया है वह बहुत ही सराहनीय कदम है, मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल की तराई में एंव उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, इस क्षेत्र का मुख्य पेशा कृषि का है , कई चीनी के मिल हैं एवं गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में होती है, मैं कुछ मांग अपने संसदीय क्षेत्र सहित बिहार के लिए रखता हूँ, आशा है कि सरकार इसे पूरा करवाने में मेरा सहयोग करेगी:-

· आज के बजट के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत देश में 12 औद्योगिक पार्को को मंजूरी मिलनी है । इसमें एक रतवल धनहा के बीच नैनहा में स्वीकृत किया जाय जहाँ टेक्सटाइल पार्क के लिए 1700 एकड़ जमीन चिन्हित की गयी थी । यहाँ कम से कम एक टेक्सटाइल पार्क को ही मंजूरी दी जाय ।

· बिहार में घोषित तीन एक्सप्रेस वे में से एक बोधगया से वैशाली का विस्तार बुद्ध की कर्मस्थली लौरिया होते गाँधी की कर्मस्थली भीतिहरवा आश्रम (गौनाहा) तक किया जाय । उत्तरप्रदेश के कुशीनगर से धनहा होते हुए वाया लौरिया - बेतिया तक भी एक एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दी जाय ताकि बिहार और यूपी के बौद्ध स्थल आपस में जुड़ सकें।

· MSME प्रोजेक्ट के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र में खाद्य प्रसंसकरण यूनिट लगाया जाय । मेरे संसदीय क्षेत्र में चार चीनी मिले हैं, गन्ना प्रोसेसिंग का ही कोई यूनिट लगाया जाय । लौरिया और सुगौली की तरह एचपीसीएल या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा एक चीनी मिल धनहा क्षेत्र में भी लगाने पर सरकार विचार करे ताकि यहाँ के गन्ना किसानों को बिहार व यूपी के निजी मिल मालिकों के शोषण का शिकार न होना पड़े ।

· बिहार के पीरपैंती में पावर प्रोजेक्ट का स्वागत लेकिन एक पावर प्रोजेक्ट मेरे संसदीय क्षेत्र में भी लगाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को बिजली के साथ रोजगार उपलब्ध हो सके ।

· विकास केंद्र के रूप में शहरों और उसके आस पास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित करने की योजना सराहनीय है । इसमें बेतिया, बगहा, नरकटियागंज, रामनगर और सिकटा शहर को भी शामिल किया जाए ।

· देश के 500 उद्योगों में 1 करोड़ बेरोजगार युवकों को इंटर्नशिप कराने की सरकार की योजना है औरउसके लिए स्टाइपेंड के रूप में 5 हजार महीना देने की घोषणा हुई है । लेकिन आज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढाकर 10 हजार रुपए मासिक करने का मेरा अनुरोध है ।

· बक्सर में गंगा नदी पर दो नए पुल की घोषणा हुई है मेरा अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी बिहार व उत्तरप्रदेश को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर बगहा और जटहा के सामने एक नए पुल की स्वीकृति दी जाय ताकि बगहा अनुमंडल के ही एक प्रखंड पिपरासी की दुरी 60 किलोमीटर से पटकर मात्र 08 किलोमीटर रह जाय और बिहार व यूपी के बीच भी बेहतर कनेक्टविटी हो सके ।

· काशी और उज्जैन की तरह झारखण्ड के पावन तीर्थ देवघर ज्योतिर्लिंग बाबा धाम को भी धार्मिक कोरिडोर के रूप में विकसित किया जाय । यहाँ भी सालों भर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने बिहार, यूपी, झारखण्ड और बंगाल से लाखों लोग आते हैं ।

· बिहार में पर्यटन पर केंद्र व राज्य सरकार का काफी ध्यान है । मेरे संसदीय क्षेत्र में भी पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थल हैं । महर्षि बाल्मीकि व लवकुश की जन्मस्थली बाल्मीकिनगर स्थित नरदेवी मंदिर, जटाशंकर मंदिर, कौलेश्वर धाम, ऐतिहासिक बाँसी धाम का रामघाट, गाँधी जी द्वारा स्थापित भीतिहरवा आश्रम, मौर्यकालीन धरोहर नंदनगढ़, धार्मिक स्थल सोफा मंदिर, सहोदरा स्थान, सोमेश्वर पर्वत और नीतिशास्त्री चाणक्य की स्मृति चानकी गढ़ को भी ध्यान में रखकर सम्पूर्ण बाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए ।

· ख़ुशी है कि बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिए राशि आवंटित की गयी है । मेरा संसदीय क्षेत्र भी गंडक, सिकरहना, मसान जैसी बड़ी नदियों के अलावा दर्जनों पहाड़ी नदियों से घिरा हुआ है जिससे हर साल बाढ़ व कटाव की समस्या बनी रहती है । योजना बनाते समय इस क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए ।

· बाल्मीकि नगर में कस्टम कार्यालय का उद्घाटन होने के बावजूद वह आजतक चालू नहीं हो सका है । इस भंसार के खुलने से भारत व नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे इसे जल्द खोला जाए ।

· सरकार का शिक्षा पर बहुत अधिक जोर है, ऐसे में माँग होगी कि बाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र में रेलवे, पोस्ट ऑफिस, संचार, एसएसबी आदि के कर्मचारियों, अधिकारियों व जवानों के बच्चों के अलावा सामान्य बच्चों के लिए एक केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति दी जाए ।

· गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 05 सालों तक मुफ्त राशन व्यवस्था लागू रखने के सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है । लेकिन गेंहू व चावल के अतिरिक्त राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दाल, तेल व चीनी भी न्यूनतम सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाय ताकि बढ़ती महंगाई से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सके ।

· मेरा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी दुर्गम है जहाँ हर जगह से रेलवे, सड़क या वायुमार्ग की बेहतर कनेक्टविटी नहीं है । यहाँ से देश के हर कोने में व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और इलाज के लिए लोग घर से बाहर जाते हैं । ऐसे में बाल्मीकिनगर में हवाई अड्डा निर्माण के साथ रेलवे की तरफ से कुछ प्रमुख स्थलों के लिए गाड़ियां चलायी जानी चाहिए । बिहार की राजधानी पटना के लिए एक गाड़ी गोरखपुर वाया नरकटियागंज व मुजफ्फरपुर चलनी चाहिए जिसमे स्लीपर व एसी बोगियां भी हों । पटना विद्यार्थी, मरीज और व्यवसायी प्रतिदिन अपने अपने काम से जाते रहते हैं जिन्हे काफी दिक्कत होती है। साथ ही बिहार के बगहा, बेतिया, नरकटियागंज से महाराष्ट्र के पूना के लिए, दक्षिण भारत के चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद आदि प्रमुख शहरों के लिए, झारखण्ड के रांची, हटिया आदि के लिए एक भी गाड़ी नहीं है । इन सभी जगहों के लिए नरकटियागंज रूट से नई गाड़ियों को स्वीकृति मिलनी चाहिए ।

· नरकटियागंज में वाशिंग पिट न होने से गाड़ियों की साफ सफाई में काफी दिक्कत होती है । कई बार इसके लिए सरकार से माँग की गयी है, इसको जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।

· पूर्वोत्तर रेलवे के छितौनी तमकुही रेलमार्ग के बंद पड़े निर्माण कार्य को अविलम्ब शुरू कराने पर विचार किया जाना चाहिए । बिहार व यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए यह वरदान साबित होगा । इसके निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी । वर्षों से लंबित इस परियोजना का निर्माण रुकने से लोगों में काफी निराशा है ।

· देश के लोगों को टैक्स स्लैब में रियायत देने से जनता को काफी राहत मिलेगी । आयकर में छूट की सीमा बढाकर 03 लाख करने से छोटे व्यापारियों और आम लोगों में काफी ख़ुशी है ।

अंत में इन सारी मांगों पर बजट में विचार करने का आग्रह करते हुए वित्त मंत्री जी द्वारा पेश लोक कल्याणकारी बजट का स्वागत करता हूँ । पूरे संसदीय क्षेत्र और पेश बजट को ध्यान में रखकर बनाया गया है । और भी मुद्दे जो सवाल में पूछे गए हैं, उसे उठाया जा सकता है । जितनी माँग रहे जनता उससे खुश होती है, पूरा हो न हो यह आपके हाथ में भी नहीं । घरेलूसंस्थानों में में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए एक ई-वाउचर दिया जाएगा, इस निर्णय की प्रशंसा करनी होगी । सादर सहित ।

SHRI ALFRED KANNGAM S. ARTHUR (OUTER MANIPUR): Madam, my State has been in the news for all the wrong reasons for the past 15 months. I have gone through the Budget that the hon. Finance Minister has placed before this august House. I think she fails to understand that at this present juncture, Manipur is the lowest per capita income bearing State and has the highest inflation. How do you expect the State that has the lowest income and highest inflation to survive?

You already have a conflict. You have the worst floods in the last 35 years, unprecedented floods that we have ever seen in the last 35 years. The hon. Finance Minister grins from ear to ear, she smiles and places a Budget that is anti-people. You do not need a rocket scientist to understand the dynamics of what is people-friendly, and what goes against the interest of a nation. I am from a family that has sacrificed in building this nation. My esteem friends from Arunachal Pradesh are fortunate enough that my grand-uncle is Major Ralengnao Bob Khathing, who fought for this nation, and today we celebrate a place called Tawang in Arunachal Pradesh. He is the gentleman responsible for our nation celebrating that area today. He is my real grand-uncle. The name that I have today was given by him. Today you are burning my State. I do not think when he went and proceeded ahead doing service to this nation way back in the 50s, did he ever think that this nation would let go of his own people, which he so fondly called as his people and his nation.

मैडम चेयरपर्सन, यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है । प्रधान मंत्री जी बोलते रहते हैं और भाजपा में सब लोग बोलते रहते हैं कि मोदी जी है तो सब मुमकिन है और सब सही हो सकता है । जहां-जहां पर मोदी जी की सरकार है, वहां कहते हैं कि हम सब कुछ दिलाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर का न्याय कहां पर है? मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदारों ने इस देश को बनाने में अपना खून बहाया है । हम देश के गद्दार नहीं हैं ।

We are not betrayers to this nation. We have helped build this nation. We deserve an equal Budget. It is my right. मेरे क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उन्होंने मुझे यहां पर विश्वास के साथ भेजा

है not to come and listen to *bhashans,* neither is it to come and listen to all fictitious figures that are brought before this august House. This nation, I have been brought up to believe, is bigger than individuals. In this nation, I have believed, I have grown, played with, wandered around with, studied with, with wonderful friends across different races, different religions, different communities, and yet, I have never felt in my life a need for saying that I am a Christian today. I do not ever want to speak out that I am a Christian, or I am a Hindu, or I am a Muslim. I should not have had a need to. Today, why am I having this fear and this need to express my desires of wanting to be a free Indian within this nation's rules and laws?

Madam Chairperson, you are a mother. I look up to you. I appreciate you. You have been sent here by your electorate to represent their wills, desires and wishes, and especially to uphold the ideals of this nation. What has happened in my State of Manipur in the last 15 months? This is no joke. Since the coming of the NDA Government in 2014, no single day or week has gone by when we have not seen a Union Minister in Manipur. Every single week we would see a Union Minister. Where are they today after the 3rd of May 2023?

वर्ष 2023 के बाद एक भी मंत्री मणिपुर में नहीं दिखा । ऐसा क्यों? मैं प्रधान मंत्री जी से मणिपुर के बारे में पूछना चाहता हूँ । मेरा दिल कहता है कि अगर वे सच्चे आदमी हैं, अगर वे सब सही करना चाहते हैं, अगर वे खुले दिल के हैं, उनका 56 इंच का सीना है तो उन्हें मणिपुर में सब ठीक करना होगा । क्या उन्हें समझ में आता है कि अपने देशवासियों को, अपने देश के नागरिकों को मणिपुर में अभी तक खाना-पीना भी नहीं मिल रहा है । उन्हें रिफ्यूजी कैंप में 15 महीने हो चुके हैं । वहां आप किसको पुकारेंगे, किसको बोलेंगे? आप अपने मुख्य मंत्री जी से पूछ लीजिए । उनके मुंह से हर दिन सिर्फ मारने-पीटने के शब्द निकलते हैं । यह क्या है? क्या यह मेरा देश है?

मैडम, हमारे परिवार ने यह देखने के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया है । हमारे परिवार ने एक-एक पल इस देश को बनाने में कुर्बान किया है । आज हमारा हक बनता है कि हमें न्याय दिलाइए, आप नीति और नीयत साफ कीजिए । प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी ये साफ-सुथरा करके मणिपुर आइए । हम लोग आपके देशवासी हैं । हम सभी भारतीय नागरिक हैं । आप हमारे पास क्यों नहीं आना चाहते हैं? हम आपकी मन की बात 10 सालों से सुनते आए हैं । For 10 years, we have listened to it. Can you not even hear the cries of the women and the children who cannot go back to their homes in one State, a small State. हमारे प्रदेश की जनसंख्या 30 लाख है । वैली दो हजार स्क्वायर किलोमीटर में है । वहां पर मैतेई लोगों की मेजॉरिटी है । From the southern side, they cannot go beyond Moirang. From the south-eastern side, they cannot go beyond Pallel. From the eastern side, they cannot go beyond Yaingangpokpi. On the northern side, they cannot go beyond Kanglatongbi.

Madam, my people have borne this conflict for 15 months. You can, at least, listen to me for 15 minutes without pressing the buzzer. I would be grateful. I think, we have earned that much of time, at least. I am from the Naga community in Manipur. We have stayed neutral to this conflict in letter and spirit. We have not taken sides with anybody thinking that being neutral, we would one day usher in peace.

On the 8th of July, 2024 our hon. LoP came to Manipur. I am extremely grateful to the hon. LoP for coming to Manipur three times. I am so grateful that all the members of the INDIA alliance ? Akhilesh ji from the Samajwadi Party, Mamata ji from the Trinamool Congress, Stalin ji from the DMK, Uddhav ji from the Shiv Sena, Sharad Pawar ji from the original NCP and all the alliance partners of the UPA on the INDIA alliance ? have kept alive the Manipur issue in this august House by telling the people of our nation that Manipur should come first. When the LoP came to Manipur, we were given an audience with the hon. Governor at 5 pm on the 8th July. I was also part of that delegation. We gave suggestions. I gave two clear suggestions on how to bring peace to Manipur. I think it has not been acted upon because they have not taken Manipur as a part of this nation. It has been clearly said that the Nagas are not part of this conflict. We are neutral to this issue. We have requested the Governor to take the help of the leaders of the Naga community, and send them out to the Kuki as well as the Meitei areas to usher in peace, to start with. We have given that suggestion.

Secondly, we have made it very clear in our suggestion. One community is saying that the Chief Minister has originated this entire conflict. You have another 49 more Members in your kitty in the State other than the Chief Minister. The hon. Prime Minister, I am sure, can replace him immediately with no questions asked. My question is this. Is it so difficult to replace one man and bring peace to our area? जब आप इतने छोटे प्रदेश में शांति और न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो आप इतने बड़े देश में क्या करेंगे?

Hon. Chairperson, Madam, Nirmala Sitharaman ji has placed the Budget before us. She has talked about tourism in the rest of the country. But she has mentioned nothing about tourism going to the North-East. If you go to any prestigious hospitality sector in the rest of the country, you will see youngsters from the North East everywhere. It is all our youngsters who are jobless in the North East. Tourism should have been encouraged in the North-East. In the Budget, there has not been a single mention about it. I would like the hon. Finance Minister to add and include the North East in the tourism map, and see that they will encourage and bring forth

tourism to such an extent that our people do not have to look to the rest of the country for their survival.

With these words, thank you very much for giving me time to speak today, and I am grateful to this nation.

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव): आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक बजट 2024-25 प्रस्तुत किया है जो वेतनभोगियों , महिलाओं, बुजुर्गों समेत सभी वर्गों के लिए एक नया उत्साह और विकास का नया विश्वास लेकर आया है । मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करती हूं तथा माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद प्रकट करती हूं जिन्होंने ऐसा दूरदर्शी बजट पेश किया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती देने वाला साबित होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहेदिल - अभिनन्दन करती हूं कि उन्होंने लगातार तीसरी बार देश की आम जनता का विश्वास के साथ -साथ दिल भी जीता है । और मैं मेरी पार्टी के सभी बड़े नेताओं और मेरे चुनाव क्षेत्र जलगांव के सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनकर इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है ।

यह बजट भारत की जनता द्वारा हम पर जताए गए भरोसे को दर्शाता है, जिन्होंने हमें लगातार तीसरी बार चुना है । हम 2047 तक समृद्ध भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध जिसमें विकास के नौ विषयों का रोडमैप है, जिसमें कृषि में उत्पादकता और लचीलेपन से लेक अगली पीढ़ी के भविष्य तक शामिल हैं । हमारा ध्यान गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर जिसमें सार्थक रोजगार, कौशल विकास और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है । हमने 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए पाँच योजनाओं और पहलों के पैट की घोषणा की है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन है । हम रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएँ भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहली बार औपचारिक कार्यबल प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक महीने की छुट्टी शामिल है । भारत को वैश्विक नेता बनाने के लिए कौशल विकास महत्वपूर्ण है, और हम 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं । हम उन युवाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं जो किसी भी सरकारी योजना के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें घरेलू संस्थान शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है ।

मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना हमारी सरकार की एक प्रमुख प्रतिबद्धता है । हम कर स्लैब को सरल बना रहे हैं, आय से काटे गए टीडीएस में टीसीएस क्रेडिट प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बना रहे हैं और टीडीएस दाखिल करने में देरी को अपराध से मुक्त कर रहे हैं । हम मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर रहे हैं और एनपीएस के लिए कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% करने सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान कर रहे हैं । सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल को साकार करना हमारी प्राथमिकता है । हम आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए पीएम-जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित कर रहे हैं । हम गरीबों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पीएम-आवास योजना के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ घरों का निर्माण भी कर रहे हैं ।

महिला शक्ति भारत की सफलता का नेतृत्व कर रही है, और हम महिला नेतृत्व विकास, सामाजिक स्वायत्तता, वित्तीय समावेशन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे रहे हैं । हम कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और चाइल्डकैअर की स्थापना कर रहे हैं, महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं, और स्वयं सहायता समूह उद्यमों के लिए बाजार तक पहुँच प्रदान कर रहे हैं ।

किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है । हम सभी प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी को इनपुट लागत पर 1.5 गुना रिटर्न तक बढ़ा रहे हैं, कृषि अनुसंधान को वित्तपोषित कर रहे हैं, और प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थागत सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

पूर्वोदय के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत का सतत विकास एक प्रमुख पहल है, जिसमें अमृतसर- कोलकाता औद्योगिक गलियारा, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और पीरपैंती में एक नया 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने जैसी बिजली परियोजनाएँ शामिल हैं ।

हम सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, पूंजीगत व्यय आवंटन बढ़ाने और लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण की त्रि-आयामी नीति के माध्यम से सकारात्मक राजकोषीय समेकन के साथ सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमता को अनलॉक करना महत्वपूर्ण है, जिसमें ऋण पहुंच और परिचालन दक्षता में सुधार, TREDS में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के दायरे को बढ़ाना और ई-कॉमर्स उद्यमिता केंद्र स्थापित करना शामिल है ।

आकार और गति के आधार पर औद्योगिक विस्तार हमारा लक्ष्य है, जिसमें 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पार्क, अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए स्वामित्व, पट्टे और ध्वज सुधार और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन शामिल है ।

बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित दीर्घकालिक विकास हमारा विजन है, जिसमें ₹11,11,111 करोड़ का बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय आवंटन है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है । हम 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY के चरण IV को लॉन्च कर रहे हैं और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ।

भारतीय शहरों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा लक्ष्य है, जिसमें सतत शहरी विकास, 14 बड़े शहरों के लिए परिवहन-उन्मुख विकास योजनाएं और एक व्यापक किराये के आवास नीति शामिल है ।

भारत की विरासत को संरक्षित करना हमारी प्रतिबद्धता है, जिसमें विष्णुपुर मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास और राजगीर और नालंदा का व्यापक विकास शामिल है ।

हमारे पास आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत रोडमैप है, जिसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, JAM-त्रयी और विभिन्न भूमि सुधारों, अनुसंधान और विकास और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार पर जोर दिया गया है ।

श्री अमरा राम **(सीकर) :** माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बजट पर अपनी बात रखने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । देश का किसान, देश का जवान, देश का गरीब और महिलाएं जैसी आशा कर रही थीं, मैं समझता हूं कि यह बजट उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं रखा गया है । यह कहा जा रहा है कि आज किसान इस देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर इस कृषि संकट के कारण आत्महत्या कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि वह अंग्रेजों के वक्त, राजशाही के वक्त भी आत्महत्या नहीं करता था । इससे भी बुरी स्थिति थी । लेकिन आज इस कृषि संकट के कारण इस देश का किसान और खेत मजदूर,

जो अपनी जिंदगी खेत पर या मजदूरी में चलाता है, वह आज आत्महत्या कर रहा है । इससे बुरी बात नहीं हो सकती है और उनके समाधान की बजाय उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है ।

आज वह अपनी पैदावार पर एमएसपी मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा है, वह देने के लिए सरकार तैयार नहीं है । आज जिस तरह से उस किसान को लूटा जा रहा है, आप अंदाजा लगाइये कि 15 रुपये में, हमारे कृषि मंत्री जी जहां से आते हैं, वहां 100 रुपये में बीज लाकर लहसुन बोया था और 5 रुपये में लेने वाला नहीं था । किसान उनसे भाव मांगने गया तो उन्होंने मंदसौर में गोली चलाने का काम किया और पांच किसानों को मौत के घाट उतारने का काम किया है । जो 15 रुपये में फसल पैदा करता है, उससे खरीदकर 300 रुपये तक बेचते हैं, तब तो देश विकास करता है । अगर किसान की लागत और मेहनत के अनुसार थोड़ा मुनाफा जोड़ कर उसे गारंटी दे दी जाए तो देश विनाश कर देगा ।

मैं सीकर से आता हूं और वहां प्याज पैदा होता है । जब किसान प्याज पैदा करके लाता है तो 5 रुपये में कोई लेने वाला नहीं होता है । जब वही प्याज बड़ी-बड़ी कपंनियों के गोदाम में चला जाता है तो वही प्याज 65 और 70 रुपये में बिकता है । जब आम आदमी उसे 65 रुपये और 70 रुपये में खरीद कर खाता है, तब देश विकास करता है । उसे भाव नहीं मिलेगा और उसे सस्ता नहीं मिलेगा । आज किसान खेती के अलावा दूध का उत्पादन करके इस देश को मक्खन खिलाता है, दूध पिलाता है । उस दूध की हालत यह है कि उस किसान का दूध और कंपनी का पानी बराबर बिकता है और हम कहते हैं कि यह देश के साथ न्याय है । मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है । आज दूध 26 रुपये में लिया जाता है और 50 रुपये में बेचा जाता है । एक पानी की बोतल भी 30 रुपये, 40 रुपये में मिलती है । अगर अमीर का पानी और किसान का दूध एक भाव बिकता है तथा सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि उस किसान के साथ हम न्याय कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है ।

यह सरकार बनते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेकर आई । इस देश का किसान लड़ा । ये अध्यादेश पास नहीं कर पाए । फिर काले कानून लेकर आए । एक साल से ज्यादा समय तक इस देश का पूरा किसान लड़ता रहा, आखिर में कानून वापस लेने पड़े । इस देश की सरकार ने 9 अगस्त, 2021 को यह लिखकर दिया था कि उनको हम एमएसपी देंगे । जितने झूठे मुकदमे हैं, सरकार ने मान लिया था कि यह आंदोलन सच था । इस तरफ बैठे हुए लोगों ने, इनके नेताओं ने किसानों के बारे में कहा था कि ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, लेकिन आखिर कानून वापस लेने पड़े । यह लिखकर दिया था कि, सभापति महोदय आप कहें तो मैं इसे टेबल कर सकता हूं, झूठे मुकदमे वापस लेंगे । जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनको पैकेज देंगे । आज तक एक को भी पैकेज नहीं दिया । केन्द्र सरकार, दिल्ली की पुलिस ने जो झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, आज तक एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया । निश्चित रूप से अगर आप उस किसान को कुछ देना नहीं चाहते हैं, तो कम से कम उसके साथ यह विश्वासघात तो नहीं करे । आप एमएसपी की बात नहीं करते हैं ।

मैं समझता हूं कि राजस्थान सबसे ज्यादा बाजारा पैदा करता है । अभी 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से एमएसपी थी । अभी सरकार ने 150 रुपये बढ़ाकर 2650 रुपये पर क्विंटल किया है ।

सरकार जब उत्तर दे, माननीय वित्त मंत्री जी जब उत्तर दें, तो वे बताएं कि क्यों इन 10 सालों में राजस्थान के किसानों का एक क्विंटल भी बाजरा नहीं खरीदा? जितनी राशि किसान सम्मान निधि के नाम से पूरे देश के किसानों को देते हैं, इन 10 वर्षों में राजस्थान के किसानों का नुकसान अकेले बाजरे के मामले में करने का काम किया है ।

यह हालत एक फसल में नहीं है, बल्कि हर फसल में है । सरकार कहती है कि हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर करेंगे । मैं समझता हूँ कि आज देश में 75 साल के बाद भी देश के आम आदमी के लिए दलहन और तिलहन की फसल पैदा नहीं की जाती है । हम दाल के लिए विदेशी किसानों को भाव दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को भाव नहीं देंगे । जब सरसों और चना खरीदने की बात आती है, तो सरकार कहती है कि एमएसपी पर हम केवल 25 क्विंटल ही खरीदेंगे । अगर किसी की फसल 50 क्विंटल हो गई, तो वह 25 क्विंटल आपके यहाँ बेचेगा और 25 क्विंटल बाजार में ले जाकर बेचेगा । मैं समझता हूँ कि इससे भयानक हालत नहीं हो सकती है ।

आप बजट में किसान की बात कर रहे हैं । महोदया, मैं कहना चाहूँगा कि किसानों के फर्टिलाइजर पर 24,894 करोड़ रुपए का बजट घटाने का काम किया है । जो डीएपी 400 रुपए में मिलती थी, आज वह 1,400 रुपए में मिलती है । इसकी जो बोरी 50 किलो की मिलती थी, आज वह 45 किलो की मिलती है । डीजल 50 रुपए में मिलता था, आज वह 95 रुपए में मिलता है । इस तरह से, खाद हो, बीज हो, डीजल हो, सब कम्पनियाँ मालामाल हैं और काम लेने वाला निश्चित रूप से बेहाल है ।

इस बजट में मनरेगा में 86 हजार करोड़ रुपए एलॉट किये गये हैं । इन चार महीनों में 41 हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं । आज ही मंत्री जी उत्तर दे रहे थे कि एक सौ दिनों का काम देने की गारंटी है । लेकिन एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, जहाँ काम मांगने वालों को एक सौ दिनों का काम दिया गया हो । इसमें 90 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो काम करने जाती हैं । इनमें 80-90 प्रतिशत एससी और एसटी की महिलाएं होती हैं । लेकिन उनको इस देश के संसद के द्वारा बनाये हुए कानून, जिसमें एक सौ दिनों के काम देने की गारंटी है, उनको काम नहीं दिया जाता है । उनको समय पर मजदूरी नहीं दी जाती है । चार-चार महीने लोगों को मजदूरी नहीं दी जाती है । राजस्थान वह राज्य है, जो आज भी पीने के पानी के लिए तरसता है । ईआरसीपी की योजना, जो राजस्थान में पीने के पानी और सिंचाई के लिए योजना थी, वहाँ की सरकार कहती है कि यह केन्द्रीय परियोजना हो गई । लेकिन इस बजट में ईआरसीपी योजना में राजस्थान का नाम नहीं है । आज पीने के पानी के मामले में हालत खराब है ।

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, आप अपनी बात एक मिनट में कम्प्लीट कीजिए ।

श्री अमरा राम**:** महोदया, मैं शेखावाटी और सीकर के क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ के सबसे ज्यादा लोग सेना में भर्ती होते हैं । जब भी युद्ध हुए हैं, तो सबसे ज्यादा शहादत शेखावाटी देती है । लेकिन अग्निवीर बनाकर देश के जवानों और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है । अब सरकार कह रही है कि चार साल के बाद वापस आने पर उन अग्निवीरों को सरकार, पुलिस और जेलों में भर्ती होने का मौका देगी ।

मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि यह बजट केवल इस बात के लिए है कि सरकार बचाओ, उद्योगपतियों को बढ़ाओ और रोज़गार खत्म करो । यह बजट केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए है ।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ**.** प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा**-**गोंदिया)**:** सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया । वर्ष 2024 का बजट माननीय वित्तमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है । हम सब उसके साक्षी बने हैं । मैं युवा हूं और मैं बजट को इस जिज्ञासा के साथ बड़े ध्यान से सुन रहा था और बार बार पढ़ा भी कि शायद युवाओं के लिए कुछ बेहतर हो, परंतु हर बार की तरह, इस बार भी निराशा ही हाथ लगी ।

मैं बजट 2024 का पुरजोर विरोध करता हूं । यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है । मैंने कुछ बिंदुओं के आधार पर अपनी बात रखना तय किया है ।

कराधान नीति **(Taxation)** - इस बजट में पेट्रोल और डीजल पर 10 प्रतिशत की कर वृद्धि की गई है । इससे परिवहन लागत बढ़ेगी और अंततः वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में 5-7 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है । आवश्यक वस्तुओं पर GST में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब है कि एक सामान्य परिवार की मासिक खर्च में औसतन 2000 रुपये की बढ़ोतरी होगी । जो हम सब के लिए चिंतनीय विषय है ।

कृषि क्षेत्र की उपेक्षा**-** इस बजट में कृषि के लिए मात्र 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र की जीडीपी में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, लेकिन किसानों की औसत आय में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई । किसानों के लिए कर्ज माफी योजना में बजट का केवल 0.5 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है, जबकि देश के 60 प्रतिशत से अधिक किसान कर्ज में डूबे हुए हैं ।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का अभाव **-** शिक्षा बजट में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कि अपर्याप्त है । शिक्षा पर खर्च जीडीपी का मात्र 3.1 प्रतिशत है, जबकि यूनेस्को के अनुसार इसे कम से कम 6 प्रतिशत होना चाहिए । स्वास्थ्य बजट में केवल 2.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का 5 प्रतिशत होना चाहिए । महामारी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन बजट में यह बात अनदेखी की गई है ।

रोजगार के अवसरों का अत्यंत अभाव**-** देश में बेरोजगारी दर 9 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले वर्ष 8 प्रतिशत थी । युवा बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत है, जो कि चिंताजनक है । एमएसएमई सेक्टर, जो देश के 40 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है, को इस बजट में कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला है । सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मात्र 1 प्रतिशत बजट का प्रावधान किया है, जो कि पर्याप्त नहीं है ।

बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है । अब बात यह है कि इस विशेष पैकेज का लाभ मिलना किसको है? इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या उन लोगों को इस विशेष पैकेज का लाभ मिलेगा, जो बिहार के नागरिक देश के विभिन्न हिस्सों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं? जवाब है कि बिलकुल नही । सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से सबसे बड़ा लाभ कुछ बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा । बिहार के औद्योगिक विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 70 प्रतिशत यानी 35,000 करोड़ रुपये बड़े उद्योगपतियों के प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किए जाएंगे । विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उद्योगों को कर में 25 प्रतिशत की छूट, सस्ती बिजली दरों में 30 प्रतिशत की रियायत, और अन्य कई लाभ मिलेंगे । बिहार की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इस पैकेज में कृषि क्षेत्र केविकास के लिए मात्र 1,000 करोड़ रुपये, यानी कुल बजट का केवल 2 प्रतिशत आवंटित किया गया है । महोदय, इस बात से सरकार की किसान विरोधी मानसिकता साफ प्रतीत होती है । जिस राज्य की नींव ही कृषि हो और वहां आप विशेष राशि आवंटित करके नींव को मात्र उस बजट का दो फीसदी हिस्सा देने का प्रावधान कर रहे । यह व्यवस्था "ऊंट के मुंह में जीरा" वाली कहावत को चरितार्थ करती है । इसके साथ ही, बिहार के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए मात्र 7,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि कुल बजट का मात्र 15 प्रतिशत है । इससे स्पष्ट होता है कि इस पैकेज का सर्वाधिक लाभ बड़े और चिन्हित उद्योगपतियों को मिलेगा, जबकि बिहार की अधिकांश आबादी को इसका लाभ नहीं मिलेगा । पैकेज इन्होंने दिया ही था तो बिहार के जन, जो अन्यत्र हिस्सों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, उन्हे सीधा लाभ देते । बिहार में निवासरत गरीब तबके के उत्थान की बात करते हैं, परंतु

नहीं इन्हें तो अपनी राजनैतिक रोटी सेंकनी है । Where is the spirit of Co-operative federalism? इन दो राज्यों को ही अधिकतम बजट क्यों दिया जाता है? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी है?

इनका नारा है "सबका साथ, सबका विकास" परंतु क्रियान्वयन है "सबका साथ, अपना विकास" सही मायने में तो इन्हे बजट पर पुनर्विचार करना चाहिए । यदि उन्होंने पिछले 10 वर्षों के बजट में वास्तव में प्रदर्शन किया होता, तो परिणाम कुछ और ही होते । मानव विकास सूचकांक में भारत पिछड़ रहा है । भारत वर्तमान में 193 देशों में 134 वें स्थान पर है । 'उदार लोकतंत्र' Liberal Democracy रैंकिंग में भारत 179 देशों में से 104 वें स्थान पर है । भारत का लोकतंत्र खतरे में है । विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लिंग अंतर (World Economic Forum on Gender Gap Report) रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 146 देशों में 129 वां है । वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index) में भारत 108 वें स्थान पर था, अब 129 देशों में 111 वें स्थान पर है । प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत वर्ष 2013 में 180 देशों में 140 वें स्थान पर था और अब 161 वें स्थान पर है । पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक Environment Performance Index में 180 देशों में भारत 176 वें स्थान पर है ।

यह बजट आम जनता के हितों के खिलाफ है । यह बजट गांव, गरीब, पिछड़ा, मजदूर, महिला, किसान, आदिवासी के हितों में बिलकुल नहीं है । मैं पुनः इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं और सदन से अपील करता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और जनता के हित में सुधार किए जाएं । धन्यवाद ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल **(महाराजगंज) :** माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के आम बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ ।

इसी के साथ, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को हृदय से बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ । इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा और एनडीए गठबंधन के मूल मंत्र- ?सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास? को केन्द्र में रखकर इस बजट को बनाया है ।

सभापति महोदया, इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़-संकल्पित है कि सभी धर्मों, जातियों, लिंगों और आयु वर्ग के भारतीयों को अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हो, ऐसा यह बजट है ।

महोदया, यह बजट भारत की आम जनता के लिए इसलिए भी विशेष है, क्योंकि इसमें मुख्यत: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान पर ध्यान केंद्रित कर विभिन्न योजनाओं में धन आवंटित किया गया है, जो भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश बनाए रखने के साथ सर्वकल्याणकारी, आत्मनिर्भरवादी, विकासवादी तथा वैश्विक अर्थ जगत में सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति वाला राष्ट्र बनाने की दिशा में यह बजट काफी प्रभावी है ।

महोदया, इस बजट की अन्य विशेषताएं निम्नवत हैं, जो हमारे देश की जनता के कल्याण के साथ राष्ट्रहित तथा भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं । विपक्ष के लोग तथा खासकर विपक्ष के नेता अपनी तरफ से किसान के बारे में चर्चा करते हैं । मैं सिर्फ दो-तीन बातें उनको चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं । अगर उनके सामने रावा, तोंगनी, सावां, मरूआ, कोदो, राई, अजवाइन, तोरी, अगर ये एक साथ रख दिए जाएं तो उनमें ये

तफ़रक़ा नहीं कर सकते हैं कि यह क्या है और कहां से आता है? किसान की बातें तो लंबी-चौड़ी करते हैं । अगर इनसे यह कह दिया जाए कि लाल मिर्च और हरी मिर्च का पौधा कैसा होता है, तो उसमें भी तफ़रक़ा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये किसान की बात जरूर करेंगे कि हम किसान हितैषी हैं ।

जब ये किसान की बात करते हैं, तो किसी एक राज्य के किसान जब यहां आंदोलन के लिए आते हैं, तो उनके साथ फोटो खींचकर शेयर जरूर करते हैं, लेकिन कभी कर्नाटक में जाकर वहां के किसानों के साथ क्या हो रहा है, यह नहीं देखते । वहां भाजपा और एनडीए के लोग जाकर उन किसानों के आंसू पोंछ रहे हैं । विधान सभा चुनावों में वहां जाकर आपने वादा किया था । आज हजारों की तादाद में कर्नाटक के किसानों ने आत्महत्या की है । उन किसानों के लिए आपने एक बार भी वहां जाने का काम नहीं किया है । भारत की सरकार सबके लिए है ।

आप किसान की बात करते हैं? वर्ष 2014 से पहले, जब आपकी सरकार थी, तो भले ही आपने कुछ किसानों के कर्ज की राशि माफ कर दी हो, लेकिन यह सरकार, जो हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में है, वह किसान हितैषी है । यह साबित करता है कि हम पूरे देश के किसानों के लिए प्रतिवर्ष छ: हजार रुपए तीन माह में किसान सम्मान निधि के तौर पर उन्हें मुहैया कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदया, यह भी इसे साबित करता है कि 9 जून को हमारे प्रधान मंत्री जी तीसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में ओथ लेते हैं और 10 जून को अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे पहुंचते हैं । वे पहला दस्तखत किसानों के लिए करते हैं और 20 हजार करोड़ रुपए किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि यह किसानों के हित की बात है ।

आप किसान के नाम पर आंसू भले ही बहा लेते हो, लेकिन किसान का दर्द कभी आपने जाना ही नहीं है । किसान के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है कि किसान कहां से, कितने कष्ट से आते हैं । किसान के दर्द को अगर किसी ने जाना है, तो श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जाना है । यह एनडीए की सरकार जानती है । आपने तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लिया है ।

?जाके पैर न फटे बिवाई,

सो क्या जाने पीर पराई ।?

इस देश के गरीबों के बारे में, इस देश के कल्याण के बारे में हमारे देश के प्रधान मंत्री जी और एनडीए सरकार में शामिल हमारे लोग जानते हैं, क्योंकि हम कष्ट से यहां आकर देश का कल्याण करने का संकल्प लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । आप सिर्फ लंबी-चौड़ी बात कर-कर के और सिर्फ एक असत्य बात बार-बार कहकर चाहते हैं कि उसको आप सत्य बना दें । लेकिन यह संभव नहीं है । आप असत्य बात कह-कहकर उसे सत्य बनाना चाहते हैं, देश की जनता आपका बंटाधार करेगी, इसे आप पूरी तरह से अपने ध्यान में रखिए ।

जहां तक धर्म की बात है, मैं उसकी बात करता हूं । हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने धर्म के प्रति और सनातन के प्रति देश भर में जागरुकता पैदा की है । उन्होंने आपको मंदिरों में जाने के लिए बाध्य कर दिया, आपको जनेऊ पहनने के लिए बाध्य कर दिया । आप मंदिरों का दरवाजा तक नहीं जानते थे, लेकिन अब आप मंदिरों में जाकर टीका-चंदन करा रहे हैं । यह देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की देन है कि हम सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बजट में रोजगार, कौशल, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्य वर्ग पर भी पूरा ध्यान केन्द्रित किया है । उदाहरण के तौर पर अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 योजनाओं और पहलों की पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इसके लिए केन्द्रीय परिव्यय दो लाख करोड़ रुपये का है । इसी के साथ शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का भी प्रावधान बजट के माध्यम से करके देश के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा खींचने का काम किया गया है ।

विपक्ष से जब भी कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो वह एक असत्य बात बोलकर देश को गुमराह करने का काम करता है । ये अग्निवीर के बारे में बात करते हैं । अग्निवीर ऐसे नहीं तैयार हुआ है, आप अग्निवीर को सिर्फ नाम से जानते हैं । अग्निवीर के बारे में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के डिफेंस और गृह मंत्री जी ने और इस सरकार ने काफी मंथन किया है । महीनों-महीनों नहीं, वर्षों मंथन किया है और तब यह योजना लायी गई है कि हमारे देश के हर युवा को काम मिले, देश का युवा मजबूती से सीमाओं की सुरक्षा भी करे और सुरक्षा के साथ-साथ यह देश भी मजबूती के साथ आगे बढ़े । देश की सुरक्षा में अब हमारी सीमाओं पर किसी को हमें आँख दिखाने का मौका न मिले और अगर कोई हमें आँख दिखाए तो चाहे हमारे अग्निवीर के जवान हों, देश के जवान हों, वे उन सीमाओं पर हमें आँख दिखाने वालों की आँख निकाल लें, यह ताकत हमारे देश के नौजवानों में है । अग्निवीर-अग्निवीर कर करके देश के युवाओं को गुमराह करना बंद कर दीजिए । आप इस पर गुमराह करना बंद कीजिए ।

मैं तो काफी हैरानी में रहता हूँ । जब बजट आया तो यही लोग कह रहे थे कि बिहार मालामाल है, बिहार में बजट का सब पैसा चला गया, ये लोग ऐसे नारे लगा रहे थे । बिहार में विधान सभा चल रही थी और इन्हीं के लोग बिहार की विधान सभा में झुनझुना ले जाकर दिखा रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला । यह इनकी कैसी दोरंगी नीति है । इस तरह की दोरंगी नीति के बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं । एक तरफ आप ही के लोग झुनझुना दिखा रहे हैं और आप ही कहते हैं कि सारा बजट बिहार को चला गया है । मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई दूँगा कि इतने वर्षों के बाद, बिहार में चाहे बाढ़ की बात हो, बाढ़ के नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपये अलग से दिये गये हैं । सड़कों का जाल बिछाने के लिए अलग से पैसा दिया गया है । वहाँ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अलग से पैसा दिया गया है । मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अलग से पैसे का प्रावधान किया गया है । युवाओं के रोजगार के लिए भी बिहार में काम करने के लिए धन का प्रावधान किया गया है । हमारे सामरिक स्थलों को विकसित करने के प्रति भी इस बजट में जितना प्रावधान किया गया है और इस देश की सरकार ने इस दिशा में जितना काम किया है, बिहार का एक सांसद होने के नाते, बिहार की जनता की भावना के माध्यम से, बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री को मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि आपने बजट में यह प्रावधान करने का काम किया है ।

महोदया, मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातों को रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के बारे में कुछ मांगना और कहना चाहता हूं । महाराजगंज में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए । नई दिल्ली से गोरखपुर, सिवान, एकमा, छपरा होते हुए पटना तक की एक जोड़ी वंदे भारत ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए । एक मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था की जाए । लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा से जलालपुर, बनियापुर, भगवानपुर, डुमरिया घाट होते हुए महात्मा गाँधी की कर्मस्थली चम्पारण के मोतिहारी तक एक नई रेल लाइन बिछाने हेतु व्यवस्था की जाए । मांझी से अयोध्या तक घाघरा/सरयू नदी में पूर्व से घोषित राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 40 में जलीय परिवहन का सुचारू संचालन किया जाए । मेगा फूड पार्क महाराजगंज में स्थापित कराने की व्यवस्था की जाए । सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करवाने

की व्यवस्था की जाए । महाराजगंज से दरौंदा, चैनवा, महेन्द्रनाथ हाल्ट, एकमा, दाउदपुर, छपरा होते हुये पाटलिपुत्रा जंक्शन तक कार्यालय समय अनुसार एक जोड़ी रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की जाए ताकि हजारों हजार लोगों को सुविधा मिल सके ।

माननीय सभापति: धन्यवाद । अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के सारण जिला अंतर्गत माझी प्रखंड के मांझी गढ एवं बनियापुर प्रखंड अंतर्गत हरपुर कराह गढ़ को धरोहर घोषित करते हुए पर्यटकीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित करने का काम किया जाए । ?नमामि गंगे? की विकास योजना के अंतर्गत पानापुर प्रखंड के मथुरा धाम, तरैयाँ प्रखंड के गंडक नदी के नारायणी तट के जिम्दाहा में घाट का निर्माण कराया जाये ।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: महोदया, नमामि गंगे की विकास योजना के अंतर्गत मांझी घाट पर डूमाईगढ़ में शवदाह गृह व घाटों का निर्माण करवाया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र के छपरा जिला के बनियापुर, एकमा व सिवान जिला के भगवानपुर, मदारपुर, महाराजगंज में नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत 50 बेड का आयुष अस्पताल का निर्माण करवाया जाए । मांझी-बरौली पथ व पैगम्बर से महाराजगंज होते हुए सिवान को जाने वाली पथ को नेशनल हाइवे का दर्जा दिया जाये । नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र में खेलो इंडिया के अंतर्गत स्टेडियम व आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करवाई जाए । दाउदपुर के दुमदुमा ढाला एवं एकमा के मांझी-बरौली पथ पर अवस्थित ढाला पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए । महाराजगंज-मशरक रेलवे खंड पर अवस्थित पटेढी में पूर्व मुख्य मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी महामाया बाबू के नाम पर हाल्ट स्टेशन का निर्माण करवाया जाए ।

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इस बजट 2024-25 पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया ।

यह बजट आम जनता को निराश करने वाला बजट है । इस बजट में किसानों, महिलाओं, गरीबों की उपेक्षा की गई है । जिस प्रकार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसमें महिलाओं के लिए काफी परेशानी का विषय है । गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने की वजह से कई घरों मे देश में गरीब महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई घरों में ऐसा है कि महंगाई की वजह से गैस नहीं भरवा पा रहे है ।

इसी प्रकार किसानों को इस बजट मे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए बहुत आस थी, परंतु इस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कोई जिक्र नहीं किया गया है एवं जिस प्रकार आज किसानों के ऊपर इतना कर्ज का भार है, आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है । परंतु सरकार का इस विषय पर कोई ध्यान नहीं जाता है । इस बजट में किसानों के ऋण माफी का कोई जिक्र नहीं किया गया है । जिस प्रकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे आम जनमानस त्रस्त है । अगर युवाओं की बात करें, तो इस बजट में देश में बढ़ती बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं किया गया है । पूर्व मे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, परंतु इस बजट में युवाओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है ।

इसलिए इस 2024-25 के बजट में जिस प्रकार महिलाओं, किसानों, युवाओं, गरीबों, मजदूरों एवं आम जनमानस की उपेक्षा की गई है, उस प्रकार इस बजट को जनविरोधी बजट माना जा सकता ।

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य): मैं वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट की उन असफलताओं पर अपने विचार रखना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है । यह बजट, जिसकी उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विफल रहा है । मुझे उम्मीद थी कि जो सबक आपको जनता ने चुनाव में दिया था, उससे आप कुछ सीख लेंगे । लेकिन सरकार ने फिर वही गलती दोहराने का काम किया है ।

महंगाई आम जनता के जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है । इस बजट में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई । आंकडे बताते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें 10% से 15% तक बढ़ी हैं । खाद्य पदार्थों, विशेषकर दालों, सब्जियों और खाने के तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है । इसके बावजूद, बजट में महंगाई पर लगाम लगाने के लिए किसी भी विशेष उपाय का अभाव है ।

डब्ल्यूपीआई महंगाई दर 3.4 प्रतिशत है, सीपीआई महंगाई दर 5.1 प्रतिशत है और खाद्य महंगाई दर 9.4 प्रतिशत है । हम सरकार के इस रवैये की निंदा करते हैं । बजट भाषण में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो हमें विश्वास दिलाए कि सरकार महंगाई के मुद्दे को गंभीरता से हल करेगी ।

बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है । कुछ दर्जन रिक्तियों या कुछ हजार पदों के लिए लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं और परीक्षा लिखते हैं या साक्षात्कार में शामिल होते हैं । सीएमआईई के अनुसार, पूरे भारत की बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत है ।

सरकार की प्रतिक्रिया बहुत कम है और गंभीर बेरोजगारी स्थिति पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ेगा । वित्त मंत्री द्वारा घोषित योजनाओं से 290 लाख लोगों को लाभ होगा, यह दावा अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है । उन्होंने 3 संख्याएं दी हैं- 210 लाख, 30 लाख और 50 लाख । प्रत्येक संख्या अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई है ।

युवा वर्ग की समस्याओं में रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । देश की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, लेकिन उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं । आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में बेरोजगारी दर 8% थी, जो इस बजट के बाद भी समान स्तर पर बनी हुई है । सरकार ने कौशल विकास के लिए कुछ योजनाएं प्रस्तावित की हैं, लेकिन ये योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई हैं, जिसके परिणामस्वरूप युवाओं को रोजगार मिलने में कठिनाई हो रही है ।

शिक्षा के संबंध में बहुत बड़ा मुद्दा एनईईटी और घोटाले-प्रभावित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का है । कई राज्यों ने मांग की है कि एनईईटी को समाप्त किया जाना चाहिए और राज्यों को चिकित्सा शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के अपने तरीकों को अपनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए । इस बारे में बजट में कोई प्रतिक्रिया नहीं है । मैंने वित्त मंत्री को स्कूल शिक्षा का उल्लेख करते हुए नहीं सुना । फिर भी, सरकार जिद्दी रूप से एनईईटी को बनाए हुए है, जिसे आप याद रखेंगे कि एनईईटी स्कूल शिक्षा के अंत में एक परीक्षा है । दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा पर 1,16,417 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के खिलाफ सरकार ने केवल 1,08,878 करोड़ रुपये खर्च किए ।

स्वास्थ्य देखभाल बेहतर है, लेकिन पर्याप्त नहीं है । सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की मात्रा में वृद्धि हो रही है, लेकिन गुणवत्ता में नहीं हो रही है । कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग 47 प्रतिशत अभी भी जेब से खर्च होता है । डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा तकनीशियनों और डायग्नॉस्टिक उपकरणों और मशीनों की भारी कमी है । केंद्र सरकार

का स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय पिछले वर्ष तक जीडीपी के अनुपात के रूप में 0.28 प्रतिशत और कुल व्यय के अनुपात के रूप में 1.9 प्रतिशत तक घट गया है ।

मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद पिछले 6 वर्षों में मजदूरी स्थिर रही है । वर्ष 2017-18 और वर्ष 2022-23 के बीच श्रमिकों की औसत मासिक आय थी - स्वरोजगार/श्रमिक 12,800 रुपये प्रति माह, आकस्मिक दैनिक मजदूर 7,400 रुपये प्रति माह और नियमित मजदूरी/श्रम 19,750 रुपये प्रति माह । हम मांग करते हैं कि न्यूनतम मजदूरी हर प्रकार के रोजगार के लिए 400 रुपये प्रति दिन तय की जाए ।

0-20 प्रतिशत कर स्लैब में कर देने वाले नागरिकों को कुछ राहत दी गई है, लेकिन गरीब तबकों, विशेष रूप से गैर-कर देने वाले वेतनभोगी श्रमिकों और आकस्मिक दैनिक श्रमिकों को कोई राहत नहीं दी गई है ।

हमारे देश की जीडीपी का लगभग 17% योगदान कृषि क्षेत्र से आता है, लेकिन इस बजट में किसानों के कल्याण के लिए अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है । किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण में मामूली वृद्धि के अलावा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है । साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है । कृषि क्षेत्र में आई इस उपेक्षा के चलते किसान आत्महत्या की घटनाओं में 5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि चिंताजनक है ।

सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित बजट में मात्र 5% की वृद्धि की गई है, जो कि उनकी वास्तविक जरूरतों के मुकाबले बहुत कम है । महिलाओं और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है, जिससे समाज में विषमता और बढ़ सकती है ।

बुनियादी ढांचे के विकास में सुस्ती देखने को मिल रही है । सरकार ने 'मेक इन इंडिया और 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन इस बजट में इन क्षेत्रों के लिए वितीय आवंटन में कोई विशेष वृद्धि नहीं की गई । सड़क, रेल और बंदरगाहों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि की कमी के चलते इन परियोजनाओं में देरी हो रही है, जो आर्थिक प्रगति में बाधक बन रही है । यह बजट पिछले वादों को पूरा करने में भी विफल रहा है । वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में किए गए वादों में से कई अभी तक अधूरे हैं । जैसे कि ?हर घर जल? योजना के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है । इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

बजट के आंकड़ों में वित्तीय अनुशासन की कमी भी देखने को मिली है । वितीय घाटा इस वर्ष जीडीपी का 6.4% रहा है, जो कि सरकार के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है । इससे साफ जाहिर होता है कि बजट में खर्च और आय के बीच संतुलन बनाने में असफलता रही है, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए हानिकारक है ।

अंत में, मैं बताना चाहूंगी कि केंद्रीय बजट 2024 में सरकार ने जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, वे सराहनीय हैं, लेकिन इनमें से कई क्षेत्रों में विफलताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं । बजट को देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने वाला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । हमें आशा है कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और अगले बजट में इन असफलताओं को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी ।

धन्यवाद ।

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): Respected Madam Chairperson, I thank you and the Leader of our Party for giving me this opportunity to speak in this discussion on the Budget which is little more than empty rhetoric.

As usual, the Government has adhered to its characteristic approach of crafting headline-grabbing schemes with arbitrary targets, rather than offering substantive and programmatic solutions. The Government has again failed to address the pressing issues facing the middle-class. The Budget speech overlooked key concerns, affecting the common man.

Madam, the Government has talked much about the unemployment rate in our country. The Government has reported that the unemployment rate in urban areas is only 6.7 per cent. But the Centre for Monitoring the Indian Economy (CMIE) has reported unemployment rate of 9.2 per cent in June 2024. In urban areas, in the month of May, it was 6.3 per cent which is as per the Government?s report. But in the month of June, it increased to 9.3 per cent. So, the unemployment problem is increasing, which we have to rationally tackle in our country.

Madam, now I come to the MGNREGS. This year?s allocation for MGNREGS is just 1.78 per cent of the total budgetary allocation, marking a 10-year low in the scheme funding. ? (*Interruptions*)

Madam, despite the recent farmers? movements in recent years, even this year, the allocation for agriculture and allied sectors has been reduced to just 3.15 per cent of the total Budget.

Madam, the Government has talked much about road connectivity. As one of the hon. Members has mentioned, the Government is talking about the Act East Policy. But for the North-East, there is no mention about the road connectivity in this Budget.

Coming to irrigation and flood mitigation, yes, the flood mitigation is there. But if we talk about the North-East and many of the other States, the natural calamities occur but our States are never included in the Budget. Our Government always says that the North-East has rich cultural heritage, and has a scope for tourism. But there is no mention about our State in the Budget.

Madam, I would like to remind this Government, especially the hon. Finance Minister that in the year 2015, in this August House, late Shri Arun Jaitley had

announced that in Nagaland, the Indian Institute of Science Education and Research would be established, but till now, it has not been established.

Madam, Nagaland is the only State in which its Capital is not connected with its airport. Therefore, I would like to request the Government to keep these two projects on priority.

We have done two agreements. One was nine years back and the other was seven years back. But for the last nine years, it has not found a place in the Budget. There have been agreements between the Government of India and the Naga political leaders during 2015 and 2017 for political solution and rehabilitation. But it has no mention in the Budget. We have been waiting for it since nine years.

15.00 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

On 31st October, 2019 the Naga Peace Talks between the Government of India and the Naga groups was successfully concluded. On 17th January, 2020 the Governor, who was the interlocutor of this settlement, announced on the floor of the House that the Naga political crisis was resolved. He also congratulated the Prime Minister as well as the Home Minister. But implementation of that agreement is still awaited. The Government of India has imposed the Armed Forces Special Powers Act in Nagaland. The ceasefire monitoring is not going well. Killing of people is still going on even in daylight. The anti-social elements are collecting taxes. We have 24 factions. Apart from that, anti-social elements are there.

Sir, through you, I would like to request the Home Minister that we want immediate implementation of the Naga Peace Talk agreement, and we want the Government to take up these two projects on priority.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity. In engineering, a ?vector? means, something that has a direction and strength. That is what our Indian Budget is, with a direction and strength, and the trajectory is *viksit Bharat* by 2047.

Sir, where there is free will and democracy, if something good is happening, people want a repetition. We saw in these elections, once again, for the third time Modi government is there. Same thing goes with the Budget. We had repeated good Budgets in the last five years and even before that, and the country is in the direction from 10th to 5th. Again, the same thing is repeated. This is also reflected in

the economy and the stock markets. Never before such continuity of progress in the economy was there despite the period during COVID-19.

Sir, I realized that I do not have much time and, therefore, I would just cover two or three important points, especially regarding what the Opposition has been accusing us of. The Opposition has been accusing us that ?*aap do hi States ka naam bole?,* and we did not mention anything about other States. I would like to say that I have read all the Budgets from 1947 till now. The first Budget was presented by Shanmukham Chetty. Then, John Mathai presented his Budget. Pt. Jawaharlal Nehru was also the Finance Minister. Indira Gandhi, Rajiv Gandhi and Morarji Desai had also been the Finance Ministers of our country. None of these eminent leaders had ever mentioned any State till 1970. This is a national Budget. It is not a roll call of States. For the first time, the name of a State was mentioned was by Smt. Indra Gandhi in 1970. It is about the nation and not about the individual State because if the nation gets something, each and every State also gets it.

Sir, the second accusation is that there is nothing in the Budget ? nothing for healthcare, nothing for children and nothing for kisan. The Budget is exactly for these. But आरोप यह है कि our Finance Minister did not use the word ?children? in the Budget. One of our former great Prime Ministers was endeared to children. They even called him ?Chacha?. In Chacha ji?s speech also as a Finance Minister, the word ?children? was not there. Does it mean that if the name of a State or the word ?children? is not there, the Budget is not for them? It is not so. They say that there is nothing in the Budget. There is something for everyone. There is a lot for everyone.

Sir, the third accusation ? this is really hilarious ? is that ?they are copying us?. Is it not good if we copy their ideas? A Budget takes ideas from everybody. Are they saying that their ideas are bad? This is a classic example of a confused Congress, both in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. ? (*Interruptions*) Is it good or bad that people are getting something? In this Budget, everyone in the middle class is getting almost Rs. 17,500 of additional benefit in income tax. The proof lies in the results and not in the accusations of the Opposition parties.

Sir, there is one more very important issue for us. I am from Telangana. We have eight MPs. Our friends from the Congress have put up posters there, saying that we have eight MPs but Telangana has got nothing. Once again, it shows that the Congress is confused. Should everything go to Rajasthan or Madhya Pradesh from where we have a lot of MPs. Again, a confused Congress is there. The number of

MPs has nothing to do with what comes by way of Budget. They are totally confused. So, they are going around with *andaa*.

Just briefly, Sir, I want to thank the Central Government and the Finance Ministry for the largesse that she has bestowed upon Telangana. As we are speaking, Rs. 31,000 crore worth of railway works of doubling, electrification and station redevelopment are proposed. Charlapalli station is going to be redeveloped. We are now getting Rs. 700 crore for Secunderabad railway station. All these years, what Congress gave is Rs. 5 crore for white-wash. It is not for white-wash; literally, it is an eye-wash. पांच करोड़ रुपये दिए, सात करोड़ रुपये दिए गए । वह वाइटवॉशा नहीं होता, वह कांग्रेस का आईवॉश है । There are works going on worth Rs. 1,00,000 crore for national highways. We have given them a wagon factory, but they have not given ten acres of land. The wagon factory has to be connected with the tracks. They have not given that land in-between as the Congress Government in Telangana thinks that wagons can jump as they have got wings.

Sir, there are so many issues. For Centrally-sponsored schemes, no matching grants are given by them. We are doing MMTS where the share of the Centre and the State is 50:50. I should thank Ashwini Vaishnaw ji that despite the State not giving anything, they are doing it. We have been given an AIIMS under bifurcation, a tribal university and a horticulture university. The NTPC has given 4,000 MW, but they are unable to utilise it. Under MGNREGS, the wages used to be Rs. 150 and now it is Rs. 300. They are mentioning about ?किसान की आय दोगुनी? । Ten years back, in Telangana villages, गांव में चार मोटर साइकिलें होती थीं । अब हर गांव में चार सौ मोटर साइकलें हैं । It is because MSP has doubled from Rs. 1,300 to Rs. 2,300 and productivity yields have increased. The Government is giving almost 90 per cent fertiliser subsidy. We are procuring paddy worth almost Rs. 22,000 crore. Today, Telangana is surviving because of the support of the Central Government. Their own Finance Minister has told that they have got Rs. 35,000 crore from the Centre, but they are angry that Rs. 15,000 crore went to Andhra Pradesh. Today, Telangana is surviving with the support of the Central Government, whether it is electricity, water or diesel in RTCs. The Central Government approved Rs. 9,000 crore beyond the FRBM in the month of January. Then, it approved Rs. 3,000 crore in February. Again, it approved Rs. 4,000 crore in March. The revenue of the State of Telangana in 2023 was Rs. 1,35,000 crore ? Rs. 55,000 crore for salaries and Rs. 80,000 crore for loans. There is nothing in their pockets except when the largesse comes from ? (*Interruptions*) Of course, it is not your fault. It is the fault of the previous Government, but you tell the truth. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Reddy *saheb*, you address the Chair. Do not look at that side.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Sorry, Sir.

Today, Telangana Government is surviving because of the Central Government?s support. I thank everyone who put up posters there.

As a citizen of India, I thank the Finance Minister, but more importantly, as an MP representing Telangana, I thank the Finance Ministry for the largesse shown to us. Thank you.

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 का आम बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले सभी बजट की तरह ही आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप है । यह बजट ऐसा है जिसमें विपक्ष को तीखी आलोचनाओं के लिए ठोस आधार प्राप्त नहीं हो सका है जो इस बजट के जनप्रिय होने का प्रमाण है । इस बजट का आरंभ युवा और रोजगार सृजन से हुआ है ।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके संदर्भ में अंतरिम बजट में काफी प्रावधान किए गए थे । यह बजट उसी का विस्तारित रूप है । बजट को समग्रता में देखे जाने की आवश्यकता है । यह एक साथ व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन के साथ कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने, स्वरोजगार सृजन पर बल देने, भारत की विरासत तीर्थ और पर्यटन स्थलों को विकसित करने तथा सबके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विस्तार पर फोकस करने वाला बजट है । यानी यह नरेंद्र मोदी सरकार की पूर्व नीतियों को आगे बढ़ा रहा है । भारत के वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से इसे एक शानदार बजट कहा जा सकता है ।

यह बजट फिर एक बार बता रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का भारत को लेकर सपना क्या हैं। उन्होंने पहले भी अपने भाषणों तथा पिछले सारे बजट में वैसे भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है जो वर्तमान अर्थव्यवस्था के मानदंड में विश्व के शीर्ष देशों की कतार में हो, जहां लोगों को जीविकोपार्जन के साधन हों, स्किल से भरे युवाओं तथा समाज का हर वर्ग युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग, कारोबारी सबके बीच संतुलन भी हो । किंतु इन सबके साथ भारत अपने अध्यात्म , सभ्यता, संस्कृति और विरासत की मूल पहचान के साथ विकसित भारत बने । इस बजट में इन सपनों का समग्रता से समावेश है लेकिन इसका मुख्य यूएसपी रोजगार है । आप देखेंगे कि 10 वर्षों के अनुभवों के आधार पर उन सारे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां-जहां सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है ।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर हैं । बजट में प्रधानमंत्री जी द्वारा सशक्तिकरण हेतु बनायी की चार जतियों गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है । विकसित भारत के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर नौ क्षेत्रों पर फोकस का अर्थ व्यवहारिक नीतियों का आधार तय हो जाना है । ये हैं, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार । रोजगार की दृष्टि से देखें तो 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए जिन पांच योजनाओं और पहलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा है वो व्यावहारिक हैं । शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48

लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है । अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख को अपस्किल या रि-स्किल किया गया है । पीएम मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना ऋण दिए गए । 3000 नए आईटीआई, सात आईआईटी, 16 आईआईआईटी, सात आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है । वस्तुतः नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर पदों की संख्या बढ़कर 1.09 करोड़ हो गई है, लेकिन नौकरी के लिए पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 87.2 लाख ही है । नौकरी की संख्या बढ़ने के बावजूद काफी युवा वंचित हैं तो इसका कारण स्किल के मापदंड पर खरा नहीं उतरना है । अब तक हम स्किल के मापदंडओं पर काफी पीछे हैं । इस दृष्टि से बजट में युवाओं की इंटर्नशिप की एक ऐसी विशिष्ट योजना है जिसकी ओर पहले ध्यान नहीं गया था । एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में शीर्ष-500 कंपनियों में 12 महीने के लिए इंटर्नशिप की योजना इस बजट का प्रमुख आकर्षण है । सीधे काम करते हुए स्किल विकास की ऐसी योजना पहले नहीं आई थी । इसमें इंटर्नशिप करने आए युवाओं तथा कंपनियों पर भी बहुत ज्यादा भार नहीं दिया गया है । युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता तथा एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे । कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 प्रतिशत लागत वहन करना होगा । कॉरपोरेट अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हर वर्ष एक निश्चित राशि खर्च करते हैं । उन्हें उसी में से प्रदान करना है । इस तरह यह पूरी तरह व्यावहारिक है । कल्पना करिए अगर यह सफल रहा तो आने वाले समय में भारत कैसे स्किल वाले युवाओं का देश बन जाएगा । प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा भी विशिष्ट है । इसके तहत सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा ।

एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), 15,000 रुपये तक तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा जिसकी पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी । इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद की गई है । इस तरह की योजना भी पहले नहीं आई थी । आर्थिक सर्वेक्षण में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 11.9% रोजगार का चिंताजनक आंकड़ा दिया गया है । स्वाभाविक ही कुछ नए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा । यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपए तक के ईपीएफओ योगदान करेगी । इससे 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है । इस तरह की कई घोषणाएं बताती है कि कितनी गहराई से विचार किया गया है । रोजगार अपने आप में अर्थव्यवस्था में टापू नहीं हो सकता । संपूर्ण विकास और उसमें स्थिरता सतत स्थाई रोजगार पैदा होने का आधार होता है । स्थायी रोजगार स्वयं में पैदा होता रहता है । आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि रोजगार सृजन में कृषि का हिस्सा अभी भी 45% है । यानी कृषि को ठीक से संभाला जाए तो यह विकास के साथ-साथ बेहतर रोजगार का साधन उपलब्ध कराने का दीर्घकालिक क्षेत्र साबित होगा । कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ दिया गया है जो पिछले साल 1 लाख 25 हजार करोड़ से 21.6% ज्यादा है । 400 जिलों में फसलों का सर्वे से वहां किसानों के लिए कौन सा फसल उपयुक्त और लाभदायक होगा उसके प्रचार और प्रोत्साहन पर काम होगा । 32 फसलों की 109 नई किस्में आएंगी । किसानों की आय बढ़ाने की बात लगातार की जाती है लेकिन वह संतोषजनक स्तर पर पहुंचेगी कैसे ? खेती की लागत घटे, किसानों की फसलों का उपयुक्त मूल्य मिले यह आवश्यक है । किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों का विविधिरण, खेती के तरीके बदलना, फलों और सब्जियां के पैदावार में वृद्धि, उनके भंडारणऔर विपणन की सुनिश्चित व्यवस्था व्यापक स्तर पर अभी तक नहीं हो पाई है । बजट में इन सब पर समान बल देना बताता है कि नीतियां सही दिशा में हैं । दाल और दलहन के मामले में आत्मनिर्भरता और इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन पर फोकस है । खाद्य तेल वाली फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने,

सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए कलस्टर बनाने, भंडारण और विपणन के ढांचों का विकास और प्रसार, एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने, कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना के साथ राज्यों ने सहयोग किया तो कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है । 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाने की बात है । सरकार ने रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया है । रेलवे को मजबूत बनाने और नई सुविधाएं लाने के लिए सरकार ने 2,62,200 करोड़ रुपये कैपेक्स के तौर पर दिए हैं । ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 2,52,200 करोड़ रुपये है । सरकार का लक्ष्य है कि अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएं । बजट का बड़ा हिस्सा सेफ्टी के लिए जाएगा । 1,08,000 करोड़ से पुराने ट्रैक्स, सिग्नलिंग, कवच, रेल के पुल बनाने में लगेंगे । इसके साथ ही वंदे मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी । वंदे मेट्रो कम दूरी के सफर के लिए होगी, जबकि वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी और रात की यात्रा के लिए होगी । इस बजट में स्वदेशी तकनीक से बने 'कवच' सिस्टम पर भी जोर दिया गया है, जो ट्रेनों की सुरक्षा को और मजबूत करेगा ।

बिहार में गया, बोधगया राजगीर और नालंदा का विकास के प्रति केंद्र अपने दायित्व को समझते हुये बजट आवंटित किया है । गया संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के लिए पितरों का सर्वप्रमुख श्रद्धा स्थल है । विष्णुपाद मंदिर उसका केंद्र है और उसकी दशा वाराणसी और अयोध्या के तर्ज पर बदल जाए तो यह बड़ी बात होगी । इन क्षेत्रों के विकास से न केवल भारत का स्वरूप निखरेगा, बल्कि तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी । इस तरह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत ने स्वयं को अपनी पहचान के साथ विकसित देश के रूप में खड़ा करने की दिशा में गति बना दी है जो इस बजट में पूरी तरह से झलकता है ।

बजट के सारे प्रस्तावों पर यहां विचार करना संभव नहीं है । मूल बात है कि विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकर लोक-लुभावन घोषणाओं से बचते हुए देश के समग्र विकास के लिए दूरगामी सोच और योजनाओं पर आगे बढ़ रही है इसलिए मैं बजट का समर्थन करता हूँ ।

मैं एक शायर के इस पंक्ति के साथ अपनी बात पूरी करता हूँ ।

चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी,

यहीं इल्जाम हम पर लगा है बेवफाई का,

चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से,

वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का ।

जय हिन्द ।

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) : ग्लोबल लीडर, गरीब, किसान, महिला, युवा के सशक्तिकरण को दृढ़ प्रतिज्ञ, विकसित भारत की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए दृढ़ता के साथ प्रयासरत, अंत्योदय को समर्पित भारतवर्ष के प्रधानसेवक श्री नरेंद्र मोदी जी का इस बजट के माध्यम से विकसित भारत बनाने की गति तेज करने के लिए एक नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ एवं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ ।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 का आम बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले सभी बजट की तरह ही आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप है । महोदय, यह बजट ऐसा है, जिसमें विपक्ष को भी आलोचनाओं के लिए ठोस आधार प्राप्त नहीं हो सका है जो इस बजट के जनप्रिय

होने का प्रमाण है । इस बजट से गाव, गरीब, युवा, किसान, जल, जंगल, जमीन सबके संरक्षण और सशक्तिकरण को तेज गति मिलने वाली है ।

इस बजट का आरंभ युवाओं और रोजगार सृजन से हुआ है । मोदी सरकार रोजगार संकट को दूर करने की तरफ गंभीर दिखती है, जिसका प्रमाण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बजट भाषण में मिलता है । वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं में रोजगार सृजन पर खासा ध्यान देते हुए कई तरह की योजनाओं का प्रस्ताव रखा । उन्होंने युवाओं को रोजगार के लायक बनाने से लेकर उनके सामने रोजगार के अवसर मुहैया कराने तक, हर तरह की योजनाओं का ऐलान किया ।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के सकल्प पत्र में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके संदर्भ में अंतरिम बजट में काफी प्रावधान किए गए थे । यह बजट उसी का विस्तारित रूप है । बजट को समग्रता में देखे जाने की आवश्यकता है ।

यह एक साथ व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन के साथ कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने, स्वरोजगार सृजन पर बल देने, भारत की विरासत तीर्थ और पर्यटन स्थलों को विकसित करने तथा सबके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विस्तार पर फोकस करने वाला बजट है । यानी यह माननीय नरेंद्र मोदी सरकार की पूर्व नीतियों को आगे बढ़ा रहा है । भारत के वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से इसे एक शानदार बजट कहा जा सकता है ।

यह बजट फिर एक बार बता रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार का भारत को लेकर सपना क्या हैं । उन्होंने पहले भी अपने भाषणों तथा पिछले सारे बजट में वैसे भारत की रूपरेखा प्रस्तुत की है जो वर्तमान अर्थव्यवस्था के मानदंड में विश्व के शीर्ष देशों की कतार में हो, जहां लोगों को जीविकोपार्जन के साधन हों, स्किल से भरे युवाओं तथा समाज का हर वर्ग युवा, महिला, किसान, बुजुर्ग, कारोबारी सबके बीच संतुलन भी हो । किंतु इन सबके साथ भारत अपने अध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति और विरासत की मूल पहचान के साथ विकसित भारत बने । इस बजट में इन सपनों का समग्रता से समावेश है लेकिन इसका मुख्य यूएसपी रोजगार है । आप देखेंगे कि 10 वर्षों के अनुभवों के आधार पर उन सारे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जहां-जहां सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है । माननीय वित मंत्री ने कहा है कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर हैं । बजट में प्रधान मंत्री जी द्वारा सशक्तिकरण हेतु बनायी गई चार जतियों गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है ।

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर नौ क्षेत्रों पर फोकस का अर्थ व्यवहारिक नीतियों का आधार तय हो जाना है । ये हैं कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार । रोजगार की दृष्टि से देखें तो 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए जिन पांच योजनाओं और पहलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा है वह व्यावहारिक हैं । शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है । अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख को अपस्किल या रि-स्किल किया गया है । पीएम मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना ऋण दिए गए । 3000 नए आईटीआई, सात आईआईटी, 16 आईआईआईटी, सात आईआईएम, एम्स और 390 विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है । वस्तुतः नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर पदों की संख्या बढ़कर 1.09 करोड़ हो गई है, लेकिन नौकरी के लिए पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 87.2 लाख ही है । नौकरी की संख्या बढ़ने के

बावजूद काफी युवा वंचित हैं तो इसका कारण स्किल के मापदंड पर खरा नहीं उतरना है । अब तक हम स्किल के मापदंडों पर काफी पीछे हैं । इस दृष्टि से बजट में युवाओं की इंटर्नशिप की एक ऐसी विशिष्ट योजना है जिसकी ओर पहले ध्यान नहीं गया था । एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में शीर्ष-500 कंपनियों में 12 महीने के लिए इंटर्नशिप की योजना इस बजट का प्रमुख आकर्षण है । सीधे काम करते हुए स्किल विकास की ऐसी योजना पहले नहीं आई थी । इसमें इंटर्नशिप करने आए युवाओं तथा कंपनियों पर भी बहुत ज्यादा भार नहीं दिया गया है । युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता तथा एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे । कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 प्रतिशत लागत वहन करना होगा । कॉरपोरेट अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हर वर्ष एक निश्चित राशि खर्च करते हैं । उन्हें उसी में से प्रदान करना है । इस तरह यह पूरी तरह व्यावहारिक है । कल्पना करिए अगर यह सफल रहा तो आने वाले समय में भारत कैसे स्किल वाले युवाओं का देश बन जाएगा । प्रधानमंत्री जी के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा भी विशिष्ट है । इसके तहत सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा । एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), 15,000 रुपये तक तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा जिसकी पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी । इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद की गई है । इस तरह की योजना भी पहले नहीं आई थी । आर्थिक सर्वेक्षण में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 11.9 प्रतिशत रोजगार का चिंताजनक आंकड़ा दिया गया है ।

स्वाभाविक ही कुछ नए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा । यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपए तक के ईपीएफओ योगदान करेगी । इससे 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है । इस तरह की कई घोषणाएं बताती हैं कि कितनी गहराई से विचार किया गया है ।

रोजगार अपने आप में अर्थव्यवस्था में टापू नहीं हो सकता । संपूर्ण विकास और उसमें स्थिरता सतत स्थाई रोजगार पैदा होने का आधार होता है । स्थायी रोजगार स्वयं में पैदा होता रहता है । आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि रोजगार सृजन में कृषि का हिस्सा अभी भी 45 प्रतिशत है । यानी कृषि को ठीक से संभाला जाए तो यह विकास के साथ-साथ बेहतर रोजगार का साधन उपलब्ध कराने का दीर्घकालिक क्षेत्र साबित होगा । कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ दिया गया है जो पिछले साल 1 लाख 25 हजार करोड़ से 21.6 प्रतिशत ज्यादा है । 400 जिलों में फसलों का सर्वे से वहां किसानों के लिए कौन सा फसल उपयुक्त और लाभदायक होगा उसके प्रचार और प्रोत्साहन पर काम होगा । 32 फसलों की 109 नई किस्में आएंगी ।

किसानों की आय बढ़ाने की बात लगातार की जाती है लेकिन वह संतोषजनक स्तर पर पहुंचेगी कैसे? खेती की लागत घटे, किसानों की फसलों का उपयुक्त मूल्य मिले यह आवश्यक है । किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों का विविधिरण, खेती के तरीके बदलना, फलों और सब्जियां के पैदावार में वृद्धि, उनके भंडारण और विपणन की सुनिश्चित व्यवस्था व्यापक स्तर पर अभी तक नहीं हो पाई है । बजट में इन सब पर समान बल देना बताता है कि नीतियां सही दिशा में हैं । दाल और दलहन के मामले में आत्मनिर्भरता और इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन पर फोकस है । खाद्य तेल वाली फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने, सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति शृंखला के लिए कलस्टर बनाने, भंडारण और विपणन के ढाचों का विकास और प्रसार, एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने, कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना के साथ राज्यों ने सहयोग किया तो कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है । 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाने की बात है ।

सरकार ने रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया है । रेलवे को मजबूत बनाने और नई सुविधाएं लाने के लिए सरकार ने 2,62,200 करोड़ रुपये कैपेक्स के तौर पर दिए हैं । ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 2,52,200 करोड़ रुपये है । सरकार का लक्ष्य है कि अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाए । बजट का बड़ा हिस्सा सेफ्टी के लिए जाएगा । 1,08,000 करोड़ से पुराने ट्रैक्स, सिग्नलिंग, कवच, रेल के पुल बनाने में लगेंगे । इसके साथ ही वंदे मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी । वंदे मेट्रो कम दूरी के सफर के लिए होगी, जबकि वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी और रात की यात्रा के लिए होगी । इस बजट में स्वदेशी तकनीक से बने 'कवच' सिस्टम पर भी जोर दिया गया है, जो ट्रेनों की सुरक्षा को और मजबूत करेगा । मेरे संसदीय क्षेत्र में आनंद जंक्शन को अमृत स्टेशन बनाने के लिए एवं गुजरात में रेलवे के विकास के लिए वर्ष 2009 से 2014 की तुलना में बजट आवंटन को 15 गुणा ज्यादा करने अर्थात 8,743 करोड़ रुपए आवंटन के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार है ।

बजट के सारे प्रस्तावों पर यहां विचार करना संभव नहीं है । मूल बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकर लोक लुभावन घोषणाओं से बचते हुऐ देश के समग्र विकास के लिए दूरगामी सोच और योजनाओं पर आगे बढ़ रही है । मोदी जी के मिशन में एकमात्र लक्ष्य विकसित भारत बनाना है । एक ऐसा विकसित भारत जिसमें किसान, गरीब, महिला एवं युवा सशक्त और सक्षम रहें, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में यह बजट तेज गति प्रदान करने वाला है । इस बजट का पूरी गंभीरता और उत्साह के साथ मैं समर्थन करता हूँ ।

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी): ईपीएस ? 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में विगत एक दशक से ज्यादा समय से देश भर में आमरण अनशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर-बसर करना कठिन हो रहा है ।

कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को लागू हुई । यह योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिन पर 1952 विविध प्रावधान अधिनियम और कर्मचार भविष्य निधि लागू होते हैं । ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, कर्मचारी पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लाभ पहुंचाना है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि ईपीएस-95 की कमियों को दूर करते हुए कर्मचारियों के हित में सकारात्मक कार्यवाही करे ताकि उन्हें इसका पूरा लाभ मिल सके ।

आज देश में केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं । लेकिन मुझे बड़ ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन योजनाओं का समुचित लाभ दबे-कुचले वर्ग को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है । इसका एक मुख्य कारण यह है कि केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं की नियमावली की पूरी जानकारी निचले स्तर पर न पहुंचने की वजह से लाभार्थी इन योजनाओं से अनभिज्ञ रहता है ।

आज स्थिति यह है कि गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि बनवाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । ये लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटकर न केवल अपनी रोजी-रोटी कमाने का समय बर्बाद करते हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उनको सही जानकारी न देकर गुमराह करते हैं जिसके परिणामस्वरूप ये लोग आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकारी योजनाओं के संचालन और इनका पूरा लाभ दलित व गरीब परिवार के सभी पात्र लोगों को मिल सके, इसके लिए एक ऐसी नियमावली बनाए, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के

चक्कर न काटने पड़ें और सरकार इनके संचालन की पूरी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के प्रति सुनिश्चित करे I

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): I wish to throw same light on the grand spectacle put on by the current Government of India in Budget 2024-25. A masterclass in creating illusions and playing with the aspirations of millions and completely forgetting about the poor, youths, unempioye farmers, and particularly the minority communities of diverse India. Let's face it - it's just an eyewash, a hollow and without substance budget, failing to allocate enough funds where it's most needed. Middle-class dreams are relegated to the realm of fantasy, while the government creates a mirage of reforms like a new tax regime or a 'copied' internship scheme.

Take, for instance, the Pirpainti power plant was first announced in 2014. Again, after ten years, the government is announcing it as if it's a new achievement. The government's trumpet of the 'Purvodaya' plan is like repainting a crumbling wall and calling it a renovation. There's no concrete or new idea for the development of the region. The special package to Bihar was already announced by the Hon'ble Prime Minister in 2015 for the development of airports in Purnea, Gaya, and Raxual which went to cold storage. Again in 2024, the Purvodaya plan reiterates the same.

The plan proudly announces new medical colleges and district hospitals, however, the allocation for the PM Swasthya Suraksha Yojana, which supports the setting up of new AIIMS and district hospitals, has slumped from Rs 3,365 crore last year to Rs 2,200 crore this year. In several districts of Bihar, the presence of heavy metal ions like chromium and copper in groundwater and fluoride contamination in drinking water has crossed the maximum desirable limits as recommended by the WHO. These toxic metals are worrisome because of their carcinogenic properties. It has been years that the reports have highlighted the grim situation but still the development of any proper medical research college is still in papers and announcements.

The emphasis on developing Bihar tourism is laughable. Major key sites have not found any mention in the Union Budget. Famous sites like Takhat Shri Harimandir Ji Patna Sahib of Guru Gobind Singhji which is a place of extreme spiritual significance for Sikhs around the world. This Gurudwara is the birthplace of Guru Gobind Singh Ji, the tenth Sikh Guru. The spiritual leader spent his early years here and transformed Sikhism into a martial faith and defended the principles of justice, equality, and religious freedom. Devotees from all over the world come here to

seek spiritual comfort and wisdom from the Guru's teachings. Gurudwara Patna Sahib is not just a place of worship; it is a symbol of spirituality, history and Sikh culture. Another highly devoted site is the Sitamarhi in Bihar which is the birthplace of the goddess Sita. She was born from an earthen pot when her father, King Janaka, was plowing the fields near Sitamarhi. There's also a pond and a temple dedicated to her in Sitamarhi. The Janaki Temple, which is around 100 years old, is also located in Sitamarhi. Thirdly, the famous Maner Sharif in Patna shelters two very popular Muslim tombs: of Sufi saint Makhdoom Yahya Maneri, known as the Bari Dargah (the great shrine), and that of Makhdum Shah Daulat, popularly called Chhoti Dargah (the small shrine). In medieval times, Maner Sharif used to be the principal site of learning and knowledge in the region. All these significant sites have been sidelined.

This Union Budget lacks focus on education and skill development even when the major educational centers in the country like JNU, AMU, Jamia Milia Islamia, and Osmania University, most IITS struggle to function, how can Bihar or India hope to become a ?Vishwaguru'?

AMU Centre in Kishanganj is a beacon of hope for the educationally and economically backward people of the Seemanchal region. As per the recommendation of the Sachar Committee, the UPA government in 2013 allocated Rs. 136.82 crores and around 224.2 acres of land to Chakla to establish AMU Kishanganj. But no construction could take place because of the objections of the National Green Tribunal which has referred the matter to the National Mission for Clean Ganga (herein referred to as NMCG). Even after ten years and several official requests, the release of allocated amount is still pending. As a result, the Centre is running from just two buildings at Millat Chowk in Kishanganj.

NMCG issued directions to the Bihar Government under Section 5 of the Environment (Protection) Act 1986 against the construction of the AMU-Kishanganj campus. In response to NGT's order, the government of Bihar formed a technical team on 21-08-2019. A report on 'Scientific study on Feasibility of flood plain zoning in the state of Bihar' submitted by the technical team of the Government of Bihar concluded that floodplain zonation is not feasible in the state because of a lack of maps and studies. After giving this reason, the Bihar government commenced building construction at the police lines, Kishanganj on the land adjacent to the campus allotted land. However, the development of the AMU campus is halted due to NGT's injunction. How come the construction of police lines is going on with full

zeal but an educational institute catering to the most backward population is trapped under procedural delays?

This is happening despite the report submitted by the Executive Engineer, Flood Control and Water Resources to the District Magistrate, Kishanganj which stated that the Police lines and AMU Kishanganj center do not fall under the Mahananda river bed nor on the flood plains. The construction will not induce any negative effect on the behavior of the river. The same report was sent to the NMCG Director, both by the Government of Bihar and AMU Even then the restriction of NMCG has not been removed and NOC to begin the construction has not been issued. Hence, jeopardizing the future of youth and education of Kishanganj, Bihar.

This unjiustified obstruction has caused a delay in the release of funds. Even after ten vears and several official requests, the allocated fund of Rs. 126.82 crore is still pending. This lack of funding has crippled the center and left it without relevant courses to offer MBA and B. Ed being the only two courses being offered, lack of infrastructure and research labs at the Centre. Not a single teaching and non-teaching post for AMU Centre Kishangani. Bibar has been sanctioned. At the same time, the two other AMU centers of Malappuram. Kerala and Murshidabad, West Bengal have been provided with 29 teaching and 19 non-teaching UGC-sanctioned posts. Similarly, fund allocation for the hostel for boys and girls under PM Jan Vikas Karyakaram has also been given to the other AMU Centres except for the Kishanganj Centre.

A decade under this present government, education spending has declined and universities struggle with loans. In comparison, between 2004 and 2014, the Congress-led union government allocated an average of 0.61% of the GDP to education. Despite its promise, between 2014 and 2024, the Union government allocated an average of only 0,44% of the annual GDP to education each year. Secondly, since 2017, the National Council of Educational Research and Training (NCERT) has made significant changes to school textbooks. The latest changes were made in 2022 references to the Mughal era and the caste system were cut down or removed entirely. Thirdly, The Higher Education Financing Agency (HEFA), took over several functions pertaining to funding from UGC and changed the mode of financing from grants to loans. This left many Central institutions struggling to repay loans. Instances like the government withdrawing the Maulana Azad Fellowship for Muslim students, excluding students from humanities backgrounds from the National Overseas Scholarship, majorly of those from marginalized

backgrounds, or reducing the number of seats for the Master of Arts (MA) Urdu course, the last decade has seen large scale student protests across the country, on issues such as privatization, cancellations of fellowships, delays in stipends, and fund cuts for research, etc.

Why is the present government hell bent to destroy Public Universities? In 2022, the funds to two leading central universities of the country - Jamia Millia Islamia (JMI), JNU, and Aligarh Muslim University (AMU) were drastically reduced. In the case of Jamia Millia Islamia, there is a sharp fall in funding of nearly Rs 68.73 seen in 2021-22. Similar is the case of Aligarh Muslim University, with a significant decline of funds of Rs 306 crore in 2021-22. In the case of JNU, the funding increased by only Rs 70 crore in the last seven years. Allahabad University has already hiked the fee for courses and hostels for the session 2022 23 almost 4 times. In a way, The New Education Policy (NEP) has weakened social justice and reservations; and opened the floodgates for privatized and commercialized education.

The recent case of The Allahabad High Court order on scrapping the 'Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004' violated Articles 29 and 30 of the Indian Constitution, which guarantees the right of religious minorities to establish and run educational institutions of their choice. In lieu of the above, the Supreme Court stayed the order of the High Court.

Under the Centre's Madrasa Modernisation Scheme that has been running since 1993-94, the state's recognized, privately-run and government-aided madrasas began employing instructors to teach modern subjects. Under the scheme, graduate teachers would receive Rs 6,000 monthly, while postgraduates would earn Rs 12,000. Allegedly, the Centre stopped paying their salaries in 2016, triggering a clause whereby the state government also stopped paying its share of the salaries. In March 2022. Centre's plan to stop funding the 'Scheme for Providing Quality Education in Madrasas' may cause around 21,000 teachers of madrasas to lose jobs and lakhs of the poorest of poor students to be excluded from receiving education. The document, from the Ministry of Minority Affairs, shows that the present government did not approve any new proposals from states under the program between the 2017/18 and 2020/21 fiscal years, before closing it altogether. In the wake of the above, states like Assam have converted hundreds of madrasas into conventional schools, despite protests from Muslim groups. If all

recognized madrasas would shut down, around 100,000 teachers would become jobless.

Around two hundred million Muslims live in India, making up the largest minority group in India. For decades, Muslim communities have faced discrimination in employment and education and encountered barriers to achieving wealth and political power. Muslims have experienced discrimination in areas including employment, education, and housing. Moreover, they often struggle to secure justice after suffering discrimination, despite constitutional protections. Over the last two decades, the representation of Muslims in parliament has stagnated. Muslims held just 5 percent of seats. In addition, authorities have turned to extrajudicial means through practices like "bulldozer justice' destroying homes in several states.

Mob attacks have become so common in recent years that India's Supreme Court warned that they could become the "new normal." One of the most common forms of anti-Muslim violence is vigilante groups attacking people rumored to trade or kill cows. The authorities have even used the National Security Act- a repressive law that permits detention without charge for up to a year - against those suspected of illegally slaughtering cows Three Muslim men, residents of Uttar Pradesh, were brutally attacked by a mob in Chhattisgarh's Raipur while transporting cattle. Three Muslim men, residents of Uttar Pradesh, were brutally attacked by a mob in Chhattisgarh's Raipur while transporting cattle Hate speech and misinformation spread online have also encouraged violence against Muslims. During the Delhi Riots, Delhi police have filed politically motivated charges, including terrorism and sedition, against 18 activists, students, opposition politicians, and residents 16 of them Muslims. the Delhi police raided the office of a prominent Muslim lawyer, Mehmoad Pracha, who was representing several riot victims. The raid prompted condemnation from hundreds of lawyers who called it an attack on 'attorney-client privilege'.

Post-election results, incidents such as a curfew being imposed for over a week in Balasore, Odisha after a communal scuffle broke out, local groups allegedly vandalizing Muslim homes in the presence of the police and a case of stone pelting in the Jalori Gate area of Jodhpur, left at least 16 people, including four policemen injured. Another incident was when a mob looted and vandalized a textile shop belonging to a Muslim man. Due to that tense atmosphere and pressure, around 16 Muslim shopkeepers had to leave the town, Several homes belonging to

Muslims were demolished by authorities in Mandla, Madhya Pradesh claiming that the reason for the demolition was that the people's houses were built on government land. Another large-scale demolition was carried out in Akbarnagar in Uttar Pradesh.

The Waqf Act of 1995 is a law that defines waqf as the permanent dedication of property for charitable and pious purposes under Muslim law. The act gives Waqf Boards more powers, including the ability to acquire properties without legal challenge. However regular encroachment of the land is happening. The president of the Sunni Central Waqf Board sub- committee in Ayodhya said that more than 3,000 square feet of an Idgah and cemetery near Saket Degree College had been encroached upon. According to a committee report, over 60% of Waqf land in Marathwada is under encroachment.

Minority not only in India but throughout the world is facing severe repression. As rightly said by Priyanka Gandhiji, it is indeed our moral responsibility to clearly condemn genocidal actions and horrifying war crimes in Gaza. Thousands of innocent children are being wiped out day after day. A country like India which has given the lesson of non-violence to the world shouldn't overlook the reality of the present events happening in other parts of the world.

Another pressing issue is the Kosi-Mechi river interlinking in Bihar. The project has received significant fund allocation in the Union Budget 2024-25. The National Water Development Agency (NWDA) which proposes intrastate river linking projects, often overlooks environmental and practical challenges. However, this project depends on the hypothetical construction of the Sapt Kosi High Dam is unnecessary as both basins receive ample rainwater during monsoon.

There's a fear of increased flooding and waterlogging, it fails to address the impacts on numerous rivers and streams it crosses, the siltation and catchment issues, and the displacement of populations. The project is more about benefiting those involved in its construction than providing genuine irrigation or flood protection. The haste in pushing this project forward, despite significant gaps in EIA report, raises serious concerns.The Economic Survey 2024 conveniently claims there's no data on employment and that 50% of the Indian youth are unemployable. The employment crisis is so severe that even IIT students are struggling to find even meagre jobs. This questions the decade-old Skill India mission.Wrapping the Union Budget 2024-25, both Bihar and Bharat go home with nothing.

श्री जिया उर रहमान (सम्भल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं अपनी बात अपने दादा मोहतरम के एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं:

मेरी बर्बादियों पर न मुस्कुराओं ए चमन वालों,

तुम्हारे सिर से भी एक दिन गुजरनी कयामत है ।

मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो आज बजट का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि यह बहुत बड़ा बजट है और आम जनता के लिए बजट है, तो यह आम जनता को बचाने के लिए बजट नहीं, बल्कि यह बजट सरकार को बचाने वाला बजट है । मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में आपने रोजगार देने के नाम पर वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे । वर्ष 2014 से लेकर अब तक 10 साल हो गए । अगर आपने रोजगार दिया होता तो आज 10 करोड़ रोजगार होता । आज हर परिवार के अंदर एक आदमी को रोजगार मिला होता, लेकिन आपने उनके साथ धोखा किया है । आप मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा नहीं कहा था । आपने रोजगार के नाम पर उन लोगों को ठगने का काम किया है । अगर आज कहीं भर्तियाँ निकलती भी हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है । हमारे कितने युवा पढ़ने के बाद पेपर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया और उनकी उम्मीदें सिर्फ धाराशायी हो जाती हैं ।

आज किसानों के मुद्दे की बात करें, तो आपने कहा था कि हम उनकी आमदनी को दोगुना कर देंगे । आमदनी दोगुनी करने की बात तो दूर है, हमारे किसान एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर तड़पते रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनकी सहायता और सुनवाई नहीं की । हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए । हमारे पास किसान समिति के लोग आए थे । उन्होंने मांग की है कि उन सारे परिवारों को या तो एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा मिलना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए । आज उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जो किसान हैं, वह इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आप उन किसानों का पैसा माफ नहीं कर रहे हैं । हमें शर्म आती हैं । मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं ।

इस वक्त हम एजुकेशन की बात करें । मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से तालीम हासिल की है । आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के बजट को लगातार घटाते जा रहे हैं । एएमयू के जो पाँच कैंपस थे, वे बंद होने के कगार पर आ गए हैं । आप उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? यूपीए के समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि मुसलमान दलितों से भी ज्यादा पिछड़ चुके हैं । भाजपा कहती थी कि हम मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर देंगे और दूसरे हाथ में कुरान देंगे । आपने उनके साथ धोखा किया और उनको छलने का काम किया । एनडीए ने वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक बजट के नाम 5020 करोड़ रुपये एलॉट किये थे, लेकिन सिर्फ 2612 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाए । वर्ष 2024-25 के बजट में सिर्फ 3123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि उनके साथ ऐसी ज्यादती क्यों है? सरकारी आँकड़ों में इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में मुस्लिम छात्रों की भागीदारी में गिरावट आई है । उनके बच्चों का एनरॉलमेंट वर्ष 2020-21 में मात्र 4.6 परसेंट था । स्कूल-कॉलेज ऐसे हो गए हैं, जैसे आप मुसलमानों को जाहिल रखना चाहते हैं । इसकी सबसे बड़ी मिसाल एएमयू और जामिया का लगातार घटता हुआ बजट है । हमारे पीएम जब मुस्लिम मुल्क में जाते हैं, तो उनका सम्मान होता है । अब पीएम अपने दोस्त उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं । यह अच्छी बात है, लेकिन भारत में मुसलमानों की आर्थिक, समाजिक तालीम और मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर यूएनओ और अमेरिका की अल्पसंख्यक रिपोर्ट हमारे देश पर उंगुली उठाती है । यह सरकार के लिए

शोभा की बात नहीं है । आखिर उसके बाद भी मॉब लिंचिंग, बुलडोजर चला कर और मुसलमानों का मकान गिराकर भाजपा सरकार क्या संदेश देना चाहती है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं । अलीगढ़ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बना कर भेजा था । उसमें मैं भी गया था । वहां पर मॉब लिंचिंग हो गई थी । अफसोस की बात है कि मॉब लिंचिंग होने के बाद वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने मॉब लिंचिंग किया था, उनको बचाने का काम करते हैं । वे बुलडोजर चला देते हैं । मैं कहता हूं कि बुलडोजर चलाने का, सजा देने का काम कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का नहीं, बल्कि न्यायपालिका का काम है ।

माननीय सभापति**:** आप अपनी बात समाप्त करें । आपकी पार्टी का टाइम समाप्त हो चुका है ।

श्री जिया उर रहमान**:** सभापति महोदय, मैं अपनी बात इस शेर के साथ समाप्त करता हूं:

लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है,

तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है,

ख़ून-ए-मजलूम ज्यादा दिन नहीं बहने वाला,

ज़ुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला,

इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा,

तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा ।

माननीय सभापति जी, मेरी दरख्वास्त है कि इस मॉब लिंचिंग? (व्यवधान) बुलडोलर की कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, already your party?s time is over.

The next Member to speak is Shri Karti Chidambaram. प्लीज अब बैठ जाएं ।

? (*Interruptions*)

श्री जिया उर रहमान**:** हमारे मुसलमानों के इंप्लायमेंट पर खास तौर से फोकस किया जाए । यह बजट कमजोर बजट है । ? (व्यवधान) *?* *

[جناب ضیاءالرحمان (سنبھل): محترم چیرمین صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ پر بولنے کا موقع دیا۔ میں اپنی بات اپنے دادا محترم کے ایک شعر کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔

میری بربادیوں پر نہ مُسکراؤ اے چمن والوں

تمہارے سر بھی گُزرنی ایک دن قیامت ہے

میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو آج بجٹ کا ڈھِنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بجٹ ہے اور عام جنتا کے لئے بجٹ ہے، تو یہ عام جنتا کو بچانے کے لئے بجٹ نہیں، بلکہ یہ بجٹ سرکار کو بچانے والا بجٹ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سال 2014 میں آپ نے روزگار دینے کے نام پر وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال دو کروڑ روزگار دیں گے۔ سال 2014 سے لیکر اب تک دس سال ہو گئے۔ اگر آپ نے روزگار دیا ہوتا تو آج دس کروڑ روزگار ہوتا۔ آج ہر پریوار کے اندر ایک آدمی کو روزگار ملا ہوتا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آپ مجھے بتایے کہ کیا آپ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ آپ نے روزگار کے نام پر ان لوگوں کو ٹھگنے کا کام کیا ہے۔ اگر آج کہیں بھرتیاں نکلتی بھی ہیں تو ان کا پیپر لیک ہوجاتا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان پڑھنے کے کے بعد پیپر تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد معلوم چلتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا اور ان کی اُمیدیں صرف دھراشائی ہو جاتی ہیں۔

آج کسانوں کے مدعے کی بات کریں، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کی آمدنی دوگنا کر دیں گے۔ آمدنی دوگنی کرنے کی بات تو دور ہے، ہمارے کسان ایک سال تک دہلی کے بارڈر پر تڑپتے رہے، ہمارے ملک کے پردھان منتری نے ان کی مدد اور سُنوائی نہیں کی۔ ہمارے 700 سے زیادہ کسان شہید ہو گئے۔ ہمارے پاس کسان سمیتی کے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے مانگ کی ہے کہ ان سارے پریواروں کو یا تو ایک۔ایک کروڑ روپئے معاوضہ ؟؟؟ ملنا چاہیے یا پھر سرکار نوکری ملنی چاہئیے۔ آج ادیوگ پتیوں کے 16 لاکھ کروڑ روپئے قرض کو معاف کرنے کے لئے آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن جو کسان ہیں، وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ ان کسانوں کا پیسہ معاف نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔

اس وقت ہم ایجوکیشن کی بات کریں۔ میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بجٹ کو لگاتارگھٹاتے جا رہے ہیں۔ اے۔ایم۔یو۔ کے جو پانچ کیمپس تھے، وہ بند ہونے کے کگار پر آ گئے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں؟ یو۔پی۔اے۔ کے وقت سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی کہ مسلمان دلتوں سے بھی زیادہ پچھڑ چکے ہیں۔ بھاجپا کہتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر دیں گے اور دوسرے ہاتھ میں قرآن دیں گے۔ آپ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو چھلنے کا کام کیا۔ این۔ڈی۔اے۔ نے سال 23-2022 میں اقلیتی بجٹ کے نام 5020 کروڑ روپئے ایلوٹ کئے تھے، لیکن صرف 2612 کروڑ روپئے ہی خرچ کر پائے۔ سال 25-2024 کے بجٹ میں صرف 3123 کروڑ روپئے کا پراوُدھان کیا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایسی زیادتی کیوں ہے؟ سرکاری آنکڑوں میں انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن میں مسلم چھاتروں کی بھاگیداری میں گِراوٹ آئی ہے۔ ان کے بچوں کا اینرولمینٹ سال 21-2020 میں صرف 4.6 فیصد تھا۔ اسکول کالج ایسے ہو گئے ہیں، جیسے آپ مسلمانوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اے۔ایم۔یو۔ اور جامعہ کا لگاتار گھٹتا ہوا بجٹ ہے۔ ہمارے پی۔ایم۔ جب مسلم ملک میں جاتے ہیں، تو ان کا سمّان ہوتا ہے۔ اب پی۔ایم۔ اپنے دوست ادیوگ پتیوں کے لئے اِنویسٹمینٹ بھی لا رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن بھارت کے مسلمانوں کی معاشی، سماجی تعلیم اور مسلمانوں کی سُرکشا کے سوال پر یو۔این۔او۔ اور امریکہ کی اقلیتی رپورٹ پر ہمارے دیش پر اُنگلی اٹھاتی ہے۔ یہ سرکار کے لئے شوبھا کی بات نہیں ہے۔ آخر اس کے بعد بھی ماب لنچنگ، بلڈوزر چلا کر اور مسلمانوں کے مکان گرا کر بھاجپا سرکار کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔۔ (مداخلت)۔

محتریم چیرمین صاحب، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علی گڑھ سے ہمارے مانئے راشٹرئے ادھیکش اکھِلیش یادو جی نے ایک ڈیلی گیشن بنا کر بھیجا تھا۔ اس میں، میں بھی گیا تھا۔ وہاں پر ماب لنچنگ ہو گئی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ ماب لنچنگ ہونے کے بعد وہاں کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ، جنہوں نے ماب لنچنگ کیا تھا، ان کو بچانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ بلڈوزر چلا دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلڈوزر چلانے کا، سزا دینے کا کام کاریہ پالیکا یا ویوستھا پِکا کا نہیں، بلکہ نیائے پالیکا کا ہے۔

چیرمین صاحب، میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں

لشکر بھی تمہارا ہے، سرکار بھی تمہاری ہے

تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے

خونِ مظلوم زیادہ دن نہیں بہنے والا،

ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا،

ان اندھیروں کا جِگر چیر کر نور آئے گا

تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔

محترم چیرمین صاحب، میری درخواست ہے کہ اس ماب لنچنگ (مداخلت) بلڈوزر کی کاروائی کو روکنے کے لئے سرکار سخت قدم اُٹھائے۔ (مداخلت)۔

ہمارے مسلمانوں کے ایمپلائمنٹ پر خاص طور سے فوکس کیا جائے۔ یہ بجٹ کمزور ہے۔ (مداخلت)۔

مجھے سنبھل پارلیمانی حلقہ کی عوام نے جیتا کر بھیجا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔

میں آپ کا دھیان اس محرم کے جلوس کی طرف دلانا چاہتا ہوں ۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے شہید ہو کر حق اور انصاف کو بچانے کا کام کیا تھا ۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس بار اتر پردیش میں سنبھل اور مرادآباد میں جلوس کے منانے میں اڑچن پیدا کی گئی۔ ایک تانا شاہ آدیش جاری کیا گیا کہ اس جلوس کو روایتی طریقے سے نہیں منا سکتے اور سنبھل، مرادآباد، امروہہ، سنبھل کُندرکی بِلاری اور چندوسی کے اندر پولس پرشاسنک ادھِیکاریوں نے اُتپیڑن پیدا کیا (مداخلت)۔

انہوں نے لوگوں کو دھمکا کر ، اس کی ہائٹ کو کم کرکے ان کے خلاف کاروائی کی (مداخلت) ہم سبھی دھرموں کی عزت کرتے ہیں۔ کاوڑ یاترا نکل رہی ہے، ہمیں اس سے بھی کوئی پرہیز نہیں ہے ۔]

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): The Budget presented by the Union Government is revengeful not only for Tamil Nadu but for the entire nation. The hon. Union Minister for Home Affairs laid the foundation for implementation of the second phase of the Chennai Metro rail project during 2020 in a hurried manner in the midst of Corona pandemic. Following that, it was announced in the Union Budget of 2021 that this project would be implemented with a cost of Rs.63,000 crore jointly by the Tamil Nadu State Government and the Union Government. But now, our Tamil Nadu Government, which is functioning on the basis of Dravidian model, has been undertaking this project on its own. The Union Government has not released a single rupee of its share for the past three years. Hence, I urge upon this Government to release its share immediately. The same Union Government has given clearance besides funding the metro rail projects even in smaller cities of the BJP-ruled States. Whereas our metropolitan cities like Chennai, Coimbatore and Madurai are made to wait. Taking cognizance of this, I urge upon the Union Government to release its share of funds for the early completion of the second phase of Chennai Metro rail project.

The BJP has come to power in 2014, promising to generate two crore employments for youth every year. In the last 10 years, has this Government provided employment to 20 crore youth? I urge that this Government should give a detailed report on providing employment to youth.

Similarly, as a move to jeopardize the epartment of School Education of Tamil Nadu, the Union Government says only when the State accepts in writing to implement the National Educational Policy, funds meant for the Samagra Shiksha Abhiyan will be released to Tamil Nadu, although this scheme has been successfully implemented during the last 20 years. This is undemocratic. In order to protect the students of Tamil Nadu without being their education affected, and to ensure disbursal of salary to teachers, the Union Government should release immediately the funds meant for this scheme. Hence, the Union Government should function in such a way similar to the functioning of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thiru *Thalapathy* M. K. Stalin under Dravidian Model, who wholeheartedly works for the welfare of those who voted him to power and also to those who did not vote. Thank you.

SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): With the rightful status as a people's representative elected from Tamil Nadu, I wish to place the flip side of the Budget. "Elections are over; Let us think about our country", this was the statement made

by hon. Prime Minister. Having so much belief on his words we sat inside this House of the People with a hope that something will be served in this Budget to satiate our hunger. Andhra Pradesh was seated on my left and Bihar on my right. But Tamil Nadu, which was in the middle, was ignored and the other two plates were served with so many delightful varieties of food. "We were not worried on what was served on these two plates; but you have made Tamil Nadu to starve". This is our rightful voice and concern." Keeping in view of this, our leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu said these words with a sense of anguish in mind. "The Union Budget can save the life of your Government but not the country. Conduct yourself for the common cause. Do not act in such a mind-set taking revenge against those who made you lose elections".

"Hon. Finance Minister has said "There is no need to mention all the names of States in the Budget". But it is very evident from the fact that BJP is reeling under political compulsions which forced them to make announcements of this magnitude making us believe that only Andhra Pradesh and Bihar are the only two States that exist in our country. Hon. Finance Minister, is it correct on your part make a few to be happy and leaving many in worries. We are not jealous to see an allocation of Rs. 15,000 crore to the reconstruction of Amaravati as Capital City of Andhra Pradesh. But hon. Union Minister of Home Affairs laid the foundation for AIIMS at Madurai in the year 2020. Why the planned allocation for the execution of this project was denied?

The Government have been generous enough to allocate Rs 26,000 crore for the construction of Highways in Bihar. But you have forgotten the Metro Rail Schemes proposed to be set-up in Coimbatore and Madurai. When disasters struck Andhra Pradesh and Bihar, you have a kind heart to allocate Rs 11,500 crore. But Tamil Nadu, as a baby crying for its food, wanted from you Rs. 37,000 crore in view of the disasters that shattered this State. How this genuine request not reaching your ears? "A King who performs his duties and protects his subjects will be specially regarded as the people's leader." How the Tamil knowing Finance Minister is unaware of this couplet. ("A just King, who guards over his subjects will be regarded as God by them"- Couplet 388 of Tirukkural). Our hon. Prime Minister has read well the epic Ramayana and is the one who constructed a temple for Ram in Ayodhya. I want to show the equality portrayed by King Janak during the wedding ceremony of Sita. King Janak gave respect to the people in the lower strata in the same magnitude as it was extended to Lord Ram. I would cite those poetic lines from the epic.

"What more to explain, this wedding ceremony lacks of dearth King Janak, Sita's father spent all his wealth to mention his worth Janak's love was evident throughout the Ceremonial theme As equal as to people in lower rung and that of Lord Ram"

There is another scene of depiction from the epic Ramanayana.

King Dasharatha of Ayodhya perfomed Putrakameshti Yajna under the supervision of Sage Kalaikkottu Muni (Rishyashringa) for the sake of bearing children. A pot of kheer (sweet dish) was handed over at the end of the Yajna to King Dasharatha. He divided it into four parts and handed over one part each to Queens Kaushalya and Kaikeyi. But he gave the remaining two parts to Queen Sumitra. Why is this partiality? Kaushalya was a queen hence one-fourth of the distribution. Kaikeyi was again a queen who was given another one-fourth quantity of Kheer. But Sumitra did not belong to the family of Kings. In order to elevate her, King Dasharatha gave Sumitra two parts i.e. half-portion. Andhra Pradesh is prosperous due to the perennial rivers which pass through the State whereas mineral resources are in abundance in Bihar. Hon. Prime Minister should have provided two portions to Tamil Nadu as done by King Dasharatha. What harm our classical language Tamil did for you? In the Ramayan taught by you, do you know why plenty of lotus flowers were seen blooming in Kishkindha Poet Kambar says that the bloom was due to singing Tamil songs. "Lotus which sings a Tamil song" is the exact verse from epic. Kamba Ramayanam talks of Ayodhya where river Ganges passes through similar to that if Tamil Nadu where river Cauvery flows. When Lord Ram left Ayodhya, it was described, "As the one leaving the all-fertile land of Cauvery, the all-wealthy Lord Ram left the Kingdom of Kosala." Ramayana did not differentiate between Tamil Nadu and Ayodhya. But since you differentiate, you lost elections in Tamil Nadu and also in Ayodhya (Faizabad, UP).

The beacon light of Dravidian movement Peraringnar Anna, while delivering his address, in the Upper House of Parliament, "I claim Sir, to come from a Dravidian country, a part of India now. I belong to Dravidian stock. I am proud to call myself a Dravidian." " This does not mean that I am against a Bengali or a Maharashtra or a Gujarati", he said. We, who came as successor of Perarignar Anna never think people from other parts of the country as our opponents. We consider them our brothers and act accordingly. Therefore, whichever part of this country is allocated funds, we welcome it with love and

happiness. At the same, we wish to register in this august House with deep anguish that the funds that are due to Tamil Nadu are not given and we loudly raise our rightful voice in the right perspective for allocating funds that are due to the people of Tamil Nadu. Thanthai Periyar had sown seeds for the Dravidian movement. Perarignar Anna protected this as good seedlings. Dr. Kalaignar nurtured this seedling to become robust tree. This tree is being nurtured by our Commander, the Thalapathy of Dravidian movement and the tall leader of Dravida Munnetra Kazhagam hon. Chief Minister Thiru M.K. Stalin by making the people of Tamil Nadu benefitted by the fruits of this grand tree.

"A thinker sculpts himself by asking lot many questions," says Plato.

"One can die by being honest; rather to live with dishonesty", says Socrates.

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu with his refined thoughts raising the rightful voice of the people of Tamil Nadu. He said, "By ignoring to allocate funds to the people of Tamil Nadu who did not vote for them, BJP could not try to isolate itself away from the people".

He further said, "For a developed Bharat, coordinated efforts are necessary". When the fishermen of Gujarat were arrested by Pakistani Navy, you swiftly acted upon and ensured immediate and safe release of those fishermen. But when fishermen from Tamil Nadu were arrested by Sinhalese, the Sri Lankan Navy. There was not even a voice of condemnation from your side. Fishermen from Tamil Nadu earn Rs 20,000 crore as foreign exchange to the country but there is no allocation for them. Mahakavi Bharathiyar says, "Can we damage one of our twin eyes ourselves to affect our vision" But by damaging the eyes of fishermen of Tamil Nadu, you prefer to provide eye glasses to the fishermen from Gujarat for an improved vision.

The Government of India have turned a blind eye and deaf ears to Tamil Nadu's demand for new schemes and trains in the railway sector. There is a mismatch between the problems at hand and what the Budget offers is even more blatant when we look at the agriculture sector. Farmers are not able to make ends meet and have a decent livelihood because crop production has become economically unviable and they have been demanding procurement at a legally guaranteed minimum support price. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) allocation there is

a different trend, for the financial year 2024-25, Rs. 86,000 crore has been allocated for the MGNREGS.

This may be Rs. 26,000 crore more than last year's allocation of just Rs. 60,000 crores, but it is still Rs. 19,297 crores less than the scheme's actual expenditure of Rs. 1.05 lakh crore in the financial year 2023-24, this year's allocation for the MGNREGS is just 1.78 percent of the budgetary allocation, a 10-year low in the scheme's funding. The rural jobs scheme has been persistent by the problem of under-allocation of funds. The lower allocation artificially suppresses the demand for work under the scheme. The allocation for FY25 is less than the expenditure in FY24. It also does not take into account the increased demand in the first quarter of this financial year. The Minorities in the country are in a condition of real danger with the anti-minority temperament of the BJP ruled Union Government and BJP-led State Governments.

There has been a meagre increase in funds allocated for minority affairs and most of the schemes have also seen budgetary cuts. The budget estimate for the coaching and allied schemes for minorities has been cut from Rs. 30 crore in 2023-24 to Rs. 10 crore in 2024-25. The Revised Estimate for this scheme in 2023-24 was Rs. 14 crore. The Budget Estimate for the interest subsidy on educational loans for overseas education for minorities has also been reduced from Rs. 21 crore to Rs. 15.30 crore. The revised estimate for this scheme was Rs. 7 crore. The Finance Minister has failed to help her gender in upliftment. The Budget allotted for the Ministry of Women and Child Development has been reduced by 0.03 percent. Despite the extension of free foodgrain allocation under the National Food Security Act, the budgeted food subsidy is set to decrease from Rs. 2,12,332 crore (RE 23-24) to Rs. 2,05,250 crore (BE 24-25).

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, this Budget lacks compassion and empathy and the blame -- I say this with all responsibility -- lies at the doorstep of the Prime Minister. I am a backbencher and I am a tailender. I say this with all responsibility. The Prime Minister has been weakened. He has not been able to have a new Cabinet even though he has won for the third time. He has appointed the same Ministers in the same portfolio. Had he chosen a Member of this House as Finance Minister, that Finance Minister would have had the native intelligence of

meeting constituents and understanding the problems of India, which is basically inflation and unemployment. Since this Finance Minister does not have a Lok Sabha constituency and since this Finance Minister does not interact with people who go through daily problems of joblessness and price rise, this Budget lacks empathy and compassion.

I hope this Finance Minister, when she comes at 4 o?clock, does not compare herself with some of her predecessors who came from the other House. Their economics background is much different from hers. If she had empathy and compassion, she would have addressed the unemployment issue. There are 10 lakh vacancies in the Government of India. This Budget does not speak about filling those vacancies.

The GST is a mess. The multi-slab GST is the cause of inflation and price rise. She has not addressed it. In fact, they levy GST even on prosthetics, artificial limbs and motorised wheelchair which basically means that this Government is levying a tax on walking. We are one of the most under-insured countries in the world. This Government levies 18 per cent GST on insurance premium for health and life. It is a shame. ? (*Interruptions*) This has to be withdrawn in this Budget. Further, there are students who have taken student loans who cannot repay it because of the unemployment crisis in India. There has been no waiver or write off or relief for those who have taken student loans and the ELI Scheme at best is woolly.

This Government has no compassion and no empathy because it is divorced from the realities of India. Even their core constituencies are complaining about them because they have removed indexation, and by removing indexation what they have really done is, you are not giving the benefit of buffering yourself against inflation. Kindly read the social media posts. Your own core constituencies are criticising you.

This Government is a fatigued Government. This Government has malice. This Government has no new ideas and no freshness, and they talk about giving Rs. 17,500 as tax relief. This translates to Rs. 47 a day. What can you buy for Rs. 47 a day except for a Jio recharge? Nothing else can be bought for Rs. 47 a day except for a Jio recharge. This Budget must be rejected by this House because it lacks compassion and empathy. Thank you very much.

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा (जूनागढ़) : मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं । श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रिकॉर्ड सातवीं बार बजट पेश किया । 2024 के बजट में कृषि,

रोजगार और कौशल विकास में उत्पादकता और संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है । ये प्राथमिकताएं प्रगति की दिशा में राह दिखाती हैं । जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की प्रक्रिया में काम करेगा और एक विकसित राष्ट्र के लिए एक ठोस नींव रखेगा ।'

केंद्रीय बजट 2024 एक विकसित भारत की दिशा में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है । यह इस सरकार में भारत के लोगों के अटूट विश्वास का प्रमाण है । यह बजट परिवर्तनकारी और प्रगतिशील है । गरीब समर्थक, किसान समर्थक और मध्यम वर्ग, युवाओं और छोटे व्यवसायों के हितों को एक साथ जोड़ता है ।

कृषि क्षेत्र ही वह आधार है जिस पर हमारा समाज फलता-फूलता है । हमारे किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । पिछले पांच वर्षों में कृषि क्षेत्र में 4.18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है ।

इस बजट में 500 कंपनियों में अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की पेशकश की गई है । मुझे विश्वास है कि भारत के युवाओं को विकास के लिए अमूल्य अनुभव और अवसर प्रदान करके बहुत लाभ होगा ।

भारत में महिला विकास बदल रहा है । यह परिवर्तन प्रधानमंत्री जन धन योजना से स्पष्ट है, जिसने करोड़ बैंक खाते खोले हैं, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं हैं । दीनदयाल अंत्योदय योजना ने स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को और सशक्त बनाया है, उनके आत्मसम्मान और समाज में उनकी भूमिका बढ़ाई है ।

मैं बजट 2024 में सक्रिय पहलों के लिए सरकार की सराहना करता हूं । जैसा कि हम भविष्य की दिशा में अग्रसर हैं, केंद्रीय बजट 2024 मजबूत आर्थिक प्रबंधन का प्रमाण है । मुझे विश्वास है कि यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले वर्षों में भारत मजबूत और अधिक समृद्ध हो ।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): This budget is not a Union Budget, but a Bihar and Andhra Budget. In the entire speech, the finance minister did not speak a single word about Kerala.

I would like to begin with the agriculture sector, the largest employer in the country, which has witnessed a reduction in successive budgets. The share of Agriculture in the overall budget has declined from 4.97% in 2019-20 to 2.74% in 2024-25. Farmer organizations have expressed concern over a significant 34.7% decrease in the allocation for fertilizers, amounting to a decrease of Rs 87,238 crore compared to the 2022-23 actuals. Given that farmers are already struggling to make ends meet, this reduction may have a negative impact on agricultural productivity. According to the latest Agriculture Statistics released, growth of agriculture reduced from 6.8% in 2016 17 to 3.3% in 2022-23.

Coverage of farmers under PMFBY has reduced by 44% for the Kharif season and 9% for the rabi season from 2018 to 2024. Area insured was reduced by 38% and

5% respectively for the kharif and the rabi season. Despite the Budget's commitment to enhancing the agriculture sector through cooperatives and FPOs, no allocation has been made to the Integrated Scheme on Agricultural Cooperation, although the scheme spending was Rs 300 crore in the revised Budget for 2023-24. The Standing Committee noted that the Government must strive hard to achieve the level of 75% farm mechanization. Today we are only at 47%.

In her speech, the finance minister spoke of the increase in MSP for crops earlier this year, but the prices are still significantly below what the Swaminathan Commission Formula recommended. The government has conveniently claimed that they have followed the recommendation but in actual they have left out the cost of production, including rent and interest foregone on land and machinery owned by farmers, from the formula.

The recent budget has also failed to address the pressing need to ensure a minimum support price for natural rubber. Rubber cultivators are facing crisis due to fall in prices of rubber. The main reason behind this is indiscriminate import of natural rubber. India is the 5th largest importer of rubber in the world. Farmers are leaving rubber cultivation which in turn affects the economy of the State. Import of rubber should be stopped with immediate effect. A scheme for natural rubber price stabilization should be introduced to support small and marginal farmers.

Farmers in Kerala are severely impacted by the human wildlife conflict in the state. As of 2021, the total area under forests including plantations is 21,253 square kilometers which is 54.7 % of the state's geographical area. Wayanad district has 74.2 % forest cover, the highest in Kerala, followed by Pathanamthitta and Idukki. Human-wildlife conflict has seen a sharp rise in the recent past. National-level statistics indicate an annual death toll of 400 people, damage to thousands of acres of crops, and the unmeasured psychological stress on the affected community. In 2022-23, in Kerala, 8,873 incidents of human-wildlife conflict were reported, including 98 human casualties. Of this, 48 people died of snake bites, 27 in elephant attacks, seven in wild boar attacks, one each in wild gaur and tiger attacks and 14 in other animal attacks. A total of 871 people were injured in the attacks while 65 cattle deaths were reported.

The most problematic' animals as per reports were elephants, wild boar, tigers, and in some locations, leopards. Amongst wild boars, 20,957 incidents of crop damage were recorded from 2017 to 2023. Farmers who inhabit the bordering forest lands

areas, are especially affected. Many national and international studies have shown that there is no threat to the wild boar populations and their numbers have increased. Being omnivorous, they cause harm to both plant and animal living creatures in farms. We urge the government to amend the Wildlife Conservation Act to allow killing of animals including wild boars, if they cause irreversible damage to life and farms. We ask the Centre to declare wild boars as vermin under Section 62, as they pose a major threat to the farmers. We also propose to empower Chief Conservators of Forests instead of Chief Wildlife Wardens to permit hunting of Schedule I mammals.

Forests are overburdened due to limited resources available. The search for water and fodder drives animals into farms. The construction of watering holes in deep forest can help to reduce the man-animal conflict. If hunting is not permitted, these animals must be transferred to other places where they can be sheltered.

I would also like to take this opportunity to talk about the Kasturirangan report recommendations. The recommendation to classify 37% of the area of the western ghats as eco sensitive areas, comes without consideration to the livelihood of people situated there. Implementation of this report, would mean displacing farmers and habitants in the marked western ghats regions which would adversely affect their socio-economic stability. Central Government not promulgated Final notification on Kasturirangan Report. The Government of India must take a decision that protected forest is the boarder and consider it as the ecologically sensitive area (ESA). The plantations, agricultural lands and inhabitants' area compulsorily excluded from the ESA

Railways and Sabarimala project:

Indian Railways plays a crucial role in passenger and freight movement between Kerala and the rest of the country. The Sabari Railway project, which would provide a direct rail route from Sabarimala to the rest of Kerala state as well as to other states in the country, is a long-standing project that is yet to be funded adequately and completed. Given the few other alternatives, this project would ensure that several million devotees who visit Sabarimala Temple annually have a seamless transport to their religious shrine. The proposal to extend the Angamali-Erumeli Sabari rail line via Ranny, Pathanamthitta, Konny.Pathanapuram, Punalur to Thiruvananthapuram from there to Vizhinjam harbour hints that the project would further uplift the regional transportation and economic landscape. Given its budget exclusion, this project also failed to address the priority

The recommended expansion of the Sabari rail range to Vizhinjam seaport requires about Rs 1,000 crore additionally, and is essential for connecting prospective Sabarimala international flight terminals. It also encourages development in numerous other markets. The budget failed to earmark anything towards this extension as a strategic project that could transform Kerala's connectivity and economy.

The current allocation is not enough to satisfy crucial railway infrastructure projects in Kerala such as demands for additional trains and a new Rail Zone. The Union budget in turn loses sight of these vital dimensions, with little attention to connectivity-a sector critical not only for economic growth but also for quality-of-life-enhancing public services that define the Kerala model.

Coming to unemployment, the biggest issue that is economically crippling the youth and middle class. Employment is at an 8-month high of 9.2%. While the government says that inflation is stable, inflation varies so much amongst goods that the middle class and poor have been hit. Growth in India is mainly due to corporates and high-income class. The Economic survey points out that corporate profit to GDP is at its 15 years peak. It also mentions that with the growth of the economy, corporate profits in India and the CSR pool will continue to grow, which will power the sustainable and inclusive development by nonprofits. Contrastingly, in the new internship scheme that this government introduced, CSR money which should be used for social issues will be diverted to the scheme. This means that corporates will just be investing in themselves.

This budget does not address any income inequalities. MNREGA, which is one of their flagship schemes, has not seen any increase in allocation. In 2022-23, Rs 90,806 crore was spent under MGNREGA. In 2024-25, Rs 86,000 crore has been allocated. Today under MGNREGA, the average wage rate paid is still lower than notified wage rate in almost all states. As of today, 8 states have more than 100% actual expenditure. So why has the government not allocated enough? Because of the lack of an updated census, we don't even know if all eligible beneficiaries are covered. Census is known to generate primary, authentic data which is used as the basis for several key statistical analyses and identifying beneficiaries under various schemes and programs. Given that India's projected population is now 140 crore, over 11 crore people could have been left out of NAFSA, MGNREGA and other eligible schemes.

The country is undergoing a water crisis. Cities like Delhi, Bengaluru, and Chennai are still as thirsty as they were in previous years. Despite huge investment in water and schemes like JJM, the reality on ground looks starkly different than what the dashboard numbers say. There are many surveys and investigations conducted by organizations that show that tap waters under JJM do not work due to issues such as electricity and barren water sources. Funds under Namami Gange have been consistently underutilized. Actual expenditure under Namami Gange was less than 70% of budget estimates between 2016-21. For three of these years, it was less than 45%. In 2023-24 RE, fund utilization is merely 60%. River pollution, poor water quality and lack of fit drinking water are the cause of many diseases.

Health:

The National Health Policy, 2017 envisages increasing the spending by a minimum of 2.5% of GDP on health by 2025. Earlier this target was to be achieved by 2022. In 2022 23, as per the economic survey, expenditure on health was only 1.9% of the GDP. This 1.9% also includes water and sanitation. So, the actual expenditure as a percentage of GDP on the health sector is even lower. The Household Consumers Expenditure Survey (HCES), released last month for 2022-23 revealed that the MPCE on health went up. MPCE in health in 2011-12 was 3.9% in rural areas. In 2022-23 it rose to 4.7%. The trend is same in urban areas. According to HCES, people are spending on health even more than education. According to the Economic Survey 2022-23, India's per capita health expenditure is Rs 4,470, of which the out-of-pocket expenditure is around 47%. India is home to a quarter of the world's undernourished population, and ranks 111 on the global hunger index, yet food security found no mention.

ASHA workers are consistently overworked and underpaid. They are not given pension and are paid in peanuts in the name of honorarium. Under the Ministry of Women and Child Development, the SAMBAL scheme which covers Beti Bacho, Beti padhao. Rs 630 crore has been allocated to it, which is more than a 200% increase in comparison to the actual expenditure in 2022-23. Rs. 562 crore allocated in 2022-23, but only Rs 195 crore was spent. In 2021-22, Rs 183 was spent while Rs 587 was allocated. Every year in the last three years, there has been a grave underutilization of funds. Children in India are facing chronic malnutrition. According to the Poshan Tracker, of the 8 crore children surveyed, 35% were found to be stunted and 17% were severely to moderately malnourished. The word 'children' was not once

mentioned in the budget speech, even though children comprise 19% of the country's population.

There exists a gender disparity in education too. The ASER 2023 'Beyond Basics survey shows that 24% female students of age 14-18 years could not read a grade II level text during the survey. It also revealed a clear gender disparity among adolescent youth. Of those who can use smartphones, only 19% female students had their own devices in comparison to 43% male students.

There has been also been a reduction of around Rs 200 crore for Central Sector Schemes under the Ministry of Youth Affairs and Sports. This includes reduction in decrease of fund allocation for Khelo India, National Service Scheme, Incentive to Sports Persons.

Lack of central institutions:

The government has been boasting about construction of central institutions such as IIMs and AIIMS across the country.The state of Kerala is highly focused on enhancing its health development and infrastructure. Yet, after repeatedly requesting the central government, Kerala still does not have an AIIMS. Additionally, being one of the biggest tourism spots in India, Kerala still does not have an IITTM set up. Establishing IITTMs would invite skilled labor in the tourism sector and create more jobs. To date, there is no National Institute of Design (NID), in the state either.

Kerala, often referred to as "God's Own Country," is known for its rich cultural heritage, stunning landscapes, and thriving tourism industry. However, there has been a lack of focus on tourism development in the 2024 budget, particularly in the district of Pathanamthitta. This area is a prime example of the urgent need for increased budget allocations to support eco-tourism and spiritual tourism.

The 2024 budget's lack of emphasis on tourism development in Kerala, especially in Pathanamthitta, represents a missed opportunity. Tourism is a vital sector for the state's economy, and insufficient investment hinders its growth. The budget's failure to announce new projects under the SWADESH and PRASHAD schemes indicates a lack of strategic vision. Additionally, the absence of specific allocations for eco-tourism and spiritual tourism in Pathanamthitta highlights a disconnect between the state's needs and the central government's priorities.

The progress of The PRASHAD Scheme, one of the main initiatives of the tourism ministry, has been undeniably slow, with only 22 out of 46 sanctioned projects completed in the last 10 years. CAG had identified that the Swadesh Darshan scheme is improperly implemented and highlighted poor fund utilization by the ministry. Despite this, the current government is increasing the budget allocation for the scheme in the current year's budget, from 1412 Cr to 1750 Cr, marking an increase of 338 Cr. What about earlier funds, what is happening and why is the growth so slow?

To conclude, this budget has seen no mention of children, SCs and STs. There is no relief to poor and non-tax paying laborers, no mention of grave deficiencies in healthcare, no response on pensions for Agniveers and no resolution on NEET. We implore the government to look beyond their alliances, and face the reality on ground so they can pay better attention to the citizens of the country, so I oppose this Budget.

श्री अजय भट्ट **(नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) :** सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, मैं अपने को ट्रेजरी बेंच की तरफ से जितने भी साथियों ने जो भी कहा है, उसके साथ सम्बद्ध करता हूं । पूरे आंकड़े आ गए हैं, सारी चीजें आ गई हैं, रिपीटेशन न हो, इसलिए मैंने अपने को सम्बद्ध किया है ।

मान्यवर, यह बजट सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी है । कोई भी इससे अछूता नहीं है । सभी लोगों को इसका लाभ जा रहा है । हर हिस्से में लाभ जा रहा है । यह कहीं सेंट्रलाइज्ड नहीं है, बल्कि इसका डीसेंट्रलाइजेशन छतरीनुमा में किया हुआ है । पूरे देश में, हर जगह पर, हर वर्ग में, हर श्रेणी में इसका लाभ जा रहा है ।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से ऊपर आएगी । कोरोना के दौर में आपने दुनिया में देखा कि अर्थव्यवस्था लगभग समापन की ओर जा रही थी । कुछ देशों ने तो हाथ जोड़ दिए, कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमसे विभिन्न मतभेद रखने वाले लोग हैं कि हम कुछ दे ही नहीं पाएंगे । ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी देश को बाहर निकाल कर लाए । हम उस समय अर्थव्यवस्था में 11 वें नम्बर पर चल रहे थे । इस तरह की योजनाएं बनाईं, इस तरह से आर्थिक प्रबंधन किया कि आज हम पांचवीं आर्थिक शक्ति के रूप में आ गए हैं । इस साल हमारा जो कार्यकाल चल रहा है, इसी सदन में बात आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को विश्वास दिलाया है कि हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं ।

मान्यवर, केवल तीन देश होंगे, दो देश, उसके बाद तीसरा भारत । उस समय देश का क्या कायाकल्प हो जाएगा । मात्र दस सालों में ही कायाकल्प हो गया, जब तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे तब क्या कायाकल्प होगा, यह हम अंदाज लगा सकते हैं । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रबंधन और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि सातवीं बार उन्होंने बजट पेश करके दुनिया के सामने एक मिसाल रखी है । अगर प्रबंधन ठीक होता है तो किस तरह देश को आगे ले जाना चाहिए । एक समय था, हमारे देश के प्रमुख लोग जब बाहर जाते थे,

दूसरे-तीसरे दिन वहां के प्रमुख लोग या राष्ट्राध्यक्ष समय देते थे । आज वह समय आ गया है, जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, बकायदा प्रोटोकॉल में लोग वहां रहते हैं । पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका जैसे देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, पूरी तरह से वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने प्रोटोकॉल दिया, यह हमारे लिए गर्व की बात है । वहां के डायसपोरा भारतवंशियों को व्हाइट हाउस में भोजन कराया गया, यह सबसे बड़ी बात है । सभी को भोजन कराया गया, इस गौरव से हमारा दिल उछाल लेने लगा । जो कहीं हमें कुछ समझते नहीं थे, आज हम इतनी ऊँचाई पर उठ गए हैं । पहले जाते थे, दे दे बाबा, एक बंदूक दे दे, एक रॉकेट दे दे, ब्रह्मोस जैसी कोई और मिसाइल दे दे । लेकिन आज हम अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो गए हैं । यह माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रबंधन है, आज दुनिया हिल गई है ।

मान्यवर, अभी मैं देख रहा था, मॉर्गन स्टेनली ने पहली बार कहा है, जिसे आर्थिक विशेषज्ञ मानिए या अथॉरिटी मानिए, पहले यह था कि भारत की अर्थव्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती है । लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सत्ता संभाली, वर्ष 2014 से 2024 के बीच आज उन्हीं का स्टेटमेंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था है । जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसके बाद वर्ष 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे । हम विकसित राष्ट्र कैसे बनेंगे? नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि ताली बजायी, थाली बजायी, यह करते रहे, वह करते रहे, हमने ताली- थाली बजायी, महलों के अंदर बैठकर लोग गुनगुनाते रहे, उस समय देश का धुंआ देखते रहे ।

वर्ष 2047 में हम विकसित देश बनने जा रहे हैं, वैसे ही नहीं बन जाएंगे । उस पर काम भी चालू कर दिया है । इस पर काम क्या हुआ है? ? (व्यवधान) आप सुन लेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठे-बैठे टिप्पणी न करें ।

? (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट**:** वर्ष 2047 तक यह देश विकसित ऐसे ही नहीं बनेगा । ? (व्यवधान) जनसंख्या 165 करोड़ होगी । कितने शहर बनाए जांएगे? कितने पानी की आवश्यकता होगी? कितनी बिजली चाहिए? कितने स्कूल होंगे? कितने प्राइमरी स्कूल होंगे? कितने इंटरमीडिएट स्कूल होंगे? कितने डिग्री कॉलेज होंगे? कितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी? कितने अस्पताल होंगे? कितने मेडिकल कॉलेज चाहिए? कितने नर्सिंग कॉलेज चाहिए? कितने एक्स-रे ऑपरेटर्स चाहिए? कितनी लैब्स होंगी? कितने पैथोलॉजी एक्सपर्ट्स होंगे? कितने दवाई के स्टोर होंगे? कितनी रेल लाइनें होंगी? कितने वार्ड ब्याएज़ चाहिए? कितने तिपहिया और दुपहिया वाहन चाहिए? कितने हवाई जहाज चाहिए? कितनी बसें चाहिए? कितनी गाड़ियां चाहिए? कितनी कृषि भूमि होगी? सिंचाई के संसाधन क्या होंगे? कितने ऑक्सीजन प्लांट होंगे? कितने गैस, पेट्रोल और डीजल प्लांट्स चाहिए? कितने आवास चाहिए? कितने रेस्ट हाउसिस चाहिए? कितने फोन चाहिए? कितने रोजगारोन्मुख उद्योग चाहिए? इन तमाम चीजों पर अभी से काम चालू कर दिया है, तभी हम वर्ष 2047 में विकसित राष्ट्र बनेंगे?

माननीय सभापति जी, कहा गया कि बिहार में पुल टूटे, मोदी है तो संभव है, मुमकिन है । एयरपोर्ट की दीवार गिरी, मोदी है तो संभव है । मणिपुर जल रहा, मोदी है तो संभव है । यहां पर यह सब कहा गया । ? (व्यवधान) मणिपुर की स्थिति किसने की? आज तक वहां कौन था? किसने राज चलाया? इससे पहले किसकी सरकार थी? ? (व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं - मोदी है तो संभव है । जन-धन योजना, मोदी है तो मुमकिन है । कौशल भारत योजना, मोदी है तो मुमकिन है । मेक इन इंडिया, मोदी है तो मुमकिन है । स्वच्छ भारत मिशन,

मोदी है तो मुमकिन है । सांसद आदर्श ग्राम योजना, मोदी है तो मुमकिन है । श्रमेव जयते, मोदी है तो मुमकिन है । बेटी बचाओ, बेटी बचाओ योजना, मोदी है तो मुमकिन है । हृदय योजना, मोदी है तो मुमकिन है । पीएम मुद्रा योजना, मोदी है तो मुमकिन है । उजाला योजना, मोदी है तो मुमकिन है । प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मोदी है तो मुमकिन है । पेंशन योजना, मोदी है तो मुमकिन है । जीवन ज्योति बीमा योजना, मोदी है तो मुमकिन है । स्मार्ट सिटी योजना, मोदी है तो मुमकिन है । अमृत योजना, मोदी है तो मुमकिन है । डिजिटल इंडिया मिशन, मोदी है तो मुमकिन है । स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, मोदी है तो मुमकिन है । उदय योजना, मोदी है तो मुमकिन है । स्टार्टअप इंडिया, मोदी है तो मुमकिन है । सेतु भारत योजना, मोदी है तो मुमकिन है । उठो भारत योजना, मोदी है तो मुमकिन है । ग्रामोदय से भारत उदय योजना, मोदी है तो मुमकिन है । प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, मोदी है तो मुमकिन है । नमामी गंगे योजना, मोदी है तो मुमकिन है । सतत योजना, मोदी है तो मुमकिन है । प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मोदी है तो मुमकिन है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** कृपया, आप अपनी बात समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट**:** कोरोना में फ्री वैक्सीन, मोदी है तो मुमकिन है । प्रधान मंत्री सड़क योजना, मोदी है तो मुमकिन है । 80 करोड़ लोगों को राशन देना, मोदी है तो मुमकिन है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** अब आप बैठ जाएं ।

सप्तगिरी शंकर उलाका जी ।

? (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट**:** जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना, मोदी है तो मुमकिन है । अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना, मोदी है तो मुमकिन है । वाराणसी में ज्योतिर्लिंग, मोदी है तो मुमकिन है । ? (व्यवधान)

श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव **(**पंचमहल**) :** मैं बजट 2024-25 पर अपने विचार रखता हूँ । मैं बजट वर्ष 2024-25 का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं ।

हमारे दूरदर्शी यशस्वी माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट वर्ष 2024-25 प्रस्तुत किया है । पिछले दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक परिवर्तनों को देखा है । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत समृद्धि की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के द्वारा आगे बढ़ा है । इसमें देश के विकास के निम्न सभी मुद्दे शामिल हैं ।

· अन्नदाता के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

· कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता

· महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए

· शहरी विकास

· उद्योग और व्यापार

· देश के एससी, एसटी और ओबीसी के उत्थान के लिए

· युवा के विकास

· सभी प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर

· रेलवे विकास

· महिला और बाल विकास

· श्रमिक के लिए सहायता

· स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोत्तरी

· शिक्षा में प्रगति और रोजगार के लिए प्रावधान

· मानव संसाधन विकास

· ऊर्जा सुरक्षा और नवीनीकरण

· इनोवेशन और रिसर्च के लिए विशेष प्रावधान

· हिंदुस्तान की नई पीढ़ी के लिए स्पष्ट आयोजन

· गरीब और मध्यम वर्ग की सुविधा के लिए आयोजन

· कृषि विकास

· पीएम आवास योजना का आयोजन

· पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास

· औद्योगिक पार्क का आयोजन

· जल संरक्षण और आपूर्ति आयोजन

· ग्राम आयोजन

माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी सरकार हिस्ट्री के साथ की जाने वाली आर्थिक परिवर्तन को जानती है, संकटों को पार करती है और अर्थव्यवस्था को सतत विकास के पथ पर रखती है । पिछले दशक के उत्कृष्ट रिकार्ड ने विश्वास और समर्थन कमाया है जिससे सरकार का विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मार्गदर्शन हुआ है ।

अंत में मैं फिर एक बार दूरदर्शी यशस्वी माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बजट 2024-25 प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं ।

मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं ।

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका (कोरापुट) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं ।

मैं सबसे पहले बजट के बारे में बोलूंगा । माननीय सदस्य ने जिन 50 स्कीम्स के बारे में बोला है, ये यूपीए की स्कीम्स हैं, नाम बदलकर बोल रहे हैं । आप पता करें कि कितनी स्कीम्स यूपीए की हैं, ये नाम बदलकर बोल रहे हैं कि भाजपा की स्कीम्स हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको अलाऊ किया है, आप चेयर को एड्रेस करें । आप मैम्बर को इस तरह से नहीं बोल सकते ।

? (व्यवधान)

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: यह बजट बहुत ही कमजोर बजट है । This is because they have reduced from 303 to 240. ? (*Interruptions*) That is why, they have been forced to deliver such a subdued Budget. ? (*Interruptions*) हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा आर्थिक मदद दी है । The main problem is that you should not discriminate against other States. ? (*Interruptions*) अगर किसी स्टेट को मिलना चाहिए तो ओडिशा को मिलना चाहिए । In the last 11 years, there have been 16 catastrophes, cyclones and super-cyclones. हर साल साइक्लोन आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है । अगर कोई स्टेट स्पेशल कैटेगिरी डिजर्व करता है तो ओडिशा डिजर्व करता है । ? (व्यवधान)

HON.CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Saptgiri Ulaka ji.

(Interruptions) ? *

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: बात, पोलावरम डैम, जिसे नैशनल प्रोजेक्ट स्टैटस आपने दिया है, उसका यदि अभी निर्माण होता है, तो मेरे मलकानगिरि के 162 गांव हजारों एकड़ लैंड, सब मर्ज हो जाएंगे । इसमें न एनवायरमेंट क्लीयरेंस मिला है, न ही आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कोल डिपॉजिट ये सारी चीजें डूबेंगी । So, the Polavaram Dam is not to be taken up. यह होगा, तो ओडिशा का मलकानगिरि जिला, बहुत सारे आदिवासी एरियाज मर्ज होंगे । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : संसदीय कार्य मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : आज सदन में वायनाड की प्राकृतिक आपदा की घटना को लेकर जो डिमांड आई थी, हमारे गृह राज्य मंत्री उस रिपोर्ट को सदन के सामने रखने के लिए तैयार हैं । जब आप उचित समझेंगे, तो वह टेबल पर रख देंगे । उसके बाद कॉपी अपलोड करके सारे मेंबर्स को दे देंगे । यह टेबल करने की इजाजत दीजिए ।

माननीय सभापति : सप्तगिरी जी की स्पीच हो जाए, उसके बाद ।

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: सर, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं ।

माननीय सभापति : सब रिकॉर्ड में जा चुका है । Do not repeat it. Whatever you have said is already on record.

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: ठीक है सर, मुझे कॉंटीन्यू करने दीजिए । ? (व्यवधान) एक तो एक स्पेशल कैटेगरी ओडिशा को मिलनी चाहिए । We deserve it. बहुत सारे साइक्लॉन्स आते हैं । दूसरा, पोलावरम डैम यदि बनेगा तो मलकानगिरी जिले के 162 गांव सबमर्ज होंगे । हजारों एकड़ लैंड सबमर्ज होंगी । कोई पब्लिक हियरिंग नहीं हुई । यह दादागिरी नहीं चलेगी । आंध्र, बिहार को आप पैसा दीजिए, लेकिन ओडिशा के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए । तीसरी बात, मेरे एक कलीग यूपीए टाइम में रेल लाने के लिए बोले थे । मैं आपको उदाहरण देता हूं । राएला रेल डिवीजन को 2017-18 में डिक्लेयर किया गया । 15-20 प्रश्न यहां पूछ चुके हैं । मंत्री जी से बात की, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है । अभी रिक्वेस्ट करके मैंने बोला कि 70 करोड़ का आवंटन करके रायगड़ा रेल डिवीजन बनाया जाए । गुरुपुत्र रेल लाइन 15 प्रश्न जीरो ऑवर व नियम-377 के अधीन मामलों में उठा चुका हूं, लेकिन कुछ नहीं होता । कभी बोलते हैं कि राज्य सरकार पैसा देगी, कभी बोलते हैं केंद्र सरकार पैसा देगी । ऐसे ही चलता रहता है । केंद्रीय विद्यालय, जाजपुर का मुद्दा मैं पिछले सदन में 20 बार उठा चुका हूं । ओडिशा के साथ यह अन्याय हो रहा है । एनडीए, भाजपा की सरकार बार-बार करती आ रही है । एम्स, संभलपुर, मेरी नहीं, आपकी ही डिमांड थी, एम्स संभलपुर, सरकारी मेडिकल कॉलेज रायगड़ा की हम डिमांड करते आ रहे हैं । कुछ भी नहीं हो रहा है । एक्सप्रेसवे को आप राशि दे रहे हैं । भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 348 किलोमीटर उन्हीं की सरकार ने बोला था कि हमें चाहिए, लेकिन यह भी नहीं मिल रहा है । ओडिशा कैपिटल रिंग रोड रिजन, आदिवासियों के बारे में ये बोल रहे हैं कि this is helping the tribals. I will give you one example. The proposed Critical Mineral Mission and the auctioning of offshore blocks for mining starkly overlooks the dire consequence. माइनिंग का एक-एक करके आप ऑक्शन कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि एक नई स्कीम ले आए कि 63 हजार गांवों के लिए 5 करोड़ ट्राइबल हैबिटेट देंगे । एक तो हमारे पहाड़, जंगल, जमीन सब बेचकर आप ऑक्शन करेंगे । ग्राम सभा नहीं है, कुछ भी नहीं है । हम लोगों को पैसे से बेदखल कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि हम स्कीम लाएंगे । एंटरिम बजट और इस बजट में यह अंतर है कि एंटरिम बजट में 1 लाख 21 हजार करोड़ 23 रुपये ट्राइबल्स के लिए सैंक्शन किए गए थे । इस बजट में 1 लाख 24 हजार नौ सौ नौ रुपये सैंक्शन किए गए । ये पैसा कहां से आया? आप बोल रहे हैं कि आदिवासियों के लिए प्रधान मंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान करेंगे । आप कैसे करेंगे, जब पैसा ही नहीं है । यह काफी अन्याय वाला बजट है । हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है । कुछ सुझावों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

Coming to long-term capital gain, सर, जब आप नया टैक्स रिजीम लेकर आते हैं, तो Long-term capital gain कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए खराब है, but this is something which you can give a leeway to. कम से कम तीन साल तो दीजिए । जो नई टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, वे लॉंग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन हटाकर जाएं, जो नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाएं । रोजगार के बारे में अंत में बोलना चाहता हूं कि जो आप एक करोड़ इंटर्नशिप देने की बात कर रहे हैं, 95 per cent of the jobs are in the information sector. जब तक एमएसएमई को आप स्ट्रेंग्थेन नहीं करेंगे, जीएसटी में सुधार नहीं करेंगे, तब तक आप नौकरी दे नहीं सकते हैं । आदिवासियों के साथ आप जो अन्याय कर रहे हैं, अपने माइन्स बेचकर जो छोटी-मोटी स्कीम आप दे रहे हैं, वह काफी नहीं है । धन्यवाद ।

श्रीमती मालविका देवी (कालाहाण्डी) : मैं बजट पर अपने विचार रखने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करती हूं । साथ ही कालाहांडी ही नहीं, बल्कि समस्त उड़ीसा की अनुग्रहित जनता की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद । उन्होंने उडीसा की विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु बजट के आवंटन के साथ-साथ "पूर्वोदय योजना" के माध्यम से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने एवं समस्त पूर्वी क्षेत्र के विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है ।

यह बजट राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का बजट है । फिर चाहे बात जल, जंगल या जमीन की हो या शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई एवं पर्यटन के विकास की, हर क्षेत्र का व्यापक स्तर पर सूक्ष्म अवलोकन करते हुए बड़े ही वैज्ञानिक एवं समावेशी तरीके से वित्तीय आवंटन किया गया है ।

यदि हम उड़ीसा की बात करें तो केन्द्र सरकार के रेल बजट में इस बार ओडिशा पर विशेष ध्यान दिया गया है । रेल बजट में ओडिशा सरकार ने 8400 करोड़ रुपए की मांग की थी । हालांकि, केन्द्र सरकार ने ओडिशा को इससे कहीं अधिक राशि दी । 10 हजार 12 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं । जबकि 2022-23 के आर्थिक वर्ष में ओडिशा को सिर्फ 9 हजार 734 करोड़ रुपये का ही अनुदान मिला था । इस राशि का उपयोग कर अनुगुल-सुकिन्दा (200 करोड़ रुपये), खुर्दा-बलांगीर के लिए (1599 करोड़ रुपये), सम्बलपुर-तालचेर (78 करोड़ रुपये), हरिदासपुर-पारादीप (50 करोड़ रुपये) आदि लगभग 30 रेल-खंडों के विकास एवं संवर्द्धन के लिए किया जाएगा इसके साथ साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष में ओडिशा में करीब 280 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

ओडिशा में पर्यटन हब बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी की पहल, जिसमें उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ओडिशा की प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, स्मारक, शिल्प कौशल, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक परिदृश्य और प्राचीन समुद्र तट इसे एक परम पर्यटन स्थल बनाते हैं और उनके विकास के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा । विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

यदि हम संपूर्ण बजट पर एक समग्र दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, संकल्पशक्ति और विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है ।

केन्द्रीय बजट वर्ष 2024-25 में नौ बुनियादी प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करके 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के साथ साथ, भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए तैयार की गई है ।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है और किसान इसके मूलाधार हैं । आज का बजट ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति में नए आयामों को स्थापित करने वाला है । साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा ।

यह बजट किसान, महिला, युवा और गरीब लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है । साथ ही किसानों की आय को बढ़ाने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास का संकल्प और मजबूत करने वाला बजट है ।

कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं । कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता पहली प्राथमिकता है । खेती के उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल 32 फसलों की 109 किस्में जारी होंगी तथा जलवायु अनुकूल फसलों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा का प्रावधान है ।

ग्रामीण विकास के लिए बजट में बड़े निर्णय हैं । ग्रामीण बहनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा । साथ ही ग्रामीण विकास (ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए 2.66 लाख करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है । पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनेंगे, ग्रामीण और शहरी मिलाकर और इसके लिए जरूरी आवंटन किया गया है । महिलाओं, बालिकाओं संबंधी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गए हैं, जो कि अभूतपूर्व है ।

भारत सरकार ने रोजगार क्षमता बढ़ाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न व्यापक पहलों के माध्यम से कौशल विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है । केन्द्रीय बजट 2024-25 के तहत एक उल्लेखनीय विशेषता राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना की घोषणा है । इस योजना का उद्देश्य पाँच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उन्नत करना है ।

इसके अतिरिक्त, मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकार की गारंटी के साथ ₹ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा दी जा सके, जिससे सालाना 25,000 छात्रों को लाभ होगा । ऐसे लोग जो मौजूदा योजनाओं का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं, उन्हें घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें ई-वाउचर प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों के लिए 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर में छूट प्रदान करेंगे ।

जल जीवन मिशन ने 5 साल की छोटी सी अवधि में 3 करोड़ से 15 करोड़ ग्रामीण नल कनेक्शनों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की तथा 2.28 लाख गांवों और 190 जिलों ने 'हर घर जल' का दर्जा हासिल किया । देश में 88.91 प्रतिशत स्कूलों और 85.08 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों में नल का पानी पहुंचा है, जिससे इन बच्चों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है । इस स्वर्णिम उपलब्धि ने न केवल हमारे देशवासियों को शुद्ध जल का उपहार दिया है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी अहम सुधार किया है ।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भारी जन समर्थन मिला है, जिसमें 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 14 लाख आवेदन पहले ही जमा हो चुके हैं । छतों पर सौर पैनल लगाने की सुविधा के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिससे एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी ।

यह बजट देश के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा यह नारी शक्ति के सामर्थ्य व हौसले को नई ऊंचाई देने वाला है ।

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की घोषणा परिवर्तनकारी सिद्ध होगी तथा 'राष्ट्रीय सहकारी नीति' सहकारी आंदोलन को सशक्त और जमीनी स्तर पर इसकी पहुँच को मजबूत करेगी साथ ही यह बजट MSME क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा । पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से जनजातीय समाज के 63 हजार गाँवों का विकास सुनिश्चित होगा।

अवयस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना 'वात्सल्य' की घोषणा की गई है । इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे । वयस्कता की आयु होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा । केन्द्रीय बजट में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर अगले 10 साल में 5 गुनी करने के लिए ₹1,000 करोड़ रुपये के एक वेंचर कैपिटल फंड का ऐलान किया गया है ।

मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है । रेसिस्टरों के विनिर्माण के लिए ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर सीमा शुल्क खत्म करने और कनेक्टरों के विनिर्माण के लिए कुछ पार्ट्स पर सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव है ।

रक्षा बजट में 6.21 लाख करोड़ का आवंटन का ऐतिहासिक आवंटन समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' की ओर बढ़ने में मदद करेगा । साथ ही यह सशस्त्र बलों को और सुदृढ़ करेगा तथा रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देगा । बजट में टैक्स में छूट और नियमों के सरलीकरण से करदाताओं को बहुत आसानी होगी और यह बजट विकसित भारत के संकल्प को अक्षरशः साकार कर सकेगा ।

मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि यह बजट मोदी सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है, जो न सिर्फ वर्तमान की गंभीर समस्याओं के निस्तारण का संकल्प प्रस्तुत करता है वरन् एक स्वर्णिम भविष्य की उम्मीद भी जगाता है ।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : बजट 2024-2025 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद ।

मै हमारे यशस्वी प्रधानमन्त्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमे देश के हर नागरिक की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया हैं ।

जैसा की हम सभी जानते है की मोदी सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए हमेशा अथक प्रयास किए हैं, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना है । परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण, शहरी सुविधाओं के उन्नयन और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, माननीय वित्त मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया है जिसमे देश के राजमार्गों, रेलवे और हवाई अड्डों के विकास से लेकर जलमार्गों और रोपवे सिस्टम को बढ़ावा देने तक, हर संभव प्रयास देश भर में समावेशी और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे हैं । पिछले 10 वर्षों में भारत ने अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनमें दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, अटल सुरंग, और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, चेनाब पुल का उद्घाटन भी शामिल है ।

भारत के लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लगातार तीसरी बार अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनके नेतृत्व वाली इस सरकार को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है । हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प हैं कि सभी धर्म, जाति, लिंग और आयु के भारतीय अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति करें ।

इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन किए हैं, जिससे हमारे देश की जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । प्राथमिकता देते हुए, इस बजट ने गरीबी को कम करने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को प्रस्तुत किया है । यह स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम है ।

इसके अतिरिक्त, भारत ने विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना जैसे आइकोनिक landmarks से रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और लद्दाख में सभी मौसमों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एशिया की सबसे लंबी सुरंग, जोजिला सुरंग जैसे परिवर्तनीय प्रोजेक्ट्स पर काम किया है । इसके अलावा, मुंबई में अटल सेतु, ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील ब्रिज, पूर्वोत्तर में जैसवाल ब्रिज और ढोला-सादिया ब्रिज जैसे वास्तुशिल्प उत्कृष्टता के साथ, न्यू इंडिया की अवसंरचना परिदृश्य अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रही है । यह सभी निर्माण कार्य यह बखूबी दर्शाते है की सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी तेजी से डेवेलोप कर रही है ।

भारत के रेलवे नेटवर्क में उन्नति: भारत का रेलवे विकास आधुनिकता और सुधारित कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है, जो सरकार द्वारा देश की प्रगति के लिए परिवहन अवसंरचना को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है ।

वंदे भारत ट्रेनों के माध्यम से रेलवे यात्रा का आधुनिकीकरण: वंदे भारत ट्रेनें भारत की रेलवे अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उन्नत सुरक्षा विशेषताओं, तेजी से त्वरित गति और सुधारित यात्री सुविधाओं के साथ हैं । स्वचालित प्लग दरवाजों, रीक्लाइनिंग एर्गोनोमिक सीटों और प्रत्येक सीट के लिए मोबाइल चार्जिंग सॉकेट से सुसज्जित, ये ट्रेनें आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करती हैं । 31 जनवरी 2024 तक, भारतीय रेलवे पर 100 से अधिक वंदे भारत ट्रेन सेवाएँ संचालन में हैं,

महोदय 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया है । इससे न केवल अधिकांश राज्यों को वंदे भारत ट्रेनों का लाभ मिला है बल्कि वंदे भारत ट्रेनों का शतक भी पूरा हो चुका है ।

भारत के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास: अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए किया गया है । इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों के विकास को निरंतर आधार पर एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ लागू करना है । इस योजना ने 1318 स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए चयन किया है ।

भारत के रेलवे का विद्युतीकरण: परिवहन के एक पारिस्थितिकीय, तेज और ऊर्जा-कुशल तरीके के रूप में, भारतीय रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर अग्रसर हो रहा है । दिसंबर 2023 तक कुल 61,508 किमी ब्रॉड गेज नेटवर्क को इलेक्ट्रिफाई किया गया है, जो भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क (65,556 आरकेएम) का 93.83% है । 2014 तक, ब्रॉड गेज नेटवर्क का 21,801 किमी इलेक्ट्रिफाई किया गया था ।

भारत की मेट्रो रेल का विस्तार: भारत की मेट्रो रेल प्रणाली का विस्तार शहरी यातायात को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है, जिसका नेटवर्क 2014 में 248 किमी से बढ़कर 2024 तक 945 किमी हो जाएगा । यह महत्वपूर्ण वृद्धि मेट्रो रेल के शहरी जनसंख्या को परिवहन की सुविधा देने की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, जिसमें लगभग 1 करोड़ यात्री दैनिक लाभान्वित होते हैं । 2014 में सिर्फ 5 शहरों से, मेट्रो रेल नेटवर्क अब 21 शहरों तक विस्तारित हो चुका है, और 26 अतिरिक्त शहरों में 919 किमी की लाइनों का निर्माण जारी है । इसके अतिरिक्त, दिल्ली-Meerut RRTS (Regional Rapid Transit System) गलियारे पर भारत की पहली अत्याधुनिक नमो भारत ट्रेन की शुरुआत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और परिवहन अवसंरचना को आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है ।

इस बजट ने व्यापारिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे व्यापार और उद्योगों को विकास के लिए उत्तेजित किया जा सकेगा । इससे आर्थिक वृद्धि होगी और नये रोजगार के अवसर बनेंगे ।

इस बजट के माध्यम से हम यह भी देख सकते हैं कि सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नए पहलू दिए हैं । जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नई योजनाएं और नीतियाँ अग्रसर की गई हैं ।

देश में आदिवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में PM- JANMAN योजना की घोषणा की है जिसके तहत आदिवासी एवं विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में पहचाने जाने वाले पीवीटीजी जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में कमज़ोर माने जाते हैं ऐसे आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लगभग 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा ।

भारत के जलमार्गों का उपयोग: भारत के जलमार्गों में महत्वपूर्ण विकास देखा गया है, जिसमें 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों (NW) के रूप में मान्यता दी गई है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत किया गया है । यह मान्यता कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, व्यापार को प्रोत्साहित करने और देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामान और यात्रियों के परिवहन को सहज बनाने का लक्ष्य रखती है ।

सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से विकास की दिशा में बढ़ते कदम: सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य पोर्ट-लेड विकास को प्रोत्साहित करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और आर्थिक वृद्धि को तेज़ करना है । कार्यक्रम में मौजूदा बंदरगाहों और टर्मिनलों का आधुनिकीकरण, बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार, मछली पकड़ने के बंदरगाह, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी केंद्रों जैसी विभिन्न श्रेणियों के परियोजनाओं को शामिल किया गया है । सागरमाला कार्यक्रम के तहत 839 परियोजनाओं के लिए लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है । इनमें से, 241 परियोजनाओं को लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है । अब तक, सागरमाला योजना के तहत कुल 171 परियोजनाओं को आंशिक वित्तपोषण के लिए समर्थन मिला है । 171 परियोजनाओं में से 55 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं ।

इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई (MSME) और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं । रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की गई, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है । इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है । इस बजट में मा. वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है की हम अगले दो वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि (Natural Farming) के लिए सहायता दी जाएगी जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी । इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा । 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र (bio-input resource centres) स्थापित किए जाएंगे । सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाई जा रही है । इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ।

PMGSY के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी को बदलना: भारत ने ग्रामीण सड़क अवसंरचना में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है, जिसमें 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 3.74 लाख किमी सड़कें

निर्माण की गई हैं । इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप 99% से अधिक ग्रामीण बस्तियाँ जुड़ गई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । अब तक, 2013-14 की 3.81 लाख किमी सड़कें की तुलना में 7.55 लाख किमी ग्रामीण सड़कें पूरी हो चुकी हैं ।

हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री पैकेज के भाग के रूप में 'रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन' के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है जिससे ईपीएफओ (EPFO) में नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिह्नित करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे । इस योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा । ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन किस्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 होगा । इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा 1 लाख का मासिक वेतन होगा । इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है । सरकार द्वारा उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे । इसके अतिरिक्त, इस साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्व- सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे ।

प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की गई । 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा । हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा । उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार की जाएंगी और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे ।

इसी तरह हमारी सरकार ने घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे जिससे कई लोगों को लाभ मिलेगा । इस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आबंटन किए जा रहे हैं । देश में महिला-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं हेतु 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आबंटन की व्यवस्था की गई है ।

प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, जनजातीय- बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज करते हुए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेंगे । इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।

हमारी सरकार ने मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है ।

देश में एमएसएमई के अंतर्गत सिडबी द्वारा 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवाएं देने हेतु अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोली जाएंगी जिससे लाभार्थियों को सीधे ऋण प्राप्त होगा । इस वर्ष ऐसी

24 शाखाएं खोले जाने के साथ ही सेवा कवरेज का विस्तार 242 प्रमुख क्लस्टरों में से 168 क्लस्टरों तक हो जाएगा और साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत 5 वीं योजना के रूप में, आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत करेगी । इस योजना में 5,000 प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 की एकबारगी सहायता दी जाएगी जिससे काफी लोगो को आर्थिक लाभ मिल सकेगा ।

सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी से भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास है । इस परियोजना से उपचारित जल का प्रयोग सिंचाई तथा आस-पास के क्षेत्रों में तालाबों को भरने के लिए भी परिकल्पना की जाएगी । यह बजट हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया एक सर्वजन हिताय बजट है । यह बजट देश के हर वर्ग के विकास एवं सामान्य जीवनशैली की हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के विकास को समर्पित इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद ।

डॉ. विनोद कुमार बिंद (भदोही) : केंद्रीय बजट 2024-25 में देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 90,958.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । 23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार, सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 87,656.90 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 3,301.73 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं । केंद्र की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को 6800 करोड़ रुपये के पिछले आवंटन की तुलना में 7,300 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है । हालांकि, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जिसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के नाम से जाना जाता है, के लिए बजट आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है, क्योंकि बजट आवंटन 200 करोड़ रुपये पर ही बना हुआ है । सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के लिए बजट आवंटन ₹2295.12 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,732.13 करोड़ कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, कैंसर के उपचार के लिए तीन दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट जीवन रक्षक उपचारों को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए एक केंद्रित प्रयास को दर्शाता है । ये कार्य सभी के स्वास्थ्य की दिशा में सराहनीय कदम हैं ।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन यह है कि हाल ही में बजटीय आवंटन में 4,400 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है - पिछले साल के 11,258 करोड़ रुपये से इस साल 15,928 करोड़ रुपये तक । अनुमान के मुताबिक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बजट में पिछले साल की तुलना में 28% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है । केंद्रीय बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । शिक्षाविदों ने, अधिकांश भाग के लिए, नए कदम का स्वागत किया है और दावा किया है कि यह अधिक नौकरी के लिए तैयार कार्यबल का मार्ग प्रशस्त करेगा, परिसर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा और छात्रों के बीच नवीन विचारों को प्रोत्साहित करेगा ।

केंद्रीय बजट 2024 ने कई पहलों की घोषणा की है जो शैक्षिक परिदृश्य को बदलने का वादा करती हैं: वित्तीय सहायताः 3% ब्याज सब्सिडी के साथ उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण । घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी । राज्य सरकारों और

उद्योगों के सहयोग से कौशल विकास के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना । पांच साल की अवधि में करीब 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा । कौशल विकास: 1,000 आईटीआई का उन्नयन और कौशल ऋण योजनाओं में संशोधन । इंटर्नशिप के अवसरः पांच वर्षों में शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ इंटर्नशिप । इन प्रशिक्षुओं को 5000 रुपये वजीफा और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता मिलेगी । कंपनियां अपने सीएसआर फंड से सरकार की इंटर्नशिप योजना का खर्च वहन करेंगी ।

शोध को बढ़ावा: अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष का संचालन ।

केंद्रीय बजट 2024 के फरवरी संस्करण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा था कि पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों और STEM पाठ्यक्रमों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का प्रभाव बताया ।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद । माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट ने स्पष्ट रूप से "विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के सरकार के संकल्प को दर्शाया है ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई 2024 को 2024-25 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें हमारी सरकार की नौ प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है ।

बजट 2024-25 यह स्पष्ट करता है कि सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि सभी भारतीय, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग या आयु के हों, अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण प्रगति करें और विकास की ओर बढ़ें ।

यह केंद्रीय बजट 2024-25 रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है । शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन करके, हम एक उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे हैं । यह निवेश हमारे युवाओं को सशक्त बनाएगा, उनके कौशल को बढ़ाएगा और कई रोजगार के अवसर पैदा करेगा ।

हमारे किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, इस बजट ने उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है । बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । 109 उच्च उपज वाली फसल किस्मों को जारी करने, 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और 10,000 जैव-इनपुट केंद्र स्थापित करने के साथ, बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को कृषि में लागू करने की बात भी की गई है. जिसमें देश भर के किसानों और उनकी जमीनों को तीन साल में शामिल किया जाएगा । डीपीआई का उपयोग करके, 400 जिलों में चल रहे खरीफ सीजन का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा । अपने बजट भाषण में, निर्मला सीतारमण जी ने उल्लेख किया है कि सरकार "पायलट परियोजना की सफलता से उत्साहित है, और सफलता यह राज्यों के साथ साझेदारी में डीपीआई के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी । यह कदम एक समग्र विकास को बढ़ावा देने और उत्पादकता में सुधार के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिससे देश की 40% से अधिक आबादी को आजीविका प्रदान करने वाले क्षेत्र को और अधिक प्रगति मिलेगी ।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं और कौशल विकास को बढ़ावा देने की पहल का परिचय देना महत्वपूर्ण है । पांच साल में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करने का लक्ष्य हमारे युवाओं को नौकरी की सुरक्षा के बारे में आश्वासन प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं.

उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और संशोधित मॉडल स्किल लोन पोजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा 25,000 छात्रों को वार्षिक लाभ प्रदान करेगी, जिससे हमारे छात्रों को ऊंची उड़ान भरने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी ।

सरकार ने स्वास्थ्य पर मजबूत फोकस सुनिश्चित किया है, जो विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है । स्वास्थ्य पर कुल व्यय को संशोधित कर 289,287 करोड़ कर दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न उद्योगों में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर बजट व्यय को 2023-24 में 2840 करोड़ से बढ़ाकर 2024-25 में 21,200 करोड़ कर दिया गया है ।

इसके अलावा, कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने तीन दवाओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव किया है ।

भारतीय रेल, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और माल और यात्री परिवहन का मुख्य साधन है, के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22.55 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है । यह पिछले साल ल के आवंटन 22.41 लाख करोड़ से 5.85% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है । इन फंडों का उपयोग सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और कोचों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाएगा ।

माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देते हुए मेरे लोकसभा क्षेत्र मालदा उत्तर में पांच रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है । और मालदा टाउन से बैंगलोर के लिए अमृत भारत ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को र को रवाना की गई । माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में तीन नई रेल आवश्यक है । जो इस प्रकार है । लाइन का विस्तार करना अति आवश्यक है । जो इस प्रकार है ।

नई रेल पटरियों के निर्माण का प्रस्ताव -

1. बुलबुलचंडी रेलवे स्टेशन से केंदपुकुर, पाकुवाहाट और नालागोला होते हुए गंगारामपुर रेलवे स्टेशन तक,

2. गाजोले से गुंजारिया वाया इटाहार

3. सामसी से बारसोई होते हुए वाया चाचल

माननीय श्री वैष्णव जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र मालदा उत्तर के विकास और परिस्थिति से परिचित है. अजादी के 75 साल बाद भी यह क्षेत्र देश के अविकसित क्षेत्रों में से एक है. इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित नई रेल पटरियों के निर्माण का प्रस्ताव किया जाता है ।

1. बुलबुलचंडी रेलवे स्टेशन से गंगारामपुर रेलवे स्टेशन तक केंदपुकुर, पाकुआहाट और नालागोला होते हुए इस मार्ग पर रेल पटरियों का निर्माण कि आवश्यकता है । इस मार्ग से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा ।

2. गाजोल से गुंजरिया तक इटाहार को भी इस रेलवे लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है । यह मार्ग क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण होगा तथा स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा ।

3. इस मार्ग से समसी से बारसोई चंचल को भी इस रेलवे लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है। इस रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्रीय संपर्क में सुधार होगा तथा यात्रा सुगम होगी ।

ये प्रस्तावित रेल पटरियां क्षेत्र के विकास तथा हमारे क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा के लिए तथा यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत सहायक होंगी । आपसे अनुरोध है कि इन प्रस्तावों पर विचार करने का कृपा करें ।

आर्थिक प्रगति की बात करें तो, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर एंजेल टैक्स का उन्मूलन रहा है । यह डीप टेक स्टार्टअप्स की लंबे समय से चली आ रही मांग है, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है ।

इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, वित्त मंत्री ने 'क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी' के विकास की घोषणा की, जिससे जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी । इस पहल से भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और हरित परिवर्तन की सुविधा मिलेगी । यह निवेशकों और बैंकों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावशाली निवेश की दिशा में महत्वपूर्ण धनराशि निर्देशित करने में मदद करेगा ।

प्रसंस्करण और परिशोधन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास का समर्थन करने के लिए, सरकार ने 25 आवश्यक खनिजों पर आयात शुल्क हटा दिया है और दो अतिरिक्त खनिजों पर लेवी को कम कर दिया है । इस कदम का उद्देश्य उन घरेलू उद्योगों के लिए इनपुट लागत को कम करना है जो इन खनिजों पर निर्भर हैं । इसके अलावा, यह कदम वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल से जुड़े आयात निर्भरता और आपूर्ति जोखिमों से भारत की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है ।

इसके अतिरिक्त, बजट में 40 मिलियन से अधिक वेतनभोगी व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा क्योंकि सरकार ने आयकर दरों को समायोजित किया है ।

मैं पूरे सम्मान के साथ यह तथ्य सामने लाना चाहता हूं कि भारी बारिश और नदी की गहराई में कमी के कारण गंगा, फुलहर और कोशी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और रतुआ । ब्लॉक के अंतर्गत खासमोहोल, नसीरुद्दीन टोला, भाषा राम टोला कानतु टोला, महानंदा टोला और भिलाई मारी पंचायतों के जैसे गांवों के नदी किनारे के आवासों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जिसमें 300 से अधिक परिवार गंगा, फुलहर और कोशी कटाव से प्रभावित हुए हैं ।

जबकि हरिश्चंद्रपुर- । । ब्लॉक के उत्तर और दखिन भकुरिया, रशीद पुर जैसे गांव जिनमें लगभग 135 से अधिक परिवार फुलहर से प्रभावित हुए हैं । उपरोक्त सभी ग्रामीण दुर्भाग्यवश तीनों नदियों के कहर के कारण अपने घरों से विस्थापित होकर सड़कों पर आ गए हैं । इन सभी लोगों को यथाशीघ्र उचित राहत एवं मुआवजा देकर पुनर्वासित किया जाना चाहिए ।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत, पश्चिम बंगाल को छोड़ कर देश के सभी राज्यों में लागू हैं, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब परिवार स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही निकृष्ट राजनीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है ।

भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण कमिटी दिशा, जिसकी एक भी बैठक पश्चिम बंगाल में आज तक नहीं हुई है. जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में विकास योजनाएं ठप हो गई है, यह पश्चिम बंगाल सरकार के दोहरे चरित्र को साफ़ दर्शाता है ।

यह बजट जन समर्थक और विकास समर्थक है और यह सरकार की लोगों के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाता है । में इस बजट के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिस कारण एक जन जातिय महिला आज देश के राष्ट्रपति पद पर आसिन है ।

मैं भी जनजाति वर्ग से संबंध रखता हूं लेकिन मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं है । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और अनारक्षित सीट पर मुझे दूसरी बार विजय श्री मिली, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित कि गई है । इस दिन भारत के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है ।

श्री शशांक मणि (देवरिया) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट पर कुछ वाक्य कहने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं । मैं देवरिया की जनता को और इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य को प्रणाम करता हूं ।

सभापति महोदय, इस बजट में हमारी सरकार के बनने के पीछे विकसित भारत की रणनीति का पूरा-पूरा समावेश है । इसमें हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय दीन दयाल जी की भावनाओं का भी पूर्ण रूप से समावेश है । इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ?मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट? की भावना है । मैं आदरणीया निर्मला सीतारमण जी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं और इस बजट का पूर्णत: समर्थन करता हूं ।

महोदय, इस बजट की चर्चा पर कई सदस्यों ने अपनी भावनाएं कुछ गणित आंकड़ों के माध्यम से की थी । मैं इस बजट को समझाने के लिए दो सिद्धांतों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक सिद्धांत है ? ?सबका प्रयास? और दूसरा सिद्धांत है ? ?एकात्म मानववाद? । सबका प्रयास कहता है कि हमारे देश के असंख्य नागरिक इस बजट से उत्प्रेरित होंगे । इस बजट से ही पिछले साल 8.2 प्रतिशत की बढ़त हमारी अर्थव्यवस्था को हुई थी । मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 7 प्रतिशत से ज्यादा बढ़त होगी और उसके होते-होते हम लोग अगले पांच सालों में पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे ।

आदरणीय सभापति महोदय जी, इस बजट की हर पंक्ति में सबका प्रयास निहित है । सबका प्रयास कहता है कि देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 100 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 18.7 लाख मतदाता मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया में हैं, उनकी हनुमत शक्ति को जगाने के लिए हम लोगों को अथक प्रयास करने पड़ेंगे ।

आदरणीय सभापति जी, इसमें मेरे क्षेत्र के हर एक नागरिक की ऊर्जा निहित है । यह बजट आज अधिकांश भारत यानी लगभग 80 करोड़ उभरते हुए नागरिक मध्यवर्गीय हैं । यह बजट इस मध्यवर्गीय भारत को उत्साहित करता है । सबके प्रयास में सामाजिक शक्ति, सरकार की शक्ति और बाजार से जुड़ने से देश की अर्थव्यवस्था केवल सरकारी निवेश पर निर्भर नहीं रहती है, बल्कि सरकार का निवेश समाज और उद्यमिता को वेग देता है । यह सोच विकसित भारत के लिए अति आवश्यक है । सबके प्रयास से ही हमारे देश ने कोरोना काल में अपनी डेफिसिट को 9.2 प्रतिशत तक सीमित रखा, जबकि पूरे विश्व में बड़े-बड़े देश 15 प्रतिशत डेफिसिट तक पहुंच गए थे ।

इसी के साथ ही साथ स्वच्छ भारत, जलजीवन मिशन अथवा चन्द्रयान-थ्री की उड़ान में सबके प्रयास की आभा निहित है । इस बजट में छोटे जिलों और शहरों में एमएसएमई में उत्साह जगाएंगे । नागरिकों को इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म मिलेगा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को संबल मिलेगा । यह बजट देवरिया की मालती यादव को प्रोत्साहित करेगा, आज की तारीख में मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये थी, अब वह 20 लाख रुपये हो गई है । मेरे संसदीय क्षेत्र में चौरसिया जी हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, यह उनको उत्साहित करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके समक्ष ?प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? के तहत 16,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे । वहां के ब्रिजेश तिवारी को उत्साहित करेगा, जब उनको मालूम पड़ेगा कि इस बजट में रेल में 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है ।

आदरणीय सभापति महोदय जी, आज की तारीख में 8.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश टेलीकॉम सेक्टर में होगा, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में लोग उद्यमिता को डिजिटल से भी आगे ले जाएंगे । सबका प्रयास एक कारण है कि हमारी फिस्कल डेफिसिट 5.6 प्रतिशत से 4.9 प्रतिशत तक आ गई है और अगले एक साल में 4.5 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी ।

दूसरा बिन्दु जो बजट में समाहित है ? ?एकात्म मानववाद की सोच? । यह 80 करोड़ उभरते मध्यवर्गों के लिए संजीवनी होगा । स्वतंत्रता के कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अपने नागरिकों को सब्जेक्ट के तौर पर देखा है । उनके दृष्टिकोण में नागरिक सिर्फ मतदाता और उपभोक्ता है । भारतीय जनता पार्टी और बजट में हर नागरिक उद्यमी और निर्माता भी है । ?इंडी? अलायंस इंडिपेन्डेंस के बाद डिपेन्डेंट बनाने का अलायंस है । इनका असली मायना डिपेन्डेंस है, ये नागरिकों को अपने पैरों पर खड़ा होने नहीं देना चाहते हैं । यह बजट उनकी सोच पर बहुत बड़ा प्रहार है । यह बजट देवरिया और कुशीनगर जैसे टियर ?टू? और टियर ?थ्री? जिलों में रहने वाले जाति-धर्म के परे भाजपा के समर्थकों के लिए है । कई सालों तक अंग्रेजी बोलने वाले बड़े शहरों में पले-बढ़े कांग्रेस के खानदानी लोगों ने देश पर राज किया है ।

सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आदरणीय शशि थरूर जी, आदरणीय महुआ मोइत्रा जी और आदरणीय दयानिधि मारन जी ने मलयालम, बंगाली और तमिल में बजट पर चर्चा की होती, तो शायद इस सदन और देश को ज्यादा शोभा देता । स्वतंत्र भारत का कटु सच तो यह है कि वही अंग्रेजी बोलने वाले वर्ग ने उन क्षेत्रों और नागरिकों को उपेक्षित रखा है, जहां स्वतंत्रता की असली लड़ाई लड़ी गई थी ।

यदि आप पूर्वांचल में देखेंगे, जहां से मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई जी निकली थीं, आज वही तिरस्कृत है । आज मोदी जी एक साधारण परिवार से उठकर आए हैं, उन्होंने उस सोच पर तगड़ा प्रहार किया है और एकात्म मानववाद से हर वर्ग को इस बजट से सुविधा मिली है ।

आदरणीय सभापति महोदय जी, किसानों के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये एवं रोजगार कौशल के लिए अगले पांच वर्षों में 4 करोड़ अधिक रोजगार दिए जाएंगे ।?(व्यवधान) मैं अंत में यही कहूंगा कि सबका प्रयास और एकात्म मानववाद के सिद्धांतों के विपरीत गरीबी हटाओ के विपक्ष के नारे खटाखट के वायदे करने वाले ?इंडी? गठबंधन का उद्देश्य इस देश को आर्थिक अराजकता की ओर ले जाना चाहता है । इनके होते-होते हमारी फिस्कल डेफिसिट की धज्जियां उड़ जाएंगी और हमारी रेटिंग को कुओं में फेंक दिया जाएगा । इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लाभ है । ?सबका प्रयास? और ?एकात्म मानववाद? 140 करोड़ लोगों को उत्साहित करने का काम कर रहा है । ?(व्यवधान)

महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं । इसमें सभी को कर्म यज्ञ की आहुति देनी पड़ती है । मैं जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा ।

?कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा,

किंतु बनेगा कौन पुरोहित, अब यह प्रश्न नया है ।?

सरकार ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष कर्मयज्ञ की ज्वाला से देश के भविष्य को प्रज्ज्वलित करने के लिए उत्सुक है । यह बजट उसी यज्ञ का परिचायक है । जय हिन्द, जय भारत ।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): At the outset I would like to thank the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Finance Minister for an inclusive and progress-oriented budget with prime focus on fast-paced economic growth, infrastructure development & employment generation.

The budget has taken care of protecting the country's food & energy security. It has taken care of farmers, women, the youth and the poor which are the 4 pillars of Viksit Bharat.

I thank the Hon'ble Prime Minister and Finance Minister for giving a record Rs. 10,000 plus crores for Odisha's railway infrastructure development. As well as a commitment to provide assistance in order to develop the scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes and pristine beaches of our beautiful State make it an ultimate tourist destination.

Reduction of BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp and fish feed to 5% while exemption of customs duty on various inputs for the manufacture of fish and shrimp feed, will help the persons in this business along the huge coastline of coastal Odisha.

This is a Budget that will take the country's villages, the poor and the farmers on the path of prosperity. Key to this is furthering progress on the path of fiscal consolidation. The fiscal deficit is 4.9 per cent of GDP. This demonstrates that the Indian economy has recovered strongly from the pandemic, but sustaining growth attain Viksit Bharat's goal will require sustained interventions and dealing with several emerging economic and policy challenges.

This Budget has specifically outlined the developmental programmes in the Eastern States of the country. The Hon'ble Prime Minister's vision of Purvodaya has been propounded this year's Budget mentioning Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. There was a time in the not so distant past, when this part of

the country was feeding the whole of India. It was rich because of its trade and commerce, because of its rich soil, because of the production of food grains. People thronged that part for employment as Odisha is rich in minerals, with abundant water and forest cover. Odisha has a long coastline with vibrant ports. Yet, I would say that this part of the country was systematically pauperised during the last 50 or 60 years until there was an intervention of the Union Government led by Modi ji. Today, we find policy intervention and the greater focus is on the eastern States. The hon. Prime Minister has repeatedly said during the last 10 years that the country cannot become fully Viksit if a region is left unattended and underdeveloped. I congratulate the Government and the Finance Minister fora bringing the eastern States into the focus of development. Investment on infrastructure will facilitate investment and investment will generate employment which will ultimately help in the economic growth of the country.

The support for the manufacturing sector, a package for employment generation and the skilling and upskilling for 4.1 crore youth across sectors are some of the key highlights of the Budget. This, coupled with the allocation of Rs.1.48 lakh crore for education and employment skilling, underscores the Government's commitment to harnessing India's demographic dividend.

The plan to upscale 1,000 industrial training institutes is a pivotal step towards enhancing the skill sets of our future workforce. I am particularly heartened by the allocation of over Rs.3 lakh crore for women-led development initiatives including provisions for hostels through working women's hostels which will greatly benefit women workforce, especially those who are in the manufacturing industries. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefitting women and girls.

In this Budget, Govt has focused on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives for employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 2 lakh crore. This year, provision of 1.48 lakh crore has been made for education, employment and skilling.

Employment generation is a real bottom line for Indian industries. Indian companies in private sector should pick up the job creation baton from the Government and invest in new manufacturing capacities so that the country can complete its journey to Viksit Bharat by 2047. Along with government, the private sector also has to play their role in providing employment.

The CAPEX budget for the financial year 2025 has been retained at Rs.11.1 lakh crore or 3.4 per cent of GDP. A massive expansion in urban housing at an investment of Rs.10 lakh crore and rural roads programmes with Rs.26,000 crore is a big infrastructure push made in this Budget.

A provision of ₹1.52 lakh crore for agriculture and allied sector has been made in this budget. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticulture crops will be released for cultivation by farmers. In the next 2 years, crore farmers across the country will be initiated into natural farming supported by certification and branding & 10,000 need-based bio-input resource centres will be established.

· For helping our youth who have not been benefitted under any government initiatives, financial support for loans upto 10 lakh for higher education in domestic institutions will be provided. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount.

· The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakhs for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the 'Tarun' category.

· Government will facilitate development of investment-ready "plug and play" industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Programme also will be sanctioned.

· Phase IV of PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations which have become eligible in view of their population increase.

· To bolster the Indian start-up eco-system, boost the entrepreneurial spirit and support innovation, the so-called angel tax for all classes of investors has been abolished.

· Monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise and service tax in the Tax Tribunals, High Courts and Supreme Court has been increased to ₹60 lakh, ₹2 crore and ₹5 crore respectively.

· To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14 % of the employee's salary.

· Under the new tax regime. the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000/- to 75,000/-.Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000/- to 25,000/-. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners.

· As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500/- in income tax.

To conclude, the Budget reflects our unwavering commitment to fostering growth, stability, and prosperity and it will lay the economic foundation for achieving the goal of Vikshit Bharat by 2047. With these words, I fully the support the Budget 2024-25. Thank you.

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): I am very much thankful for giving me this opportunity to express my views on the Union Budget.

The budget presented by the Finance Minister for the year 2024-25 has a clear road map and with policy narrative to materialise the 'Vision' and 'Sankalp' of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji for a Vikasit Bharat. The beginning of 5 trillion economy has already on the way and the budget 2024-25 will add further push from various quarters.

Once again, the people of India, who pose faith on the calling of 'Modi hai to Mumkin hai' and gave mandate for the Modi's 3.0. Given this context, it was a challenging task for the finance minister to present the Budget for 2024-25 with such a clear policy vision articulated through numbers to fulfil the expectations of 140 crore Indians. This budget is full of vision, clarity in development roadmap and a budget for further strengthening and reassuring cooperative federalism, and a futuristic budget.

Many sectors in India grappled with the multi-dimensional impact of the COVID-19 pandemic. Sectors such as agriculture, education, health, employments, among others, were particularly hit during the pandemic years. It was not easy to devise appropriate strategies for these sectors bring them to the track of development trajectory. The projection of 'Viksit Bharat' and the nuances of the idea have already started translating into a meaningful reality with budgetary allocation to various sector. The country is on the fast-growing economic transition; hence, fiscal consolidation measures are crucial to give direction of economic growth. In the budget 2024-25, Fiscal Consolidation majors have been kept at the top of the

agenda to make the country's overall progress and economic growth sustainable by limiting the fiscal deficit projection at 4.9 per cent for this year.

The focus of the ongoing budget on major sections of our society: The Poor, Women, Youth and Farmer continued with adequate budgetary allocations. For instance, the extended benefit Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for another five years, benefitting more than 80 crore people of India received required budgetary support under the head Food Subsidy. On top of these, the full announced 5 crucial schemes to facilitate employment and skilling more than 4 crore youth for period of five-year with a budgetary allocation of Rs. 2 lakh crores. In terms of redistribution of limited resources, the Union Budget 2024-25 touched upon each and every sector and section of population and also gave top priority for employment generation and skilling. Higher capital spending proposed to support the economy and job creation. Government allocates over Rs 3 lakh crore for schemes benefiting women, girls. The Budget focus on employment, skilling, MSMEs and middle class.

This budget continued with the vision of 9 broad priority areas and stressed on important principles needed for India's sustainable growth with social justice. This budget is going to add strength to the ongoing well carved out governance model, focusing on results and outcomes rather than outlays. In prioritising the needs of the poor, women, youth and farmers, leveraging digital infrastructure, skilling the youth etc. received priority attention in the budget 2024-25. Digital coverage of farm land and farmers to help farmers get their long dues is one such example of the initiatives proposed in this budget.

Incentive 30 lakh youth entering job market by providing PF contribution, proposal to launch three employment-linked schemes and setting up working women hostels to promote women participation in workforce are some of the testimonies of the Vision for Vikasit Bharat.

The vision of our Hon'ble Prime Minister, 'Look East Policy' is going to be materialised i this budget. For all round development of plan Purvodaya for all round development of Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. First ever highest allocation, i.e. Rs. 2.66 lakh crore, has been made for rural development sector. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan has been announced for improving the socio-economic condition of tribal communities, which will cover 63,000 villages benefitting 5 crore tribal people.

The push for natural farming, which is sustainable, the provision of certification and branding has been made for one crore farmers across the country. Further, to achieve Aatmanirbharta in pulses and oil seeds, their production, storage, and, marketing, all round initiatives have been made in this budget.

While run up to the general election 2024, our party had promised for electricity free of cost upto 300 units per month. This budget has translated that promise into reality by introducing a scheme for rooftop solar panels that would enable 1 crore households. PM Awas Yojana is going to fulfil housing requirements of 1 crore poor and middle-class families and the central assistance of Rs 2.2 lakh crore for urban housing over next five years shows the commitment of Modi Sarkar.

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : सभापति महोदय, सदन में पेश केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान बहस में हिस्सा लेने का अवसर देने के लिए, मैं स्वयं और अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर की महान जनता की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं । भारत की महान जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और रिकॉर्ड सातवीं बार देश का बजट पेश करने हेतु वित्त मंत्री महोदया को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं ।

महोदय, महिला सांसद होने के नाते एक महिला वित मंत्री को महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजनाओं, महिलाओ द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर टैक्स की छूट, उज्ज्वला योजना के तहत निर्धन महिलाओं के लिए फ्री गैस कनेक्शन, विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए हृदय की गहराईयों से आभार प्रकट करती हूं । मैं इस बजट में बिहार के लिए ?स्पेशल आर्थिक पैकेज? के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री महोदया का आभार व्यक्त करती हूं । यह बिहार में द्रुत विकास का द्वार खोलने वाला और तरक्की की रफ्तार तेज करने वाला बजट है । इस बजट से बिहार के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने में काफी मदद मिलेगी । इस बजट में बिहार को थोडा विशेष क्या मिल जाने पर हमारे विरोधी दल चिल्ल पौं मचाने लगे । मैं प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगी कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किनकी बेइमानी और उपेक्षा की वजह से बिहार सबसे पीछे गया था? गुलाम भारत में समृद्धि के मामले में अव्वल रहा बिहार आज़ादी के सात दशकों बाद लुढ़क कर अंतिम पायदान पर पहुंच गया । सभी लोग जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2005 से कम संसाधनों के बावजूद भी बिहार को गति दी है और काफी आगे बढ़ाया है ।

महोदय, अंत में इसी बहाने मैं अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की ओर केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं । मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर शायद देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । आज़ादी के सात दशकों बाद भी शिवहर में एक इंच रेल लाईन नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है । अब तक वहां चालू स्थिति में कोई एनएच नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, अच्छा खेल स्टेडियम नहीं है । मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी एवं बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी से पुरजोर मांग करती हूं कि इस बजट का लाभ देकर जानकी धाम से बापू धाम, यानि सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी को रेल लाइन से जोड़ा जाए । बागमती में अदौरी खोरीपाकर पुल, बूढ़ी गंडक पर सरसावां मोतिहारी को पुल से जोड़कर शिवहर पूर्वी चंपारण में यातायत को सुगम किया जाए । मेरे संसदीय क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़ा रीगा चीनी मिल, जो स्थानीय किसानों का आर्थिक मेरुदंड है, को अति शीघ्र

चालू करने का प्रयत्न किया जाए । शिवहर में मेडिकल कॉलेज व खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए अच्छे स्टेडियम का निर्माण हो । बैरगनियां घोड़ासहन से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएं एवं इन स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो और एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव बैरगनियां में सुनिश्चित किया जाए ।

मैं यही कहती हूं कि जो बजट है, वह बहुत ही सराहनीय है । इसमें हर वर्ग पर ध्यान दिया गया है, उसमें चाहे महिला हो, कृषि हो, नौजवान हो । इस बजट में हर तरह से सहयोग दिया गया है । मैं इस बजट का स्वागत करती हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूं।

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAGAON): Sir, first of all, I must commend the hon. Finance Minister for her remarkable consistency in overlooking the North-East in her Budget speeches and this time again she has done that.

Sir, there has been a much-hyped policy announced by the Modi Sarkaar and that is the ?Act East policy?. ?Acting East? is basically more of acting and less of action. It is very unfortunate especially when it comes to addressing the perennial, the most pressing, and the real-time problems of the North East, this Budget has completely overlooked.

We do not have any grudge for Bihar having bagged Rs. 11,500 crore for flood mitigation measures. She has given merely a lip service to the North East for addressing the most pressing, perennial, most difficult, and deeper malice of the Assam floods, especially, when the Finance Minister herself admitted in her speech that the Brahmaputra Water System originates beyond the borders. So, it has got international ramifications. But, it is very unfortunate that we felt that this Budget of the hon. Finance Minister ought to have taken a greater cognizance of this problem of the North-East.

Sir, the North-East or Assam basically suffers from three perennial problems. One is flood, second is riverine erosion, and third is the protection of almost 5,000 kilometre length of river embankments. Sir, I have a suggestion also.

I have a submission before the Government. Sir, we want three things. The greatest contribution that the North-East can give to the country at a time when we are going to have climate change and global warming is our abundant source of fresh water. This water is the moot cause and it gives us floods every year. Sir, this water should be brought to the Concurrent List because the Government of India should also have a say and they should play a responsible role as a stakeholder. That is why, my plea is this. As per the Ashok Chawla Report, as per the Standing Committee on Water Resources Department, as they have suggested, water should be brought to the Concurrent List.

The second thing is that floods and the asset that we have, the hydropower projects, everything taken in totality, we need to have a River Valley Authority. So, the Government must consider that we should have a Brahmaputra River Valley Authority which can always include the other States of the North-East. At a time, when you say about double-engine sarkar, I think there would not be any problem for convincing a State like Arunachal Pradesh to become a stakeholder of the River Valley Authority. That can holistically treat this perennial problem.

Apart from floods, the year-long phenomenon that Assam suffers most is the riverine erosion. The riverine erosion should be considered as a national calamity like as floods. This is the consistent demand of the Government of Assam and the people of Assam. That is why, I would like to put forward our request that the Government of India should also consider setting up a Riverine Erosion and Embankment Management Authority so that all these three problems can be tackled, while the Central Government will be playing a very, very important role in addressing all these problems.

Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the copy of the statement should be circulated to us in advance.

HON. CHAIRPERSON: It is on your e-portal also.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): It is being uploaded on the portal. This is the practice. It is always better to have digital copies and we have the facilities for everything. If you need hard copies, they are available. But it is being uploaded.

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): I thank you for the opportunity given to me to express my views on the Union Budget. The Indian Constitution clearly affirms India as a secular, socialist, sovereign and democratic republic, ensuring that its citizens get liberty, equality and justice. Federalism is an integral part of our republic that ensures diversity, peace, stability and mutual accommodation in a multicultural, cultural and diversified country like ours.

However, the Union Government and the Budget have abandoned key aspects of both the Constitution and the federalism. My State of Tamil Nadu has been neglected in the Union Budget though the State is the second largest economy contributing nearly 8.8 per cent to the nation's GDP and also contributing 10 per

cent to the country's total exports. Though my State Tamil Nadu accounts for nearly six per cent of the country's population, Tamil Nadu's share from the total divisible pool of Central taxes has decreased to just four per cent. In spite of numerous letters by our hon. Chief Minister, Mr. M. K. Stalin, seeking Rs. 37,907 crore for flood relief, the Centre had sanctioned a mere Rs. 276 crore, that too, after the Supreme Court's intervention. However, the Central Government with a step motherly attitude has allotted thousands of crores of rupees for flood mitigation measures to other States. Is this because we believe in the teachings of Mahatma and Babasaheb Ambedkar.

Though a budget of Rs. 24,930 crore has been allotted to MRTS and Metro projects in this Unon Budget, it is highly disheartening to note that the second phase of Chennai Metro and the much-awaited Metro projects in Madurai and Coimbatore have not been mentioned. Out of the cost of Rs. 63,000 crore for the second phase of Chennai Metro. the Central Government has allotted so far Rs. 21,000 crore in spite of strained finances. Is this because Tamil Nadu denied the BJP even a single seat? Is this because Tamil Nadu does not believe in politics of hatred? Is this because of Tamil Nadu does not believe in divisive politics? The Union Budget has not only neglected my State of Tamil Nadu but also ignored the interests of the farmers, youth, poor and women of our country.

The growing divide between the haves and the have-nots in our country is alarming and shameful. Ten per cent of our population holds 77 per cent of our nation's wealth. A handful of corporate have immensely profited at the expense of the MSME sector. A billionaire spends Rs. 5,000 crore for a wedding in his family whereas more than 10,000 farmers commit suicide every year due to mounting farm debts. This Budget fails to legalise the guarantee for MSP based on the M.S. Swaminathan Commission formula of C2-plus-50 per cent. This Budget also fails to provide pensions, waivers on farm loans and compensation for more than 700 farmers who lost their lives during the 2020-2021 farm protests. There has been no waiver of GST on farm inputs like seeds, pesticides and fertilizers.

The demand to reduce GST on pesticides from 18 per cent to five per cent has been ignored. The allocation for agriculture and allied sectors as a percentage of the total Budget has been declining from 2019 onwards from 5.4 per cent to the present 3.15 per cent. In a stark contrast to the all-is-well story story of the Union Government, the unemployment ratio and inflation, the true indicators of the nation's economy, portray a very grim picture.

Unemployment ratio is at an all-time high of 9.2 per cent. Food inflation has crossed the 10 per cent barrier. India ranks a pathetic 111 out of 125 countries in the Global Hunger Index. This Government for the past 10 years boasts of its love for the Indian youth. However, more than 10,000 youth commit suicide every year due to the stress caused by mounting education loans, unemployment and a faulty education system plagued by question paper leaks and scams. All the announcements in this Budget about lakhs of crores allotted for upskilling and employment opportunities for the youth are nothing but false promises, just like the lie of doubling the farmers' income made in 2016 by this very Government.

I would like to conclude by saying that this Budget is not a Budget for the farmers, poor, youth and women. On the contrary, it is a Budget that has been drafted to keep this Government alive by appeasing its coalition partners, and it is rightly called the Nitish-Naidu Budget'. I also say that this Budget aids crony capitalism. It is a Budget which goes against the basic tenets of the Constitution, that is, equality and justice. It is a Budget that goes against the spirit of Ambedkar's federalism. I humbly request the Union Government to transcend political boundaries and ideologies to serve the common man and this great country. Thank you.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका और अपनी पार्टी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने लगातार सांतवां बजट पेश किया है । यह केवल केन्द्रीय बजट ही नहीं, बल्कि जनभावनाओं का बजट है इसलिए मैं उनको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ ।

अगर आप बजट की ओर देखेंगे तो इसकी सब तरफ से भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है, लेकिन एक नेता ने यहां पर खड़े होकर जिस तरह से पहले कमल पर कटाक्ष किया, न जाने उनको कमल से क्या विरोध है? कमल शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है । अगर कमल के फूल को राजीव भी कहेंगे तो वह भी उसका पर्यायवाची है, लेकिन कहीं न कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया ।

यह बात सही है कि हमारा चुनाव चिह्न कमल का फूल है और जनता ने हमें लगातार तीसरी बार सत्ता में बैठाने का काम किया है । इन्होंने केवल कमल के फूल को ही नहीं, बल्कि कुछ और अपमानित करने का काम भी किया है । मैं उसका यहां पर थोड़ा उल्लेख जरूर करना चाहता हूँ । कमल से जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और आप जानते हैं कि राजीव किसका नाम है । आप सब जानते ही हैं तो क्या ये उनको भी बुरा समझते हैं? ?(व्यवधान) इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है । हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी कमल है । सिंधु सभ्यता में पद्मासन मुद्रा में भगवान शिव की पशुपतिनाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे और आप कहते हैं कि कमल के चारों तरफ हिंसा है । आप कमल का अपमान ही

नहीं कर रहे हैं, बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का भी अपमान कर रहे हैं । इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोचकर बोलिएगा कि आप किस-किस का अपमान कर रहे हैं ।

आप केवल रील के नेता मत बनिए । आपकी मीम्स खूब बनती हैं । ? (व्यवधान) रीयल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है । ? (व्यवधान) कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है । उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध सात महारथियों ने मिलकर किया था और वे थे ? जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी । शायद राहुल जी ने कभी महाभारत पढ़ी तो क्या देखी भी नहीं होगी । शायद मुझे लगता है कि अंकल सेम ने लिखकर दिया होगा, अंकल सोरस ने लिखकर दिया होगा । कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा । मैं इतना ही कहूंगा कि कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे, वे कर्ण को कर्णा बोल रहे थे और कृपाचार्य जी को कृपचार्य बोल रहे थे ।

सभापति जी, कल सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो । कहीं न कहीं उन्होंने एक बार महाभारत पढ़ने के लिए मुझे फिर से प्रेरित किया । मगर इस बार मैंने महाभारत पर एक नई पुस्तक पढ़ी, जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उन्होंने लिखी है और उस पुस्तक का नाम ?दी ग्रेट इंडियन नोवल? है । राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है तो अपने उस सांसद से वे सम्पर्क कर सकते हैं ।

<u>16.00 hrs</u>

शायद शशि थरूर जी ही राहुल गांधी को बता दें या बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिला कर जो उपन्यास लिखा है, उसके पात्र कौन-कौन हैं? इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधन कौन है । जब राहुल जी को इसका पता चलेगा, तो मुझे लगता है कि कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई न हो जाए ।?(व्यवधान) साहब, क्या है कि ये लोग संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे । मैंने उस दिन पूछ लिया कि कितने पन्ने होते हैं, तो वे यह भी नहीं बता पाए । उसके बाद मैंने पूछा कि आप संविधान की कॉपी लेकर चलते हो, क्या आपने इसका प्रीफेस पढ़ा है, इसका फोरवर्ड पढ़ा है, इसकी प्रस्तावना किसने की है? के.के.वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल, इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे । यह सीनियर ऐडवोकेट हैं । गोपाल शंकर नारायण सीनियर ऐडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना की थी और प्रस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याय, वह इमरजेंसी का समय था ।? (व्यवधान) यह संविधान बी. आर. अम्बेडकर जी ने दिया, अगर यह नहीं दिया गया होता, तो आम जनमानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता, लेकिन इन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं था । ये इतने दिनों से केवल कॉपी दिखा रहे थे।?(व्यवधान) गुगल दादा थे, वे इनसे पूछ लेते ।?(व्यवधान) आप साथ में क्या करते हैं, कुछ बताया करें ।

माननीय सभापति जी, इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वेसर्वा आप हैं, उस उपन्यास की ही कौरव पार्टी है ।? (व्यवधान) मैं अपनी तसल्ली के लिए कुछ पंक्तियों को यहां उद्धृत कर देता हूं । मैं पेज नम्बर 245 से कोट कर रहा हूं ।

?The India of which Dhritarashtra assumed the leadership on 15th August, 1947 had just been through a cathartic process of regeneration, another stage in this endless cycle.?

15 अगस्त, 1947 को प्रधान मंत्री के रूप में मोदी जी नहीं थे और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को सत्ता संभाली थी, वे धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया??(व्यवधान) आपने मुझे बांध रखा है । कल स्पीकर महोदय ने कहा है कि उस समय के लोगों का नाम नहीं लेना है । मैंने प्रथम प्रधान मंत्री जी को धृतराष्ट्र नहीं कहा, इनके अपने सांसद ने अपने द ग्रेट इंडियन नॉवेल में कहा । शाशि थरूर जी कहां हैं? वे कहीं छिप तो नहीं गए? आज सोकाउज हो सकता है ।? (व्यवधान) फिर देखिए कि प्रिय दुर्योधनी और धृतराष्ट्र के विषय में क्या लिखा है?

Sir, I quote it from page 293,

?In Delhi blind Dhritarashtra ruled with Priya Duryodhani by his side, and he pledged the nation not so much to the gas and hot water of his Fabian preceptors but to the smoke and steam of the modern industrial revolution their ancestors had denied his country.?

सर, यह सभी को पता है कि इस देश के एक मात्र फैबियन समाजवादी कौन थे । फैबियन समाजवादी कौन थे, उसके बारे में किसी और ने नहीं, बल्कि आपके ही माननीय सांसद ने लिखा है।? (व्यवधान) आगे इसमें इमरजेंसी की चर्चा भी है, जिसे इंदिरा गांधी जी ने थोपा था ।? (व्यवधान)

सर, यह देश इमरजेंसी के समय इनकी यातनाओं का भुक्तभोगी रहा है । वह काला खंड, वह काला अध्याय देश कभी भूल नहीं पाएगा, जिसने देश के लोगों को कठिन शब्द इमरजेंसी के बारे में भी बताया ।

हम द ग्रेट इंडियन नॉवेल के अध्याय सेवेन्थ बुक की चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रिय दुर्योधनी और उनके प्रिय पात्र शकुनि, शंकर डे देश में आपातकाल लगाने की योजना बना रहे थे । सर, मैं पढ़ता हूं कि शकुनि ने क्या कहा । I quote,

?What you could do now is to declare an internal siege. A grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption.?

माननीय सभापति**:** आप जिस बुक को कोट कर रहे हैं, उस बुक को आप सब्मिट कर दीजिएगा ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** सर, मैं सब्मिट कर दूंगा । एक कॉपी आपको भी भिजवा दूंगा और एक टेबल पर भी रख दूंगा ।

? ?What you could do now is to declare an internal siege. A grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption. No one has ever

defined the permissible procedures under an internal siege, which leaves it more or less up to us to define them.? Shakuni added.?

Next, I quote from page 366:

? ?Not to mention censorship of the press, which is nowhere explicitly ruled out in the Constitution, suspension of certain fundamental rights ? free speech, assembly, that sort of thing ? and measures to put the judiciary in their place,? said Shakuni.? ? (*Interruptions*)

यह किसी और ने नहीं, मैं कहना चाहता हूं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय अनुराग जी, एक किताब गौरव जी को भी भिजवा दीजिएगा ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** सर, मैं एक कॉपी गौरव जी को भिजवा दूंगा । ? (व्यवधान) सर, मैं जिनकी बात कर रहा हूं, वह उस समय की प्रधान मंत्री थीं, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी । एक नेता की स्वर्गीय दादी जी भी हैं और उनके नाम के आगे प्रियदर्शनी भी लिखा जाता था । उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी । माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि दु:शासन और दुर्योधन दोनों बहुत ही दुष्ट और बदमाश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इमरजेंसी नहीं लगाई थी । ? (व्यवधान) दु:शासन और दुर्योधन दुष्ट भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं लगाई थी । सर, पूरे उपन्यास में 74 बार कौरव और कौरव पार्टी की चर्चा हुई । हरेक में कांग्रेस का चरित्र झलकता है । ? (व्यवधान) राहुल जी, इस सदन में हजारों साल पूर्व हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे । मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े-लिखे एक विद्वान, पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनि था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दु:शासन था, कौन दुर्योधन था, कौन करण था? आप जरूर पढ़ियेगा । सब के किरदार उसी में मिलने वाले हैं । शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे, उस समय आपका टैलेंट इनको पता नहीं था, नहीं तो 100 पन्ने आप पर ही लिख देते । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो जाए?

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** माननीय सभापति जी, कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर बहुत ज्ञान दे रहे थे तो पीछे दो लोग कुमारी सैलजा जी और दीपेन्द्र जी बैठ कर मुस्कुरा रहे थे । अब शायद राहुल जी, वे पीछे हँस तो रहे थे, लेकिन आप एक बात जरूर कर लीजिए ? (व्यवधान) चक्रव्यूह के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है, हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, जान लीजिए कि कौन शकुनि है और कौन अभिमन्यु है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी । ? (व्यवधान) आपको एक और सुझाव देना है । मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने तो कई सारे चक्रव्यूह बनाने का काम किया है । जब उस समय किशोर अभिमन्यु पर कौरवों ने युद्ध नीति के विपरीत जाकर प्रहार किया था, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं?

?इतने में पुत्र दु:शासन ने, पीछे से था वार किया,

निष्प्राण हुआ एक गदा से, सिर पर था प्रहार किया ।

मां धरती की गोद में, वह आंख मूंदकर सो गया ।

अम्बर का तेजस्वी तारा, धूमकेतु सा खो गया ।

लेकिन कोई तारे का तेज, फीका नहीं कर सकता है ।

वीरगति पाकर अमर हुआ हो, कभी नहीं मर सकता है ।

पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में, जिसकी अमर कहानी थी ।

नौ माह में सीखी विद्या, तब सोलह साल जवानी थी ।?

अब उस अभिमन्यु को, जिसने सारे चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया । ? (व्यवधान) मैं इतना ही कहूंगा कि चक्रव्यूह का प्रसंग छेड़कर आपने अच्छा किया । ? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am on a point of order.

HON. CHAIRPERSON : Let the hon. Member complete his speech. Then, I will give you an opportunity.

? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** इस देश ने बहुत सारे चक्रव्यूह देखे हैं । कांग्रेस का चक्रव्यूह ? (व्यवधान) सर, मैं इसके सात किरदार बताता हूं । पहला, कांग्रेस । दूसरा, ...* सर, नाम लेने के लिए मना किया है । मैं दूसरी तरह से बोलता हूं ।

पहला कांग्रेस, दूसरा पहले प्रधानमंत्री एनजी, फिर तीसरा किरदार आईजी, पूर्व प्रधानमंत्री, चौथा आरजी-1 उस समय के प्रधानमंत्री, पाँचवाँ एसजी, छठा आरजी-2 और सातवाँ तो आप सब जानते ही हैं । आप समझदार हैं, समझ गए होंगे ।

सर, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन कराया । दूसरे एनजी ने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी ।? (व्यवधान) तीसरे चक्रव्यूह आईजी ने, पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने देश को आपातकाल दिया, इमरजेंसी दी और पंजाब में अशांति दी । चौथे, जो आरजी-1 हैं, ने बोफोर्स दिया और सिखों का नरसंहार किया ।? (व्यवधान) पाँचवें जो एसजी हैं, उन्होंने सनातन धर्म परम्परा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया । 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भँवर जाल में फँसाया । छठे ठहरे आप, जिन्होंने 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परम्परा और संस्कृति को इतना नुकसान पहुँचाया, जितना कि ये बाकी छ: मिलकर, सारे चक्रव्यूह एक साथ भी मिलकर नहीं कर पाए ।? (व्यवधान) रही बात सातवें की, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं इतना ही कहूँगा कि सातों चक्रव्यूहों ने मिलकर देश को गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे अनगिनत दुष्चक्रों में फंसा दिया था । देश को हमने आपके दुष्चक्रों से बचाया है ।? (व्यवधान)

आज़ाद कराया है । माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास रथ को आगे बढ़ाया है । आज दुनिया में, भारत पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है ।? (व्यवधान) आप जिस अभिमन्यु को पिछले 22 सालों से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गईं, लेकिन आप उनको घेर नहीं पाए, क्योंकि वे जनता के दिलों में बसे हैं ।? (व्यवधान) आज यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं । भले ही आपके पास कर्ण जैसे धुरंधर हों, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हों, लेकिन धर्म हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है ।? (व्यवधान)

भले ही आपके पास नारायणी सेना हो, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं ।? (व्यवधान) हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता? (व्यवधान) हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया माथ तो किस बात की चिंता । हमारे साथ तो जनता रूपी रघुनाथ है और आगे भी रहने वाला है ।

आप देखिए, ये कल से हलवा बांटने की बात कर रहे थे । महोदय, …* के पैर नहीं होते । ये …* अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करते हैं ।? (व्यवधान) जैसे मदारी के कंधे? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** हम उसको देख लेंगे ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप … * शब्द के स्थान पर असत्य कहें । … * असंसदीय शब्द है, उसे हम कार्यवाही का हिस्सा नहीं मानते हैं । आप असत्य कहिए ।

? (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, it is totally unparliamentary and irrelevant speech. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have already given the ruling. Mr. Venugopal, I have given the ruling.

? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** माननीय सभापति जी, असत्य के पैर नहीं होते ।? (व्यवधान) असत्य के पैर नहीं होते ।? (व्यवधान) यह असत्य अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करता है ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manickam Tagore has raised the issue. I have taken it into cognizance.

? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर … * का बंडल होता है ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manickam Tagore has raised the issue. I have taken it into cognizance. मैंने कर दिया गौरव ।

? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर **:** जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल जी के कंधे पर …* का बंडल होता है ।? (व्यवधान) जिसे वे रोज़ यहाँ परोसते हैं ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will give you the opportunity after he concludes his speech.

? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं हो, संसदीय कार्य में रुचि न हो, जिसने मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? ? (व्यवधान)

मैं पूछना चाहता हूं कि हलवा किसको मिला? ? (व्यवधान) राहुल जी, बताइए, आपने हलवा की बात की थी । ? (व्यवधान) जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) बोफोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) नेशनल हैराल्ड घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) 2 जी स्कैम का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) कॉमनवैल्थ गेम्स घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? ? (व्यवधान) राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका था? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं । ? (व्यवधान) मैं यह कहता हूं कि इनके लिए ओबीसी ? (व्यवधान) गौरव जी, मेरी बात सुनिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair.

? (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ? ?ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन? । ? (व्यवधान) ?ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन? के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट्स की बात करती है, तो आदमी को भी पंखे के साथ लटककर आत्महत्या कर लेनी चाहिए । ? (व्यवधान) मतलब जिस पार्टी ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष, जो एक पिछड़े वर्ग समाज से आते थे, उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहज़ादे हमें ज्ञान बांट रहे हैं? ? (व्यवधान)

अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा । ? (व्यवधान) इसका मतलब ?लीडर ऑफ प्रोपोगैंडा? नहीं ?लीडर ऑफ अपोजीशन? है । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He is responding on behalf of his party.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly listen to me.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति **:** गौरव जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं । मैं आपको जवाब दे रहा हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आप एक मिनट के लिए चुप हो जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आप एक मिनट के लिए चुप हो जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय गौरव जी, आप या माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी एलओपी हैं और उन्होंने भी सरकार के बारे में बात कही, सरकार के मंत्रियों का नाम लिया । श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी उसका जवाब दे रहे हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अगर कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा, तो उसको मैं एक्सपंज कर दूंगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** उन्होंने ? * शब्द कहा था, मैंने उसको एक्सपंज कर दिया ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ? आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब ये ?* परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब ?लीडर ऑफ प्रोपोगैंडा? नहीं ?लीडर ऑफ अपोजीशन? होता है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आप ?* शब्द न इस्तेमाल करें । यह असंसदीय शब्द है ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: ठीक है, सर, असत्य है, निराधार है । ठीक है, सर । ? (व्यवधान) ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है । ? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव **(कन्नौज) :** सभापति महोदय, यह क्या है? ? (व्यवधान) ये ओबीसी की बात कैसे कर सकते हैं? ? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं, वह गणना की बात करता है? ? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** ये जात की बात कैसे कर सकते हैं? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आप कृपया बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव**:** अनुराग जी, आपकी क्या जात है? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है, मैं उसको दिखवा लूंगा । मैं आपकी बात को संज्ञान में ले रहा हूं । उन्होंने जो बात कही है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** कृपया आप लोग बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** माननीय सभापति जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में एक पूर्व प्रधान मंत्री जी ने, आरजी-1 ने ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** अनुराग जी, एक मिनट रूकिए । लीडर ऑफ अपोजीशन बोलना चाहते हैं । आप लोग बैठ जाएं । माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए, आप लोग बैठ जाएं, मैं उन्हें अलाऊ कर दूँगा ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी **(रायबरेली) :** सर, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया है, मुझे बोलने दीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** उनकी बात खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको अवसर दूँगा ।

श्री राहुल गांधी**:** नहीं सर । उन्होंने मुझे इंसल्ट किया है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** मैं उनके बाद आपको अवसर दूँगा । आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** पहले उनकी स्पीच खत्म हो जाए । कृपया आप बैठ जाइए ।

एक माननीय सदस्य : कल किस-किस का इंसल्ट कर रहे थे?? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको अवसर दूँगा ।

अनुराग जी, आप एक मिनट बैठ जाएं ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, एक मिनट, मैं क्लेरिटी कर दूँ ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सब लोग बैठ जाएं । मैं लीडर ऑफ अपोजीशन को बुला रहा हूँ । Is it fair when I am allowing the Leader of the Opposition? फिर मैं उनको बुला लूँगा । मैं आपको बुला रहा हूँ । पहले सब लोग बैठ जाएं । पहले सब लोग बैठ जाएं तब मैं आपको अलाऊ करूँगा । सब बैठ जाएं तब मैं आपको अलाऊ करूँगा ।

श्री राहुल गांधी: सर, उन्होंने मेरा इंसल्ट किया है । मुझे माइक तो दीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको अलाऊ करूँगा, लेकिन पहले सभी लोग बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको अलाऊ करूँगा । आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं । मैं आपको अलाऊ करूँगा । हाउस इन ऑर्डर हो जाए । गौरव जी, आप भी बैठ जाएं । मैं लीडर ऑफ अपोजीशन को अलाऊ कर दे रहा हूँ । अगर आप यह कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया है तो मैं बिल्कुल आपको अलाऊ कर रहा हूँ ।

श्री राहुल गांधी: सर, मुझे बोलने दीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपका नाम तो ले लूँ ।

श्री राहुल गाँधी जी ।

श्री राहुल गांधी: महोदय, देखिए जितना आप लोग मेरा इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से कीजिए ।? (व्यवधान) आप रोज कीजिए, मगर एक बात मत भूलिए कि जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे । धन्यवाद ।? (व्यवधान) जितना इंसल्ट करना है करिए ।? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसमें अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप चुप रहिए ।

श्री अनुराग ठाकुर जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : हमने समय दे दिया । अब आप बैठिए । यह तरीका नहीं है । नहीं, यह तरीका ठीक नहीं है । हमने आपको टाइम दे दिया है ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप बैठ चुके हैं । यह नहीं होता है ।

श्री अनुराग ठाकुर ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी ।? (व्यवधान) लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है ।? (व्यवधान) अपने बलबूते पर? (व्यवधान) सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है ।? (व्यवधान) उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है ।? (व्यवधान) यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है ।? (व्यवधान)

<u>16.23 hrs</u>

At this stage Shri B. Manickam Tagore and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** मणिक्कम जी, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** आप बोलकर हटते हो, फिर पर्ची आती है, फिर बोलते हो ।? (व्यवधान) ऐसे कैसे चलता है?? (व्यवधान) I am not yielding. ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** मैंने उनको बिठाकर, आपको बुलाया । अब मैं ऐसा नहीं करूँगा । मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठाकर आपको समय दिया । अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** सर, मैं इतना ही कहूँगा कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है ।? (व्यवधान) आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है ।? (व्यवधान) लेकिन मैं इतना कहूँगा ।? (व्यवधान) सर, मैंने क्या कहा था? ? (व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ ।? (व्यवधान) ये नहीं सुन रहे हैं ।? (व्यवधान) मैंने कहा था कि? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप वापस जाइए । I have already given an opportunity to Shri Rahul Gandhi Ji. He has expressed his views जो उनको था । नहीं-नहीं, आप वेल से बाहर आ जाएं । कृपया आप वेल से बाहर आ जाएं, मैं उनको फिर समय दे दूँगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** मैं उनको फिर समय दे दूँगा ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं, वह गणना की बात करता है ।? (व्यवधान) मैंने नाम किसी का नहीं लिया था ।? (व्यवधान) सर, मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया था ।? (व्यवधान) मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए ।? (व्यवधान) सर, मैं कहना चाहता हूँ ।? (व्यवधान) माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने अनुराग जी को बिठाकर माननीय राहुल गाँधी को समय दिया था । मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठाकर उन्हें समय दिया था । कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाइए। जब एलओपी को टाइम मिल गया तो अब आप सदन में व्यवधान मत कीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: राहुल गांधी जी, क्या आप दोबारा बोलना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलेंगे । आप सभी वेल से वापस चले जाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यदि मैं आपके एलओपी को बोलने का समय दे रहा हूं तो आपको वेल से बाहर चले जाना चाहिए ।

? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : अनुराग ठाकुर जी को माफी मांगनी चाहिए । वे जाति की बात कह रहे हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : राहुल जी, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को कहें कि वे वेल से बाहर चले जाएं । मैं आपको बोलने का समय दे रहा हूं ।

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: सभापति जी, माइक ऑन कराएं ।

माननीय सभापति : आपको माइक मिल जाएगा । आप सभी वेल से चले जाएं । बजट पर इतनी अच्छी एवं सार्थक चर्चा चल रही है । पूरा देश देख रहा है । राहुल जी ने कह दिया है, अब आप वापस चले जाएं । आप अपने लीडर का सम्मान करें । मैं आपके लीडर को दूसरी बार बोलने का मौका दे रहा हूं । वे हाउस के एलओपी हैं और उनके लिए मैंने माननीय सदस्य को बैठा दिया है । आप कम से कम इस बात का तो सम्मान करें ।

राहुल गांधी जी ।

16.26 hrs

At this stage Shri B. Manickam Tagore and some other hon. Members went back to their seats.

-

श्री राहुल गांधी**:** सभापति जी, माइक ऑन नहीं है ।

माननीय सभापति **:** जब पीठासीन नाम लेते हैं, तो माइक ऑन हो जाता है ।

श्री राहुल गांधी**:** सभापति जी, देश में जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसे गाली खानी ही पड़ती है । मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा । महाभारत की बात यहां हुई । महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, इसी प्रकार मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है । हम जाति जनगणना कराकर दिखाएंगे । आपको जितनी गाली देनी है, आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे । धन्यवाद ।

श्री गौरव गोगोई**:** अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** गौरव जी, एलओपी को समय दे दिया है । क्या राहुल जी आप फिर बोलना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी**:** जी हाँ ।

माननीय सभापति **:** राहुल जी, आप देख लीजिए, आप जब-जब चाह रहे हैं, मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं इसलिए कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति क्रिएट न करें कि सदन अव्यवस्थित हो । सदन चलाने की जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, उतनी प्रतिपक्ष की भी है ।

श्री राहुल गांधी**:** अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली दी है ।? (व्यवधान) मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है । मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको मुझे गाली देनी है, मैं आपसे कभी माफी नहीं मंगवाऊंगा । मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए ।

माननीय सभापति **:** राहुल गांधी जी, मैं चेयर पर हूं । चेयर का काम है कि यदि कोई असंसदीय शब्द या किसी को गाली दी गई है तो मैं उसे देखूंगा और कार्यवाही से निकलवाऊंगा । यदि गाली दी है तो मैं उसे कार्यवाही का हिस्सा दिखाकर एक्सपंज करवाऊंगा ।

? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी **(**श्रीरामपुर**) :** सभापति जी, क्या आपने कुछ नहीं सुना? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** मैं सुन रहा हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री अखिलेश यादव जी ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव: सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है कि माननीय सदस्य मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं और बड़ी बात कह रहे थे, महाभारत के समय की बात भी कह रहे थे । शकुनी और दुर्योधन तक यहां ले आए । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने ?जाति? कैसे पूछ ली? आप ?जाति? कैसे पूछ सकते हैं? ?(व्यवधान) आप पूछकर दिखाओ ?जाति? को ।? (व्यवधान) आप ?जाति? कैसे पूछोगे? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अखिलेश जी, आप बैठ जाओ ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव: ये ?जाति? नहीं पूछ सकते हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप हमारी व्यवस्था सुन लें । कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : इसे एक्सपंज कर दिया ।

माननीय अनुराग ठाकुर जी ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधान मंत्री स्वर्गीय ?आर.जी. - 1? जी ने यही कहा था कि ?ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं ।?? (व्यवधान) यह तो सदन में है । ?आर.जी. - 1? ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं ।? (व्यवधान) अब ये तय करें कि वे सही थे या ये सही हैं और आपकी पार्टी गलत थी या आप गलत हैं? ? (व्यवधान) क्या वे पिछड़ा विरोधी थे या आप पिछड़े के पक्ष में हैं? ?(व्यवधान) उस समय की पूर्व प्रधान मंत्री ?आई.जी.? ने कहा था कि ?जात पर न पात पर ।? मैंने तो यह नहीं कहा, उस समय यह कहा गया था।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया अपना भाषण संक्षिप्त करें ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर वर्षों तक कौन बैठा रहा?? (व्यवधान) इसका इन्हें जवाब देना होगा । कौन जवाब देगा? ? (व्यवधान) अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते और बाकी भी होते ।? (व्यवधान)

सर, यही नहीं, इन्होंने दलित, आदिवासी का विरोध किया ।? (व्यवधान) ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्ज़ा भी नहीं दिया । अगर किसी ने उसे संवैधानिक दर्ज़ा दिया तो उसे मोदी सरकार ने आकर दिया है ।?(व्यवधान)

सर, मैं इस सदन के लिए यह पढ़ देता हूं । नेहरू जी ने वर्ष 1951 में आरक्षण के विरुद्ध लिखा था ।?(व्यवधान)

I quote:

?I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be a first-class country in everything. The moment we encourage the second-rate, we are lost.?

यह किसने कहा? इसे देश के पहले प्रधान मंत्री ने कहा । आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, यह बताइए ।?(व्यवधान) आप उसके लिए माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अनुराग जी, कृपया आप चेयर को एड्रेस करें और अपना भाषण समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** सर, मैं इतना ही कहूंगा ?

लहज़े में बदज़ुबानी, चेहरे पर नक़ाब लिए फिरते हैं,

वो, जिनके खुद के बही-खाते बिगड़े हैं, वे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं ।

सर, मैं एक बात क्लियर कर दूं ।? (व्यवधान) मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कोई अपने आप क्यों खड़ा हुआ?? (व्यवधान) मैंने किसी का नाम नहीं लिया था । आप रिकॉर्ड चेक कीजिए ।

माननीय सभापति **:** मैं रिकॉर्ड दिखवा लूंगा ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** सर, हमने ?सबका साथ, सबका विकास? किया । अगर अल्पसंख्यक के रूप में किसी को राष्ट्रपति बनाया गया, तो कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनाया गया । राम नाथ कोविंद जी, जो एस.सी. समाज से आते हैं, अगर उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया तो वह मोदी जी की पहली सरकार में बनाया गया । अगर एक महिला ट्राइबल को उनकी अपनी क्षमता के आधार पर देश का राष्ट्रपति बनाया गया, तो द्रौपदी मुर्मु जी को हमारी सरकार में बनाया गया ।? (व्यवधान) अगर कोई ओबीसी प्रधान मंत्री है तो आज माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी हैं ।? (व्यवधान) आज अगर एस.सी., एस.टी., ओबीसी के सबसे ज्यादा मंत्री हैं, तो वे हमारी सरकार में हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अब अपना भाषण समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** सर, मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।? (व्यवधान)

सर, ये एमएसपी की बात कर रहे थे ।? (व्यवधान) एमएसपी कौन लाया?? (व्यवधान) वर्ष 1961 में उस समय के पहले प्रधान मंत्री जी इसे लाए, लेकिन इन्होंने उसकी गारंटी क्यों नहीं दी? वर्ष 1961 के बाद वर्ष 1966 में आप लाए ।? (व्यवधान) इतने सालों तक आप क्या करते रहे?? (व्यवधान) आपने उसका प्रावधान क्यों नहीं किया?? (व्यवधान)

सर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की । क्या आप उनसे मिलने गए?? (व्यवधान) उनमें कितने एस.सी., एस.टी., ओबीसी थे? ? (व्यवधान) वहां के ओबीसी, एस.सी., एस.टी. के पैसे को, कर्नाटक में उनके 34 प्रतिशत बजट को खत्म करके अलग कर दिया गया । क्या आपने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया?? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर**:** सर, यही नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

सर, आप देखिए कि आज ओबीसी के कोटे को खत्म करके अगर कोई मुसलमान को आरक्षण देने की बात करता है तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में आपके कहने पर वे लोग ऐसी बात करते हैं और आप यहां पर ओबीसी की बात करते हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, यहां पर अग्निवीर की बात कही गयी और अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम लेकर कहा ।? (व्यवधान)

सर, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं । वह बहुत छोटा राज्य है । वहां 70 लाख की आबादी है । देश में कारगिल के समय अगर सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी तो वह हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों ने दी ।? (व्यवधान) चार परमवीर चक्र विजेता हुए, जिनमें से दो हमारे यहां से हुए ।? (व्यवधान)

सर, ?वन रैंक, वन पेंशन? 40 सालों तक इन्होंने नहीं दिया और अगर उसे किसी ने दिया तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने आकर दिया ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** यह बात सदन में आ चुकी है, आपके ही द्वारा आ चुकी है ।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर **:** सर, अग्निवीर योजना में 100 प्रतिशत इम्प्लॉयमेंट की गारंटी है ।? (व्यवधान)

सर, मैं अंत में एक बात कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए बजट में बहुत कुछ है । नौकरी से ले कर, इंटर्नशिप से ले कर बाकी सब बहुत कुछ है । मैं निर्मला जी और प्रधान मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । सर, स्पेस सैक्टर के लिए एक हज़ार रुपये का वेंचर कैपिटल फंड भी दिया गया । सर, जिस देश में सपेस के नाम पर शायद बहुत कम कुछ दिखता था, आज चन्द्रयान मिशन की सफलता के कारण दुनिया का पहला देश भारत बना है । ? (व्यवधान) सर, इनके समय हेमराज का गला रेत कर ले गए थे, वापस नहीं लाए थे । हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर के अपनी जगह को मज़बूत किया है । ? (व्यवधान) सर, स्टार्टअप में हम नंबर वन हैं । ? (व्यवधान)

सर, मैं आखिरी लाइन बोल रहा हूँ ।? (व्यवधान) ये कहते हैं कि देश में डर का माहौल है । सर, मैं इतना ही कहूंगा कि डर का माहौल अपराधियों में हैं, डर का माहौल भ्रष्टाचारियों में है, डर और भय का माहौल देशद्रोहियों, अधर्मियों में, कुकर्मियों में है । ? (व्यवधान) सबसे ज्यादा डर का माहौल देश के दुश्मनों में है । ? (व्यवधान)

सर, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि माननीय निर्मला जी ने जो सातवां बजट पेश किया है, यह जन भावना का बजट है, जिसका पूरा सदन पूरी-पूरी प्रशंसा करता है । ? (व्यवधान) साथ ही, इनको और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और साधुवाद देता है । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही जी ।

? (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, under Rule 353, he cannot take my name repeatedly without notice. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have given it. Whatever issue you want to raise, the LoP has already raised that issue. Even Akhilesh Yadav ji has also raised the issue. There is no Point of Order.

? (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR : Mr. Chairperson, Sir, let me point it out. He has repeatedly taken my name. ? (*Interruptions*) Sir, he has repeatedly taken my name. I think I have a right to respond. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will allow you.

? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री बिष्णु पद राय जी ।

? (व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय **(**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**) :** सर, मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूँ कि एक बढ़िया खबर है । सुन लो, आपको ज़रूरत है, आपका भला होगा । मोदी जी की वजह से ऑयल एण्ड गैस के नाम पर अंडमान में चार जगहों पर अक्टूबर महीने में ऑयल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जा जाएगा । ? (व्यवधान) दूसरा, वाइपर द्वीप किसने बेचा था? वाइपर द्वीप पर महाराजा पुरी, इंफाल के राजा आदि लोगों को कमर और पांवों में चेन बांध कर ब्रिटिशों ने जेल में बंदी बनाया था । इस कांग्रेस पार्टी ने वाइपर द्वीप को कैसिनो के नाम पर, जुआ खेलने के नाम पर बेचा था । मैंने बचाया था, बिष्णु पद राय ने बचाया था । इसके लिए एंटोनी ने माफी मांगी थी । इन कांग्रेसियों ने बफ़र ज़ोन जारवा रिज़र्व बनाया था । उसको मैंने बचाया । आप लोग अंडमान निकोबार को देखो कि मोदी जी ने क्या बना दिया है और आपने क्या बना कर रखा हुआ था?

मोदी जी ने अंडमान को क्या दिया है? ओएफसी कैबल, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, नेशनल हाईवे पीएमजीएसवाई, शिप रिपेयर यार्ड, सीआरएफ फंड दिया और द्वीप समूह में उत्तरा ब्रिज और नेशनल हाईवे का फर्स्ट फेज़ कम्पलीट हो गया है ।

जय हिन्द । भारत माता की जय ।

माननीय सभापति : डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही जी ।

? (व्यवधान)

<u>**16.39 hrs**</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

DR. SHASHI THAROOR : Sir, I just want to point out one thing.

Under Rule 353, the hon. Member has no business taking my name repeatedly without a valid notice, and the notice was not given. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : चलिए बैठिए ।

माननीय वित्त मंत्री जी ।

माननीय अध्यक्ष : आपका यह तरीका ठीक नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बोलिए, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का नंबर बताइए ।

? (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: It is Rule 353. He has repeatedly taken my name without notice.

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं रूल 353 को दोबारा पढ़ लूं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग आज रूल 352 और 353 को पढ़ ही लो । रोज़ मुझे पढ़ाते हो ।

शशि थरूर जी बोलिए ।

? (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: I have the right to respond. ? (*Interruptions*) The gentleman has repeatedly taken my name and quoted me. Actually, I should be grateful that he has revived the 35-year-old book of mine, which he has quoted extensively. It is ?The Great Indian Novel?, which was published in 1989. It is a satirical novel. Unfortunately, the gentleman has missed this satire. I do want to point out that the

fact is that we have recently fought the elections of 2024 and not the elections of 1989.

So, the first point is to understand the context in which this has been read.

Second and more important is I think it is important to understand that, whereas many things have been said in the course of writing novels, there are also many subsequent books I have written which he could have quoted where he may be somewhat less happy with the result, and thirdly, Sir, there are many people on that side of the fence, who have said many things far more recently against their own Party which, he should remember, can also be quoted back as well.

So, I think at this point, this is not a literary discussion. I am grateful for this. But I do not believe this is the right way to proceed in this matter.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: सदन में आप रोज इस किताब को उठाते हैं । इस किताब के 352 और 353 को आप रोज उठाते हैं ।

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, यह किताब बाइबिल की तरह है ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, यह बाइबिल है । इस बाइबिल के दो अंश को मैं इस सदन में पढ़ कर सुना देता हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह खत्म हो गया ।

? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I was raising a Point of Order at the time of the speech made by Shri Anurag Singh Thakur.

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है । आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रेमचन्द्रन जी, प्लीज आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी मैं प्रशिक्षण में सबको सुनाऊंगा । विशेष रूप से जो सीनियर हैं, उनको भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा । दादा सौगत रॉय जी को भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा॥

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं नियम की किताब को रोज पढ़ता हूं ।

? (व्यवधान)

श्री दुलू महतो (धनबाद) : बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे वर्ष 2024-2025 के बजट अपना विचार रखने का अवसर प्रदान किया ।

सबसे पहले मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक जीत पर अपने क्षेत्र की जनता, की तरफ से बधाई देता हूँ । साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सफलतापूर्वक देश के विकास के लिए सातवां बजट पेश किया गया ओर यह एक ऐसा बजट है जिसमे देश के हर नागरिक की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया हैं।

जैसा कि हम सभी जानते है की हमारी सरकार के इस बजट से मोदी 3.0 का आर्थिक विजन स्पष्ट हो गया है ।

UPA के वर्ष 2005-2014 तक 10 वर्षों के शासनकाल में पेश किये गए बजट की अधिकतम राशि सोलह लाख पैंसठ हजार दो सौ संतान्वे (16,65297) करोड़ रु थी जो की वर्तमान वित् वर्ष में 2024-2025 के लिए एक्सपेंडिचर 48.21 लाख रु रहने का अनुमान है । यह हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है जिसके कारण अगले साल हमारे देश का राजकोषीय घाटा भी 4.1% से कम रहने का अनुमान है । हमारी सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि सभी धर्म जाति लिंग और आयु के भारतीय अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति करें ।

इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन किए हैं, जिससे हमारे देश की जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । प्राथमिकता देते हुए, इस बजट ने गरीबी को कम करने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को प्रस्तुत किया है । यह स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम है ।

इस बजट में व्यापारिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे व्यापार और उद्योगों को विकास के लिए उत्तेजित किया जा सकेगा । इससे आर्थिक वृद्धि होगी और नये रोजगार के अवसर बनेंगे ।

इस बजट के माध्यम से हम यह भी देख सकते हैं कि सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नए पहलू दिए हैं । जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नई योजनाएं और नीतियाँ अग्रसर की गई हैं ।

इस बजट के माध्यम से, सरकार ने समग्र नागरिक समुदाय के हित में कई कदम उठाए हैं, जिससे हमारे देश की समृद्धि और सामरिक संघर्ष को ध्यान में रखा गया है ।

इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई (MSME) और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं । रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की गई, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है ।

इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है ।

अगले दो वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि (Natural Farming) के लिए सहायता दी जाएगी जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी । इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा । 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र (bio-input resource centres) स्थापित किए जाएंगे । सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाई जा रही है । इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ।

हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री पैकेज के भाग के रूप में 'रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन' के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है जिससे ईपीएफओ (EPFO) में नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिन्हित करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे । इस योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा । ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन किस्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 होगा । इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा 1 लाख का मासिक वेतन होगा । इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है ।

सरकार द्वारा उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे । इसके अतिरिक्त, इस साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्व सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे ।

प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की गई । 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा । हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा । उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार की जाएंगी और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे ।

इसी तरह हमारी सरकार ने घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे जिससे कई लोगो को लाभ मिलेगा ।

इस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए मकानों के आवश्यक आबंटन किए भी जा रहे हैं ।

देश में महिला-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं हेतु 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आबंटन की व्यवस्था की गई है ।

प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज

करते हुए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेंगे । इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।

हमारी सरकार ने मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है ।

देश में एमएसएमई के अंतर्गत सिडबी द्वारा 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवाएं देने हेतु अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोली जाएंगी जिससे लाभार्थियों को सीधे ऋण प्राप्त होगा । प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत 5 वीं योजना के रूप में, आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत करेगी । इस योजना में 5,000 प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 की सहायता दी जाएगी जिससे काफी लोगो को आर्थिक लाभ मिल सकेगा ।

मैं वित्तमंत्री जी की अद्भुत योजनाओं की सराहना करता हूँ जिन्होंने कृषि, पर्यावरण, और ऊर्जा क्षेत्रों में नए उत्पादन के अवसर प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है । इस बजट के माध्यम से हमारे देश को विश्व स्तर पर उच्च स्थान पर ले जाने का संकल्प दिखाया गया है ।

मैं यह कह कर अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा की यह बजट हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया एक सर्वजन हिताय बजट है ।

यह बजट देश के हर वर्ग के विकास एवं सामान्य जीवनशैली की हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के विकास को समर्पित इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी **(चित्तौड़गढ़) :** बजट वर्ष 2024-25 के लिये मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद एवं आभार ।

देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 11 वां बजट इस देश ने देखा हैं, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट में देश के किसानों, मजदूरों, युवाओं, आधारभूत अवसरंचनाओं, आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया हैं ।

देश की वित्त मंत्री महोदया आदरणीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बार भी बेहतर देश का बजट प्रस्तुत किया हैं ।

वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो 2023-24 में वास्तविक व्यय से 8.5 प्रतिशत अधिक है । इसी प्रकार 2024-25 में प्राप्तियां 32 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 में वास्तविक व्यय से 15 प्रतिशत अधिक है । सरकार ने 2024-25 में 10.5 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है ।

जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया था, हमें 4 मुख्य समूहों नामतः ?गरीब?, ?महिलाएं?, ?युवा? और ?अन्नदाता? पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है । अन्नदाता के लिए हमने एक महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने का वायदा पूरा किया । प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा ।

इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ।

बजट प्राथमिकताएं ? इस बजट में 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है ।

1) कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, 2) रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, 3) समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, 4) विनिर्माण और सेवाएं, 5) शहरी विकास, 6) ऊर्जा सुरक्षा, 7) अवसंरचना, 8) नवाचार, अनुसंधान और विकास, और 9) अगली पीढ़ी के सुधार ।

प्राथमिकता **1 :** कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता **:** परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान ? नई किस्मों को शुरू करना ? किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी ।

प्राकृतिक कृषि ? अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी ।

दलहन और तिलहन मिशन ? दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए, हम इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाएंगे ।

सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला ? प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे । हम उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देंगे ।

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना? प्रायोगिक परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर, हमारी सरकार, 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डी.पी.आई.) को लागू करने में सहायता ।

झींगा उत्पादन और निर्यात, राष्ट्रीय सहकारिता नीति? हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुँमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी ।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है ।

<u>प्राथमिकता **2 :** रोजगार और कौशल प्रशिक्षण</u> **:** रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन ? प्रधान मंत्री पैकेज के भाग के रूप में ?रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन? के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी ।

योजना कः पहली बार रोजगार पाने वाले ? इस योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 होगा ।

योजना खः विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन ? इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पहली बार रोजगार पाने वालों के रोजगार से जुड़ा है ।

योजना गः नियोक्ताओं को सहायता ? नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा । सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी । इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा है ।

कामगारों में महिलाओं की भागीदारी ? हम उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे ।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ? 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा । परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा ।

कौशल प्रशिक्षण ऋण ? सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ।

<u>प्राथमिकता **3:** समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय</u> **:** परिपूर्णता दृष्टिकोण ? शिल्पकारों, कारीगरों, स्व-सहायता समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला उद्यमियों और स्ट्रीट वेंडरों के आर्थिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री विश्वकर्मा, प्रधान मंत्री स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशनों और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाएगी ।

पीएम आवास योजना ? प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आबंटन किए जा रहे हैं ।

महिला-संचालित विकास ? महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं हेतु 3 लाख करोड़ से अधिक के आबंटन की व्यवस्था की गई है । यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है ।

प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ? जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, हम जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज करते हुए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करेंगे ।

<u>प्राथमिकता **4:** विनिर्माण और सेवाएं </u>**:** विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, एमएसएमई ऋण के लिए नया आकलन मॉडल, संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता ।

मुद्रा ऋण ? मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाएगा जिन्होंने ?तरुण? श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है ।

ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना, एम.एस.एम.ई. क्लस्टरों में सिडबी की शाखाएं, फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एम.एस.एम.ई. इकाइयां, ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र ।

विनिर्माण और सेवाओं के संवर्धन के उपाय शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप ? प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत 5 वीं योजना के रूप में, हमारी सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरूआत करेगी ।

औद्योगिक पार्क ? राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी ।

किराए का आवास ? औद्योगिक कामगारों के लिए वीजीएफ सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी ।

महत्वपूर्ण खनिज मिशन ? हम महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करेंगे ।

खनिजों का अपतटीय खनन ? हमारी सरकार पहले से किये गए खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू करेगी ।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग ? सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए, मैं निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभों, व्यवसाय अवसरों तथा नवाचार के लिए आबादी के पैमाने पर डीपीआई अनुप्रयोग विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ ।

आईबीसी इको-सिस्टम के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ? दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत परिणामों को बेहतर बनाने तथा निरंतरता, पारदर्शिता, समयोचित प्रसंस्करण तथा बेहतर पर्यवेक्षण हेतु सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ।

एलएलपी का स्वैच्छिक क्लोजर ? एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) की सेवाएं प्रदान की जाएंगी ताकि क्लोजर के समय को कम किया जा सके ।

ऋण वसूली ? ऋण वसूली अधिकरणों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे। वसूली में तेजी के लिए अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी ।

<u>प्राथमिकता **5:** शहरी विकास </u>**:** विकास केंद्रों के रूप में शहर-राज्यों के साथ मिलकर, हमारी सरकार ?विकास केंद्रों के रूप में शहरों? को विकसित करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी । आर्थिक और आवागमन की योजना तथा नगर आयोजना स्कीमों का उपयोग करके शहरों के आस-पास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा ।

शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास ? परिवर्तनकारी प्रभाव के साथ मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए, हमारी सरकार समर्थकारी नीतियों, बाजार आधारित तंत्र तथा विनियमन हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी ।

आवागमन उन्मुखी विकास ? 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।

शहरी आवास ? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा । इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी ।

जल आपूर्ति और स्वच्छता ? राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी में हम भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे ।

<u>प्राथमिकता **6:** ऊर्जा सुरक्षा </u>**:** ऊर्जा परिवर्तन ? हम समुचित ऊर्जा परिवर्तन पथ के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करेंगे जो रोजगार, विकास और पर्यावरण स्थायित्व की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम करेगा ।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ? अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप, एक करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है ।

पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, छोटे तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास, उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ?हार्ड टू एबेट? उद्योगों के लिए रोडमैप, पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सहायता ।

<u>प्राथमिकता: **7** अवसंरचना </u>**:** केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना निवेश ? केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना निवेश ? हम राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के अध्यधीन, अवसंरचना के लिए उसी पैमाने की सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करेंगे । राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है ।

अवसंरचना में निजी निवेश ? वीजीएफ तथा समर्थकारी नीतियों और विनियमनों के माध्यम से अवसंरचना में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा । एक बाजार आधारित वित्तपोषण फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा ।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ? जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएमजीएसवाई का चरण 4 आरंभ किया जाएगा ।

प्राथमिकता **8:** नवाचार**,** अनुसंधान और विकास **:** हम मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरूआत करेंगे । इसके अलावा, हम अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप 1 लाख करोड़ के वित्तीय पूल से वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे ।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था ? अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए 1,000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी ।

प्राथमिकता **9:** अगली पीढ़ी के सुधार **:** आर्थिक नीति फ्रेमवर्क ? हम आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएंगे और रोजगार के अवसरों तथा सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेंगे ।

राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार, ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य, शहरी भूमि संबंधी कार्य, श्रम संबंधी सुधार, श्रमिकों के लिए सेवाएं, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल, पूंजी और उद्यमशीलता संबंधी सुधार, वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति, जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी, परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश, एन.पी.एस. वात्सल्य, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, व्यवसाय करने की आसानी, डाटा और सांख्यिकी, नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) ।

अप्रत्यक्ष कर **:** औषधियां और चिकित्सीय उपकरण, मोबाइल फोन और उससे जुड़े पार्ट, आवश्यक खनिज, सौर ऊर्जा, समुद्री उत्पाद, दूरसंचार उपकरण आदि पर सीमा शुल्क कम किया जाना हैं जिस कारण से इन वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जायेगी ।

प्रत्यक्ष कर **:** नई कर प्रणाली के अंतर्गत नए कर स्लैब के साथ पर्याप्त राहत का प्रस्ताव किया जाता है, कर की दर निम्नानुसार है:- 3,00,000 रु. तक शून्य, 3,00,001 रू. से 7,00,000 रु. तक 5 प्रतिशत, 7,00,001 रु. से 10,00,000 रु. तक 10 प्रतिशत, 10,00,001 रू. से 12,00,000 रु. तक 15 प्रतिशत, 12,00,001 रू. से 15,00,000 रू. तक 20 प्रतिशत, 15,00,000 रु. से अधिक 30 प्रतिशत का कर का प्रावधान किया हैं । मानक कटौतीः वेतनभोगियों तथा पेंशनभोगियों को नई कर प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली मानक कटौती को 50,000 रू. से बढ़ाकर 75,000 रू. किए जाने का प्रस्ताव है । पारिवारिक पेंशन कटौतीः नई कर प्रणाली में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 15,000 रू. बढ़ाकर 25,000 रू. की जाने का प्रस्ताव है ।

DR.C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL): Thank you for giving me the opportunity to express my views on the General Budget presented by the hon. Finance Minister, Smt. Nirmala Sitaraman ji for the year 2024-25.

At the outset, I would like to congratulate the hon. Finance Minister for presenting a pro-development and pro-people Budget. The Government proposes to spend Rs.48,20,512 crores. It was Rs 45,03,097 crore in 2023-24, and it was Rs 39,44,909 crore in 2022-23. These statistics show that there is a significant increase in the proposed spending year on year.

The receipts except borrowings in 2023-24 are expected to be to Rs.32,07,200 crore. The receipts except borrowings in 2022-23 were Rs.22,83,713 crore. It is also seen a huge increase in comparison to the last year.

As we all know that India has already entered into the *'Amritkaal'* of Independence by completing 75 years of Independence. In order to put India on the path of continuous progress in this *'Amritkaal'*, the overall development of the country including the poor farmers, labourers, women, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and minorities is the need of the hour.

In her Budget, hon. Finance Minister under the able guidance and dynamic leadership of the Prime Minister, made her best efforts to bring a transparent economy and include all these sections of the society on the path of development. Despite economic disparity and the COVID-19 epidemic, India's GDP growth was between 6.5 to 7 percent. In the next five years, 4.1 crore youths will be provided an opportunity to earn through *Rojgar Kaushal Yojna*. One crore youth will be given the internship opportunity by applying on the portal of the top 500 companies in the country. Under this scheme, they will be given Rs.6000 in the first month and subsequently, Rs.5000 per month up to one year. This Budget has a provision of Rs.1.48 lakh crore for education, employment and development.

This Budget has made a provision of Rs 1.52 lakh crore for the farmers. It has provided Rs.1.75 lakh crore as an extra provision for fertilizers. Over the last ten years, approximately Rs.14 lakh crores have been provided as MSP beginning from the year 2014 to 2023.

Today, India holds the top position in milk production. It ranks first in the production of coarse grains and ranks second in the production of rice and wheat. Our Government has implemented 'Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojna', 'Ujjwala Yojna', 'Surya Ghar Yojna', 'Pradhan Mantri Awas Yojna', 'Ayushman Bharat

Yojna' and 'Pradhan Mantri Sadak Yojna'. Under the 'Jal Jeevan Mission', a provision has been made to supply water to every household. Eighty crore people are being provided free ration.

As a result of all these initiatives by the Union Government, 25 crore families have been uplifted today from the poverty line and have entered into the middle class category. Our Government has ensured 33 per cent reservation for women. Nearly 10 crore women work in Self-Help Groups and have become self-employed. I welcome the proposal of the Government to provide three crore houses to homeless people in the country. I am sure that these initiatives of the Government will certainly ensure that the benefits would reach to all the eligible beneficiaries of the society.

As far as railway projects of the State of Karnataka are concerned, an amount of Rs.7,500 crore has been allocated to implement 31 projects of total 3866 kilometers railway lines. Also, an amount of Rs.350 crore has been allocated for suburban railways in Bangalore.

I would like to request the hon. Railway Minister to allocate funds for Hejjala-Chamarajanagar railway line. It is a new line of 142 kilometers. It was touted to be an alternative line connecting Bengaluru with Chamarajanagar besides connecting Malavalli and Kollegal and bringing vast swathe of my Bengaluru rural Parliamentary constituency in Karnataka. Though sanctioned in 1997-98, the physical progress after more than 25 years after approval, is almost nil. So, I would like to request the hon. Minister to give top priority to the work on the proposed new railway line.

One of the most difficult thing is to provide corruption-free and scam-free administration in a democratic system. But Shri Narendra Modi ji has achieved this rare distinction in his last 10 years of governance. The hon. Prime Minister has taken a bold step to remove Article 370 from Kashmir, as a result normalcy is getting restored, and terrorist activities have come down significantly. There is a transition from terrorism to tourism. Nearly two million tourists have visited Kashmir in the last eight months.

Investment in climate resilient agriculture is a welcome step, which would reduce the use of water, pesticides and release of greenhouse gases.

This Budget has further strengthened MSMEs which generate lakhs of job opportunities and contribute about 29 per cent to GDP.

There is a phenomenal increase in our defence export by almost 30 times.

Under PMS Gram Sadak Scheme, Rs.19,000 crores have been provided for construction of roads in small and medium sized villages.

The Budget has all the ingredients to uplift poor, youths, farmers, women and people of middle classes. Despite global economic crisis, inflation is kept at 4.9 per cent which is a testimony of financial discipline.

With these words, I support this Budget.

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) : मैं तहेदिल से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया । जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ ।

मैं भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित एकता के प्रतीक सरदार वल्लभभाई पटेल जी के जी कर्मभूमि, 23 बारडोली लोकसभा गुजरात से जीतकर आया हूँ ।

हमारी तीसरी बार सरकार बनने पर हमारे देश का किसान, मजदूर, युवा और महिला, सभी वर्गों में खुशी की लहर है । नई सरकार का यह पहला बजट है । यह अमृत काल का पहला बजट है । यह वह बजट है, जो हमारे देश को विकसित भारत बनाने की नींव रखेगा ।

यह बजट नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है । इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी । यह मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है । यह जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है । इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित

करने में मदद मिलेगी । इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMEs को, यानी की लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा ।

इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है । इस बजट में किसानों को आत्मनिर्भर

बनाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं । कृषि क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद देने की घोषणा की गई है ।

अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम Vegetable Production Clusters बनाने जा रहे हैं । इससे छोटे किसानों को फल-सब्ज़ियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे और उनको आमदनी का बेहतर विकल्प मिलेगा ।

हमारी सरकार का ध्यान गरीबों पर है, किसानों पर है, मजदूरों पर है, युवाओं पर है ।

पिछले दस वर्षों में गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए अनोकों योजनाएं चल रही हैं । इन योजनाओं से उनको जमीनी स्तर पर बहुत फायदा पहुँच रहा है । किसान सम्मान योजना के तहत उनको प्रति वर्ष सरकार द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है । फसलों की कई जीन्सों पर एमएसपी बढ़ायी गई है । यह हमारे देश के छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा ।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह गन्ना किसानों का क्षेत्र है । हम देश को शुद्ध गुड़ और चीनी खिलाते हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी हमेशा यह कहते हैं कि यह देश तभी प्रगति कर सकता है, जब इस पुनीत कार्य में सभी वर्गों का सहयोग होगा । ?सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास? हमारा मूल मंत्र है । इसी मंत्र को हम विकास का मूल मंत्र मानते हैं । देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं ।

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने का फैसला हुआ है, वह बहुत महत्वाकांक्षी है ।

इस बजट में भी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को All

Weather Roads से जोड़े जाने का प्रस्ताव है । यह अद्भुत है । निश्चित ही इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर-दराज गांवों को मिलेगा ।

मैं इस बजट की इसलिए भी प्रशंसा करना चाहता हूँ क्योंकि इसके फोकस में देश का युवा है, ग्रामीण युवा है, उनके आँखों में जो सपने हैं, उसको सच में तब्दील करने का रोडमैप

हमारी सरकार के पॉलिसी और प्रोग्राम में है ।

यह बजट नए अवसर, नई ऊर्जा और नई उम्मीद लेकर आया है । यह ढेर सारे नए रोजगार,

स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है । यह Better Growth और Bright Future लेकर आया है ।

अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पांचवें नंबर पर है । जिस प्रकार नीतियों और कार्यक्रमों को पूरे मनोयोग से धरती पर उतारने का काम हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही

हमारा देश भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर विश्व पटल पर उभरेगा । यही हमारे देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा ।

इस बजट में मैन्यूफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया गया है, उतना ही जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दिया गया है । रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बनाना, हमारी सरकार की पहचान रही है । आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है । इस बजट में सरकार ने Employment Linked Incentive scheme की घोषणा की है । इससे देश में करोड़ों नए रोजगार बनेंगे । इस योजना से जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी ।

चाहे स्किल डेवलपमेंट हो और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप देने की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे-बेटी, देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे ।

इस बजट में यह परिकल्पना की गई कि हमें हर शहर, हर गाँव, हर घर में entrepreneurs बनाना हैं । इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है । निश्चित ही इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा ।

MSME सेक्टर से ही गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है । छोटे उद्योगों को बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है । इस बजट में MSMEs के लिए Ease of Credit

बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है ।

मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम

घोषणा की गई है । E-Commerce Export Hubs और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से ?वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट? अभियान को गति मिलेगी ।

यह बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है । Space इकोनोमी को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का फंड हो, Angel Tax हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं ।

मुझे खुशी है कि देश में 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, नए सैटलाइट टाउन्स का विकास

और 14 बड़े शहरों के लिए Transit Plans, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिनसे देश में नए economic hub विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोज़गार बनेंगे ।

पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में भी कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं । इसलिए आज डिफेन्स सेक्टर में भी भारत से एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर हैं । इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं । यह इंडियन इकोनॉमी का एक अट्रैक्शन बनकर उभरा है ।

हमारी सरकार ने पिछले दस वर्षों में देश में पर्यटन के क्षेत्र में, ऐवीऐशन सेक्टर में, संस्कृति के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है । इसलिए, आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई

संभावनाएं बनी हैं । टूरिज्म क्षेत्र, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेकर आता है । इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है ।

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हमारी विरासत को सहेजने का पावन प्रयास है । निश्चय ही इनसे हमारे यहाँ पर्यटन में वृद्धि होगी । इस बजट में गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर को विकसित करना और राजगीर में पर्यटन स्थल को विकसित करने की घोषणा सर्वाधिक लाभकारी है ।

माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है, वह इस बात की तसल्ली करता है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे ।

इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है । TDS के नियमों को भी सरल किया गया है । इन कदमों से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है ।

इस बजट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि देश के विकास के पथ पर पिछड़ रहे देश के पूर्वी भाग को महत्ता देते हुए उनके लिए एक नए अभियान ?पूर्वोदय" आरंभ करने का दूरगामी निर्णय लिया

है । इसके तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विकास के लिए नए कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना है । पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी । पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर

प्रोजेक्ट्स का निर्माण होने से देश में विकास को नई गति मिलेगी ।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि यह बजट नए संसद भवन में 18 वीं लोक सभा के दूसरे सत्र में पेश किया एक युगांतरकारी बजट होगा और यह देश को विकसित और विश्वगुरु बनाने की दिशा में launching पैड साबित होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए इस क्रांतिकारी बजट

बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): I would like to thank the Finance Minister for a visionary Budget which exemplifies the Government's unwavering commitment to Viksit Bharat and the goal of making India the third-largest economy by 2027.

The Government proposes to spend Rs. 48,20,512 lakh crore for the nation?s development this year. And it was spent Rs. 45,00,097 crore during 2022-23 and Rs. 39,44,909 crores in 2021-22.

Under the able leadership of hon. Prime Minister, a transparent economy has been put in place since 2014. Despite economic disparity and the COVID Pandemic, GDP growth of 6.50 to 7.0 per cent has been estimated in the Economic Survey and this country is set to become a Five million Dollar Economy in the coming one or two years.

I would like to highlight certain aspects of the Budget which is helping to become Viksit Bharat by 2047. This Budget focuses on infrastructure and capital expenditure, take the country's villages, farmers and poor on the path of prosperity, and set advancement towards an all-round development.

I welcome the allocation of over Rs 3 lakh crore for women development initiatives. In urban housing, an investment of Rs 10 lakh crore and for rural roads programme, a budget of Rs 26,000 crore is a big push to infrastructure development. I would also thank the commitment of the Government to give support to one crore families for housing and welfare support through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to about 80 crore people.

This Budget allocated Rs. 7,500 crore to implement 31 Railway projects of 3,866 km in the state of Karnataka. At this juncture, I would request to provide further financial support for these following issues of my constituency on priority:

1) Visweswaraya Iron and Steel Plant, Bhadravathi (VISL) unit under the Steel Authority of India Limited (SAIL) is located in my home district Shimoga. It holds historical significance and has played a pivotal role in India's industrial landscape since 1923 with an employment of 1000 dedicated employees and 2000 contractual labourers. Now, VISL granted approval for 150 acres of iron ore land in Bellary district which is ready to operate by 2025. This plant truly has immense potential for revival and growth. In this regard, I am requesting to exclude' Visweswaraya Iron and Steel Plant (VISL)? from disinvestment and request your intervention to reconsider the revival of VISL, by ensuring adequate investment through SAIL and

financial support for a vibrant and sustainable future for VISL, which is benefitting the region and the nation at large.

2) The famous Tourist and Pilgrimage corridor Kolluru, Kodachadri of Byndhur Talk is having ample opportunities for the growth of tourism. There were about 10 to 20 thousand devotees who were visiting daily at the famous Shakti peehtas and pilgrimage Temple of Sri Mookambika Devi of Kollur and the divine centre Kodachadri hills. The proposal of providing Cable Car from Kodachadri to Kollur which is considered for sanction by NHLML during the year 2023 helps to boost the development of tourism.

The most beautiful Maravanthe beach located along the highway NH66 and river Souparnika on the other side is also having big opportunities for development of tourism. In this regard I am requesting to extend the financial support for development of this Tourism corridor.

Further, it is to bring to the kind notice of the Government that Udutadi or Udugani), the capital of King Kaushika during the 12th Century is now a small village in Shikaripur taluk of Shimoga District in Karnataka. Sharane Akka Mahadevi was the greatest saint of the 12th Century, great devotees of Para Shiva in Udutadi Village, around 1130.. Her verses in Kannada are known as Vachanas. The development of Sri Akkamahadevi heritage project will attract both national and international tourists, and will become a place of worship and knowledge centre. This will help in spreading the valuable preachings to overall benefit of the entire mankind across the globe as being promoted by our hon. Prime Minister- Vasudhaiva Kutumbakam. At this juncture, financial assistance from GOI will benefit the development of this tourist and pilgrimage centre.

3) I'm requesting to consider the proposal of doubling work between Birur (RRB) and Shivamogga (SMET) section and new Railway lane from Mookambika road Byndoor-Kollur-Hebrii-Karkala-Dharmastala-Uppinangadi -Putthur.

4) Further, I am requesting to consider the proposal of up gradation of state Highway SH 25 Shimoga-Harihara-Mariyammanahalli road of length 182 km land having an average traffic of 12000 to 20000 PCUD, which was approved, in principle, as aNational Highway during 2015.

I also wish to bring to the kind notice of the Government that all Highways from the State of Karnataka pass through Western Ghat hills to connect coastal line. and, during this rainy season, roads were blocked and closed due to slips of hillock earth

for long duration in almost all ghat sections roads. It is too unsafe to travel through these ghats during rainy season.

The Agumbe ghat situated in middle of the State and the proposal of construction of tunnel road leads to safe journey towards coastal lane from Karnataka. In this regard, on the occasion of inaugural function of works at Shimoga during February, 2022 the hon. Union Minister of MoRTH announced the proposal of Tunnel for Agumbe ghat will be considered for sanction.

At this juncture I am requesting to consider these important proposals for approval with necessary financial support.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): The Union Budget 2024 marks a significant milestone in our journey towards a Viksit Bharat. It stands as a testament to the unwavering faith the people of India have in this Government. This Budget is transformative and forward-thinking. With pro-poor, pro-farmer, and growth-oriented measures, it unites the interests of farmers, the middle class, youth, and small businesses under one umbrella.

I extend my congratulations to the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, for presenting such a comprehensive budget for the record seventh time. This Budget truly lays a strong foundation for inclusive growth, sustainable development, and economic resilience.

The 2024 Budget has clearly defined its nine priorities: productivity and resilience in agriculture, employment and skilling, inclusive human resource development and social justice, manufacturing and services, urban development, energy security, infrastructure, innovation, research and development, and next-generation reforms. These priorities light the path ahead toward progress. As our hon. Prime Minister has aptly said, "This Budget will serve as a catalyst in the process of making Bharat the third largest economic power in the world, laying a solid foundation for a developed nation."

The Indian economy is moving in the right direction, and we are on the path to a golden future. Despite global challenges, our exports hit a record $776.68 billion in the last financial year. This achievement has shown our country's strength and competitiveness on the world stage. Our government has demonstrated fiscal prudence by lowering its deficit target to 4.9 percent of GDP, down from 5.1 percent as presented in the interim budget. The unemployment rate has seen a notable decline to 3.1 percent. While business activity and job creation are at an 18-

year high, reflecting a robust economy. This progress shows the resilience and determination of our people and the visionary leadership guiding us.

The agricultural sector is the very foundation upon which our society thrives. Our farmers play a pivotal role in ensuring food security. Over the past five years, the agriculture sector has grown at an annual growth rate of 4.18 percent. The seeds for a prosperous and self-reliant Bharat are being sown through significant provisions for the agriculture and its allied sectors with a substantial allocation of Rs. 71.52 lakh crore.

One of the many takeaways from the Budget in the agriculture sector is - over the next two years, 1 crore farmers will transition to natural farming. To ensure the all-round development of the cooperative sector, a new the National Cooperation Policy will be introduced. By leveraging the power of digital technology to enhance food security, the Digital Public Infrastructure (DPI) in agriculture will be implemented over the next three years. This will provide timely and reliable agricultural information to our farmers giving them better decision-making tools. These are just some of the many steps this Budget has introduced to not only support our farmers but also to empower them.

This Government recognizes the importance of skill development and employment in driving economic growth, and this budget is a clear testament to that. It is about creating opportunities, providing support, and building a stronger, more skilled India.

The schemes under the 'Prime Minister's 'Employment Linked Incentive' will be a game-changer for employment and skill development.

These schemes will focus on enrolling new employees in the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), recognizing first-time employees, and supporting both employees and employers.

In a groundbreaking move, this Budget includes a scheme offering internships in 500 top companies to one crore youth over the next five years. I am confident that this forward-thinking scheme will greatly benefit the youth of India by providing them with invaluable experience and opportunities for growth.

Making sure that there is something for everyone, this Budget includes financial support for higher education loans up to 710 lakh to 1 lakh students each year. This

means more students can pursue their dreams without any financial burden holding them back.

India is shifting from women's development to women-led development.

This transformation is evident through initiatives like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), which has opened 52.3 crore bank accounts, with women holding 55.6 percent of these accounts. The Deendayal Antyodaya Yojana-NRLM, covering over 89 million women in 8.3 million Self-Help Groups (SHGs), has empowered women, boosted their self-esteem, and enhanced their role in society.

To further this commitment, the 2024 Budget allocates over 73 lakh crore for schemes benefiting women and girls. To support women in the workforce, working women hostels and crèches are being established in collaboration with industry partners. Women-specific skilling programs are being organized to enhance their employability, and market access for women-led SHG enterprises is being promoted, empowering women both economically and socially.

The Government's commitment to economically disadvantaged urban residents and the middle class can be seen in the substantial investment of 710 lakh crore in urban housing under the Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0. To make buying more accessible and attractive, stamp duty will be reduced, lower rates will be available for female buyers, and property data will be digitized.

The PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants, enabling 1 crore households to receive free electricity up to 300 units every month. It has seen a remarkable response, with over 1.28 crore registrations and 14 lakh applications. I am heartened to see this enthusiastic participation which demonstrates India's commitment to sustainable energy solutions and the potential for widespread adoption of renewable energy sources.

When we look at the Budget, it is not just target-based but also outcome-based. The Government has a clear roadmap in improving rural road infrastructure. Since 2014, 3.74 lakh km of roads have been constructed under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY). This means over 99 percent of rural areas are now connected by roads showing this government's dedication in improving rural connectivity.

To further this progress, the Government will launch Phase 4 of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana aiming to provide all-weather roads to 25,000 rural habitats.

This commendable step will significantly boost connectivity and support economic growth in these areas.

India has made impressive progress in the World Bank's Doing Business Report, jumping from 142nd place in 2014 to 63rd in 2019. Showing an improvement of 79 ranks in just five years. The Government has been backing MSMEs all along, and I would like to take this opportunity to specifically mention the support provided to the MSME sector in Jamnagar, which is my constituency.

To keep this momentum going, Budget 2024 has introduced a comprehensive support package for MSMEs. A major highlight is the new credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector, offering coverage up to Rs. 100 crores. The Mudra loan limits for entrepreneurs have been increased, and SIDBI branches will expand in key MSME clusters, promoting substantial business growth. In a transformative step, the establishment of E-Commerce Export Hubs through a Public-Private Partnership (PPP) model will allow MSMEs and traditional artisans to market their products internationally. I am proud to represent a constituency with a significant MSME presence. By supporting these initiatives, we are not only fostering innovation and growth but also ensuring a brighter future for countless entrepreneurs and workers. I wholeheartedly commend the Government for the proactive initiatives outlined in Budget 2024. The economic transformation has been remarkable, and the holistic approach to development adopted by the Government will take our country to greater heights. As we navigate towards the future, the Union Budget 2024 stands as a testament to sound economic management and visionary leadership. I am confident it will ensure that India emerges stronger and more prosperous in the years to come.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): I would like to express my views on the Union Budget 2024-25.

The Budget analysis usually goes where the ruling party and its allies will praise it to the skies and the opposition parties will dump it in either the Bay of Bengal or the dustbin. However, the true appraisal comes from the general public and they have criticized the Budget no end. They claim that this Budget has destroyed the already struggling middle-class of this country.

The tinkering of the income tax claiming benefit of Rs. 12,500 for tax-payers is pitiable.

The decision to remove indexation in the long-term capital gain will have adverse effects in the economy of this country and I hope, the FM will repeal it.

Also, the increase in the short-term and long-term capital gains tax will punish the people who are already in doldrums.

The way to improving the economy of the common man starts from giving good education to all. This has been achieved in States like Tamil Nadu and Kerala. The New Education Policy which proposes public examination in class 5 and class 8 will only reduce the possibility of education to crores of children.

This Government harps about emergency where Indira Gandhi ji and every congress person including Rahul ji have accepted that it was a bad decision. But this Government does not want to set right the amendment which shifted Education from the State List to the Concurrent List. I hope, they will set it right by shifting Education back to the State List.

The BJP Government does not have any moral standing to talk about the emergency as they have unleashed an undeclared emergency, corrupting the constitutional bodies. The Enforcement Directorate has become the *?* * Directorate. The Income Tax Department has become the ?Inquest Terror Department?. The Central Bureau of Investigation has become the *?**

The Supreme Court striking down heavily on the electoral bonds (or aptly *?* * Bond) and irregularities will be a historic blot on this Government for centuries to come.

This Government claiming credit for becoming the fifth largest economy based on GDP is sad. It has been proved that GDP does not reflect the condition of its people. Hence, several other indicators are used to assess the growth of its people, like Human Development Index (HDI), *per capita* income, Gini Coefficient, Happiness Index etc. We rank very poorly in all of these indices. In fact, to be called a developed country, our *per capita* income has to be 15,000 USD while in reality, it is a paltry 2,500 USD.

This Government does not understand or value the federal nature the founding fathers wanted India to be. India is more like the European Union where we are a Union of States with varied languages, food habits, clothing, culture and customs. The Union Government should restrict itself to defence, post, external affairs, civil aviation and railways, and allow other decision to the States.

The alarming rate of accidents in railways questions the decision of this Government to deny a separate Railway Budget.

The alarming rate of naval accidents (incidents in the last ten years, especially during peace time and not war time) raises doubts on the defence capability, with hostile neighbours like Pakistan and China. Especially the recent incident of ?keel over? of INS-Brahmaputra, a Rs. 6,000 vessel, is alarming as it happened while launching it in the dock.

The appeasement Budget with special focus on Bihar and Andhra Pradesh is criticized even by the common man for the new found love of this Government to these two States despite their problems being the same for more than a decade.

The Government has not only forsaken the Opposition-ruled States like Tamil Nadu, Kerala, Telangana, West Bengal and Delhi, but has also punished its own States like UP, Maharashtra and Rajasthan for having defeated them in the 2024 elections.

I oppose this Budget for the step-motherly treatment of several States which have defeated the BJP and also the middle class.

I hope that the hon. Finance Minister sets right these wrongs by heeding to the voices of dissent.

DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI): I want to thank the hon. Finance Minister wholeheartedly for two aspects. First, for letting go poor Thiruvalluvar and the artificial affection, which is also called hypocrisy, towards Thirukkural, Tamil, Tamilargal and Tamil Nadu. I pity you. I am reminded of the boyhood story where a greedy fox jumps to reach the grapes in the vineyard and after many failures, the fox quits and says, ?I do not want sour grapes....?. I pity the fox, poor fox, unlucky fox, and selfish fox for abandoning the vineyard. Like sour grapes, Tamil Nadu has become sour for the hon. Minister that she did not even mention Tamil Nadu in her self- elating budget speech. Second, for neglecting the interest of Tamil Nadu, neglecting seven crore Tamilians, and neglecting the economic super power, Tamil Nadu.

Our mentor, Aringar Anna rightly and rightfully named our State as Tamil Nadu. ? Nadu? in Tamil is our own land or country. ?Tamil Nadu? is a country within a country in truest sense of self-sustenance. After you neglected Tamil Nadu in your speech, you have rekindled the spark of Tamil country which is nothing but Tamil

Nadu. Do not worry, Madam. We will keep paying GST to the Government so that the friendly States of the Government are taken care of to protect the minority Government from falling.

I would like to start my speech with the blessings of my mentor, former Chief Minister of Tamil Nadu, Late Muthamizh Arignar Kalaignar M. Karunanidhi and the present DMK leader and Chief Minister Thalapathi M.K. Stalin. This Budget is anti-people but pro-NDA which can be seen from the discrimination in the allocation of funds allotted to non-NDA ally-ruled States versus NDA ally-ruled States. For example, no funds have been allotted to schemes in my State of Tamil Nadu. Putting it in perspective in the words of our Chief Minister, Thiru. M.K. Stalin, the Union Budget did not seem to cover all of India and was more like ?an agreement or alliance? with the rulers of Bihar and Andhra Pradesh for ?political reasons?. The States like Tamil Nadu, which have contributed to the country's development, were being targeted. It is painful that the BJP-led Union Government is using the Union Budget to settle electoral scores. It will affect the people of Tamil Nadu.

There is ?no specific project? in the Budget for the people of Tamil Nadu. The promises of substantial budget allocations for Bihar and our neighbouring State of Andhra Pradesh have not been backed by significant financial assistance from the Union Government. Most of the spending is expected to be financed through borrowing, particularly from multilateral development banks (MDBs) with the Union Government's facilitation. Even if MDBs provide funding, it will only add to the debt burden of these States. Furthermore, considering the borrowing restrictions imposed on the States, it is not certain how this debt for the proposed purposes can be regarded as ?additional? to what the States might have already chosen to incur. We think the hon. Finance Minister has taken a photocopy of many successful schemes being implemented in Tamil Nadu and used them in the Union Budget, but you have not come up with a single scheme for Tamil Nadu, the State which has given you to this country.

The Union Budget is a ?huge disappointment? to the middle class, and even the few relaxations announced do not apply to those in the old income tax regime. The AIIMS Madurai project has no significant progress except some announcements being made from time to time and there has been no significant budgetary allocation. The Budget does not speak about any new projects for Tamil Nadu in the railway sector. It may be noted that Royapuram is one of the oldest standing railway station buildings in the Indian sub-continent and Royapuram made history

by rolling out the first train service in the Carnatic region when a train rolled from Royapuram in erstwhile Madras to Wallajah Road. Such is the history and heritage of railways in Tamil Nadu but you have turned a blind eye and deaf ear to Tamil Nadu's demand for new schemes and trains in the railway sector.

Now let me turn my attention toward the micro aspects of the Budget. The Modi-led anti-farmer Government has always been against the farmers, which is evident from this year's Budget. The fertilizer and food subsidies have been reduced. The allocation for the Fertilizers Department is Rs. 1,64,150.81 crore. In the Revised Estimates in 2023-24, the amount was Rs. 1,88,947.29 crore and the actual expenditure incurred in 2022-23 was Rs. 2,51,369.18 crore. There is a ?huge decline? of about 34.7 per cent in the allocation for fertilizers. Compared to the 2022-23 actuals, it amounts to a decrease of Rs. 87,238 crore and this will have a deleterious impact on agricultural productivity.

There is a mismatch between the problems at hand and what the Budget offers is even more blatant when we look at the agriculture sector. Farmers are not able to make both ends meet and have a decent livelihood because crop production has become economically unviable and they have been demanding procurement at a legally guaranteed minimum support price. The Budget promises a long-term program to raise productivity and production. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) allocation, there is a different trend, for the financial year 2024-25, Rs. 86,000 crore has been allocated for the MGNREGS. This may be Rs. 26,000 crore more than last year's allocation of just Rs. 60,000 crore, but it is still Rs. 19,297 crore less than the scheme's actual expenditure of Rs. 1.05 lakh crore in the financial year 2023-24, according to data available on the website of the Union Ministry of Rural Development. As per an analysis, this year's allocation for the MGNREGS is just 1.78 per cent of the budgetary allocation, a 10-year low in the scheme's funding.

The rural jobs scheme has been persistent by the problem of under-allocation of funds. The lower allocation artificially suppresses the demand for work under the scheme. The allocation for financial year 2024-25 is less than the expenditure in financial year 2023-24. It also does not take into account the increased demand in the first quarter of this financial year.

The minorities in the country are in a condition of real danger with the anti-minority temperament of the BJP-ruled Union Government and BJP-led State Governments. There has been a meagre increase in funds allocated for the Ministry

of Minority Affairs and most of the schemes have also seen budgetary cuts. The Ministry of Minority Affairs has seen a mere 2.7 per cent increase from funds allocated in the previous year's Budget Estimate (BE) for the financial year 2024-25 in the Union Budget. This allocation is only about 22 per cent of the Revised Estimate (RE), but the budget allocation for schemes like coaching and education loans has been reduced. It can be seen from this year's Budget Estimate that the Ministry has been allocated 0.07 per cent of the Government's total outlay, which amounts to a mere 0.01 per cent increase compared to last year's share of the total outlay. The budget estimate for the coaching and allied schemes for minorities has been cut from Rs. 30 crore in 2023-24 to Rs. 10 crore in 2024-25. The Revised Estimate for this scheme in 2023-24 was Rs. 14 crore. The Budget Estimate for the interest subsidy on educational loans for overseas education for minorities has also been reduced from Rs. 21 crore to Rs. 15.30 crore. The revised estimate for this scheme was Rs. 7 crore.

The Finance Minister has failed to help her gender in upliftment. The budget allotted for the Ministry of Women and Child Development has been reduced by 0.03 per cent. The Budget Estimate for 2024-25 is Rs. 26,092 crore, and the Revised Estimate in 2023-24 was Rs. 25,448 crore. The Government's policy of skipping core economic issues, such as rural distress, widespread unemployment, and food price inflation, could end up being quite expensive.

In the 2024-25 Budget, the National Social Assistance Programme, which includes pensions and disability benefits, has been allocated the same amount as the revised estimates for 2023-24, which is Rs. 9,652 crore. Similarly, the allocation for the National Rural Employment Guarantee Programme for 2024-25 matches the revised expenditure estimate for 2023-24. Despite the extension of free foodgrain allocation under the National Food Security Act, the budgeted food subsidy is set to decrease from Rs. 2,12,332 crore (RE 23-24) to Rs. 2,05,250 crore (BE 24-25).

To sum up I would say that this Budget is just a BJP and Modi Budget to satisfy those people who have voted in BJP's favour and an anti-people Budget. The Budget is filled with full of gas and lacks not only substance but finance too.

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 के समर्थन में मैं अपने कुछ बिन्दु प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

वित्त मंत्री जी ने करदाताओं की माँग को पूरा किया है और नई कर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की है । स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है । नया टैक्स स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है । 0-3 लाख रुपये पर शून्य टैक्स, 3-7 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत टैक्स, 7-10 लाख पर 10

प्रतिशत, 10-12 लाख पर 15 प्रतिशत, 12-15 लाख पर 20 प्रतिशत और 15 लाख और उससे अधिक पर 30 प्रतिशत टैक्स होगा । नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी ।

विकसित भारत के लिए निम्न 9 प्राथमिकताएं हैं:-

कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रा, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के सुधार ।

बजट में सरकार ने स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ।

5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार

इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने कहा, मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को 15 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव है । इसके अलावा सरकार ने सोने और चाँदी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है । उन्होंने आगे कहा है कि अगले 6 महीनों में कस्टम ड्यूटी संरचना की बारीकी से समीक्षा की जाएगी । ई-कॉमर्स पर टीडीएस रेट को घटाकर 0.1 प्रतिशत किया जाएगा ।

इसके अलावा दान के लिए दो टैक्स छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाए । कर दाखिल करने की तारीख तक टीडीएस में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है । एक लाख करोड़ रुपये के वित्तीय कोष से निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा । काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बिहार में गलियारों का निर्माण होगा । 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप कराएगी । छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर फोकस दिया जाएगा । इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा । पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा । जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी । इस योजना से 63 हजार गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे ।

2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा । 16 हजार करोड़ रुपये की कुल लागत से सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास किया जाएगा । एमएसएमई को टर्म लोन के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का प्रस्ताव किया गया है । देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा ।

प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू की जाएंगी । ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेगी ।

क्या-क्या सस्ता हुआ है: बजट में दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है । इससे कैंसर संबंधी कुछ और दवाओं की कीमतों में कमी आएगी । फोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी

15 फीसदी घटाई जाएगी, इससे फोन सस्ते होंगे । सोने और चाँदी पर छह फीसदी कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है । 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है ।

रोजगार के क्षेत्र में निम्न प्रावधान बजट के माध्यम से किए गए हैं ।

केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी । घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने का ऐलान किया गया है । हर साल एक लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स दिए जाएंगे । रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे । इससे 4.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा । केंद्र सरकार की ओर से 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी । हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में एक हजार आईटीआईज को हाईटेक किया जाएगा । शीर्ष कंपनियों में 5 साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा । 5 हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी । ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का सीधा लाभ, अनुदान, तीन किस्तों में 15 हजार रुपये तक दिए जाएंगे । सीमा-एक लाख रुपये प्रति महीना वेतन, दो करोड़ से ज्यादा युवाओं को इसका फायदा होने की उम्मीद है।

धन्यवाद ।

श्री विनोद लखमशी चावड़ा (कच्छ) : वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 का आम बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले सभी बजट की तरह ही आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप है । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके संदर्भ में अंतरिम बजट में काफी प्रावधान किए गए थे । यह बजट उसी का विस्तारित रूप है । बजट को समग्रता में देखे जाने की आवश्यकता है । यह एक साथ व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन के साथ कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने, स्वरोजगार सृजन पर बल देने, भारत की विरासत तीर्थ और पर्यटन स्थलों को विकसित करने तथा सबके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विस्तार पर फोकस करने वाला बजट है । यानी यह नरेंद्र मोदी सरकार की पूर्व नीतियों को आगे बढ़ा रहा है । भारत के वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से इसे एक शानदार बजट कहा जा सकता है ।

आप देखेंगे कि 10 वर्षों के अनुभवों के आधार पर उन सारे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां-जहां सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है । माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर हैं ।

बजट में प्रधानमंत्री जी द्वारा सशक्तिकरण हेतु बनायी की चार जतियों गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है ।

विकसित भारत के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर नौ क्षेत्रों पर फोकस का अर्थ व्यवहारिक नीतियों का आधार तय हो जाना है । ये हैं, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार । रोजगार की दृष्टि से देखें तो 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए जिन पांच योजनाओं और पहलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा है वो व्यावहारिक हैं । शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है । अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, 54 लाख को अपस्किल या रि-स्किल किया गया है । पीएम मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना ऋण दिए गए । 3000 नए आईटीआई, सात आईआईटी, 16 आईआईआईटी, सात आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है । वस्तुतः नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर पदों की संख्या बढ़कर 1.09 करोड़ हो गई है, लेकिन नौकरी के लिए पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 87.2 लाख ही है । नौकरी की संख्या बढ़ने के बावजूद काफी युवा वंचित हैं तो इसका कारण स्किल के मापदंड पर खरा नहीं उतरना है । अब तक हम स्किल के मापदंडओं पर काफी पीछे हैं ।

इस दृष्टि से बजट में युवाओं की इंटर्नशिप की एक ऐसी विशिष्ट योजना है जिसकी ओर पहले ध्यान नहीं गया था । एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में शीर्ष-500 कंपनियों में 12 महीने के लिए इंटर्नशिप की योजना इस बजट का प्रमुख आकर्षण है । सीधे काम करते हुए स्किल विकास की ऐसी योजना पहले नहीं आई थी । इसमें इंटर्नशिप करने आए युवाओं तथा कंपनियों पर भी बहुत ज्यादा भार नहीं दिया गया है । युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता तथा एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे । कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 प्रतिशत लागत वहन करना होगा । कॉरपोरेट अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हर वर्ष एक निश्चित राशि खर्च करते हैं । उन्हें उसी में से प्रदान करना है । इस तरह यह पूरी तरह व्यावहारिक है । कल्पना करिए अगर यह सफल रहा तो आने वाले समय में भारत कैसे स्किल वाले युवाओं का देश बन जाएगा । प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा भी विशिष्ट है । दाल और दलहन के मामले में आत्मनिर्भरता और इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन पर फोकस है । खाद्य तेल वाली फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने, सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति शृंखला के लिए कलस्टर बनाने, भंडारण और विपणन के ढांचों का विकास और प्रसार, एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने, कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना के साथ राज्यों ने सहयोग किया तो कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है । 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाने की बात है ।

सरकार ने रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया है । रेलवे को मजबूत बनाने और नई सुविधाएं लाने के लिए सरकार ने 2,62,200 करोड़ रुपये कैपेक्स के तौर पर दिए हैं । ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 2,52,200 करोड़ रुपये है । सरकार का लक्ष्य है कि अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएं । बजट का बड़ा हिस्सा सेफ्टी के लिए जाएगा । 1,08,000 करोड़ से पुराने ट्रैक्स, सिग्नलिंग, कवच, रेल के पुल बनाने में लगेंगे । इसके साथ ही वंदे मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी । वंदे मेट्रो कम दूरी के सफर के लिए होगी, जबकि वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी और रात की यात्रा के लिए होगी । इस

बजट में स्वदेशी तकनीक से बने 'कवच' सिस्टम पर भी जोर दिया गया है, जो ट्रेनों की सुरक्षा को और मजबूत करेगा ।

बजट के सारे प्रस्तावों पर यहां विचार करना संभव नहीं है । भारत सरकर लोक-लुभावन घोषणाओं से बचते हुए देश के समग्र विकास के लिए दूरगामी सोच और योजनाओं पर आगे बढ़ रही है इसका लाभ सभी क्षेत्रों को मिल सकेगा । अध्यक्ष महोदय मैं पुनः आपको एवं माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देता हूं एवं मैं बजट 2024-2025 का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : हम सभी जानते हैं कि बजट किसी भी देश की आर्थिक नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है । यह सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं का प्रतिबिंब होता है । लेकिन जब यह बजट विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए ।

कृषि क्षेत्र : पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के कृषि बजट में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है । लेकिन यह केवल संख्या का खेल है । असल मुद्दा यह है कि क्या यह बढ़ी हुई राशि किसानों तक पहुंच रही है और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है? वास्तविकता में, केवल बजट बढ़ाने से किसानों की समस्याएं हल नहीं होतीं । कई बार यह देखा गया है कि बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होता । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद, बीज, और कीटनाशकों की कीमतों में औसतन 15% की वृद्धि हुई है । उदाहरण के लिए, यूरिया की कीमत 2023 में 266 रुपये प्रति बोरी थी, जो 2024 में बढ़कर 306 रुपये प्रति बोरी हो गई है । इस महंगाई का सीधा असर किसानों की आय पर पड़ता है, जो कि बजट में की गई मामूली वृद्धि को बेअसर कर देता है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, और फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पातीं । बजट में आवंटन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है अगर उसका उपयोग सही तरीके से नहीं होता ।

शिक्षा क्षेत्र: पिछले वर्ष (2023-24) शिक्षा मंत्रालय को कुल 1.12 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस वर्ष (2024-25) इसे बढ़ाकर 1.18 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है । यह लगभग 5% की वृद्धि है । हालांकि, यह वृद्धि शिक्षा क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । UNESCO के अनुसार, भारत को अपनी GDP का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, जबकि वर्तमान आवंटन केवल 3.1% है । शिक्षा किसी भी देश की प्रगति का मूलभूत आधार है । लेकिन आज भी हमारे सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है । शिक्षक की कमी, पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता और गुणवत्ता की शिक्षा में कमी हमारे भविष्य को खतरे में डाल रही है । बजट में शिक्षा के लिए आवंटन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह धन सही तरीके से खर्च हो । पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के शिक्षा बजट की तुलना करते समय केवल संख्याओं की वृद्धि पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है । वास्तविकता में, शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं । बजट की बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की कमी, मिड-डे मील योजना, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा के मुद्दों का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा बजट का प्रभावी ढंग से उपयोग हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्र: महामारी ने हमें यह सिखाया है कि मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की कितनी जरूरत है। बावजूद इसके, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों और नर्सों की कमी और दवाओं की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं आम हैं। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की जाती, जो कि चिंता का विषय है। पिछले वर्ष (2023-24) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कुल 86,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस वर्ष (2024-25) इसे बढ़ाकर 92,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह लगभग 6.7% की वृद्धि है। हालांकि, यह वृद्धि स्वास्थ्य क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। WHO के अनुसार, भारत को अपनी GDP का कम से कम 5% स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, जबकि वर्तमान आवंटन केवल 2.5% है। देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 60% सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पीने का पानी, और बिजली की कमी है। बजट में इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। देश में डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। 2023 में, देश में लगभग 2 लाख डॉक्टरों और 5 लाख नर्सों की कमी थी। बजट में इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 10,000 जनसंख्या पर केवल 1 डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि WHO मानक के अनुसार यह संख्या 1:1000 होनी चाहिए।

रोजगार और उद्योग: देश की युवाशक्ति को रोजगार देने के लिए उद्योगों का विकास आवश्यक है। लेकिन मौजूदा बजट में छोटे और मझौले उद्योगों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। बेरोजगारी दर बढ़ रही है और नई नौकरियों के सृजन के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पिछले वर्ष (2023-24) श्रम और रोजगार मंत्रालय को कुल 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस वर्ष (2024-25) इसे बढ़ाकर 14,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह लगभग 11.5% की वृद्धि है। हालांकि, यह वृद्धि रोजगार क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत को अपनी GDP का कम से कम 3% रोजगार पर खर्च करना चाहिए, जबकि वर्तमान आवंटन केवल 0.5% है। देश में बेरोजगारी दर अभी भी एक गंभीर समस्या है। 2023 में बेरोजगारी दर 7.5% थी, जो 2024 में भी लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है। खासकर युवा बेरोजगारी दर 20% के आसपास है। बजट में बेरोजगारी के समाधान के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। आज मैं आपके सामने यह स्पष्ट करने के लिए खड़ा हूँ कि क्यों पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के रोजगार बजट की तुलना पर्याप्त नहीं है। हमें केवल बजट में बढ़ोतरी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि यह बढ़ा हुआ बजट वास्तव में रोजगार क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में कितना प्रभावी है।

पर्यावरण और स्थायित्व: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की समस्याएं हमारे सामने बड़ी चुनौती हैं। बावजूद इसके, बजट में पर्यावरण संरक्षण और स्थायित्व के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। हमें हरित ऊर्जा स्रोतों, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस योजनाओं की जरूरत है। देशभर में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं। बजट में वायु प्रदूषण के समाधान के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के लिए आवंटन पिछले वर्ष 600 करोड़ रुपये था, जबकि इस वर्ष इसे बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, इसे कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए बजट में मामूली वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस वर्ष इसे बढ़ाकर 1,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लेकिन जल संकट की

गंभीरता को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है । भारत में 2023 में, 40% जिलों में गंभीर जल संकट था, और 60% ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं था ।

देश का बजट केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य का खाका है । यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़े, तो हमें बजट में विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा **(भरूच) :** मुझे वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार ।

आज जब भारत आगामी वर्ष 2047 में आजादी की 100 वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए आगे बढ़ रहा है ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उच्च आर्थिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है । यह हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और उनके नेतृत्व में भारत सरकार 2047 तक एक विकसित भारत के लिए संकल्प ले चुकी है । देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए बजट 2024-2025 उसी लक्ष्य की छाप दिखाई पड़ती है । ये बजट मोदी सरकार के प्रति देश के लोगों द्वारा जताए गये विश्वास को दर्शाता है । इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी समूहों सहित अन्य सभी का ध्यान रखा गया है । इस बजट में विकास के 9 सूत्रीय कार्यक्रम को शामिल किया गया है जो कृषि में उत्पादकता और लचीलापन से लेकर अगली पीढ़ी के सुधारों तक सर्वांगीण और समग्र कल्याण तथा विकास को समेटे हुए है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पाँच वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए पाँच योजनाओं और पहलों का एक पैकेज घोषित किया गया है जिसका केन्द्रीय आबंटन 2 लाख करोड़ रुपए है ।

ईपीएफ योगदान के लिए नियोक्ताओं को 2 वर्षों के लिए प्रति माह 3,000 रुपए का प्रतिपूर्ति समर्थन दिए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है जिससे 50 लाख से अधिक युवाओं को लाभ पहुंचेगा । इस बजट में कौशल विकास हेतु जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है उसके तहत पाँच वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । इसके लिए देश के 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा । इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी योजना के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण का वित्तीय समर्थन दिया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए हर साल एक एक लाख छात्रों को ई-वॉउचर प्रदान किए जाएंगे जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान होगा । इसके अलावा सरकार ने युवाओं को 500 कंपनियों में उद्योग का अनुभव प्राप्त करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू करने का प्रावधान किया है जिसमें आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को लाभ होगा । पहली बार नौकरी में आए कर्मियों को 15,000 रुपए तक का एक महीने का पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिसमें 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा । शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आने वाले छात्रों के लिए छात्रावासों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए ।

मध्यम वर्ग के लिए असमानताओं को कम करने के लिए बजट में सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान किए गए हैं जिसमे NPS की कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है और NPS वात्सल्य की शुरुआत की गई है । बजट में एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रदान किया गया है ।

सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल को साकार करना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । भारत का अमृत काल उसका कर्तव्यकाल भी है इसके दौरान समाज के सभी वर्गों जिसमे गरीब, अन्नदाता, युवा और

नारी शक्ति है इन सभी को राष्ट्र की सफलता की कहानी में आपना योगदान देना है । इसके साथ ही देश के आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए देश के 63,000 गावों को कवर किया गया है जिसका देश के 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा । इस तरह देश के गरीबों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पीएम-आवास योजना के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे ।

भारत सरकार देश की सफलता में नारी शक्ति का अहम योगदान मानती है । इसको ध्यान में रखते हुए इस बजट में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है ।

मोदी सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में अन्नदाताओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं क्योंकि भारत का किसान सदैव राष्ट्र के विकास का केंद्र रहा है । इस दिशा में सरकार ने सभी प्रमुख फसलों के लिए एम.एस.पी. बढ़ाकर इनपुट लागत पर 1.5 गुना रिटर्न देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है । इस बजट में सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और नियमित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी नीति की भी घोषणा की गई है ।

देश के पूर्वोत्तर राज्यों के सतत विकास को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने पूर्वोदय के अंतर्गत पूर्वोत्तर में शांति और विकास के लिए सार्थक और ठोस प्रयास किए हैं ।

इस बजट में मोदी सरकार ने MSME की क्रेडिट पहुँच और परिचालन दक्षता में सुधार की पहल की है । इस उदेश्य के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है ।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत और बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय आबंटन को बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए कर दिया गया है जोकि GDP का 3.4% है जबकि UPA सरकार के तहत वित्त वर्ष 2013-14 के लिए यह व्यय आबंटन 2,57,614 करोड़ रुपए था जोकि GDP का केवल 2.8% था । हमारी सरकार का यह आबंटन देश में चौगुनी आर्थिक वृद्धि की ओर इशारा करता है ।

देश के ऋषितुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दुनिया के राजनीतिक दिग्गज ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दिग्गज भी हैं । इसकी झलक उनके विगत 10 वर्षों के शासन काल में राष्ट्र की प्रगति के साथ-साथ उनके प्राचीन विरासत और संस्कृति को संजोए रखने में दिखाई पड़ती है । इस केन्द्रीय बजट में भी इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे- विष्णुपद मंदिर कॉरीडोर और महाबोधि मंदिर कॉरीडोर के विकास के लिए धन आबंटित किया गया है जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरीडोर के सफल मॉडल के बाद तैयार किया गया है ।

सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल को साकार करना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । भारत का अमृत काल उसका कर्तव्य काल भी है । इसके तहत देश के आदिवासी समुदायों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए देश के 63,000 गांवों को कवर किया गया है जिसका देश के 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा । इस तरह देश के गरीबों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे । इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि गरीब लोगों को शहर में आवास प्रदान करने के लिए जो 3 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है वही 3 लाख रुपए की धनराशि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को भी आवास बनाने के लिए आवंटित की जानी चाहिए ।

भारत का किसान सदैव राष्ट्र के विकास का केंद्र रहा है । इस दिशा में सरकार ने सभी प्रमुख फसलों के लिए एम.एस.पी. बढ़ाकर इनपुट लागत पर 1.5 गुना रिटर्न देने का इस बजट में प्रावधान किया है । इस बजट में सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और नियमित विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी नीति की भी घोषणा की गई है । इस तरह किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा बहुत सराहनीय योजनाओं का प्रावधान किया गया है । देश के दूरस्थ अंचलों में जहां जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ ही अन्य लोग निवास करते हैं वहां पर किसानों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना नितांत आवश्यक है । सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होने से पशुपालन तथा डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और इससे पशुपालकों को रोजगार प्राप्त होगा ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : मुझे वर्ष 2024-25 के आम बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभार । मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंन्द्र मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी अगुवाई में एन०डी०ए० ने एतिहासिक विजय प्राप्त कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का कार्य किया है ।

समावेशी विकास का यह आम बजट वाकई में राष्ट्रहित / देशहित और जनहित के लिए अमृत एवं संजीवनी के रूप में कार्य करेगी ।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियाँ एवं योजनायें जो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गो को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है इसके लिये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एवं माननीया वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । महोदय, यह बजट भारत के किसानों, युवाओं एवं महिलाओं तथा सभी वर्गो के उत्थान तथा विकास के लिए है ।

रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मा० प्रधानमंत्री जी की 5 योजनाएं जिसका पहले पैकेज में 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा जिसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड रूपए का है एवं इस वर्ष में शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है जो विकसित भारत बनानें में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

प्रधानमंत्री जी नें किसान भाइयों के लिए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को प्राथमिकता देते हुए परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, फसलों की नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकुल किस्मों को शुरू करना, प्राकृतिक कृषि, दलहन और तिलहन मिशन, सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, झींगा उत्पादन और निर्यात, राष्ट्रीय सहकारिता नीति जैसी योजनाओं को कार्यान्वित किया है ।

प्रधानमंत्री जी नें भारत के युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए रोजगार संबंद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं को लागू करने का काम किया है जिसमें पहली बार

रोजगार पाने वाले, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, एवं नियोक्ताओं की सहायता जैसी योजनाएं शामिल है जिसका लाभ करोडों युवाओं को मिलेगा । साथ ही कामगारों में महिलाओं की भागीदारी की प्राथमिकता, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण ऋण, शिक्षा ऋण जैसी योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है । समावेशी मानव संसाधन विकास और समाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हुए परिपूर्णता दृष्टिकोण जैसी योजनाओं को भी शामिल किया है ।

पूर्वोदय योजना के तहत बिहार का विकास की गति की रफ्तार चौगुनी हो जाएगी साथ ही पूर्वी क्षेत्रों का भी चहुँमुखी विकास होगा । जिसमें मुल रूप से मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों को शामिल किया गया है । पूर्वोदय योजना अन्य राज्यों क साथ बिहार के लिए अत्यंत ही संजीवनी के रूप में कार्य करेगी जिससे बिहार के किसानों की आयवृद्धि, महिलायों की सुरक्षा-रोजगार, व्यापारीयों के लिए व्यवसाय के साथ-साथ युवाओं को शिक्षा, एवं रोजगार को बढ़ावा देने का काम करेगा । बजट में 26000 करोड़ रू0 से बिहार के सड़क एवं पुलों का निर्माण किया जाएगा साथ ही 21,400 करोड़ की लागत से पिरपैतीं में 2400 मेगावाट के एक नए विद्युत संयंत्र की भी स्थापना की जाएगी जो बिहार के विकास की गति को तेज करने का काम करेगा । साथ ही बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महोबोधि मंदिर का काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल के अनुरूप समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान किया जाएगा एवं नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी ।

मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार का सीमावर्ती, अतिपिछड़ा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है कोशी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आ जाने से जान एवं माल का भारी नुकसान होता है जिसकी रोक थाम के लिए कोशी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना चालु करने के हेतु मा० प्रधानमंत्री एवं वित मंत्री जी के द्वारा 11,500 करोड़ की आर्थिक सहायता देकर कोशी क्षेत्र को संजीवनी देने का काम किया है । इस तरह बिहार को अर्थिक सहायता देकर अतिपिछड़ा एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को अन्य राज्यों के सामानांतर में लाने के लिए मा० प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ ।

इस अवसर पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल में रेलवे संबंधित मुख्य अतिआवश्यक समस्यायों का समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि:-

(1) पूर्व मध्य रेल अंतर्गत समस्तीपुर मंडल के प्रतापगंज रेलवे स्टेशन पर गाड़ी सं0-13211/13212 (जोगबनी-दानापुर) तथा 13213/13214 (जोगबनी-सहरसा) का ठहराव 2 मिनट किया जाय जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को बिहार की राजधानी पटना तथा जिला मुख्यालय सुपौल जाने-आने में सुविधा हो ।

(2) सरायगढ़ से नई दिल्ली वाया सुपौल-सहरसा तथा पटना होते हुए वंदे भारत एक्सप्रेश का परिचालन किया जाय ।

(3) वैशाली एक्सप्रेश (12553/12554) एवं राज्यरानी एक्सप्रेश (12567/12568) का विस्तार सहरसा से सरायगढ़ किया जाय या अन्य मेल एक्सप्रेश गाड़ी बिहार की राजधानी पटना एवं देश की राजधानी दिल्ली तक परिचालन किया जाय ।

(4) 1934 के भूकंप में ध्वस्त रेल का सर्वे प्रतापगंज से भीमनगर तक हो चूका है, उक्त खंड पर नई रेल परियोजना की स्वीकृति कर रेल लाईन बिछाकर रेल परिचालन का कार्य किया जाय ।

इसी के साथ मैं 2024-25 के आम बजट का सर्मथन करते हुए बिहार के समस्त जनता एवं जनतादल (यूनायटेड) के तरफ से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ । जय भारत-जय बिहार ।

SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI (UTTARA KANNADA): Thank you for giving me an opportunity to express my views on this Budget.

On July 23, hon. Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for 2024-25 in this House, marking her seventh consecutive Budget presentation. This Budget aims to bolster India's economy, projected to become the world's third-largest by 2027, with a focus on creating job opportunities and enhancing growth in key sectors.

The Budget outlines nine priority areas: agriculture, employment and skilling, inclusive human resource development, manufacturing and services, rural development, energy security, infrastructure, innovation, and next-generation reforms. These priorities are designed to facilitate transformative changes across the economy, laying the foundation for India's vision of becoming a developed nation by 2047.

A significant allocation of Rs. 1.52 lakh crore has been made for the agriculture sector, reflecting the Government's commitment to enhancing productivity and ensuring food security. The Budget proposes the introduction of 109 new climate-resilient crop varieties, empowering farmers to adapt to changing environmental conditions. Additionally, the Government plans to initiate one crore farmers into natural farming practices, emphasizing sustainable agricultural methods that reduce dependence on chemical inputs and promote soil health.

To address employment challenges, the Budget proposes a Rs. 2 lakh crore package aimed at skill development and job creation for 4.1 crore youth over five years. This includes a comprehensive internship scheme for one crore young individuals, enhancing their employability and providing them with valuable work experience. The Government also plans to establish 10,000 Skill India International Centres across the country, offering industry-relevant training and certifications.

The Budget prioritizes inclusive human resource development with a focus on improving access to quality education and healthcare. The Government has allocated Rs. 1.5 lakh crore for the National Education Mission, which aims to enhance digital infrastructure in schools and provide digital devices to students. Additionally, the Budget proposes the establishment of 50 new Eklavya Model Residential Schools ensuring quality education for tribal children. To boost manufacturing and services. the budget introduces a Rs. 1 lakh crore Production

Linked Incentive (PLI) scheme for 10 sectors, including electronics, pharmaceuticals, and renewable energy. This initiative aims to attract investments, promote exports, and create job opportunities. The Government also plans to establish 100 new clusters for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), providing them with access to modern infrastructure and technology.

Rural development remains a key focus area with the Government allocating Rs. 10 lakh crore under the PM Awas Yojana Urban 2.0 to address housing needs for the urban poor and middle class. Additionally, the fourth phase of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) will enhance connectivity for 25,000 rural habitations, improving access to markets and social services.

The Budget emphasizes the importance of energy security with a focus on promoting renewable energy sources. The Government has allocated Rs. 50,000 crore for the National Hydrogen Mission aiming to position India as a global hub for green hydrogen production and exports. Additionally, the Budget proposes the establishment of 10,000 MW of solar power capacity in the next five years contributing to the country's goal of achieving 450 GW of renewable energy by 2030.

Infrastructure development remains a priority with the Government allocating Rs. 5 lakh crore for the Pradhan Mantri Gati Shakti National Master Plan. This initiative aims to enhance multimodal connectivity, reducing logistics costs and improving efficiency. The Budget also proposes the construction of 10,000 km of national highways and the development of 100 cargo terminals under the Sagarmala program boosting maritime trade and logistics.

The Budget recognizes the importance of innovation in driving economic growth and competitiveness. The government has allocated Rs. 25,000 crore for the National Research Foundation, supporting research and development in key areas such as artificial intelligence, quantum computing, and biotechnology. Additionally, the Budget proposes the establishment of 50 new centres of excellence in emerging technologies, fostering innovation and entrepreneurship.

The Budget emphasizes the need for next-generation reforms to enhance the ease of doing business and attract investments. The Government plans to introduce a new law to regulate cryptocurrencies and digital assets, providing clarity and certainty to investors. Additionally, the Budget proposes the simplification of the tax regime reducing compliance burdens for businesses and individuals.

The Budget emphasizes fiscal consolidation, targeting a fiscal deficit of 5.1 per cent of GDP for 2024-25. This aligns with the Government's commitment to reduce the fiscal deficit below 4.5 per cent by 2025-26, reflecting a disciplined approach to public finances. The Government also plans to introduce a new fiscal responsibility and budget management framework ensuring transparency and accountability in public spending.

The Budget provides significant relief to the middle class, increasing the standard deduction from Rs. 50,000 to Rs. 75,000 and raising the family pension deduction from Rs. 15,000 to Rs. 25,000. These measures aim to provide more disposable income to salaried individuals and pensioners, boosting consumption and economic growth.

Sitharaman ji highlighted the Government's efforts to streamline regulations and boost the economic ecosystem aiming to attract investments and stimulate growth. The Budget proposes the establishment of a National Logistics Efficiency Advancement Predictability and Safety (NEAPS) portal, providing a single window for logistics services and reducing transaction costs for businesses.

Overall, the 2024 Budget reflects a comprehensive strategy to address economic challenges, enhance productivity, and promote inclusive growth. The Government's focus on job creation, skill development, and infrastructure development is expected to create a conducive environment for businesses and individuals to thrive. The Budget also emphasizes the importance of sustainability, innovation, and next-generation reforms, setting the stage for India's ambitious goal of becoming a developed nation by 2047.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बजट पर विचार व्यक्त का अवसर प्रदान किया गया । आज की दुनिया कई मानवीय संकटों का सामना कर रही है, दुनिया में कई देश युद्ध से जूझ रहे हैं जैसे-

? रूस-यूक्रेन युद्ध

? गाजा

? सूडान (सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई)

? सीरिया-तुर्की

? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (सशस्त्र संघर्ष और आर्थिक संकट)

इस युद्ध के समय में भारत ने एक मजबूत बजट को प्रस्तुत किया है । यह बजट कोई सामान्य बजट नहीं, अपितु विकसित भारत का foundational budget है ।

GROWTH RATES : ? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वर्ष 2047 तक अपनी शताब्दी तक उच्च मध्यम आय की स्थिति तक पहुंचने की आकांक्षाओं के साथ इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार) है । (World Bank)

? RBI ने अपनी रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था की ताजा स्थिति के बारे में कहा है कि:

"India is said to become the second largest economy of the world within the century even at current growth rates and even perhaps match the dominant position in the world economy that it enjoyed in 1700 AD before the colonial invasion.

Economic growth- IMF said about 2024

India-6.5%-7%

China-4.6%

UK- 0.6%

Unemployment it decreases at the rate of 3.2%.

Specially with respect to youth--- 2017-18=17.8%

2022-23=10%

Foreign Direct Investment over the year : पीएम मोदी जी के निरंतर प्रयासों के कारण, वर्ष 2014-2023 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह पिछले नौ वर्षों (2005-2014) में 96 बिलियन डॉलर की तुलना में 55% बढ़कर 148.97 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया ।

वैश्विक स्तर पर भी भारत ने अन्य देशों के साथ सहयोग किया । विनिर्माण क्षेत्रों में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए, वर्ष 2015 में, भारत और जापान ने $12 बिलियन के "Japan-India Make-in-India Special Finance, और भारत सरकार की मेक-इन-इंडिया नीति को मूर्त रूप देने में मदद की । वर्ष 2000 और जून 2023 के बीच, जापान ने भारत में लगभग $39.94 बिलियन का निवेश किया, जो एफडीआई स्रोतों में पांचवें स्थान पर है । जापानी निवेश मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, रसायन, वित्त (बीमा), और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गया ।

RESPECT IN THE WORLD AND GLOBAL SOUTH : भारत अपनी G20 अध्यक्षता में नियमित रूप से वैश्विक दक्षिण की आवाज़ रहा है और ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा न्याय, टिकाऊ ऊर्जा संक्रमण की आम चिंताओं पर प्रकाश डाला है ताकि सभी विकासशील देश विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर सकें ।

पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री 'जेम्स मारापे' ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उनके पैर छूने के लिए झुके, पापुआ न्यू गिनी आमतौर पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं करता है, लेकिन मोदी के लिए यह किया गया, क्या दर्शाता हैं ये, यह मोदी जी कि लोकप्रियकता को दर्शाता है जो कि वैश्विक स्तर पर हैं ।

VIKSIT BHARAT BY 2047 MISSION : माननीय मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत के चार मूलभूत स्तंभ हैं:

· युवा

· गरीब

· महिला

· किसान

पीएम मोदी जी ने दिसंबर में Viksit Bharat@ 2047: voice of Youth' लॉन्च किया । 2023 और उन्होंने सभी से अपनी सीमाओं से परे जाकर विकसित भारत के दृष्टिकोण में अपने विचारों को योगदान देने का आग्रह किया ।

? इस विकसित भारत के बजट में युवा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लॉन्च हुए हैं जो कि उन्हें अपने व्यक्तित्व तथा कॉर्पोरेट को समझने में मददगार होगा ।

? 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों के लिय 1 करोड़ युवाओ के लिये अवसर इस बजट ने पेश किया है ।

Poverty - CONTEXT OF INDIAN GOVERNANCE : हमने इस शताब्दी में अपनी जनसंख्या में एक संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक की वृद्धि की है । यह वह दबाव है जिसके तहत हमारा कल्याणकारी राज्य कार्य करता है:

? भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है ।

? पिछले नौ वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, यह भारत और

मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धि है ।

? बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई । यह 17.89% अंक की कमी है ।

विशेष रूप से उत्तर-प्रदेश में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जहां 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं ।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अगले पांच साल तक विस्तार सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है ।

Women : साक्षरता - 2011 की जनगणना के अनुसार 64.63% National Family Health Survey5 -2019-20= 71.5%

women having bank or saving accounts that the they themselves use-

Uttar-Pradesh

NFHS-4=53% 54.6%

NFHS-5= 78 % 75.4%

And these things I am not comparing with the UPA government but within the tenure of the Modi ji.The Union Budget 2024-25 carried an allocation of more than Rs 3 lakh crore for schemes benefitting women and girls and promoting women-led development.

Kisan : हमारे देश की नींव कृषि है और कृषि ही प्राथमिक क्षेत्र है, जिससे सभी क्षेत्रों को कच्चा माल मिलता है और कृषि के सशक्त होने से आत्मनिर्भरता से देश की नींव मजबूत होगी । अगर नींव मजबूत होगी तो उस पर कितनी भी बड़ी इमारत बन जाए, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी । इस बार देश में न केवल उत्पादन अपितु उत्पादकता पर ध्यान दिया जायेगा, जिससे Research and development के तहत कृषि को और मजबूत बनाया जायेगा ।

माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य देश की कृषि को मजबूत करना है, जिसमें मैं पिछले दस वर्षों में सरकार द्वारा किये गये कुछ कार्यों का उल्लेख करना चाहता हूं ।

? Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है । 2016-17 से योजना के तहत कुल 5,549.4 लाख किसान आवेदनों का बीमा किया गया और दावे के रूप में 1,50,589 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है ।

Agriculture Infrastructure Fund (AIF) : मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत Agri Infrastructure Fund लॉन्च किया गया था ।

AIF को देश के कृषि बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से पेश किया गया था ।

वर्ष 2023 तक, AIF के तहत 44,912 projects के लिए 33.209 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से 25,504 करोड़ रुपये योजना लाभ के तहत कवर किए गए हैं । इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 56.471 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है ।

Integrated Scheme for Agriculture Marketing (ISAM) : National Agriculture Market (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC मंडियों को नेटवर्क बनाता है । 1,389 और 23 राज्यों, 4 केंद्रशासित प्रदेशों की मंडियों को e-NAM प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है और 1.76 करोड़ से अधिक किसानों और 2.5 लाख व्यापारियों को e- NAM portal पर पंजीकृत किया गया है और अभी बदलते मौसम को देखते सरकार ने

किसानों के लिय नई High Yield Variety(HYV) seed कि घोषणा कि हैं जिसके तहत 109 नई किस्मे किसानो को कृषि और उधेयनिकी (Horticulture) 32 विभिन्न फसलों में दी जाएंगी जो कि मौसम परिवर्तन के प्रति सहनशील होंगी । विशेष तौर से आज देश मे वर्ल्ड मे dietary pattern बदले हैं, उस हिसाब से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इस बजट कि प्राथमिकताओं में से एक रहा है ।

Under this 1 crore farmer will be initiating the natural farming. किसानो के लिए आय सृजन बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा की गई पहल किसानों को आय की अनिश्चितताओं से उबार सकती है ।

भारतीय कृषि क्षेत्र को NDA सरकार की कई योजनाओं जैसे कम ब्याज दरों, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और फसल बीमा और सब्सिडी और कोल्ड स्टोरेज से लाभ हुआ है ।

INFRASTRUCTURE :

? One notable area of focus was infrastructure development, particularly in the construction of highways and airports. PM Modi pointed out that while the Congress government constructed approximately 12 km of highways per day, his administration has significantly increased that figure to 30km per day.

? Similarly, he highlighted the establishment of new airports saying, "Congress made 70 airports in 60 years, Modi made 70 new airports in 10 years."

? The government's decision to do the heavy lifting on capital expenditure appears to be a part of the well-crafted medium-term strategy to not just accelerate the pace of infrastructure project execution, but also to trigger a cycle of private sector investment, or what economists sometimes describe as the "crowding in" phenomenon.

Item	2014	2023	% change
Length of National Highways in km	91,287	1,46,145	60.10%
NH construction speed in km/day	9	36	300%

highways are built now in a day, four times the speed of nine kilometres in 2014. The ship turnaround time in ports have also fallen from an average of 4.3 days in 2014 to 2.1 days now.

Renewable energy sector : ? कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है ।

? भारत ने नवंबर 2021 में ही गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है ।

? विश्व स्तर पर भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5 वें स्थान पर है ।

? भारत की बिजली-उत्पादन क्षमता 22% बढ़ी है और Renewable energy capacity 2022 तक पांच वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है ।

इसके अलावा, MSMEs क्षेत्र भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है । 2 अगस्त, 2023 तक, उद्यम पंजीकरण पोर्टल ने बताया कि 1 जुलाई, 2020 और 1 अगस्त, 2023 के बीच पंजीकृत MSMEs में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या प्रभावशाली 12,36,15,681 (12 करोड़) थी ।

MSMEs निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात में भी एक समान पैटर्न दिखा । Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics के डेटा से संकेत मिलता है कि भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई उत्पादों की हिस्सेदारी 2022-23 में 43.6% थी । जैसा कि Mr. बनर्जी ने MGNREGA का सवाल उठाया तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि-

Bengal under MGNREGA were stopped following audit objections by the CAG as the state had failed to submit utilisation certificates. there was no discrimination against any state as disbursement of funds were as per guidelines of the finance commission and audit reports of the Comptroller and Auditor General (CAG).

? The delay in payment of wages are due to implementation issues in the states which include inadequate staffing, measurement, data entry, generation of wage list, Fund Transfer Order (FTO), etc. In case of delay in wage payment, the beneficiary is entitled for delay compensation as per the provisions,the last financial year till October 2023, 99.12% pay orders have been generated within 15 days.

मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ ।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : बजट भाषण पर मुझे विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट भाषण में किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग एवं संविदा कर्मचारियों और छोटे एवं सीमांत व्यापारियों तथा समाज के निचले और वंचित तबके के लोगों के कल्याण के लिए और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई विशेष प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है ।

इस बजट भाषण में उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था नहीं की गई है । राप्ती नदी जो नेपाल से निकल कर मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर आकांक्षी जिलों से होते हुए

सिद्धार्थनगर गोरखपुर को होकर बहती है, जिसमें लगभग हर साल बाढ़ आने के कारण आस-पास के क्षेत्रों में लोगों को भारी जान-माल का नुकसान होता है ।

पिछले हफ्ते राप्ती नदी में आए भीषण जल सैलाब के कारण सैकड़ों गाँव तबाह हो गए हैं । किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं । धान की नर्सरी, गन्ना एवं अन्य कई फसलें नष्ट हो हो गई हैं । किसान धान की बुवाई भी नहीं कर पा रहे हैं । बाढ़ में डूबने के कारण कई लोगों की जानें भी चली गई हैं और कई लोगों के घर पानी मे बह गए हैं जिसका बजट भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है । सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और बाढ़ के कारण जिन लोगों की जानें चली गई हैं, उनके परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपये सहायता राशि के रूप में दिए जाने चाहिए ।

इस बजट में MSP गारंटी कानून लाने के बारे में और किसानों के बकाया कृषि लोन को माफ़ करने के सम्बंध में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है । आज देश का किसान बहुत परेशान है । कितने किसान रोजाना आत्महत्या करने को मजबूर हैं । सरकार को किसानों के हितों की रक्षा के लिए MSP गारंटी कानून लाना चाहिए था, साथ ही किसानों के बकाया कृषि लोन को माफ किया जाना चाहिए था । कृषि उपकरणों में लगने वाले टैक्स पर 100% छूट देने के साथ-साथ बिजली किसानों को सिचाई के लिए फ्री बिजली देने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी । कृषि मे उपयोग होने वाले खाद, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, जिंक, डी०ए०पी० आदि के दाम आसमान छू रहे है । सरकार ने यूरिया बैग जो पहले 50 किलो का आता था, घटाकर 40 किलो कर दिया लेकिन उसके दाम मे कोई कमी नहीं की और न ही इसका बजट में कहीं भी कोई जिक्र किया गया है.

बजट भाषण मे सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है । वर्तमान समय में समाज के सबसे निचले तबके और वंचित वर्ग के लोगों को, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराना आवश्यक है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वास्तव में जो पात्र लाभार्थी हैं, उनकी पहचान कर उनके अनुरूप संसाधनों की व्यवस्था और नीति का निर्धारण किया जा सके और जिससे उनको इसका सीधे लाभ मिल सके, लेकिन बजट भाषण में इसका कोई जिक्र नही है ।

शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । बढ़ती कमरतोड़ महंगाई के दौर में बच्चों की शिक्षा आज बहुत ही महंगी हो गयी है । हमारा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर जो आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आता है, जो शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, के साथ-साथ पूरे देश में बच्चों के लिए फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करने और उच्च शिक्षा में सुधार करने की ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ।

जिस तरीके से देश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है, वह आज की कमरतोड़ महँगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा के समान है । मनरेगा मजदूरों की 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 365 दिन किया जाना चाहिए था और उन्हें मिलने वाली दैनिक मजदूरी को 237 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की जानी चाहिए थी, जिसका इस बजट भाषण मे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है.

बजट भाषण में सांसद निधि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । हम सब यह जानते हैं कि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का दायरा विधान सभा से बहुत जायदा होता है । अमूमन एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत करीब 5 से 7 विधान सभा क्षेत्र आते हैं । प्रत्येक सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलते हैं, जो बहुत ही कम हैं । जबकि उत्तर प्रदेश में विधायक को विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए सांसद के बराबर ही 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं । उक्त निधि से सांसद एक विधान सभा में केवल एक किलो मीटर तक ही सड़क बनवा सकता है । इस तरह वह साल भर में केवल 5 किमी ही सड़क बनवा सकता है । ऐसे में इतने बड़े संसदीय क्षेत्र का विकास कैसे हो पायेगा? इसलिए सरकार को सांसद निधि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए ।

बजट भाषण में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है । सरकार से मेरी मांग है कि कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ।

इस बजट ने समाज के सभी वर्गों को निराश किया है । यह बजट असल में सरकार बचाओ बजट है । मैं और हमारी पार्टी इस बजट का विरोध करते हैं ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : मैं वर्ष, 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखता हूं।

मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्तमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा को शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए बजट में घोषणा करने का काम किए हैं । मा.वित्त मंत्री जी बिहार के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उल्लेख किए हैं और इसके लिए बिहार को करीब 58 हजार 900 करोड़ रु. के आबंटन का प्रावधान किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है । इससे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति मिलेगा । सड़क परियोजनाओं में पटना- पूर्णियां और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे एवं बोधगया?राजगीर-वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले परियोजनाओं के लिए करीब 26 हजार करोड़ रू., बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए कई परियोजनाओं के लिए करीब 12 हजार करोड़ रु., भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए करीब 21 हजार 400 करोड़ रू. का प्रावधान करने के लिए मा.वित्तमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले महीने नालंदा विश्वविद्यालय के नये कैम्पस का उद्घाटन किए थे । अब बजट में भी इसका उल्लेख है और सरकार ने इसे टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित करने की घोषणा किया है ।

नालंदा एक पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी है । यहाँ हिन्दू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का तीर्थस्थल माने जाने वाले राजगीर को भी ग्लोबल टूरिज्म सेंटर के तौर पर विकसित करने का प्रावधान किया गया है । बिहार के महाबोधी मंदिर और विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है । बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की घोषणा की गई है । गंगा नदी पर दो पुल निर्माण की घोषणा हुई है । बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और कई एयरपोर्ट बनाये जाने का प्रावधान किया गया है । बिहार के गया में अमृतसर-कोलकता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है ।

यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार बिहार राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि नीति आयोग की कई रिपोर्टस यह साफ-साफ दर्शाता है कि बिहार के विकास के लिए वहाँ विशेष प्रावधान की आवश्यकता है । इन्हीं सब कठिनाइयों के मद्देनजर हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का आग्रह करते आ रहे हैं । किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि जिन मापदण्डों का हवाला दिया जा रहा है और 30 मार्च, 2012 के अन्तर मंत्रालयी समूह की बातें, सब बिहार के

लिए अन्यायपूर्ण लगता है । नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्टस एवं एनडीसी के मापदण्ड चार एवं पाँच क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए सक्षम आधार नहीं बनता है ।

बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार के आर्थिक प्रगति के लिए, बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए, बिहार में औघोगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बिहार को देश के अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान ही एक मात्र उपाय है ।

यह बजट विकसित भारत की ध्येय प्राप्ति का आधार बनकर हर भारतीय की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला साबित होगा ।

2024-25 का कुल बजट करीब 47,65,768 करोड़ रू. का है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि एवं किसानों के कल्याण के लिए 1 लाख 51 हजार 851 करोड़ का आबंटन, शिक्षा करने वाला बजट है । यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केन्द्रित है । नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजारसे 75 हजार रुपये, मुद्रा लोन को दस लाख से 20 लाख रुपये और 30 लाख युवाओ को कौशल लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज देने का निर्णय ऐतिहासिक है ।

एक लाख 25 हजार 638 करोड़ का आबंटन स्वास्थ्य के क्षेत्र के विकास के लिए, 19 हजार 227 करोड़ का आबंटन रक्षा के लिए, 6 लाख 21 हजार का आबंटन सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए, 2 लाख 78 हजार का आबंटन रेलवे के लिए, 2 लाख 55 हजार 393 करोड़ गृह मंत्रालय को, 2 लाख 19 हजार 644 का आबंटन ग्रामीण विकास के लिए, 1 लाख 80 हजार 244 करोड़ का आबंटन अहम योजनाओं के लिए जैसे मनरेगा योजना को 86 हजार, पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ का आबंटन हुआ है ।

मेरा मानना है कि मनरेगा जो ग्रामीण मजदूरों के लिए बैकबोन का काम करती है, उसमें पिछले साल के समान ही आबंटन हुआ है । इसे मा. वित्तमंत्री जी कुछ बढ़ाने का काम करेंगी, तो देश में मजदूरों को अधिक कार्य दिवस का सृजन हो सकता है । इससे ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा ।

कृषि क्षेत्र को 1 लाख 52 हजार करोड़ के आबंटन, जो पिछले वर्ष से करीब 21.6 प्रतिशत अधिक है, इससे करीब 6 करोड़ किसानों को जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर खर्च होगा और 5 राज्यों में नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी होगा । सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली से देश के आम नागरिकों को काफी राहत मिलेगी ।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को माननीय वित्तमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ । माननीय वित्त मंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर के 2024-25 के लिए कुल 42,277.74 करोड़ रू. आबंटित किए हैं । जम्मू-कश्मीर वर्तमान में केन्द्र शासित प्रदेश है । केन्द्र सरकार उसके सभी संसाधानों की कमी को पूरा कर रही है । राज्य के आपदा प्रबंधन कोष में 279 करोड़ रू. आबंटन का प्रावधान है । केन्द्र सरकार 624 मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना के लिए 130 करोड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है । और 800 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है । 540 मेगावाट के डब्लूआर के लिए भी 171.23 करोड़ रू.के अंशदान का प्रावधान है । इस प्रकार जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन से राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी । जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था में सुधार है । छिट-पुट घटनाओं को छोड़कर वहाँ अमन-चैन कायम करने में केन्द्र सरकार सफल होती दिख रही है । युवा भी अब मेन स्ट्रीम में आने लगे हैं ।

अलगाववादियों का सफाया हुआ है । स्थानीय लोग चिन्हित अलगाववादियों को धरपकड़ करवाने में सहयोग दे रहे हैं ।

आशा है कि वहाँ की जनता को एक चुनी हुई सरकार अतिशीघ्र मिलेगी और इसके लिए अभी अनुकूल समय है कि जम्मू-कश्मीर में अविलम्ब राज्य का चुनाव हो । वहाँ राज्य सरकार की पुनः बहाली हो । आशा है, सरकार जल्द से जल्द इस दिशा में कार्य करेगी । धन्यवाद ।

श्रीमती संध्या राय (भिण्ड) : आपने मुझे इस स्वर्णिम बजट के विषय पर विचार व्यक्त करने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं । यह विकसित भारत का स्वर्णिम बजट है। पिछले 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को तेज गति प्राप्त हुई है, जो कि पिछले 60 साल में भी किसी सरकार ने कल्पना भी नहीं की होगी । आज हमारा भारत विश्व पटल पर ऊंचा स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रेषित हो रहा है । आज पूरा विश्व देख रहा है जिस प्रकार विश्व प्रसिद्ध आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि हो आर्थिक मजबूती हो या फिर गरीब उत्थान हो या महिला सम्मान सभी प्रकार से आज भारत देश अव्वल स्थान पर हैं । साल 2024-25 का जो बजट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है । यह स्वर्णिम बजट भारत देश को और तेजी से गति प्रदान करेगा । इस बजट में देश के अंतिम व्यक्ति तक को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है यह बजट विद्यार्थी, महिला उत्थान, बुजुर्गों, कर्मचारियों, गरीबों और बेरोजगारों के हित को देखते हुए बनाया गया है । इस बजट से यह साफ हो गया कि देश एक सुरक्षित हाथों में है । आज देश का एक-एक नागरिक भारत देश पर गर्व करता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है । यह बजट मोदी जी की गारंटी पूरी होने का प्रमाण है, इस बजट पर टीका टिप्पणी करने वालों से मैं एक सवाल करना चाहती हूं, कि जिस प्रकार उनके कार्यकाल में देश को भयंकर स्थिति और एक डर का माहौल आपातकालीन लगाकर किया गया सरेआम कत्लेआम हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई उस इतिहास को जानते हुए भी आज इस स्वर्णिम बजट पर देश को भ्रमित क्यों किया जा रहा है?

देश को मोदी जी की गारंटी पर पूरा विश्वास है । आज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी एवं सड़क निर्माण जैसे की नेशनल हाईवे पूरा देश जानता है कि जिस प्रकार तेज गति से नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं और कई ऐसे बड़े-बड़े नेशनल हाईवे बनाकर तैयार किए गए हैं, जिससे एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ा गया है इस बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसका बजट 2 लाख करोड रुपए की राशि तय की गई है, जिससे देश के चार करोड़ से अधिक युवाओं को आने वाले 5 वर्षों में लाभ पहुंचेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें हमारे गरीब भाइयों-बहनों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा कौशल प्रशिक्षण की एक नई योजना के माध्यम से 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा । इससे कई लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और कौशल प्रशिक्षण ऋण के माध्यम से साढे सात लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रतिवर्ष 25000 छात्रों को सहायता मिलेगी शिक्षा को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने एक गारंटी सुनिश्चित की है जिसके माध्यम से छात्रों को 10 लाख रुपए तक का ऋण की सहायता प्रदान की जाएगी ।

हमारी सरकार, किसान, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और पिछड़ों के चहुंमुखी सर्वव्यापी तथा सर्व समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है । हमारी सरकार पूरे दृढ़ संकल्प के साथ सामाजिक न्याय एवं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देश के अंतिम नागरिक तक पहुंचाने का कार्य कर रही है । पीएम आवास योजना के माध्यम से सरकार ने पिछले 10 साल में लगभग साढ़े चार करोड़ घर बनाएं गए है और इस योजना के माध्यम से अन्य तीन करोड़ घर

बनाने की घोषणा की गई है । मोदी जी की गारंटी का यह स्वर्णिम बजट देश के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने में कामयाब होगा । धन्यवाद । **SHRI KOTA SRINIVASA POOJARY (UDUPI CHIKMAGALUR):** Thank you very much for giving me an opportunity to express my views on the Union Budget, 2024-25.

On behalf of my Party, I support the Union Budget. The intent of the Budget is aimed at driving India?s economic growth and progress. The Budget has introduced a framework with nine priorities, which seems to be developing priorities of the country. An important focus of the Budget is simplification and rationalisation of the tax service, which means ease of doing business in the country in various sectors, which is the need of the hour. While the budgeted spending on infrastructure, rural and agriculture has remained same as Interim Budget, it maintains a fine balance between improving efficiency in agriculture, supporting the rural economy and keeping the focus intact on infrastructure spending given the limited time left in the current fiscal year. The Government managed to strike a fair balance between fiscal prudence and growth. The Budget has aimed to strike a fine balance between fiscal prudence and growth impetus. The Budget has focused on continuing SIP ? Sustainable development, Inclusive growth, and Prudence (fiscal consolidation). From infrastructure to education, the Budget focused on four major categories: farmers, poor, women, and youth. The FM also announced reforms in the new tax regime.

The full Budget for FY 2025 signals policy continuity and retains focus on fiscal consolidation. It also underscores the Government?s key focus areas which are fiscal prudence, job creation, infrastructure capital expenditure (capex), and simplification of the tax regime.

The fiscal deficit for FY 2025 was pegged at 4.9 per cent, well below the 5.1 per cent target presented in the Interim Budget in February 2024. The Government has judiciously used available fiscal headroom from the higher-than-expected RBI dividend and strong tax collections to increase expenditure in key sectors such as agriculture and labour, while simultaneously accelerating fiscal consolidation. Further, the Government has also laid out a credible plan to achieve an even lower fiscal deficit of 4.5 per cent of GDP by FY 2026. The projected decrease in Government borrowing, combined with the ongoing inflows related to India?s bond index inclusion, is positive for fixed-income markets and will help reduce borrowing costs across the economy.

The Budget had a strong focus on employment generation with measures including a wage incentive for first-time employees entering the formal sector, three new schemes for job creation, and support for the MSME and agri sectors, which are large employment generators. There was also an emphasis on skilling with the announcement of a plan to skill two million youth, an internship programme for young students, and an annual interest subvention scheme of three per cent for 1,00,000 students.

Several support measures were announced for the MSME sector, which accounts for about 30 per cent of GDP and provides employment to over 120 million Indians. The measures include credit guarantee schemes, doubling of the Mudra loan limit, as well as guaranteed funding for stressed companies. Further, COVID related learnings from the ECLGS ? a scheme that benefitted 119 million MSMEs and CGTMSE ? have been incorporated.

On individual income tax, a higher standard deduction and expansion of slabs were announced, both applicable under the new simplified tax regime. These will provide a fillip to household consumption while spurring higher adoption of the new simplified tax regime. Abolishing the angel tax is a very progressive step and will encourage new investments in the startup sector.

On the sustainability front, the announcement to set up the Critical Mineral Mission for domestic production, recycling of critical minerals, overseas acquisition of critical mineral assets, and the exemption of customs duties on 25 critical minerals, will ensure access to strategic rare earth supplies, and help achieve net-zero emission targets.

As regards employment, three schemes to promote employment and increase workforce participation were announced. These will provide: (i) wage support up to Rs. 15,000 to first time employees registered with EPFO, (ii) incentives to employees and employers in the manufacturing sector for their EPFO contributions, and (iii) reimbursement of up to Rs. 3,000 per month for employer EPFO contributions, per new employee for two years.

With regard to skilling, a scheme to upskill 20 lakh youth over five years will be launched. Under this, 1,000 Industrial Training Institutes will be upgraded to meet the skilling needs of the industry. Another scheme to provide internship opportunities for one crore youth in 500 top companies has been announced. Under this, a monthly allowance of Rs. 5,000 and a one-time assistance of Rs. 6,000

will be provided to the beneficiaries. Companies can bear the training cost and ten per cent of the internship cost from their CSR funds.

Regarding assistance to States, plan will be formulated to enhance human resources, infrastructure and economic opportunities in Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. Financial support of Rs. 15,000 crore will be provided to Andhra Pradesh for a new capital this year.

As regards MSMEs, credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector has been announced. It will facilitate term loans for purchasing machinery and equipment without collateral or guarantee. A Self-Financing Guarantee Fund will be constituted to provide guarantee cover up to Rs. 100 crore. The limit of Mudra loans will be increased from Rs. 10 lakh to Rs. 20 lakh, for entrepreneurs who have availed and paid loans previously.

With regard to energy, a roadmap will be designed for industries with high carbon dioxide emissions, setting emission targets for them. Investment towards emerging technologies in nuclear energy will be made in collaboration with the private sector.

As regards agriculture, existing agricultural research setup will be reviewed with a focus on raising productivity and developing climate resilient crops. Vegetable production clusters near major consumption centres will be established. A National Policy will be drafted for development of the cooperative sector.

With regard to urban and rural development, a transit-oriented development plan will be formulated for 14 large cities with a population over 30 lakhs. States charging high stamp duties will be encouraged to reduce them, and further lower them for women buying property. Three crore additional houses will be built under PM Awas Yojana (PMAY) in rural and urban areas.

In 2024-25, the top 13 Ministries in terms of allocations account for 54 per cent of the estimated total expenditure. Of these, the Ministry of Defence has the highest allocation in 2024-25, at Rs. 6,21,941 crore. It accounts for 13 per cent of the total budgeted expenditure of the Central Government. Other Ministries with high allocation include: (i) Road Transport and Highways (5.8 per cent of total expenditure), (ii) Railways (5.3 per cent), and (iii) Consumer Affairs, Food and Public Distribution (4.6 per cent).

As regards food subsidy, allocation for food subsidy is estimated at Rs. 2,05,250 crore in 2024-25, a 3.1 per cent decrease over the actual expenditure in 2023-24. A higher level of food subsidy was budgeted in 2021-22 and 2022-23. This was mainly on account of PMGKAY, which provides free additional foodgrains to eligible beneficiaries to mitigate the impact of COVID.

With regard to fertiliser subsidy, expenditure on fertiliser subsidy is estimated at Rs. 1,64,000 crore in 2024-25. This is a decrease of Rs. 25,488 crore (13.5 per cent) from the actual expenditure in 2023-24. Fertiliser subsidy was increased substantially in 2022- 23 due to a sharp increase in the international prices of raw materials used in the manufacturing of fertilisers.

The Government also provides subsidies for LPG and various schemes. In 2024- 25, Rs. 10,000 crore has been allocated to the Price Stabilisation Fund under the Department of Consumer Affairs. This fund is utilised for maintaining buffer stocks of pulses, onions, and potatoes.

MGNREGS has the highest allocation in 2024-25 at Rs. 86,000 crore. This amount is the same as the Revised Estimate for 2023-24.

The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) has the second highest allocation in 2024-25 at Rs. 84,671 crore, an increase of 56.5 per cent over the Revised Estimate of 2023-24. In 2023-24, expenditure for the scheme is expected to be lower by 32 per cent as compared to the Budget Estimates. This was mainly on account of the rural component falling short of original plans. The allocation for 2024-25 is Rs. 5,038 crore (6.4 per cent) more than the Budget Estimates for 2023-24 on account of a higher allocation to the urban component of the scheme.

The Jal Jeevan Mission has the third highest allocation in 2024-25 at Rs. 70,163 crore, an increase of 0.2 per cent over the Revised Estimate of 2023-24.

PM KISAN has been allocated Rs. 60,000 crore in 2024-25, which is the same as the Revised Estimate of 2023-24.

Programmes for the welfare of women and children have been allocated Rs. 4,37,079 crore in 2024-25, an increase of 18.5 per cent over the Revised Estimate of 2023-24. These allocations include programmes being implemented across all Ministries.

Allocation towards the welfare of women is expected to increase due to a higher allocation towards the Pradhan Mantri Awas Yojana. Under the Awas Yojana, the female head of the family must be the owner or co-owner of the house.

Allocation towards the welfare of children is expected to increase due to a higher allocation towards school education.

Women, youth and farmers have been given a future in this nation. At the same time, confidence level to the people of India has been given on the infrastructure of the country. We say, ?If a boy is educated, we get an educated man. But, if a girl is educated, we get an educated family.? The Budget gives women skill development, hostel creations, market access for self-help groups. Allocation of Rs. 3 lakh crore to the women-led development schemes shows the commitment of the Government. When it comes to the youth of the country, the youth today consist of a large population, waiting to be tapped properly in this country. I welcome the announcement to increase the amount of education loans and skill development loans to the youth. Especially, the internship scheme for one crore young men and women will go a long way to meet their hopes and aspirations. I would again like to say that the backbone of the country is the farmers. Farmers provide us food every day. There has been a special place for the farmers in the successive Budgets of the NDA Government. This is to encourage farmers. According to the Budget, one crore farmers are going to adopt organic farming. It means we will get healthy and nutritious food free from chemicals.

The various initiatives like augmenting vegetable production and digital surveys of agricultural process at an estimated allocation of more than Rs. 1.5 lakh crore show continued encouragement to farmers.

Lastly, I come to infrastructure. Ever since the NDA Government, under the leadership of our hon. Prime Minister, has come to power at the Centre, investments in infrastructure have witnessed a big push. This year also, the allocation for infrastructure development is Rs. 11.11 lakh crore, which is commendable. Especially, for agricultural produce to reach the markets and for our industries to function efficiently, capacity augmentation, infrastructural facilities like roads, ports and highways are the need of the hour. The assurance of viability gap funding for private investments in infrastructure, I would say, is a step for promoting economic development.

To conclude, this Budget has shown the Government?s strong commitment to policy continuity, job creation, and infrastructure thrust, while maintaining fiscal prudence. Finally, while appreciating the Finance Minister for bringing out the schemes and programmes which are for the benefit of the country as a whole without regional discrimination, I would also like to mention that this third time successful NDA Government, getting people?s support in the country, has shown a roadmap for the country?s future. I thank the hon. Prime Minister, the Finance Minister, and the Central Government for giving hope to the countrymen. Thank you very much.

डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : मैं बजट 2024-25 पर अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं ।

सबसे पहले, मैं देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को ऐतिहासिक तीसरी बार भारत माँ की सेवा का अवसर दिया है । साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने न केवल एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है बल्कि 6 पूर्ण बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन मातृशक्ति की एक अनूठी मिसाल पेश की है । हमारे देश में women led development को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ावा मिल रहा है ।

यह बजट 2047 के विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । यह बजट सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रावधान करता है । यह हमारे देश के हर वर्ग - गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगों के वृद्धि व सभी के हितों का ध्यान रखता है ।

मैं Maharashtra का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां हमारी डबल इंजन सरकार विकास के नए मापदंड स्थापित कर रही है । चाहे वह निवेश हो, हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, स्टार्टअप्स हो या बेहतर कानून व्यवस्था - हर क्षेत्र में Maharashtra आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है ।

आज, विश्व के प्रमुख देश, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या यूरोपीय राष्ट्र हों, सभी भारत में हो रहे विकास की सराहना कर रहे हैं । भारत का डंका विश्वभर में गूंज रहा है और यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है । purchasing power parity के संदर्भ में विश्व जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% है । यही नहीं, पीपीपी के संदर्भ में जीडीपी के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है । अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2023 में 2.5% से घटकर 2024 में 1.4% रहने की उम्मीद है, दूसरी तरफ चीन में विकास दर 2024 में 4.7% तक रहने की उम्मीद है और एक तरफ भारत है जो 2024 में 6.2% की दर से बढ़ने की ओर अग्रसर है ।

हमारी सरकार देश के हर कोने में विकास पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है । चाहे वह Infrastructure क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या शहरी विकास हो हमारा संकल्प है कि हर क्षेत्र में सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक लाभ पहुंचाए ।

जनता से वादा कर पूरा ना करना एक भष्टाचार है और लोकतंत्र के लिए एक ख़तरा है 2004 से 2014 तक हुए विकास कार्यों की तुलना में हमारी सरकार ने 2014 से 2024 के दशक में कई गुना अधिक प्रगति की है । हमारी सरकार अपने वादों को एक मिशन की तरह पूरा करने में दृढ़ विश्वास रखती है ।

यह बजट न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव को दर्शाता है, बल्कि भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है ।

सबसे पहले, मैं हमारी अर्थव्यवस्था की अभूतपूर्व प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । 2014 में, जब मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला, हम विश्व की 10 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे । आज, 2024 में, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं । यह उपलब्धि कोरोना महामारी और Geo-Political चुनौतियों के बावजूद हासिल की गई है।

यह गर्व की बात है कि भारत के कुल बजट आकार में पिछले एक दशक में तीन गुने की वृद्धि हुई है । 2013-14 में, हमारा कुल बजट आकार लगभग ₹16.65 लाख करोड़ था । आज, 2024-25 में, यह बढ़कर ₹48.21 लाख करोड़ हो गया है । यह वृद्धि न केवल हमारी

अर्थव्यवस्था के आकार में विस्तार को दर्शाती है, बल्कि यह हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियों और सुधारों का भी परिणाम है ।

सरकार के खर्च में Capital Expenditure (जैसे बड़े निर्माण कार्य या मशीनें खरीदना) का हिस्सा 2004 में 31% से घटकर 2014 में 16% हो गया था । लेकिन अच्छी बात यह है कि Capital Expenditure 2014 से 2024 के बीच यह खर्च पांच गुना बढ़ गया ।

2013-14 में पूंजीगत खर्च 1.9 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 9.5 लाख करोड़ रुपये हो गया ।

2010 से 2014 के बीच कुल खर्च में पूंजीगत खर्च का हिस्सा औसतन 12% था । 2015 से 2024 के बीच यह बढ़कर 14.5% हो गया, और पिछले पांच सालों में यह और बढ़कर 15.8% हो गया ।

कोरोना महामारी के कारण सरकार को सिर्फ 8 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन इस दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया गया । महामारी के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था कई विकसित देशों से भी ज़्यादा स्थिर थी ।

हमारी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है inclusive growth के साथ साथ भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना । भारत की

अर्थव्यवस्था अभी 3.1 ट्रिलियन डॉलर की है । आज़ादी के बाद से भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लग गए, 1 ट्रिलियन से 3.1 ट्रिलियन तक का सफर हमने सिर्फ 10 सालों में पूरा किया, जिसमे 2 वर्ष कोरोना महामारी के भी थे ।

बढ़ती हुई रफ़्तार के कारण भारत अगले 14-15 सालों तक हर दो साल में अपनी अर्थव्यवस्था में औसतन 1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है । सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (CEBR) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2035 तक दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा ।

वित्तीय स्थिरता हमारी प्राथमिकता रही है । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा Fiscal Deficit, जो वित्त वर्ष 21 में 9.2% था, वित्त वर्ष 24 में घटकर 5.6% हो गया है । 2024-25 के बजट में, हम इसे और

कम करके 4.9% तक लाने का लक्ष्य रखते हैं । और हमारा पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसी के आधार पर विश्वास के साथ इसे पूरा करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को और stable बनाएंगे ।

हमारे प्रधानमंत्री का ये सपना है की हर गरीब के पास अपना मकान हो । वह न केवल सबके लिए घर बनवा रहे, बल्कि एक सम्मानपूर्वक जीवन भी दे रहे है । देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा 2024-2025 के केंद्रीय बजट में की गई है ।

अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करेगी और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा ।

इन मकानों के साथ साथ राशन, जल बिजली स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है । प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब भारत सरकार 1 करोड़ लोगों के घरों में रुफ टॉप सोलर पैनल भी लगा रही है । यह हमारे green energy और infrastructure के प्रति जो प्राथमिकता है उसका प्रमाण है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे रियल एस्टेट स्टांप ड्यूटी को कम करें, विशेष रूप से महिलाओं के लिए । इस पहल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे कई शहरों में महिलाओं को मदद मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी

हाल के वर्षों में, भारत की रियल एस्टेट क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, विशेषकर RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) कानून के लागू होने के बाद । इस कानून ने घर खरीदारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, उनको एक भरोसा दिया है और रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा भी मिला है । पहले की सरकारों की तुलना में, अब परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवा मिल रही है जिसके कारण भारत वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 36 वें स्थान पर पहुंच गया है ।

2024 की पहली तिमाही में चीन में रियल एस्टेट निवेश, 2023 की पहली तिमाही की तुलना में 9.5% घटकर 2.2 ट्रिलियन युआन (लगभग 0.31 ट्रिलियन डॉलर) रह गया । वहीं, भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेश 2017 से 2022 के बीच तीन गुना बढ़कर 26.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और अब मोदी 3.0 में 2025 तक रियल एस्टेट क्षेत्र के जीडीपी में योगदान को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत करने का है । यह foreign investors का भारत की सरकार और उनकी नीतियों में अटूट विश्वास का प्रतीक है ।

हमारी सरकार के नीतियों के कारण रियल स्टेट के क्षेत्र में Black Money का प्रचलन कम हो गया है और साथ ही Metro के साथ साथ non Metro City में भी तेज़ी से विकास हो रहा है । **श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) :** मैं माननीया वित्त मंत्री जी द्वारा 22 जुलाई 2024 को सदन में पेश बजट का पुरजोर समर्थन करती हूं । मैं सबसे पहले माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से बधाई देती हूं कि वह स्वतंत्र भारत की पहली वित्त मंत्री हैं जिसने सातवीं बार लगातार बजट पेश किया है ।

यह बजट देश के गरीबों, युवाओं, किसानों ,महिलाओं एवं समस्त देशवासियों को समर्पित है और उनके सपनों को साकार करने वाला है । इस वर्ष माननीया वित्त मंत्री जी ने 48 लाख करोड रुपए से अधिक के व्यय का बजट प्रस्तुत किया है ।

आज देश में आर्थिक मंदी का दौर है और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था मंदी से प्रभावित है ,जहां बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है । लेकिन हमारे यह यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की सूझबूझ का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है जहां हम 2012 में विश्व की 40 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वहीं आज हम विश्व को सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था हैं और हम जल्दी ही पांच ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे ।

मैं यह कहूंगी कि मौजूदा परिस्थितियों में माननीया वित्त मंत्री जी द्वारा बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है बजट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे कि किसी को हानि हो उन्होंने पूंजीगत व्यय रखने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जताई है और अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के प्रयास किए हैं ।

माननीया वित्त मंत्री जी ने देश के हर वर्ग को कुछ ना कुछ राहत प्रदान की है आज व्यापारिक वर्ग, हर उद्योगपति, किसान, नौकरी पैसा व्यक्ति, बुजुर्गों और महिलाओं या अन्य किसी भी वर्ग से संबंधित प्रत्येक को इस बजट से आर्थिक लाभ हुआ है दूसरे शब्दों में कहें इस बजट से देश का हर वर्ग खुश है ।

रक्षा क्षेत्र में वित्त मंत्री जी ने 6.21 लाख करोड रुपए से अधिक का आवंटन किया है जिसमें से 6500 करोड रुपए से सीमा पर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और रक्षा से जुड़े स्टार्टअप की मजबूती के लिए 518 करोड आवंटित किए गए हैं जो समय की मांग है इस बेहतरीन कदम के लिए वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करती हूं ।

शिक्षा के क्षेत्र में 20 लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निपुण बनाया जाएगा । देश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए छात्रों को 10 लख रुपए कर्ज के तौर पर वित्तीय सहायता मिलेगी । 20 लाख युवाओं को अलग-अलग क्षेत्र में 5 वर्ष में निपुण बनाया जाएगा और आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा ।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर सरकार 89,287 करोड रुपए खर्च करेगी । फार्मा उद्योग को पीएलआई के तहत 2,143 करोड रुपए का आवंटन किया है । कैंसर की 3 दवाओं पर से सीमा शुल्क हटा दिया है । कुपोषण से जंग के लिए आंगनबाड़ी केन्दों को अपडेट किया जाएगा । बायोटिक रिसर्च पर भी वित्त मंत्री जी का ध्यान गया है और उन्होंने इसके लिए 1100 करोड़ का आवंटन दिया है ।

बजट में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने पर जोर दिया गया है वित्त मंत्री जी ने मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए कर दिया है । एमएसएमई क्षेत्र की 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिटों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब पीपीपी मॉडल पर बनाने की योजना है जो एक सराहनीय कदम है ।

देश के गांव के सर्वांगीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है । गांव की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के साथ सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा । यह सभी सराहनीय कदम है ।

ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी और भेल एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर टेक्नोलॉजी की मदद से खेती में उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है । सरसों, मूंगफली, सोयाबीन ,सूरजमुखी तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है । साथ ही साथ अगले 2 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जुड़ने का प्रावधान किया है यह सभी अच्छे और सराहनीय कदम हैं ।

मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूं ।

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद) **:** आपने मुझे वर्ष 2024 के अंतरिम बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

हम सभी जानते हैं कि बजट किसी भी देश की आर्थिक नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है । यह सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं का प्रतिबिंब होता है । लेकिन जब यह बजट विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए । यह बजट पढ़ने के बाद समझ नहीं आया कि यह एक देश का बजट नहीं बल्कि किसी एक राज्य या प्रदेशिक पार्टी को खुश करने के लिए बनाया गया है । सच कहूँ तो यह बजट 'राजनीतिक रूप से पक्षपाती और गरीब विरोधी है । महाराष्ट्र जो जीएसटी के रूप में केंद्र शासन को सबसे ज्यादा आय देने वाला राज्य है, इस बजट में उस महाराष्ट्र की अनदेखी की गई है । यह कहने में मुझे परहेज नहीं है कि यह बजट खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बना है । इसका कारण यह है कि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ सरकार का समर्थन कर रही हैं अथवा सरकार में शामिल हैं । इसमें केंद्र सरकार की मजबूरी झलक रही है । पहले बजट गुजरात के लिए बनता था । अब इसमें दो प्रदेश और शामिल हो गए हैं, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं हैं ।

इस बजट में गठबंधन की मजबूरी साफ झलक रही है । महाराष्ट्र के साथ-साथ अन्य राज्यों की अनदेखी की गई है । इस बजट में महाराष्ट्र के साथ भेदभाव किया गया है और महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है । सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के फंड में कटौती की है । महंगाई का सीधा असर आम उपभोक्ता के घरेलू खर्च पर पड़ता है । इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि थोक और खुदरा महंगाई की बढ़ी दरों के साथ-साथ उपभोक्ता व्यय के आंकड़े भी बढ़े हैं । इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण पिछले दो वर्ष में सबसे ज्यादा गोल्ड लोन हुए हैं । इसका मतलब यह है कि महंगाई सामान्य नागरिकों को परेशानी कर रही है । इस अंतरिम बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

खाद्य सुरक्षा कानून के बावजूद देश में कुपोषण के मामलों में कोई कमी नहीं आई है । यह सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों को लाभ देती है । यह गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का दर्द कैसे समझेगी? यह जनविरोधी बजट है । बेरोजगारी दर बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस समस्या को हल करने में विफल रही है । आज देश के शिक्षित युवा और कुशल युवा भी रोजगार की तलाश में सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार इस समस्या को हल करने में विफल रही है । अच्छा होता अगर सरकार मध्यम वर्ग के बारे में भी सोचती । आज मध्यम वर्ग करों के बोझ तले दबा हुआ है । इस बजट में मध्यम वर्ग को उम्मीद थी कि उनको कर में छूट बढ़ेगी, लेकिन उनकी उम्मीदें भी टूट गईं । इस तरह सरकार ने सभी वर्गों को निराश किया है ।

इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा अनेक विविध नवीनतम उपक्रम योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड नये घर बनाने और समय पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, लेकिन पिछले साल में कितने आवास उपलब्ध करवाये गये हैं और कितने निराधारों को इस योजना का लाभ मिला है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है । घोषणा सिर्फ सुनने और देखने में ही आ रही है ।

कृषि क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के कृषि बजट में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है । लेकिन, यह केवल संख्या का खेल है । असल मुद्दा यह है कि क्या यह बढ़ी हुई राशि किसानों तक पहुंच रही है और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है? वास्तविकता में, केवल बजट बढ़ाने से किसानों की समस्याएं हल नहीं होतीं । कई बार यह देखा गया है कि बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं होता है । कृषि क्षेत्र को विकास दर्शते हुए पांच राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड सक्षमकरण योजना

बताई जा रही है, लेकिन पहले से ही किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया है । किसानों को सहजता से ऋण मिलने में कई सारी दिक्कतें आती हैं । बैंक से किसानों को लोन लेते समय सिविल की मांग कि जाती है । जिन किसानों का ऋण एनपीए में है, उन किसानों के लिये बैंक द्वारा सेटलमेंट की जाती है । (ओटीस) बाद में जरूरत होने पर किसानों को ऋण नहीं मिलता है । कृषी क्षेत्र के विकास के लिये 1.52 लाख करोड रुपये अवंटित किए गये हैं, लेकिन किसानों को आवश्यक रसायनिक खाद के ऊपर जीएसटी कम करने के बारे में कोई जिक्र नहीं है । इसी के साथ दूध उत्पादक और दूध से उत्पादित सामग्री बनाने वाले किसानों के लिए इस बजट में कोई राहत नहीं दिख रही है । डिजिटल फसल सर्वेक्षण करके केवल सर्वेक्षण करने वाले कंपनी को लाभ होगा । उससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

रोजगार सृजन योजना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पांच सालों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा, लेकिन कौशल प्रदान करने के लिए, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वह अधूरी अथवा आभासी योजना है । प्रत्यक्ष रूप में इसका कोई आउटकम दिखाई नहीं देता । आज तक कौशल विकास योजना के माध्यम से जिन्होंने कौशल प्राप्त किया है, उनमें से कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुई है? यह कोई नहीं बता सकता है । युवाओं को व्यवसाय तथा स्वयं रोजगार निर्माण करने हेतु मुद्रा लोन योजना द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसकी स्थिती शोचनीय है । इस बजट में महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए निर्णय नहीं लिया गया है । महिलाओं के शिक्षा के लिए कोई उचित निर्णय अथवा प्रावधान नहीं किया गया है ।

आंध्र प्रदेश सहित अन्य पांच राज्यों को विशेष स्वरूप आर्थिक सहायता दिया गया है । आश्चर्य की बात यह है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती के लिये विशेष पैकेज द्वारा 15000 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है, लेकिन मुंबई जो देश को सबसे ज्यादा आय देने वाला शहर है, उसके सर्वागीण विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । सरकार द्वारा प्रादेशिक असंतोष कम करने की बजाय उसे बढ़ावा दिया जा रहा है ।

महामारी ने हमें यह सिखाया है कि मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की कितनी जरूरत है । बावजूद इसके, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दयनीय है । सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है । डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी और दवाओं की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं आम हैं । देश की युवाशक्ति को रोजगार देने के लिए उद्योगों का विकास आवश्यक है । लेकिन, मौजूदा बजट में छोटे और मझोले उद्योगों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है । बेरोजगारी दर बढ़ रही है, इसलिए नई नौकरियों के सृजन के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है । जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की समस्याएं हमारे सामने बड़ी चुनौती है । बावजूद इसके, बजट में पर्यावरण संरक्षण और स्थायित्व के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । हमें हरित ऊर्जा स्रोतों, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस योजनाओं की जरूरत है । देशभर में वायु प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है ।

सरकार द्वारा 63 हजार नये गाँव को दत्तक लेने की घोषणा की गई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सांसदों द्वारा दत्तक लिए गए गाँवों के विकास का प्रारूप क्या है और 63 हजार गाँव का विकास का प्रारूप क्या होगा? सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए । इस बजट में ग्रामीण इलाकों के विकास के लिये कोर्ड महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है । कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है । युवा वर्ग के शिक्षण तथा उन्हें रोजगार देने के लिए इस बजट में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है ।

सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में धाराशिव, यवतमाल, गोंदिया, पालघर जैसे आकांक्षी जिले हैं, जिनके विकास के लिए विशेष स्वरूप योजना का जिक्र इस बजेट में नहीं किया गया है । इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन आकांक्षी जिलों को इसमें से बाहर निकालने के लिए इन जिलों का सर्वांगीण विकास करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए । कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बजट सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए है । यह केवल एक गुट अथवा केवल अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए बनाया गया है ।

देश का बजट केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य का खाका है । यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़े तो हमें बजट में विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ।

अच्छा होता कि यह बजट सर्व समावेश अर्थसंकल्प होता । धन्यवाद ।

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): Thank you for giving me an opportunity to express my views on the Union Budget 2024. I would like to congratulate the hon. Finance Minister for her record seventh consecutive Budget that reiterates PM Narendra Modi?s commitment to the crafting of Vikshit Bharat under the third term of the NDA Government.

I welcome this Budget, that reinstates the strong commitment and continuity of policies of the NDA Government. The special focus that is laid on the socio-economic policies addressing the four pillars of Vikshit Bharat, the garib, yuva, annadata and nari will surely reform the social and economic landscape of Bharat. The proposal to upskill 20 lakh youth over the next five years will surely plug the gap between industry and academia. The increase in the limit of mudra loans from Rs. 10 lakh to Rs. 20 lakh will enable a new ecosystem of young entrepreneurs to shine and make Bharat the new manufacturing hub.

The estimated nominal GDP growth rate of 10.5 per cent in 2024-25 is an affirmation that Bharat enroute to becoming the third largest economy. The increase in Budget allocation for the agriculture sector from Rs. 1,25,000 crores to Rs. 1,32,000 crores shows the commitment of the NDA Government towards the annadata.

I come from Tulunadu, the Dakshin Kannada region which boasts of unique culture, geography, people and economy, and I am sure that this Budget echoes the sentiments of them all and caters to their unique needs.

Within the provisions of the Budget, I am advocating for the need for improved, modern high speed network of roadways and railways between the port city of Mangalore and the capital city of Bengaluru.

India is among the top five fish exporting countries in the world, value of exports being 1.36 MT. I also call for the establishment of the fisheries university in Mangalore that would facilitate research and marine based industries. This would drive the export of marine products.

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : विकसित भारत 2047 के लिए रोडमैपः यह केंद्रीय बजट मोदी सरकार के प्रति देश के लोगों द्वारा जताए गए विश्वास को दर्शाता है, जिन्होंने लगातार तीसरी चार चुना है । इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (ज्ञान) समूहों सहित अन्य सभी का ध्यान रखा गया है । यह बजट अंतरिम बजट के अनुरूप विकसित भारत 22047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है । इसमें विकास के नौ सूत्री विषय को शामिल किया गया है जो कृषि में उत्पादकता और लचीलापन से लेकर अगली पीढ़ी के सुधारों तक सर्वांगीण और समग्र कल्याण और विकास को समाहित करता है ।

अमृत पीढ़ी के लिए सार्थक रोजगार सुनिश्चित करनाः यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमृत पीढ़ी विकास के पथ पर बनी रहे, बजट में युवाओं के लिए सार्थक रोजगार सृजित करने, उन्हें बाजार के लिए कौशल प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर जोर दिया गया है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पांच वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए पांच योजनाओं और पहलों का एक पैकेज घोषित किया गया है, जिसका केंद्रीय आवंटन ₹2 लाख करोड़ है । इसके अलावा, उपरोक्त पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए तीन योजनाएं शुरू की गई है, अर्थात पहली बार औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक महीने का वेतन, जिससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा; निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि योगदान के साथ नियोक्ता और कर्मचारी को 4 वर्षों के रोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे; प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ई.पी.एफ योगदान के लिए नियोक्ताओं को 2 वर्षों के लिए प्रति माह ₹3000 की प्रतिपूर्ति करके समर्थन देना, जिससे 50 लाख से अधिक युवाओं को लाभ होने का अनुमान है ।

युवा का कौशल विकासः मोदी सरकार, भारत को विश्वगुरु बनाने की अपनी आकांक्षा को साकार करने के लिए देश के युवाओं के कौशल विकास के महत्व को समझती है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बजट में एक कौशल विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा । 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और पाठ्यक्रम की सामग्री को आधुनिक समय की कौशल आवश्यकताओं के अनुसार संरेखित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, किसी भी सरकारी योजना के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ₹10 लाख तक के ऋण का वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई-याउचर दिया जाएगा, जिसमें ऋण राशि का 3% वार्षिक व्याज अनुदान होगा । मोदी सरकार ने युवाओं को 500 कंपनियों में उद्योग का अनुभव प्राप्त करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिससे 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इस कार्यक्रम के तहत ₹5000 प्रति माह के साथ-साथ ₹7000 की एक बार की सहायता प्रदान की जाएगी ।

बेहतर कल के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनानाः ज्ञान के मुख्य समूहों के अलावा, मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की नई प्रतिबद्धता पर जोर दिया है । इस संबंध में बजट, करदाता को केंद्र में रखता है और कर स्लैब को सरल बनाने और वेतन से काटे गए टी. डीए.स में टी.सी.एस का क्रेडिट प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर देता है । इसके अलावा, टी.डी.एस फाइलिंग में देरी को अपराधमुक्त कर दिया गया है । वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत बढ़ाने के लिए, मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 किया जाएगा । मध्यम वर्ग के लिए असमानताओं को कम करने के दृष्टिकोण से, बजट में सामाजिक सुरक्षा लाभ भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें एन.पी.एस के लिए कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% करना और एन.पी.एस वात्सल्य की शुरुआत करना शामिल है, जहां माता-पिता और अभिभावकों से नाबालिगों के लिए योगदान प्राप्त

किया जाता है । सरकार की मुख्य प्रतिबद्धता हर परिवार के लिए रोटी, घर, और मकान प्रदान करना रही है । इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, बजट में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं के लिए ₹10 लाख करोड़ का निवेश प्रदान किया गया है । इसके अलावा, मध्यम वर्ग की चचत को बढ़ाने के लिए, बजट में हर घर में सोलर रूफटॉप पैनल लगाने की योजना को दोहराया गया है, जिससे हर घर के लिए प्रति वर्ष 12 से 18 हजार की बचत होगी ।

सामाजिक न्याय के माध्यम से अमृत काल को साकार करना: मोदी सरकार समझती है कि भारत का "अमृत काल" उसका "कर्तव्य काल" भी है, इसके दौरान समाज के सभी वर्गों, जिसमें गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शामिल हैं, इन सभी को राष्ट्र की सफलता की कहानी में योगदान देना होगा । आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, बजट का उद्देश्य आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए पी.एम-जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है । इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा । इसी तरह, देश के गरीबों के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे ।

भारत की सफलता में नारी शक्ति अग्रणी: मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया है, जिसे सामाजिक स्वायत्तता, वित्तीय समावेशन और महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के उपायों द्वारा सुगम बनाया गया है । इस बजट में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए ₹3 लाख करोड़ का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आंध्र प्रदेश की राजधानी की आवश्यकता की भी मान्यता दी गई है । इस उद्देश्य के लिए ₹15,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । इसके अलावा, बजट में आंध्र प्रदेश के किसानों की जीवनरेखा पोलावरम परियोजना के लिए भी प्रावधान किया गया है ।

सतत आर्थिक विकास और राजकोषीय समेकन: मोदी सरकार ने, विरासत में निराशाजनक कॉर्पोरेट क्षेत्र और अत्यधिक गैर-निष्पादित संपत्तियों वाली कमजोर अर्थव्यवस्था मिलने के बावजूद, सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित करने, पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाने और लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण की तीन गुनी नीति के माध्यम से सकारात्मक राजकोषीय समेकन में सफलता प्राप्त की है । इन्हीं सक्रिय उपायों के कारण, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद, भारत एक सफल अपवाद के रूप में उभरा है । भारत ने स्थायी विकास का अनुभव किया है, जिसके 6.5-7% और राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया है । मुद्रास्फीति के कम और स्थिर होने के कारण, 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य का अनुमान लगाया जा रहा है । इसके अलावा, बजट में बताया गया कि जी.एस.टी आने से कैसे आम आदमी पर टैक्स का भार कम हुआ और व्यापार और उद्योगों के लिए अनुपालन बोझ और लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई । घरेलू उत्पादकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए, सरकार ने व्यापार पहुंच को सुविधाजनक बनाने, शुल्क व्युत्क्रम को हटाने और विवादों को कम करने के लिए कस्टम शुल्क संरचना को तर्कसंगत और सरल बनाने का प्रस्ताव भी रखा ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के संभावनाओं को अनलॉक करना: एम.एस.एम.ई को विकास का एक प्रमुख प्रेरक मानते हुए, बजट ने विशेष रूप से श्रम प्रधान विनिर्माण के संदर्भ में उनके प्रचार पर जोर दिया । वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, मोदी सरकार ने एम.एस.एम.ई की क्रेडिट पहुंच और परिचालन दक्षता में सुधार की पहल की है । बजट ने प्रणालीगत बाधाओं और संपार्श्विक की कमी के कारण ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को स्वीकार किया । इस उद्देश्य के लिए, तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख

से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है । एम.एस.एम ई की संचालन में सुगमता लाने के लिए, बजट ने टी.आर.ई.डी.एस में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के दायरे को बढ़ाया, जिससे अधिक कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलेगी । भारत की बढ़ती आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप, बजट में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों की स्थापना की भी घोषणा की गई है, जो एम.एस.एम.ई और पारंपरिक कारीगरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार और निर्यात से संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देगा ।

आकार और गति के आधार पर औद्योगिक विस्तारः आर्थिक विकास और व्यापार के लिए औद्योगिक विस्तार के महत्व को देखते हुए, बजट ने उद्योगों और इसके संबद्ध क्षेत्रों की क्षमताओं में सुधार के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है । उधोग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, चजट ने 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार "प्लग एंड प्ले" औद्योगिक पाकों के विकास की घोषणा की । शिपिंग उद्योग को मजबूत करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, सरकार ने अधिक रोजगार सृजित करने के लिए स्वामित्व, पट्टे और ध्वज सुधारों की भी शुरुआत की है । इसके अलावा, प्राकृतिक संसाधनों के पारदर्शी उपयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए, मोदी सरकार ने घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्चक्रण, और महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू करने की भी घोषणा की है । विनिर्माण क्षेत्र के अलावा, बजट ने भारत की एक उभरती हुई सेवाओं की अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दी है और उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और निजी क्षेत्र द्वारा नवाचार के लिए जनसंख्या स्तर पर डी.पी आई अनुप्रयोगों के एकीकरण का प्रावधान किया है । नवाचार के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को पहचानते हुए, सरकार ने सभी प्रकार के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त करने की भी योजना बनाई है ।

बुनियादी ढांचे द्वारा दीर्घकालिक विकासः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत, बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाकर ₹11,11,111 करोड़ कर दिया गया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है, जबकि यूपीए सरकार के तहत वित्त वर्ष 2013-14 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन ₹2,57,641 करोड़ था, जो जीडीपी का केवल 2.8% था । यह आवंटन में चौगुनी वृद्धि की ओर इशारा करता है, जिसका बदले में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, जिसमें बुनियादी ढांचा विकास और सामाजिक क्षेत्र शामिल है, पर 2.45x गुणक प्रभाव होगा । बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सीधे साधन के रूप में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर देता है और 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पी.एम. जी.एस.वाई. के चरण IV की शुरुआत करता है । मोदी सरकार राज्यों को बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए समर्थन प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करेगी, जिसमें उन्हें ₹1.5 लाख करोड़ दीर्घकालिक व्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे ।

भारतीय शहरों को नए आयाम तक पहुंचाने की दिशा में: बजट ने आर्थिक और परिवहन योजनाओं का उपयोग करके सतत शहरी विकास पर जोर दिया है । मोदी सरकार मौजूदा शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास के लिए सक्षम नीतियों, बाजार आधारित तंत्र और विनियमों के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी । बजट में 30 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए परिवहन उन्मुख विकास योजनाएं तैयार की गई हैं । इसके अलावा, एक व्यापक किराये की आवास नीति भी लागू की जाएगी । बजट में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना भी शामिल है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सके ।

मोदी सरकार की भारत की विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धताः मोदी सरकार ने हमेशा राष्ट्र की प्रगति के साथ-साथ उसकी प्राचीन विरासत और संस्कृति को संजोए रखने पर जोर दिया है ताकि विश्व में इसकी सराहना हो सके । केंद्रीय बजट भी इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और

महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के विकास के लिए धन आवंटित करता है, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के सफल मॉडल के बाद तैयार किया गया है । मोदी सरकार हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान राजगीर के लिए एक व्यापक विकास की पहल करेगी । यह बजट नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय को उसकी पूर्व महिमा में पुनर्जीवित करने पर भी जोर देता है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, बजट ओडिशा के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, शिल्प कौशल, वन्यजीव अभयारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्यों और निर्मल समुद्र तटों की सुंदर बनाने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है ।

आकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत रोडमैपः मोदी सरकार ने देश में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का नेतृत्व किया है, जिसमें जे.ए.एम-त्रयी (जन धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी) क्रांति शामिल है । इसके कारण राष्ट्र वित्तीय समावेशन और सामाजिक कल्याण के नए, डिजिटल युग में प्रवेश कर गया है । इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, बजट अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का प्रयास करता है । सरकार ने विभिन्न भूमि सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें सभी भूमि के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान या भू-आधार का आवंटन, भू-संपत्ति मानचित्र का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उपखंडों का सर्वेक्षण, शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, जी.आई.एस मैपिंग के साथ भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और इसे किसानों की रजिस्ट्री से जोड़ना आदि शामिल हैं । इसके अलावा, मोदी सरकार ने तकनीकी विकास के लाभ प्राप्त करने के लिए देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के महत्व को भी समझा है । इस दिशा में, सरकार बुनियादी अनुसंधान और प्रतिकृति विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान निधि को क्रियान्वित करेगी । इसके अतिरिक्त, बजट अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना विस्तार देने पर भी जोर देता है. जिसमें ₹1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष बनाना शामिल है ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय वित्त मंत्री जी ।

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you very much Speaker Sir. I thank every Member of this House, who has spoken and taken interest in the Budget which has been presented here.

Let me, at the outset, thank the people of this country for giving this Government headed by our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji this historic third consecutive term in office. It actually reaffirms the faith the people have and the commitment with which the hon. Prime Minister is leading the country and, therefore, building stability and coming up with people-centric policies. We shall all work together to build a Viksit Bharat by the year 2047. I am extremely humbled by the trust vested in me by the hon. Prime Minister and it encourages me to work even harder to attain the Government?s vision of Viksit Bharat.

I would like to thank all the Members for having participated in this robust debate and I am trying here to address almost all the issues raised by the hon. Members. I shall go by issue which would cover many Members under each issue but I am trying to name as many of them as possible.

Just before I do their part where I am responding to the hon. Members, I would like to highlight some of the budgetary features, which is very important for us to understand where this Budget fits in itself in the long path towards Viksit Bharat.

Sir, this Budget actually draws upon what was mentioned in the Vote on Account. So, essentially, this Budget infuses into itself almost everything said in the Vote on Account, and after that, of course, brings in newer addition towards making this year the first step towards the next five years leading towards Viksit Bharat. So, the continuity from the Vote on Account is something that I would like to underline.

The principle of governance has been sabka saath sabka vikas sabka viswas sabka prayas since 2014. Following that, we shall come forward and work together to make sure that we overcome all the difficulties. The Budget actually seeks to consolidate all the earlier accomplishments. It also outlines the measures to overcome our challenges. Two core elements have been highlighted here. One is the social inclusivity, that is, reaching out to all the people in the society and the other is geographical inclusivity through equitable development for all the regions in our country. So, we are taking a whole-of-nation approach. We are now trying to make sure that we fulfil the aspirations of our people. So, briefly, if I may summarise the points, which are meeting these objectives that we set before ourselves, it is this.

The expenditure of the Government has actually grown exponentially. Today, it is Rs.48.21 lakh crore. It is projected to grow by about 7.3 per cent over 2023-24 and 8.5 per cent over pre-actuals of 2023-24. We call it pre-actuals though the final figures are almost there. As it has to be certified and audited, we give it the nomenclature ?pre-actuals?. But they are actually close to the real RE. Within the total expenditure, one feature, which has marked India?s growth story in post COVID-19 period is the capital expenditure with which we are building assets, that is, the Government-owned expenditure to build the assets. So, capital expenditure is the one which has actually enabled us to come out of COVID-19 period. Many other countries in the world are doing very many things. But it is a tested formula, depending on the multiplier which comes out of spending on public expenditure and spending on capital expenditure through public money. It has actually yielded

us such results that post COVID-19 period, we have maintained consistently high growth rate and we are the fastest growing economy in the world. As a result of this, our Government?s approach is very clear.

In the total expenditure of Rs.48.21 lakh crore, Rs.11.11 lakh crore goes to capital expenditure. The budgeted capital expenditure is now almost 3.3 times the capital expenditure which was there in 2019-20, that is, prior to COVID-19 period. If you actually calculate the effective capital expenditure, it is the sum which is referred to for the budgeted capital outlay and the grants-in-aid for creation of capital asset which is given to the States account. It remains in the revenue account and it also creates capital in the States? name. If we want to calculate the effective expenditure, it is Rs.15.02 lakh crore or above 18 per cent over RE of 2023-24. That is the impetus we are giving to the growth to be sustainable and to retain that growth, we have been very clearly attributing this to the hard work of the people of this country.

I am not going into the details of the Revenue Expenditure because it is already in the Budget documents. But more importantly, I want to talk about the allocation because I think a lot of hon. Members have said that probably the allocation in the social sector has come down. I want to, by giving the data, showcase to the hon. Members that the expenditure, on the contrary, has gone up. Just Rs.0.30 lakh crore was allocated to agriculture and allied sector in 2013-14 whereas it is now Rs.1.52 lakh crore. It is even Rs.8,000 crore more than the last year of 2023-24. So, over the last years, we have made an increase in it and not brought a reduction on it.

Sir, education, employment, and skilling is the next item for which Rs. 0.85 lakh crore was allocated in 2013-14 whereas today, it is Rs.1.48 lakh crore, which is 23 per cent more allocation even over the last year. It is Rs. 28,000 crore more than the last year, which is 23 per cent more allocation compared to even last year. In 10 years, it goes up from Rs. 0.85 lakh crore to Rs. 1.48 lakh crores.

As far as the allocation towards women and girls is concerned, Rs. 0.96 lakh crore was allocated in 2013-14 which is Rs. 3.27 lakh crore now. That means, there is 41 per cent more allocation or Rs. 96,000 crores more than the last year.

In the case of rural development, including infrastructure, Rs. 0.87 lakh crore was allocated in 2013-14 whereas this year it is Rs. 2.66 lakh crore, which is 11.7 per cent more allocation over the last year. It is Rs. 28,000 crore more than the last

year. In the case of urban development, it was only Rs. 0.12 lakh crore in 2013-14, whereas it is close to Rs. 1 lakh crore now. It is Rs. 7,000 crore more than the last year. In the case of health and social welfare, Rs. 0.72 lakh crore was allocated in 2013-14, it is now Rs. 1.46 lakh crore. It is Rs. 3,000 crore more than the last year itself. Nowhere has the budget given lesser allocation than the previous year. I would like to appeal to hon. Members to please have a look at the document in full and see that no allocation has been reduced.

Just briefly what the Budget 2024-25 tries to bring in is a balance among several objectives because growth is important and through better growth, higher growth, we believe that inequality can be addressed. So, growth, employment, welfare spending, capital investments, and fiscal consolidation, are the factors which we have tried balancing in the Budget. It is an indicator which is very important for us. If I am insisting on doing public spending on capital expenditure, the quality of public spending is the revenue deficit to fiscal deficit ratio normally. From about 80 per cent in 2020-2021, COVID-19 year, on account of COVID-19 pandemic, the revenue deficit to fiscal deficit ratio was expected to fall to 36 per cent which was very high, whereas it has now fallen to and it is expected to fall to 36 per cent in 2024-25. It is, therefore, reflecting the fact that expenditure is going towards quality asset creation. No one can refute this data, Sir. These are all available in public domain.

The other thing which is an important indicator is this. Sir, I had promised in this House in 2021-22 that the Government would endeavour to attain fiscal deficit to GDP level below 4.5 per cent by the year 2025-26. From an unprecedented high of 9.2 per cent in 2020-2021, we have kept completely to the trajectory projected. We have not deviated from it. We are complying by that fiscal deficit trajectory given by me. Even today, you see that we have reached close to 4.6 per cent, actually, this year. We have clearly given 4.9 per cent as the fiscal deficit. So, we are keeping our word on that.

India's exceptional post-pandemic economic recovery to become the fastest growing economy over the last three years is truly magnificent and I thank every citizen. The middle-class, the entrepreneurs, the farmers, the marginal workers, traders, everyone who I have mentioned or not mentioned, deserves big gratitude, a word of thanks from all of us. It is because of their toil, hard work, and their belief that they have to bring up the situation for their families to be better, has resulted in India becoming the fastest growing economy. How many nations ? may I ask this

here ? have achieved this balance through the budget since the post-COVID-19 to retain that growth, ensure that this balance happens, and continues that sustainable growth momentum?

So at least, these sorts of things have to be remembered for the sake of thanking our people. I would like to highlight these as the last few years? achievements of this Government and entirely thank the people of India. This could not have been possible unless there is a hardworking visionary leadership which takes us forward so that the country can really come out of the COVID distress, and I thank the hon. Prime Minister for his leadership on this.

Sir, I had also presented the Jammu and Kashmir Budget for 2024-25. I am happy to inform that concrete steps have been taken to enable the Union Territory to break free from the fetters of the past, namely the legacy of fiscal distress which has been inherited from the erstwhile State. We have provided substantial financial support ? I will give the numbers ? of Rs. 17,000 crore in the Union Budget of the UT of J&K this year. It includes Rs. 12,000 crore towards financing the cost of Jammu and Kashmir Police. That is a burden we want to take on our shoulders so that J&K has more flexibility to spend money for developmental activities. And, the additional Central assistance of Rs. 5,000 crore has been provided. With this support, I expect that the fiscal deficit to GSDP ratio of the Union Territory would be somewhere in the range of three per cent for the year 2024-25. The public finances of the Union Territory are now back on the rails, and they are now able to focus on developmental activities much more than ever before. And, the fiscal prudence is the biggest spirit with which the welfare activities are being taken up without any compromise on ?Sabka Saath, Sabka Vikas?.

So, because Jammu and Kashmir Budget was particularly of interest to some of the Members, I would like to respond to the Members as well, much before I go to responding to the Members on the General Budget.

Sir, some Members of J&K have raised questions about unemployment rate in J&K. Hon. MP, Shri Mian Altaf Ahmad and hon. MP, Shri Aga Syed Ruhullah Mehdi have raised issues about unemployment. I would want to put on the record of this House that unemployment rate for the age group of 15-59 years has actually come down for J&K from 6.4 per cent in 2020-2021, to 5.7 per cent in 2021-2022, to 4.4 per cent in 2022-2023. So, there is a reduction in the unemployment rate in J&K. The reduction is primarily because there are a lot of avenues being created for self-employment, and livelihood opportunities, through the Government of India?s

schemes. They are reaching all the people in J&K. And, as a result, you can see that employment opportunities in the sense of self-employment have actually grown.

Sir, again the hon. Member Mian Altaf had raised the issue about the works that were undertaken by the Union Territory Government for the welfare of the tribals. I would certainly like to say that there are about nine important things which need to be highlighted. The Union Territory Government has undertaken several initiatives for the tribal welfare in the areas of healthcare, education, culture, infrastructure development and livelihood. After two decades, actually, the forest rights were granted to the tribal communities. दो शतक इंतजार करने के बाद ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उनके हक फोरेस्ट राइट्स द्वारा दिए गए हैं । About 5,943 forest rights certificates have been issued to the tribal people. The first ever survey of the nomadic tribal population has also been conducted. Transport facilities are being provided to the nomadic tribes and the Bakarwals because they move up the range during summer and come down from the higher reaches to the lower levels. Transport facility is also being provided to them. Transit accommodation is being provided to migratory tribal communities, the communities which move from colder to slightly warmer regions in winter. The facilities also include community kitchens, medical and veterinary dispensaries, and community toilets. All these have been provided for the migratory tribal communities. Moreover, professional coaching centres, scholarships, skilling for 48,000 tribal youth, eight new hostel buildings, 285 smart schools, and six Ekalavya residential schools have been developed in the Union Territory of Kashmir.

17.00 hrs

Eighty schools are to be transformed into smart schools in the tribal areas. That is a very important step forward, and it will benefit tribal children. A total of 186 tribal villages are being developed under the PM Aadharsh Gram Yojana to help the tribal communities. A tribal research institute is being developed in Srinagar. These are some of the very specific measures being taken by the Government, and I hope the hon. Member has got substantial information on the question that he has asked.

Sir, now I come to the General Budget. I would go by issues on which many hon. Members of Parliament have spoken. So, I have clubbed them together. The first issue I take up was raised by the opening speaker, Kumari Selja. Then, many other hon. Members like Prof. Sougata Ray, Shri Hibi Eden Dr. T. Sumathi, Shri Charanjit Singh Channi, etc. have all spoken about how there is a threat to cooperative federalism, and only a few States have been given the benefits in the Budget.

Sir, I would like to humbly state this, and I am sure that all the Members know that if a State is not named in a Budget speech, it does not mean that no money goes to it. Therefore, that was a misleading campaign which, being in the Opposition, unfortunately, a lot of Members did speak about. ....*(Interruptions)* I would like to mention it from 2004-05 Budgets onwards. ....*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो सदस्य बैठे-बैठे बोलें, आपको उनका जवाब नहीं देना है ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I will take an example. ....*(Interruptions)* Sir, I am picking up on the Budget speeches since 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and so on. ....*(Interruptions)* Sir, 2004-05 Budget did not take the name of 17 States. I would like to ask the Members of the Opposition, who were a part of the then UPA Government, whether money did not go to those 17 States. Did they stop it? If they had stopped it, then they have every business to ask this question. I presume they did not stop money going to those 17 States as they did not name them. So, when it is one thing for them, it is all right, and when the same thing happens somewhere else, it is not all right, you would deceive. ....*(Interruptions)*

Sir, 17 States were not named in 2004-05. ....*(Interruptions)* Eighteen States were not named in 2005-06. ....*(Interruptions)* Thirteen states were not named in 2006-07. ....*(Interruptions)* Sixteen states were not named in 2007-08. Money did not go to them! Thirteen States were not named in 2008-09. In 2009-10, 26 States were not named. Twenty-six, which means only two States were named. ....*(Interruptions)*

If we are being blamed that only two States were named and other States are not getting anything, then I would mention that 2009-10 Budget had only two States, Bihar and Uttar Pradesh, and no other State. Then, what does that mean? Is it all right when you do it? You did not give money to those States which you did not name. ? (*Interruptions*) Sir, you cannot have it both the ways. You do one thing and then you blame the same thing on somebody else. What happened to the States which were not named? I am asking now. In 2009-10 Budget, 26 States of India did not have a mention. The Interim Budget did not have 26 States. The full regular Budget did not have 20 States. What does that mean? They continued to ignore States. In 2010-11 Budget, 19 States were ignored. In 2011-12 Budget, 15 States were ignored. They did not mention them. In 2012-13 Budget, 16 States were ignored. In 2013-14, 10 States were ignored. So, Sir, for that matter, the Interim

Budget of 2014-15 ignored 26 States. Was there a noise? Did people say that you ignored those States and you did not give them money? So, if you want to distort and create *afwaah*, and if you want to give a sense of fear among people, you can go about distorting data, but this stands here. ? (*Interruptions*) Sir, in the last few years, we had Ministers to go and explain how much has been given to each of the States. ? (*Interruptions*)

Sir, I just want to say this as random examples of how much money has gone to different States. The Bulk Drug Parks in Himachal Pradesh worth Rs. 1,900 crore were very recently announced by Prime Minister Modi. PM Mitra Textile Park went to Karnataka, Tamil Nadu and Telangana. Have they not received moneys for that? We have given Rs. 500 crore for greenfield park and Rs. 200 crore for brownfield park. Sir, these are just random examples.

Regarding railways, West Bengal, Jharkhand and Bihar got multi-tracking of Son Nagar-Andal section. ? (*Interruptions*) Yes, it is everybody?s right and that is why, I am answering. But instead of reading the complete list, I am giving random examples so that people can understand. ? (*Interruptions*) Regarding railways, Telangana and Maharashtra got doubling of Mudkhed-Medchal-Mahbubnagar-Dhone route, Telangana and Maharashtra got doubling of Motumari-Vishnupuram section and Telangana and AP got doubling of Bhadrachalam-Dornakal section. The amount is Rs. 12,334 crore for West Bengal, Jharkhand and Bihar, Rs. 4,686 crore for Telangana and Maharashtra and Rs. 1,596 crore for Telangana and AP. For Telangana and AP, the amount is Rs. 770 crore for Bhadrachalam-Dornakal section. These are the amounts which are going for railways alone.

Sir, now I come to major highways projects. I will like to put on record that after all the respective hon. Members of Kerala insisted - and I am glad to have received them - that much before I deliver the reply today, I have to meet them. It was an all-party delegation and I happily met them. I have no problems. I will also address the issues that they have stated. Let it go on record that all the MPs came and met me before I gave the reply. I have no hesitation. There is no *vanchana* to any State. Nobody is being denied any money. ? (*Interruptions*)

Sir, I mentioned Kerala. There is a major highway project for NH66 from Kappirikkad to Edappally in Thrissur District worth Rs. 967 crore in Kerala. Money has come. An amount of Rs. 9,667 crore has come. Did money come or not? For Mukkola Junction to Kerala/Tamil Nadu border, Rs. 1,148 crore has been allocated.

For J&K, Punjab, Haryana, and Delhi, Amritsar-Katra Road project is there at a cost of Rs. 18,274 crore.

I will again come to Kerala. India?s first trans-shipment port is there. All of us happily celebrated when a very big vessel reached Vizhinjam Port. The Kerala Congress Government gave it. Nobody who is speaking about AAs, A1, and A2 questioned the Kerala Congress Government when Vizhinjam was given on invitation to ? I am not taking the names ? one of the As. Nobody from the Congress Party said, ?Why are you giving it to AA, you can not give it to AA?. They did not say anything. Afterwards, when the Communist Party came to power in Kerala, even they did not disturb it. Congress gave it. Communist Party came afterwards. Even they also did not touch it. How much of viability gap funding has been given by Government of India? An amount of Rs. 818 crore has been given for Vizhinjam Port by Government of India for a project to which they themselves invited one of the As and gave it. That was given by Congress to one of the As. Another one who came as a Communist also did not touch it. It is going on fine till today. But lectures on AA is only for all of us.

Cooperative federalism and States not being mentioned in the Budget Speech does not have to be a very big issue. They all know. They have presented Budget in this country for decades. But when it is an ordinary *chaivala* OBC leader who comes to become Prime Minister and he does administration well, you then have a problem saying अरे, क्या हो रहा है? Is he doing well? No, no, we will have to protest. This will not work out. People are seeing this game.

The total resources transferred to States in BE 2024-25 is Rs. 22,91,182 crore. That is an increase of Rs. 4,93,645 crore, which is 27.5 per cent over last year?s BE. Transfer to States is Rs. 22,91,182 crore. You know the size of the Budget and rightly that much which is due to go to the States is going on time.

I have spoken about the criticism about not being mentioned in the Budget Speech. I do not want to elaborate. There are other things. As regards agricultural allocation coming down and legal guarantee for MSP, this also has been spoken about by more than 20 speakers. Twenty hon. Members have spoken. I will just elaborate. I know hon. Minister, Shivraj ji has been answering a lot of questions related to agriculture in the last few days. There may be some repetitions in my statement but I would like to highlight. The budget allocation for the Department of Agriculture and Farmers? Welfare was only Rs. 21,934 crore in 2013-14. वर्ष 2013-14 में एग्रीकल्चर के लिए 21,934 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट किया गया था । मगर वर्ष 2024-25 में वह

बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं । पांच गुना इन्क्रीज हुआ है । More than Rs. 3.2 lakh crore have been disbursed to over 11 crore farmers under the PM Kisan since its launch. So, Rs. 3.4 lakh crore have been disbursed to 11 crore farmers.

Institutional credit targets for agriculture have increased more than 2.5 times. In 2014-2015, it was Rs. 8 lakh crore. Now, it is Rs. 20 lakh crore. किसान को यह पैसा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पर मिल रहा है । Interest subsidy is also being given to Kisan. It has increased 2.4 times. वर्ष 2014-15 में 6 हजार करोड़ रुपये इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ किसानों को बैंक से लोन मिलता था, अब वह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 14 हजार 252 करोड़ रुपये है । Number of accounts of small and marginal farmers availing agricultural loans has grown from 57 per cent to 76 percent. वर्ष 2014 में 57 परसेंट लोन एग्रीकल्चर फार्मर्स लेते थे, लेकिन अभी 76 परसेंट लोन सब्सिडी के साथ ले रहे हैं । अभी यह नंबर और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा किसानों के साथ अच्छा प्रयत्न चल रहा है ।

Also, a Committee has been constituted some time ago to look at how the CACP -- Commission for Agricultural Costs and Prices can work better so that किसानों के लिए जो भी सुविधा मिलनी चाहिए, उसको बेहतर तरीके से देने के लिए कैसे काम करना है, उसके ऊपर यह कमेटी काम कर रही है ।

If anything, I think that many of the Members have already said this, but I would like to highlight this point. Today, the Congress party and the INDIA alliance partners are all doing good lot of politics on the farmers. I am saying it with consideration. I am not speaking loosely. The National Commission on Farmers, M. S. Swaminathan had recommended in 2006 minimum support price should be at 50 per cent more than the weighted average cost of production. This was not accepted by the UPA Government. The Cabinet Note, which was drafted in July 2007 said and I quote: ?? MSP is recommended by the CACP on objective criteria considering a variety of factors involved. Therefore, setting an increase of at least 50 per cent on the cost may cause distortion in the market. In some cases, there may be a mechanical linkage between MSP and cost of production per producer ??.

इतना कहकर यूपीए गवर्नमेंट नें वर्ष 2007 में एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया था । वर्ष 2004 के मेनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी बोलती है कि कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस लेकर आएंगे, मगर सचमुच में पीएम फसल बीमा योजना लाने वाले कौन हैं -- हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी हैं । उसके बाद Congress पार्टी ने यह भी कहा कि it would examine the feasibility of direct income support to farmers. मगर किसान सम्मान निधि वर्ष 2019 में लाने वाले कौन हैं -- माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी हैं । The Congress party can go on shedding crocodile tears about farmers. पिछले दस साल में किसी इम्प्लिमेंटशन में कुछ नहीं किया । I would say even for several decades कुछ भी नहीं किया ।

I come to the failure of the flagship loan waiver. सर, मैं फेल्योर ऑफ द लोन वेवर 2008 के ऊपर बात करना चाहती हूं । वर्ष 2008 के चुनाव में किसान के लिए लोन वेवर के ऊपर इतनी सारे बातें की गई हैं । CAG found gross irregularities in the implementation of the Rs. 50,000 crore agricultural debt waiver and debt relief schemes. सीएजी की रिपोर्ट में एकाध विषय कहा गया that around Rs. 164 crore was waived off in violation of the guidelines. इम्प्लिमेंटेशन में पूरा घपलेबाजी करने वाली कांग्रेस है । 22 परसेंट ऑफ द केसेज़ में लेप्सेस एंड ऐरर्स पाए गए । 8.5 per cent out of the accounts audited were not eligible to get loans. शायद जीजा, भतीजा आ गए, इसलिए जिसको मर्जी लोन दिए गए । इसमें कोई मापदण्ड फॉलो नहीं किया गया ।

34 per cent of the eligible beneficiaries of the test checked accounts were not issued debt waiver certificates. मैं यह मानती हूं कि यह एक बेरहम स्टेप है, जिसमें अगर बैंक वह सर्टिफिकेट नहीं देता तो वह किसान दोबारा लोन नहीं ले पाता । 34 परसेंट एलिजिबल केसेस में सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया, जिस लोन वैवर के ऊपर वे वर्ष 2009 में जीतकर आए थे । उसमें बहुत घपलेबाजी हुई थी और आज ये किसान के ऊपर रो रहे हैं । ? (व्यवधान)

सर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 15 माननीय सदस्यों ने यहां बात कही है, जिसमें कुमारी सैलजा जी, अभिषेक बनर्जी जी, सौगत राय जी, हैबी ईडन जी, राजीव जी, दुरई वाइको जी, पप्पू यादव जी, डिंपल यादव जी, एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, के. सुब्बरायण जी और डॉ. सुमति । मैं इनको एकाध विषय स्पष्ट करना चाहती हूं । इस बजट में यूथ के लिए पांच स्कीम्स को मिलाकर युवाओं के लिए एक पैकेज हम लेकर आए हैं । इसमें इम्प्लॉयमेंट भी है, स्किल ट्रेनिंग भी है और इंटर्नशिप भी है । Our policy is therefore to make youth *saksham*, *swatantra*, and *samarth*. To make them competent, independent, and capable, a lot of schemes have been brought in other than the five schemes put into the PM Package. Forty-eight crore MUDRA loans worth Rs. 29 lakh crore have been disbursed since 2014. 29 लाख करोड़ रुपये के लोन्स का डिसबर्सल मुद्रा योजना के अंतर्गत हुआ है । इसीलिए इस बार, चूंकि वह सक्सैसफुल हुआ है, हम उसका अमाउंट 20 लाख रुपये तक बढ़ा रहे हैं । हम इसे 10 से लेकर 20 लाख रुपये तक बढ़ा रहे हैं । मैं इन पांच स्कीम्स के ऊपर ज्यादा नहीं बोल रही हूं । But I want to say, यूपीए ईरा में जॉबलैस ग्रोथ का एक विषय हाईलाइट करना चाहती हूं । आरबीआई के गिल्म्प्स डेटा, जो पीरियोडिकली इकोनमी के ऊपर पिक्चर देता है, उसमें यूपीए के ईरा में इम्प्लॉयमेंट, मतलब, वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 में टोटल इम्प्लॉयमेंट एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है । आरबीआई की रिपोर्ट इसका जिक्र करती है । उनके कार्यकाल में जब टोटल इम्प्लॉयमेंट का नंबर डिक्लाइन होता है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं । मैं आज इसको इस हाउस में उठा रही हूं कि उस समय में इम्प्लॉयमेंट क्यों घटा? Why did it come down? If you are claiming that your economy management was all very good, how did total employment figure come down? This is RBI data, not mine. Secondly, formal employment was badly hit. Total persons engaged during the UPA time, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहता है कि टोटल पर्सन्स के इंगेजमेंट में डिक्लाइन कोविड महामारी के दौरान, यानी हमारी सरकार के टाइम से ज्यादा डिक्लाइन उस समय हुआ था । This is the data of 2012-13. The number of total persons engaged declined. उस समय डिक्लाइन हुआ था । We want to highlight the fact that the Annual Periodic Labour Force Survey Report shows that

the labour market indicators for persons in the age group of 15 years and above have steadily improved under the leadership of Prime Minister Modi. Between 2017-18 and 2022-23, our employment figures have improved. I am giving you at least four indicators for that. Labour force participation has increased from 49.8 per cent in 2017-18 to 57.9 per cent in 2022-23. Women labour force participation has risen to 37 per cent in 2022-23 from 23 per cent in 2017-18. इसमें विमिन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ हुआ है ।

The unemployment rate has declined from 6 per cent in 2017-18 to a low of 3.2 per cent in 2022-23.

Youth unemployment for the age group 15 to 29 has declined sharply from 17.8 per cent in 2017-18 to 10 per cent in 2022-23. So, the last point on this employment debate is this. The SBI research report which was released in July 2024 said, India created 12.5 crore jobs between 2014 and 2023, compared to only 2.9 crore during the UPA?s 10-years term. ? (*Interruptions*)

यूपीए के 10 सालों में, मगर अभी हमारे दस सालों में यह आँकड़ा 12.5 करोड़ का है । इसलिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बार-बार गलत प्रचार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि डेटा उसके खिलाफ है । ? (व्यवधान)

Sir, next is the question of inflation management. ? (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी **(श्रीरामपुर) :** आप एक काम कीजिए कि हमें इन 12.5 करोड़ लोगों का नाम दे दीजिए । हम लोग मान लेंगे । ? (व्यवधान) मैडम, आप 12.5 करोड़ लोगों की लिस्ट दे दीजिए । ? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The Periodic Labour Force does not include MGNREGA. It does not include it. I am sorry. No comfort on that. ? (*Interruptions*)

Sir, on the subject of inflation, seven hon. Members spoke. ? (*Interruptions*) I am not taking their names. ? (*Interruptions*) We saw double digit high inflation period during the UPA era, and it was because of their reckless policies. I want to differentiate between the inflation which prevailed during the UPA regime and the inflation, if at all, within the range which prevails now for some months which has gone up. There is a difference. Domestic inflation used to be higher than the global average during UPA?s time. Sir, with regard to global financial crisis 2008 - if we are talking about COVID-19 which is much, much more complex than the global financial crisis 2008 - the UPA Government took stimulus measures to boost the economy. But, I am sorry to say, I will come to this particular matter because it has relevance to one of the hon. Members. The UPA Government was run by the Harvard and Oxford educated leaders for the economy. They did not know when

and how to withdraw the stimulus leading to a high double-digit inflation between 2009 and 2013. There was high fiscal deficit and debt crowding out private investments. So, between January 2012 and 2014, just the 22 months of the total 28 months, inflation was above 9 per cent, almost double digit and almost double of the forbearance limit that is permitted. सर, इंफ्लेशन पर इनके रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही हैं । उसको बीट करना आसान नहीं है । UPA inherited a stable macro-economic environment with inflation at 3.8 per cent. During the periods 1999-2000 to 2003-04, अटल जी के समय पर इंफ्लेशन उस रेंज पर था, उसको यूपीए ने इनहेरिट किया । Comparatively, annual inflation rose to 8.1 per cent between 2004-05 and 2013-14. अटल जी के समय 3.8 परसेंट था और इनके समय 8.1 परसेंट था । इंफ्लेशन मैनेजमेंट पर यही इनका रिकॉर्ड है । हमारे एमपी साहब ऑलरेडी एक स्लोगन दे रहे हैं, उसे मैं बोलना चाहती हूँ । मैं हिंदीभाषी क्षेत्र से नहीं आती हूँ फिर भी मुझे यह याद है । ?कांग्रेस आई, महंगाई लाई? यह है इनका रिकॉर्ड । Sir, since the economy was in such poorly managed state because of inflation, I want to quote the RBI Governor. सर, आरबीआई गवर्नर का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वे इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है । उस किताब में वे जो बोलते हैं, उसे मैं क्वोट कर रही हूँ ।

I quote:

?The Finance Ministry used to pressurise the RBI to soften interest rates and present a rosier picture of growth to shore up sentiments.?

क्योंकि आपकी आर्थिक व्यवस्था इतनी बिगड़ गई थी कि आप आरबीआई को फोन करके उनको कह रहे हैं कि भइया, ठीक से मैनेज करो, क्योंकि सेंटीमेंट अफेक्ट हो जाएगा । आपने कुछ मैनेजमेंट नहीं किया । मगर इस किताब में फॉर्मर गवर्नर इनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में लिख रहे हैं । शेम? (व्यवधान) वह हमसे पूछते हैं कि इकोनॉमी कैसे मैनेज करते हो । India?s inflation between 2020 and 2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of Covid, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records. एनडीए के समय वर्ष 1999 से 2004 तक 3.8 प्रतिशत, यूपीए वन में 06 प्रतिशत, यूपीए टू में 10.2 प्रतिशत । So, during the UPA I and II put together, it is 8.1 per cent. अभी हम एनडीए वन पर आ रहे हैं । वर्ष 2014-15 से लेकर पांच सालों में इंफ्लेशन 4.5 प्रतिशत, एनडीए टू में इंफ्लेशन 5.7 प्रतिशत । During the NDA I and II put together, it is 5.1 per cent. 5.1 प्रतिशत कहां है? मैं यह भी दु:ख के साथ कहना चाह रही हूं कि जब प्रधान मंत्री जी ने पेट्रोल और डीजल प्राइस को दो बार कम किया, तो बीजेपी स्टेट्स ने इसका मूल्य कम किया, इंफ्लेशन घटवाए । मगर यूपीए के स्टेट्स ने कुछ नहीं किया । इसके कारण उनके स्टेट्स में इंफ्लेशन हाई रहा । यूपीए की पॉलिसी देश के लिए नुकसानदायक है ।? (व्यवधान) हमने इंफ्लेशन कैसे मैनेज किया ।? (व्यवधान)

सर, एनडीए गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इंफ्लेशन को मॉनिटर करते हुए सप्लाई साइड से हर स्टेप हर बार उठाते हैं । मैं उदाहरण देती हूं कि हम भारत ब्रांड आटा, राइस और पल्सेज को खरीद कर, सब्सिडी के साथ जनता तक पहुंचा रहे हैं । लोग भारत आटा 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम खरीद रहे

हैं या नहीं खरीद रहे हैं । वे बिल्कुल खरीद रहे हैं । 14.87 lakh tonnes have been sold to the common public. भारत राइस 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल मिलता है और 13.98 लाख टन बिक्री हो गया है । लोग यह खरीद रहे हैं । भारत चना दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम का पैक 11.52 लाख टन बिक गया है । भारत मूंग दाल और साबूत मूंग दाल 2984.37 टन सेल हो गया है । आम नागरिक तक हमारा भारत ब्रांड आटा पहुंच रहा है । इसीलिए वे इंफ्लेशन को फेस कर पा रहे हैं ।

मैं भूख के विषय पर आ रही हूं । यह सरकार एससी और एसटी को इग्नोर कर रही है, विमेन और पुअर्स को इग्नोर कर रही है । इस पर चार लोगों ने अपनी बात कही है । Shri Charanjit Singh Channi, Shrimati Dimple Yadav and Dr. Thol Thirumaavalavan, hon. Members of Parliament, have raised this issue. I want to say that the allocation for SC, ST and women has gone up substantially. मैं नम्बर दे रही हूं । एससी के लिए वर्ष 2023-24 में 1,59,148 रुपए करोड़ था, इस साल 1,65,493 करोड़ रुपए हैं । यह 6,345 करोड़ बढ़ा है । एसटी के लिए 1,19,706 करोड़ रुपए थे, अब उनके लिए 1,24,909 करोड़ रुपए हैं ।. We have increased it by Rs.5,113 crore.

वुमेन **?** पिछले साल 2 लाख 38 हजार 220 करोड़ रुपये और इस साल 3 लाख 27 हजार 158 करोड़ रुपये दिये हैं । इस साल 88 हजार 938 करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं । ? (व्यवधान) ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके सामने इस विषय को थोड़ा ध्यान से रख रही हूं । एससी, एसटी का एलोकेशन कम हो गया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूं । कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट ने एससी, एसटी फंड्स से बजट में 9 हजार 980 करोड़ रुपये, दिए हुए बजट से 4 हजार 301 करोड़ रुपये ट्राइबल सब-प्लान से निकाले गए, उसका पता नहीं चल रहा है कि वह कहां गए? ? (व्यवधान) So far, of the total, the Karnataka Government has spent Rs. 2,228 crore including Rs. 1,587 crore from the SC/ST sub-plan, and Rs. 641 crore from the Tribal sub-plan specifically. God knows where this is going. As this has been questioned in Karnataka itself by the Leader of the Opposition and the media, I want to ask one thing. माननीय पूर्व चीफ मिनिस्टर चरनजीत सिंह चन्नी जी आप कर्नाटक में जाकर अपने लीडर से बात कीजिए और एससी की हालत के ऊपर प्रश्न पूछिये । इधर पूछने की आवश्यकता नहीं है । उधर कांग्रेस गवर्नमेंट में इतने सारे घपले हो रहे हैं । ? (व्यवधान)

सर, कर्नाटक के बारे में एक और विषय है । मैं जरूर मानती हूं कि कांग्रेस में एससी के विषय में बात करने वाले हर नेता आज ही कर्नाटक जाएं और पूछे लें कि क्या हो रहा है? एससी के पैसे को निकाल कर प्राइवेट एकाउंट में डाला जा रहा है । किसी को मालूम नहीं हो रहा है और एससी के ऊपर इधर लेक्चर हो रहा है । ? (व्यवधान) सर, कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब्स डेवलपमेंट कारपोरेशन स्कैम? (व्यवधान) सर, बड़ा सा स्कैम है । इसमें विषय देख लीजिए कि कितनी इंट्रेस्टिंग बात है?? (व्यवधान) Normally, the Government stands up to say, ?*no gapla*, क्या आरोप लगा रही हो? सॉरी, ऐसी बात करने के लिए सरकार के पक्ष में से खड़े होते हैं । मगर उधर, मैं नाम नहीं ले रही हूं, पूर्व मुख्य मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे हैं कि अरे भइया, वह 187 करोड़ रुपये नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ रुपये है । ? (व्यवधान) घपला है, मगर? (व्यवधान) ?. not Rs. 187 crore but only Rs. 89 crore. यह देख लीजिए । क्या कॉन्फिडेंस है? ? (व्यवधान) घपला करो, फिर आरग्यु करो, बोलो कि 189 करोड़ रुपये नहीं है, जस्ट 89 करोड़ रुपये है । छोड़ दो । एससी का पैसा है, एसटी का पैसा है । उधर दोनों में घपला हो रहा है । मगर इधर एससी के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे हैं ।? (व्यवधान) पंजाब के पूर्व चीफ

मिनिस्टर एससी के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं । क्या घमंड है? ? (व्यवधान) सर, स्किल इंडिया मिशन के ऊपर ऑनरेबल मैम्बर श्री अभिषेक बनर्जी जी, श्री असादुद्दीन ओवैसी जी और श्री वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा ।

I want to highlight this to three hon. Members. तीन ऑनरेबल मैम्बर्स ने श्री अभिषेक बनर्जी जी, श्री असादुद्दीन ओवैसी जी और श्री वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा । इन द लास्ट डिकेड, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नेसेसरी हो गया है, स्किल इंडिया डिजिटल हब के बारे में विषय कैसे क्या है? उनका यह कंसर्न है कि स्किल इंडिया मिशन सक्सेस नहीं हुआ है । मैं उनको जेंटली बोल सकती हूं । In the last decade, the employment of Indian youth has increased sharply, rising from 34 per cent in 2014 to 51 per cent in 2024. क्योंकि उनका स्किलिंग हुआ, उनका अपग्रेडिंग ऑफ स्किलिंग हुआ, उसकी वजह से वे आगे आना सम्भव मान रहे हैं ।

इस बार के बजट के द्वारा 5 स्कीम्स के पैकेज, पीएम स्किल फॉर यूथ्स और एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ्स के पैकेजेज के द्वारा इसको और आगे बढ़ाएंगे । हम यूथ्स के लिए काम करेंग ।

वर्ष 2017 में हम स्किलिंग में, वर्ल्ड स्किल्स कंपिटिशन में हमारी पोजिशन 19 वें स्थान पर थी और आज वर्ष 2024 में हम 11 वें पोजिशन पर आ गये हैं ।

Sir, three Members have spoken on poverty and Global Hunger Index. Kumari Selja Ji, Durai Vaiko Ji and Gurmeet Singh spoken on poverty and Global Hunger Index.

Sir, I want to first of all, with all humility and modesty, say these are flawed indicators. The Global Hunger Index for India?s sake may not work out. I am not saying because you have raised a point but I will tell you why.

इन सबकी विश्वसनीयता, I will try to say it in Hindi मैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पर कुछ बातें रखना चाहती हूँ ।? (व्यवधान) मैं क्वेश्चन के द्वारा जवाब दे रही हूँ ।

Conflict recurring countries like पाकिस्तान और सूडान जैसे कंट्रीज को भारत से आगे रैकिंग कैसे मिल रही है? ? (व्यवधान) अफ्रीकन नेशंस में, आज भी उनका पर-कैपिटा इनकम भी कम है । पाकिस्तान में आज तक आटे का क्यों, I am not saying it in a sense, *ayyo*, look at them, they are suffering. No, I do not want them to suffer but it is a reality. Today, they are not able to obtain even basic food. Here भारत देश में हम 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में अनाज दे रहे हैं । फिर भी यह हंगर इंडेक्स में है । इस पर कैसे विश्वसनीयता स्थापित करेंगे? ? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Why do you not challenge it?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: We will do that.

Sir, they said that the households debt is at 50 years low while the household debt has increased. ऑनरेबल एमपी श्री अभिषेक बनर्जी ने यह प्रश्न पूछा था । Sir, this is very interesting data. I will request the hon. Members to kindly pay attention to this fact. The net financial savings of the household sector from Rs. 8.32 lakh crore in 2013-

14, has risen to Rs. 14.16 lakh crore in 2022-2023. This is the net financial savings of the household sector. This is an increase of 70 per cent. Regarding the household savings in the form of physical assets, बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट में कैश रखना एक बात है, लेकिन घर खरीदना या घर का विस्तार करने के लिए कमरा बनाना अलग विषय है ।

Today, in the form of physical assets, construction of houses or other immovable properties have increased from Rs. 14 lakh crore in 2013-14 to Rs. 35 lakh crore in 2022-23. It clearly indicates a shift of savings in the form of physical assets rather than in the form of financial assets. The registered investor base at the National Stock Exchange has tripled from March, 2020 to March, 2024 to 9.2 crore Indians - this is as on 31st March, 2024 - potentially translating into 20 per cent of India?s households are now channelling their household savings into the financial markets. इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए ।? (व्यवधान)

Hon. Speaker, I am almost coming to the end but one or two important points I have.

Sir, lack of transparency in the Budget was the issue that was raised by hon. Member Shri N. K. Premachandran. I want to highlight the fact.

In fact, it has come completely the opposite of what used to prevail during the UPA time and I will give you the examples. I want to say that this charge of lack of transparency in the Budget should actually be posed by Shri N.K. Premachandran on the UPA Budgets. All the details have already been provided. I am not going to say how much the revenue receipt is and how much the other receipts are.

The borrowings are meant for financing the fiscal deficit. He also asked as to how the Government will finance the additional allocation of around Rs.56,000 crore. So, I want to highlight that the borrowings are meant for financing the fiscal deficit in a way. I would like to mention that the borrowing has been reduced due to better fiscal management and it has also reduced the fiscal deficit from 5.1 per cent in the Interim Budget to 4.9 per cent in the regular Budget of 2024-25. The hallmark of Prime Minister Modi, since the days when he was the Chief Minister of Gujarat, has been his fiscal prudence without compromising on the welfare measures. He has not compromised on the welfare measures or schemes. He manages his finances very carefully. That is why, you have this fiscal prudence which is reflected in the fiscal deficit.

Sir, this is a total contrast to what had prevailed during the UPA time. I want to highlight how the Congress-led UPA Government had the constant practice of

hiding the deficits through off budget borrowings and issuance of Oil bonds which shifted the fiscal burden on the future generations. Under the UPA, the standard fiscal practices were routinely changed to make the Budget numbers look favourable. I have already said how the RBI?s Governor spoke. In order to make an impression of nice, goody-goody, you fudged the numbers; you put it under the carpet. All these things happened during the UPA time but not in our time.

In the financial year 2020-21, our Government, under the leadership of Prime Minister Modi ji, rapidly repaid all the outstanding National Small Saving fund loans which were provided to FCI in lieu of food subsidy by providing additional budgetary support. We cleared the account. That was shown in our Budget. There was no hiding under the carpet that एक्सटर्नल बॉरोइंग्स कर दिया, बजट में नहीं दिखाया । ?(व्यवधान) मैं बजट में फिसकल डेफिसिट का अच्छा नंबर दिखाऊंगा, लेकिन उधर बॉरो करते रहे । अब ऐसा नहीं है । No, everything that happens in the Finance Ministry is now in the Budget for all of us to see. इसमें अब कुछ ऐसा नहीं है कि पीछे से बॉरो करो, उधर रखो, इधर नहीं दिखाना नहीं है, अब ऐसा नहीं होता है । ? (व्यवधान) लैक-ऑफ-ट्रांसपेरेंसी यूपीए की गवर्नमेंट में थी, अब नहीं है ।

Sir, food subsidy under the PM Garib Kalyan Anna Yojana is being provided with complete transparency. From 2021-22, off the Budget-funded schemes are being proactively disclosed in the Budget documents? (व्यवधान) हम हर स्टेप ट्रांसपेरेंसी की ओर ले रहे हैं । I want this to be recognised by the hon. Member.

Two hon. Members asked some particular questions that the budget on the minority has been reduced. One is hon. Member, Shri Zia Ur Rehman from UP. I am forgetting his constituency. It is Sambhal. I must say one thing. You normally do not allow us to mention the names of the people who are not the Members. But with your permission, I want, for a moment, to pay my homage to his grandfather, late Shri Shafiqur Rahman Barq. He was a very elder Member. He came several times to meet me on his constituency-related problems. I used to respect him. I gave him a lot of time to understand his issues and where I could help, I have helped him. I do recognise the dignity with which he approached his concerns even in that age.

So, I want to respect his grandson who has now come in his position. The budget on minorities has not come down. I want to very clearly say this. In 2022-23, the actuals were Rs.803 crore. In 2023-24, the Budget Estimates were Rs.3,098 crore.

In 2024-25, the Budget Estimates are Rs. 3,183 crore which is Rs. 85 crore more than the last year?s allocation. There is no reduction in the funds.

Under the National Minorities Development and Finance Corporation, since 2014, Rs. 8,300 crore worth of loans have been disbursed to more than 22.5 lakh minority beneficiaries of whom 85 per cent are women. I want to give this information to our young new Member.

Lastly, there was a question asked by hon. Member, Karthik Chidambaram ji, about the under-insurance problem in the country and there is an 18 per cent GST on health insurance. I want to highlight that the PM Jeevan Jyothi Bhima Yojana has over 20 crore enrolments and over 16,087 crore claims have been paid till date wherein Rs. 2 lakh insurance cover is given at just Rs. 436 per annum premium. We have paid for 20 crore enrolments and 16,087 crore have been settled as insurance claims.

In the PM Suraksha Bima Yojana, there are 44 crore enrolments and 2,757 crore claims have already been settled or paid. In this Yojana, Rs. 2 lakh will be paid for total disability or accidental death at just Rs. 20 per annum premium. So, this is the way insurance for the common people has been given by Prime Minister Modi, and this is reaching a lot of poor people. I am happy to say that even during COVID-19, we had cleared a lot of claims even if they did not meet the usual requirements of doctor's certificate, mortuary certificate, etc. The hon. Prime Minister gave a clear instruction saying during COVID-19, all the claims must be settled. We do not want anyone to suffer due to lack of insurance certificates. ? (*Interruptions*) Sir, this is not something I very much would want to speak about, but there are one or two things which I need to highlight before I come to the last two points. Professor Sougata Roy has raised a lot of issues. But, I am astonished. From the land of West Bengal, which inspired our freedom movement, which gave us the slogan, *Vande Mataram*, ? (*Interruptions*) Yeah, you do not hear me all right ? (*Interruptions*) *Vande Mataram.* ? (*Interruptions*) I will be happy to say it 10 times, *Vande Mataram*. ? (*Interruptions*) West Bengal gave this call and we are very inspired by that. Today, from that Bengal, we have a professor, Professor Saugata Roy, who said something. I am not bothered. I am not worried. But it is worth mentioning for the consideration of this House. He said: ?I do not expect the Finance Minister to be like Dr. Manmohan Singh.? Certainly, I also do not want to be like Dr. Manmohan Singh. He further said: ?She is not a Ph. D., from Oxford, not even like Chidambaram, who has got a management degree from Harvard. She is from our own JNU. But the problem is, she is bereft of new ideas.? ? (*Interruptions*) सर, मैं सीधा प्रश्न पर आ रही हूँ । A lady who I respect a lot, a lady who I respect a lot, who sits equally in the GST

Council with me, ?* who is the Finance Minister of West Bengal, studied in the University of Kolkata. ? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: She is not a Member of this House. Sir, how can she take her name in this House? Sir, you are allowing her now. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, you may delete the name. ? (*Interruptions*) You may delete it. She is the Finance Minister of West Bengal and studied in the University of Kolkata.? (*Interruptions*) That is all right. I respect her. ? (*Interruptions*) Is she also bereft of new ideas? I do not want to take her name. She is the Finance Minister of West Bengal. ? (*Interruptions*) Please delete the name. I am not against it. I respect her, Sir. She does wonderful contribution in the GST Council.

So, the reference was made to me saying that she is from the JNU, but she is bereft of new ideas. ? (*Interruptions*) Is she bereft of new ideas? ? (*Interruptions*) Equally, I want to ask you a question. The Chief Minister of West Bengal is also from the colleges affiliated to the University of Kolkata. ? (*Interruptions*) Does this mean that if you study in the Indian universities, you are bereft of ideas? ? (*Interruptions*) She is a fighter who is leading the State for so many years. ? (*Interruptions*) You have made chauvinist comments. ? (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Where is the White Paper on MGNREGA? ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will come to that. ? (*Interruptions*)

Sir, I am astonished. ? (*Interruptions*) We talk about the Chief Minister?s qualification and say that she is a good Chief Minister who is fighting. ? (*Interruptions*) We are from the Indian universities, whether it is the Chief Minister of Bengal or it is me. ? (*Interruptions*) We all are from the Indian universities. ? (*Interruptions*) In what way are we less than the Harvards of the world or the Oxfords of the world? ? (*Interruptions*) I want to ask this question to the main chauvinist Professor who seems to be attacking women. And, it is even worse, he is a professor in one of the Indian colleges. ? (*Interruptions*) He is not teaching in Harvard; he is not teaching in Oxford. So, is he also equally not so qualified? ? (*Interruptions*) A Professor in the Indian University demeans people who have got qualifications from the Indian universities. ? (*Interruptions*) Prof. Sougata Ray, please be ashamed of yourself! ? (*Interruptions*) Even worse, he says that the inequality in India in 1920 was less than it is now. ? (*Interruptions*) It is the statement that Professor made. ? (*Interruptions*) I cannot believe the statement. ? (*Interruptions*)

Sir, West Bengal suffered under the British rule. ? (*Interruptions*) We all see the images of skinny, starved and skinned Indians, the people of West Bengal, who were starved by the British; and the entire grain of West Bengal was taken to fund the war. ? (*Interruptions*) People were photographed, sitting skinny with wounds on skin, and you say that that West Bengal was better in equality than now. ? (*Interruptions*) What a shameful statement to make! In this House, you said that inequality was less under the British rule than it is now. What a shameful statement to make! ? (*Interruptions*)

Sir, now I come to talking about West Bengal's economy. ? (*Interruptions*) I will give the White Paper they want. ? (*Interruptions*)

Sir, I would like to draw your attention and say that West Bengal's share of the total industrial production of this country used to be 24 per cent. ? (*Interruptions*) I want the hon. Members to keep paying attention to this data as it is very important for this country. ? (*Interruptions*) West Bengal's contribution to the total industrial production of this country at the time of Independence was 24 per cent. ? (*Interruptions*) Do you want to know what that number is today? ? (*Interruptions*) It is 3.5 per cent. ? (*Interruptions*) That is the West Bengal?s economy. ? (*Interruptions*) That is the West Bengal?s economy. ? (*Interruptions*)

Sir, there has been a downward trend in the Gross Capital Formation. ? (*Interruptions*) In 2010, West Bengal accounted for 6.7 per cent of the capital formation in India but now it accounts for only 2.9 per cent. ? (*Interruptions*) They want the White Paper! I will give the White Paper. ? (*Interruptions*) I will definitely give the White Paper. ? (*Interruptions*) This is the performance of West Bengal's economy, Sir. ? (*Interruptions*)

18.00 hrs

माननीय अध्यक्ष **:** सभा की कार्यवाही आज आठ बजे तक बढ़ायी जाती है ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The State of West Bengal attracts less than one per cent of the total Indian FDI. ….*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, अगर आप सवाल पूछेंगे, तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा । आपने सवाल किया है, तो वित्त मंत्री जी जवाब दे रही हैं ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, hon. Member, Supriya Sule had asked a question about the fiscal deficit target. She said that the target of 4.9 per cent may not be achieved and with Supplementary Demand it might go up to 5.6 per cent. ....*(Interruptions)* This is her apprehension. ....*(Interruptions)* I want to reply to the hon. Member, Supriya Sule. ....*(Interruptions)*

The year-end actuals of a year represent the full financial year?s expenditure. It is inclusive of additional appropriations that may have been granted to the Parliament by the parliamentary Supplementary Demand. ....*(Interruptions)* But I want to present before the hon. Member my fiscal deficit numbers. For the year 2021-22, the fiscal target deficit set was 6.8 per cent. What we achieved was 6.7 per cent. In 2022-23, 6.4 per cent was the target set, and 6.4 per cent was achieved. In 2023-24, 5.9 per cent was the target set, and 5.6 per cent was achieved, and in 2024-25, 4.9 per cent is what we mentioned here, I am confident of achieving that fiscal goal through the glide path which we have given. Therefore, 4.5 per cent of GDP for 2025-26 is what we will achieve though this method. ....*(Interruptions)*

Sir, before I come to the conclusion, I want to highlight one very important fact. ....*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, प्लीज़ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आसन की तरफ पीठ करके नहीं बैठते हैं ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, this is an important issue that I want to raise before I come to the conclusion. ....*(Interruptions)*

Sir, today, when we are discussing the journey of *Viksit Bharat*, I want to draw your attention towards a very serious issue. ....*(Interruptions)* To make India develop, it is necessary for the country to have big economic and strategic power. ....*(Interruptions)* But if there will be instability and anarchism in the country, the journey towards *Viksit Bharat* will become more difficult. ....*(Interruptions)* This is a huge challenge for us, and as a nation we have to understand where the problem is. ....*(Interruptions)*

<u>18.03 hrs</u>

At this stage Shri Abhishek Banerjee and some other hon. Member laft

the House.

Sir, India's social fabric, parliamentary traditions, economy and the Armed Forces ? all four are being severely attacked. ....*(Interruptions)* We have united our diverse society through the hard-working people of this country over the generations. ....*(Interruptions)* After Independence our Constitution was put in place and it has put in place several arrangements to keep the society united. ....*(Interruptions)* But today through a conspiracy the faultlines of our society are being exposed. ....*(Interruptions)* Mistrust is being created against each other in the society through fallacies, lies and deceit. ....*(Interruptions)*

Sir, efforts are being made to create such a situation that even a spark will lead to a lot of conflict. ....*(Interruptions)* Similarly, the attacks on the Armed Forces are also being intensified. ....*(Interruptions)* On some pretext or the other, or one pretext or the other, efforts are being made to divide the Army and the soldiers. ....*(Interruptions)* The strength of the Army is its discipline and unity. ....*(Interruptions)* As a part of a conspiracy, this strength of the Army is being challenged. ....*(Interruptions)* Whatever is happening today regarding Agniveer is a part of this conspiracy, I am afraid to say this. ....*(Interruptions)*

Apart from the society, Parliament and Army are all under attack and even the economy is being attacked. When the people of India have really struggled to come out of COVID-19 and are building a society on their efforts, we, as people representing them in this House, at least should recognise the hard work of our people and not undermine India as a country which is growing at this rate. So, entrepreneurship itself is being made a villain, which is a shame. The hard-

working entrepreneurs are building this country. The conspiracy is to end India?s entrepreneurship culture even before it fully blooms and thereby hitting at India?s core backbone, which is the entrepreneurship - small and medium units and enterprises ? what is building India.

Negativity is being spread in the society towards all those who do business. This hatred for business and wealth creators is filling everyone. There is a conspiracy to send a message to the entire world that India is not safe for investors, and this is

not good. Rumours are being spread that Indian institutions cannot guarantee security to foreign investments, which is really a sad situation. Strategic instability, economic instability and political instability ? some forces are working to create this kind of an image of India and we should all fight together so that this kind of instability building people should be told a lesson.

There is a huge nexus behind this, which is carrying out this conspiracy from the streets and even to the Parliament. No debates without protests, which are aggressive protests, are happening. You do not even hear answers which are being given. I am sorry to remind this hon. House that when the hon. Prime Minister stood up to speak, utmost disruption happened and people did not want to listen to him. They were screaming, but parliamentary institutional मर्यादा के ऊपर उनसे फर्स्ट लैक्चर आता है when all over the Well, they had people standing and people were forced or nudged or cajoled to say ?go into the Well and protest?. Sir, we have to keep institutional respect. Every countryman has come together to fight this conspiracy. We have to be alert. I take this opportunity to say this ? (*Interruptions*)

Sir, I come to the last matter. ? (*Interruptions*) Sir, the last matter is halwa. We should talk about it. Sir, it pains me actually ? (*Interruptions*) If only we know the background with which halwa ceremonies are conducted before the Budget is prepared ? (*Interruptions*) Why does the halwa ceremony happen? It is a very important phase. Actually in this country, halwa ceremonies have been happening for a very long time.

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी, कब से हो रही है, यह भी बता दीजिए ।

? (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण **:** सर, मिंटो रोड़ पर जब प्रिंटिंग प्रेस थी । जब बजट वहां पर प्रिंट होता था, तब से ले कर, staff who get themselves inside that premises, बजट प्रेज़ेंट होने तक जब तक बाहर नहीं आते थे, आज भी वह सिस्टम बरकरार है । वे लोग अपने आप, क्योंकि अंदर जाने के बाद, they cannot come out till the Budget is read, on their own, used to organise halwa making क्योंकि भारत में एक ट्रेडिशन है कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मुंह मीठा किया जाता है ।

यह भारत में हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा है । Sir, Navratri means nine nights and eight days. In earlier times, they used to stay inside only. There was no phone, no contact, and no landline. If anything happens, one officer who was given the power to come in and go out, he would convey the message. कुछ नहीं और बाहर वर्ल्ड से संपर्क है ।? (व्यवधान) Now-a-days, for five nights and four days, they stay in the cellar of North Block. This is essentially because the confidentiality of the Budget making has to be

respected. They go in and before going in we start this halwa ceremony. There are media reports, which captures this. I will read out one report. One media report says: ?It serves as a recognition for the hard work and dedication of the Finance Ministry officials and staff who have been diligently preparing the Budget documents. Dating back to 1980, the halwa ceremony precedes the printing of the Budget documents, which take place at the basement of the North Block, a process that must be completed without any official leaving the premises until the Budget is formally presented.? I would read one more line: ??a sense of solidarity and teamwork among the team members.? It also says: ?It stands as a testament to the tradition and protocols observed in one of the most significant events in the Indian governance calendar.?

The staff themselves make the halwa. ? (*Interruptions*) I wish hon. Members listen because they are very scared that something is coming to hit them. When did this become a photo event? I want to underline this. वर्ष 2013-14 में मंत्री जी ने नीचे सेलर में जाकर हलवा बाँटने की शुरुआत की । मैं उनसे पूछ रही हूं । By that time, the leader of the Opposition was a full active leader. इससे पहले ऑर्डिनेंस भी फाड़ा गया । विपक्ष के नेता ने वह इंडिपेंडेंस दिखाया । उस समय के फाइनैंस मिनिस्टर से पूछा नहीं गया कि कितने एससी हैं । आप फोटो के लिए नीचे जा रहे हैं, आप बोलो, नहीं तो मैं उस हलवा सेरेमनी को कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वह पावरफुल थे । उनके पास रिमोट कंट्रोल था । उन्होंने हलवा सेरेमनी क्यों नहीं कैंसिल की । तब यह नहीं पूछा गया कि भारत का हलवा बाँटा जा रहा है ।

सर, यह आदत किसी का होगा, अब वह जमाना चला गया । मलाई खाकर इस देश को छोड़ कर या पार्लियामेंट को छोड़ कर लोग गए । मलाई खाने वाले को लोगों ने रास्ता दिखा दिया कि आप चले जाओ, आपको सत्ता में नहीं बैठना है । वह जमाना चला गया । उस समय के फाइनैंस मिनिस्टर से यह पूछा नहीं गया कि आप नीचे बंटवारा करने के लिए जा रहे हो, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, उस समय नहीं पूछा गया । उस समय के ऑफिसर्स लोगों की स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुई, मगर अभी पूछा जा रहा है । इसीलिए, मैं बोल रही हूं कि इस देश में लोगों का बंटवारा करने में कुछ षडयंत्र के साथ प्रश्न पूछा जा रहा है । It is a shame. मैं इस मौके पर दो लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहती हूं । सर, आप नाम लेने के लिए परमिट नहीं करते हैं । वह मेम्बर भी नहीं है, मगर हमारे फाइनैंस मिनिस्ट्री की प्रिंटिंग के दो इम्पॉर्टेंट स्टाफ हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहती हूं ।? (व्यवधान)

प्लीज, आप सेक्रेड हलवा के विषय में सुन लीजिए । इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है । यह समझ में आएगा । रिटायर्ड अफसर जब अंदर पहुंचे, तो उनके पिता जी गुजर गए और उनके बाहर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी । श्री कुलदीप शर्मा जी, प्रेस के डिप्टी मैनेजर थे, उनके पिता जी के देहान्त होने की सूचना उनको अंदर जाने के बाद मिली । फिर भी वह कमिटमेंट देखिए, जब तक फाइनेंस का बजट डिक्लेयर हुआ, तब तक वे बाहर नहीं आए । मैं उनका सिर झुकाकर नमन करती हूं । ऐसे लोग उधर हैं । उनका सेंटीमेंट है, हलवा बनाना और बंटवारा करना । उनको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है । ?(व्यवधान)

मैं दूसरा बता रही हूं ।?(व्यवधान) श्री सुभाष अभी भी प्रिंटिंग प्रेस में हैं । ?(व्यवधान) अंदर जाने के समय उनको यह मैसेज आया ।?(व्यवधान) उनके सुपुत्र का देहान्त हो गया । वे बोले कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हलवा की सेरेमनी हो गई है । मैं अंदर आ रहा है । ?(व्यवधान) He said that I will not come out. उधर यह सेंटीमेंट है । हलवा बनाना और अंदर जाना, पूरा कर्तव्य निभाना और बाहर आना । ?(व्यवधान) इनको नीचे दिखाना सही नहीं है ।?(व्यवधान)

सर, एससी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर बहुत सारे विषयों पर हमारे एमपीज़ ने बात की।?(व्यवधान) फर्स्ट प्रधान मंत्री नेहरू जी का लेख शायद अनुराग जी ने पढ़कर सुना दिया । नेहरू जी ने 27 जून, 1961 को लिखा था । I quote: ?? I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards…?. This is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Okay. ?(*Interruptions*)

काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट की वर्ष 1955 में जब रिकमेंडेशन आ चुकी थी, तब से लेकर कांग्रेस पार्टी की हर गवर्नमेंट ने उसको दरकिनार कर दिया । बैकवर्ड कमीशन के लिए कहीं कोई सोच नहीं थी । In 1980, the Mandal Commission Report was submitted to Shrimati Indira Gandhi, तब की प्राइम मिनिस्टर and even she did not touch it. ? (*Interruptions*) मैं तब की कांग्रेस का नारा बोल रही हूं । My Hindi is not very good, but still I will say it. What was the slogan? ?न जात पर, न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर ।? जाति तब नहीं है, मगर अभी जाति बोला जा रहा है । ? (व्यवधान) कितने लोग हलवा सेरेमनी में थे, कितने लोग हलवा सेरेमनी फोटो में थे, कितने नीचे थे । ?(व्यवधान) अगर आप इसको तभी ले आते, तो ओबीसी आफिसर्स के लिए आज सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका था । ?(व्यवधान) You stopped it. ? (*Interruptions*)

शायद अनुराग जी ने नहीं बताया, मैं एक और कोटेशन पढ़ना चाह रही हूं । Late Rajiv Gandhi ji, the former Prime Minister gave an interview to Alok Mehta, a senior journalist in March, 1985. In that interview, the former Prime Minister says this about OBC reservation. मैं कोट कर रही हूं : ?? No promotion of idiots in the name of reservation and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country??. ? (*Interruptions*) ये रिजर्वेशन के ऊपर इतना लेक्चर दे रहे हैं ।? (व्यवधान)

अंबेडकर जी कैबिनेट से निकल करके, he said, ?I do not want to be in this because there is no justice for backward communities or for SCs?. ? (*Interruptions*) उनकी चिट्ठी में यह सब विषय है । लंबी सी चिट्ठी है, मगर मैं रेलवेंट पैराग्राफ पढ़ रही हूं । ?(व्यवधान)

?I will now refer to another matter that has made me dissatisfied with the Government. It relates to the treatment accorded to the backward classes and Scheduled Castes. I was very sorry that the Constitution did not embody any safeguards for the backward classes. It was left to be done by the Executive Government on the basis of recommendations of a Commission to be appointed by

the President. More than a year has elapsed since we passed the Constitution. But the Government has not even thought of appointing a Commission?. सरकार किसकी थी? the first Government was under Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. दादा-परदादा के ये सारे बयान हैं । आज रिजर्वेशन के ऊपर और एससी/एसटी की बात करते हैं । मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं, अंग्रेजी में बोलते हैं । Charity begins at home which means आप जो दूसरे को बोल रहे है, वह पहले आप करके दिखाओ, मैं पूछ रही हूं । राजीव गांधी फाउन्डेशन में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, बाहर वाले लोगों का नाम नहीं पढ़ना है, नौ लोग हैं, कोई एससी नहीं है, Charity begins at home. आप पहले अपनी व्यवस्था सही करो, एससी को जगह दो, फिर आकर हमसे पूछ लो ।

मैं फिर दूसरा उदाहरण देती हूं, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें पांच लोग बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हैं, नाम नहीं पढ़ रही हूं, मगर मुझे एक भी एससी नहीं दिखाई दे रहा है । एससी/एसटी के ऊपर हम सभी लोग कुछ अच्छा करने का इरादा रख सकते हैं । मगर जेनरेशन ऑफ्टर जेनरेशन दादा, परदादा, सबके बयान जब एक जैसे ही हैं और काम कुछ नहीं हुआ । आप आज जाकर बोलेंगे तो कैसे भरोसा आएगा? हलवा सेरेमनी जैसे एक इमोशनल सेंटिमेंटल मैटर, जिसमें पूरे मिन्ट का फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ अंदर बंद कमरे में रहकर काम करते हैं, उनके मुंह मीठा करने का काम मैं कर रही थी, लेकिन आप ऐसे प्रश्नचिन्ह लगाएंगे? मैं इस विषय में कैसे जवाब दूं, ऐसे सोच कर सिर पर हाथ रखा तो पूरी ट्रोल आर्मी के द्वारा मुझसे पूछा जा रहा है कि एससी के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं तो आप सिर पर हाथ रख रही है, हंस रही हो । एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे हैं । आपने बजट पर बोलने के लिए इतना समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूं । _

-

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

?कि कार्य-सूची के दूसरे स्तम्भ में मांग संख्या 1 से 36 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध मे 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों का भुगतान करने के निमित्त अथवा के उद्देश्य से, संबंधित धनराशियां, जो कार्य-सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी रकमों से अधिक न हों जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से राष्ट्रपति को लेखे पर प्रदान की जाएं ।?

<image: image002.gif>

<image: image003.gif>

<image: image004.gif>